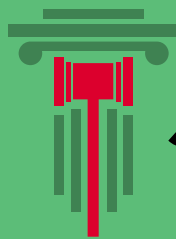


# इंडिया जस्टिस रिपोर्ट



पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी  
सहायता पर राज्यों की रैंकिंग



**India  
Justice**  
Report | 2022

# इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर या IJR) : पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता (Legal Aid) पर राज्यों की रैंकिंग

अप्रैल 2023 में प्रकाशित

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो राज्यों की न्याय देने की क्षमता को रैंक करती है।

मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, बजट, कार्यभार और विविधता के फिल्टर के माध्यम से यह जनादेश को पूरा करने के लिए न्याय प्रणाली के 4 मुख्य स्तंभों की क्षमता का आकलन करता है जिसमें पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पांच साल की अवधि के आंकड़ों की तुलना करके, आईजेआर न्याय प्रशासन में सुधार के लिए सरकारों द्वारा साल-दर-साल किए गए प्रयासों का आकलन करता है। यह 'रुझान' विश्लेषण न्याय की पहुँच में सुधार करने और इसे जमीनी स्तर पर जरूरतों के साथ मिलाने के प्रत्येक राज्य के इरादे को समझने में मदद करता है।

अलग अलग स्रोतों के द्वारा पहले से मौजूदा डेटा को एक ही स्थान पर लाकर आईजेआर नीति निर्माताओं को एक आसान लेकिन व्यापक उपकरण प्रदान करता है। एक ओर सभी डेटा को एक ही स्थान पर रखना, समग्र नीति ढांचे को आधार बनाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। जबकि दूसरी ओर, बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता में डेटा का विभाजन हमें न्याय व्यवस्था में कमजोरी और विकास को चिन्हित करने में मदद करता है। इस रिपोर्ट के माध्यम हम ये भी कोशिश करते हैं कि इस व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को पहले समझकर यदि शीघ्र ही निपट लिया जाए तो देश भर में इन क्षेत्रों में सुधारात्मक प्रतिक्रिया की श्रृंखला स्थापित हो सकती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष सरकारों, नागरिक समाज और व्यापारिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण हितधारकों को वस्तुनिष्ठ डेटा (Objective Data) प्रदान करता है, जिसके आधार पर वे अपनी सिफारिशें तैयार कर सकते हैं। यह सरकारों और अलग-अलग विचारधाराओं के सक्रिय नागरिकों के बीच एक ऐसा संवाद शुरू करने की कोशिश करता है जहां भागीदारी एक दूसरे की व्यक्तिगत राय के बजाय वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित रहती है। हमारा मानना है कि इस प्रकार सर्व सहमति के माध्यम से सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिरकार, न्याय हम सभी का हक है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://indiajusticereport.org> पर जाएं

**कवर डिजाइन :** नियति सिंह

**रिपोर्ट डिजाइन:** हाउ इंडिया लिक्स

**अनुवाद:** आवाज़ पहल, यूथ की आवाज़

**प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित**

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, प्रथम और यूजीएफ, कोटला मुबारकपुर साउथ एक्स के पास। भाग I, नई दिल्ली-110003

रिपोर्ट को ऑनलाइन देखने और वेब इंटरैक्टिव एक्सप्लोर करने के लिए इस कोड को स्कैन करें



© सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, 2023

यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। यह सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए कि यहां प्रस्तुत जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है। टाटा ट्रस्ट और लेखक इस रिपोर्ट में आमतौर पर और/या रैंकिंग के समर्थन में उपयोग किए गए संदर्भों, सूचना, डेटा या उनके स्रोतों की शुद्धता या सटीकता के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। डिजाइन सहित इस रिपोर्ट के किसी भी हिस्से को नीचे दिए गए उदाहरण या अध्याय का उपयोग करके किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, फोटो कॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिए दृष्टांत प्रारूप निम्नलिखित है :

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग (2022)',



## पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग

## इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2022 विभिन्न राज्यों में संचालित औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक करने के लिए सरकार के अपने आंकड़ों का उपयोग करने वाला एकमात्र व्यापक परिमाणात्मक सूचकांक (Quantitative Index) है। यह DAKSH, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के साथ साझेदारी में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित,आईजेआर का तीसरा संस्करण राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का आकलन जोड़ता है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता में बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता के मात्रात्मक माप के आधार पर न्याय प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और निरंतर घाटे को ट्रैक करना जारी रखता है।

### संचालन समिति

- डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, संस्थापक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- गगन सेठी, सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
- हरीश नरसम्पा, सह-संस्थापक, दक्ष
- माया दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- वलय सिंह, प्रोजेक्ट लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, भारत
- प्रोफेसर विजय राघवन, टीआईएसएस-प्रयास
- विपुल मुद्दल, निदेशक, कॉमन कॉज

### इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम

- माया दारूवाला, मुख्य संपादक
- वलय सिंह, प्रोजेक्ट लीड
- डॉ. रेहाना मंजूर, वरिष्ठ शोधकर्ता
- नयनिका सिंघल, अनुसंधान सहयोगी
- लखविंदर कौर, सांख्यिकी अधिकारी

### लेखक

- नूपुर, सामाजिक न्याय केंद्र
- राधिका झा, कॉमन कॉज
- वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, भारत
- देवयानी श्रीवास्तव, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
- देविका प्रसाद, स्वतंत्र शोधकर्ता
- मधुरिमा धानुका, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल
- सुगंधा माथुर, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
- संध्या आर, दक्ष
- लिआ वर्गीस, दक्ष
- स्मिता मठ, दक्ष
- प्रोफेसर विजय राघवन, टीआईएसएस-प्रयास
- अपूर्वा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- दीपिका किन्हल, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- वलय सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- डॉ. रेहाना मंजूर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

## साझेदारों के बारे में

- **सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (आइडियल)** एक संगठन है जो मुख्य रूप से न्याय तक पहुंच के क्षेत्र में हाशिये पर पड़े और कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। फ्रिरियन विचार से प्रेरित होकर, सीएसजे भारत भर के आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय रहा है, मानवाधिकार हस्तक्षेप कर रहा है, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के माध्यम से कानून को एक प्रमुख रणनीति के रूप में उपयोग कर रहा है। सीएसजे के प्रयासों के केंद्र में कानूनी सुधार और अनुसंधान में इसके संस्थागत हस्तक्षेप हैं, जो महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकारों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर जमीनी स्तर की सक्रियता, कानून और नीति निर्माण को जोड़ते हैं।
- **कॉमन कॉज** सार्वजनिक मुद्दों की वकालत करने, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संस्थानों की अखंडता के लिए अभियान चलाने के लिए समर्पित है। यह वकालत और लोकतांत्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीति सुधारों को बढ़ावा देना चाहता है। कॉमन कॉज को विशेष रूप से बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से किए गए अंतर के लिए जाना जाता है, जैसे कि हाल ही में संपूर्ण दूरसंचार स्पेक्ट्रम को रद्द करने पर; मनमाने ढंग से आवंटित कोयला ब्लॉकों को रद्द करना; और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देना।
- **राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई)** एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल के भीतर अनुसंधान, रणनीतिक वकालत और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव अधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। सीएचआरआई न्याय तक पहुंच (पुलिस और जेल सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया अधिकारों और गुलामी के समकालीन रूपों के उन्मूलन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करता है। सीएचआरआई एक राष्ट्रमंडल मान्यता प्राप्त संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र ईसीओएसओसी के साथ विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है।
- **DAKSH** एक बेंगलुरु स्थित नागरिक समाज संगठन है जो डेटा विज्ञान, सार्वजनिक नीति और संचालन अनुसंधान के चौराहे पर न्यायिक सुधारों पर काम कर रहा है। 2014 में शुरू की गई रूल ऑफ लॉ परियोजना के तहत वे भारत में जवाबदेही और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और गतिविधियां चलाते हैं।
- **TISS-प्रयास** 1990 में स्थापित सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। प्रयास का ध्यान सेवा वितरण, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण और हिरासत के संबंध में नीति परिवर्तन पर है। सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और समूहों के संस्थागत अधिकार और पुनर्वास। उनका मिशन सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर और बहिष्कृत समुदायों, समूहों और व्यक्तियों के विशिष्ट संदर्भ में आपराधिक न्याय प्रणाली नीति और प्रक्रिया के पहलुओं की वर्तमान समझ में ज्ञान और अंतर्दृष्टि का योगदान करना है, जिनके अपराधी होने या तस्करों के संपर्क में आने का अधिक खतरा है। यौन शोषण के उद्देश्य से।
- **विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो बेहतर कानून बनाने और जनता की भलाई के लिए शासन में सुधार करने के लिए कानूनी शोध कर रहा है। विधि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ भी जुड़ती है, और प्रभावी कानूनों और नीतियों को बेहतर ढंग से सूचित करने और सहायता करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों और नागरिक समाज के सदस्यों के भीतर अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ भी सहयोग करती है। केंद्र कानूनी सुधार के क्षेत्रों में स्वतंत्र अनुसंधान भी करता है और स्वतंत्र रूप से इसका प्रसार करता है, जिसे वह भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

# प्रस्तावना

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तीसरे संस्करण की प्रस्तावना लिखना मेरे लिए सम्मान की बात है। आईजेआर, जैसा कि ज्ञात हो चुका है, एक उत्सुकता से प्रतीक्षित मूल्यांकन है

भारतीय राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता। यह न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध समर्पित शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा हमारे पास लाया गया है। यह सक्रिय नागरिकों, मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन सरकारी एजेंसियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है जिन्हें सभी को प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान करने की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बजट, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यभार पर डेटा को विखंडित करके और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक उप-प्रणाली में समय के साथ परिवर्तनों को मापकर और सभी को एक ही स्थान पर लाकर, आईजेआर हमें न्याय के वितरण का समग्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है।

हाल के दिनों में, प्रौद्योगिकी ने सार्वजनिक डोमेन में अधिक डेटा डालने में मदद की है और राज्यों के प्रदर्शन और प्रगति की रिपोर्ट की आवश्यकता रैकिंग पूरी तरह से सरकार के अपने डेटा पर निर्भर करती है। यह स्व-लगाया गया प्रतिबंध रिपोर्ट को प्रामाणिकता प्रदान करता है, साथ ही यह न्याय वितरण तंत्र का दर्पण भी है। फिर भी, भले ही यह विश्लेषण के लिए वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में डेटा के मूल्य का प्रमाण देता है, यह

अनजाने में कई खामियों को सामने लाता है जो अकेले सरकारी डेटा के आधार पर विश्लेषण को प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट की एक विशेषता यह है कि यह जानबूझकर प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने से बचती है या यहां तक कि पुरानी कमजोरियों और मरम्मत में आसान तत्वों पर दशकों से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। यह समय श्रृंखला डेटा को - जैसे कि महिलाओं को शामिल करने की धीमी गति और समाज के पारंपरिक रूप से भेदभाव वाले वर्गों को सिस्टम के भीतर जगह खोजने की अनुमति देता है - खुद के लिए बोलने देता है। लेकिन इसकी खोज की सच्चाई मरम्मत के लिए शीघ्र कदम उठाने पर मजबूर करती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) का यह तीसरा संस्करण ऐसे समय में आया है जब न्याय की आवश्यकता - सुलभ विवाद समाधान और समाज में समानता और समानता को बढ़ावा देने के अर्थ में - हमारे लोगों की संतुष्टि तक इसे पहुंचाने की क्षमता से आगे निकल रही है।

मैं न्याय प्रणाली में शामिल सभी एजेंसियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे आईजेआर के निष्कर्षों और अंतर्दृष्टि पर ध्यान दें। इस तरह की रिपोर्ट सहभागी कामकाज के हमारे लोकतांत्रिक तरीकों का एक प्रमाण है और सक्रिय नागरिकों के अपने शासन में योगदान के रूप में इसका स्वागत किया जाना चाहिए।



**उदय उमेश ललित**

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश  
[27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022]

14 फरवरी 2023

# अभिस्वीकृति (एकनाँलेजमेंट)

तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सामूहिक सदस्यों और टाटा ट्रस्ट की संस्थापक टीम के बीच निरंतर और निरंतर सहयोग का परिणाम है। एक संस्थापक सदस्य के रूप में यह बहुत गर्व और खुशी की बात है कि यह समूह महामारी के कठिन दौर में भी एकजुट रहा। समूह के प्रत्येक सदस्य के दृढ़ समर्थन के बिना यह रिपोर्ट संभव नहीं होती। गगन सेठी, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, विपुल मुद्गल, कॉमन कॉज, हरीश नरसम्पा, दक्ष, डॉ. विजय राघवन, प्रयास-टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, और वेंकटेश नायक को हार्दिक धन्यवाद। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव में उनके पूर्ववर्ती संजय हजारीका। हमारे विधि सहयोगियों को, जो सबसे उदार और मददगार रहे हैं, विशेष धन्यवाद।

हमारे सहयोगी संगठनों के सहकर्मियों-राधिका झा, देवयानी श्रीवास्तव, देविका प्रसाद, मधुरिमा धानुका, सुगंधा शंकर, नूपुर, अपूर्वा, दीपिका किन्हल, संध्या पी.आर., स्मिता मट, लीह वर्गीस और बी.एस. सूर्यप्रकाश का उदार योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा इस रिपोर्ट के लिए एंकरिंग लेख लिखना सम्मान की बात है।

आईजेआर को हमारे विषय सलाहकारों- ईश कुमार (पूर्व डीजी, एनसीआरबी), जयंतो चौधरी (डीजी, एनएसजी), सुश्री मीरान बोरवकर, (पूर्व डीजी, बीपीआरएंडडी), सुनील चौहान, के लंबे वर्षों के अनुभव और अंतर्दृष्टि से काफी फायदा हुआ है। एनएएलएसए के पूर्व निदेशक, अविनाश राजवंशी, एन. रामचंद्रन (आईपीएफ), डॉ. विनीत कपूर, रीवा पोचा, प्रोफेसर मुरली कर्णम, और ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के रामनाथ झा और प्रोफेसर मधु भल्ला।

हम न्यायमूर्ति मदन बी. लोकर के आभारी हैं - हर कदम पर एक निरंतर मार्गदर्शक, रिपोर्ट के एक दुर्लभ संरक्षक संत, जिनकी सलाह और ज्ञान के बिना आईजेआर बहुत खराब होता।

राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों से प्रतिक्रियाएं एकत्र करने और साझा करने के लिए श्री प्रदीप शर्मा (एनएएलएसए) के साथ-साथ आरटीआई उत्तरों को एकत्रित करने में हमारी मदद करने के लिए संगीता मुखर्जी, सीएचआरआई को हमारा आभारी धन्यवाद।

हम अपने डेटा और डिजाइन पार्टनर हाउ इंडिया लिक्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वेबसाइट निःशुल्क बनाने के लिए रुषभ मेहता, फारिस अंसारी और फ्रैपे टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे।

शुरुआत से ही हमारे साथी यात्रियों को हार्दिक धन्यवाद: देबासिस रे, नयनतारा दत्ता, अनिरुद्ध मेनन, साथ ही नियति सिंह, उनके रचनात्मक इनपुट और सलाह के लिए।

हमें जयंत बांठिया, आलोक प्रसन्ना कुमार, ऋषभ लालानी, स्मिता गुप्ता, निकुंज, उदिता सिंह, प्रोफेसर वेद कुमारी, प्रोफेसर जीएस बाजपेयी, अंकित कौशिक, इवनीत वालिया और गौतम मिश्रा के समर्थन और परामर्श से लाभ हुआ है।

हमारे प्रतिभाशाली प्रशिक्षु- रितिका गोयल, अनन्या गिरी उपाध्याय, निवेदिता प्रसाद, अविरल मिश्रा, स्नेहा भांभरी, कार्तिक भारद्वाज, वैष्णवी गौड़, कौशिक चन्द्रशेखर, अलेख श्रेयस राव- विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

हम अपने दानदाताओं- रोहिणी नीलेकणि फिलैंथ्रोपीज, ट्री ऑफ लाइफ फाउंडेशन, लाल फैमिली फाउंडेशन, फियोना और लुईस मिरांडा, साइरस गुजडर, स्वयं चैरिटेबल ट्रस्ट और फ्रैपे के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं।

अंत में, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस कोर टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम किया और चौबीसों घंटे काम किया। हमारे वरिष्ठ सलाहकार और मुख्य संपादक, माजा दारूवाला, जो हमें गुणवत्ता और कठोरता के उच्चतम मानकों पर रखते हैं। लखविंदर कौर, हमारी आंतरिक सांख्यिकी विशेषज्ञ, जिनकी दृढ़ता और विस्तार पर नजर यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट न केवल त्रुटियों से मुक्त रहे बल्कि प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ इसमें सुधार भी हो। नयनिका सिंघल और रेहाना मंजूर को शोध की एंकरिंग और रिपोर्ट लिखने के लिए धन्यवाद।

**वलय सिंह**

प्रोजेक्ट लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स

# संक्षिप्तिकरण (एबीवीएशंस)

एडीडीएल. डीजीपी	एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	एमपीएफ	मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस स्कीम
एडीडीएल. एसपी	एडिशनल सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस	एमएसएमई	मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल, एंड मीडियम एंटरप्राइजेज
एएफएसपीए	आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट	नालसा	नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी
एआईजीपी	असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	एनसीआरबी	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
एआईएमओ	ऑल इण्डिया मैनुफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन	एनजेडीजी	नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रीड
एसआइ	असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस	एनपीसी	नेशनल पुलिस कमीशन
एसपी	असिस्टेंट सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस	एनआरसी	नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन
ए एंड एन आईलैंड्स	अंडमान एंड निकोबार आइलैंड	ओबीसी	अदर बैकवर्ड क्लासेज
बीपीआर एंड डी	ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट	पीएचआरए 1993	प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट
ब्रिक्स	ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, एंड साउथ अफ्रीका	पीएलए	परमानेंट लोक अदालत
सीएजी	कंश्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया	पीएलवी	पेरालीगल वॉलंटियर
सीसीआर	केस क्लीयरेंस रेट	पीपी	पर्सोनेल पॉइंट्स
सीसीटीएनएस	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स	पीएसआई	प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया
सीसीटीवी कैमरा	क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा	आरटीआई	राइट टू इन्फॉर्मेशन
सीआरपीसी	कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर	एससी	शेड्यूल्ड कास्ट
डीजीपी	डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	एचएचआरसी	स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन
डीआईजी	डेप्युटी इंस्पेक्टर जनरल	एसआई	सब इंस्पेक्टर
डीएलएसए	डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी	एसएलएसए	स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी
डीएनएच एंड डीडी	दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियू	एसपी	सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस
डीवाई. एसपी	डेप्युटी सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस	एसपीएल. डीजीपी	स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
एफवाई	फाइनेंशियल ईयर	एसएसपी	सीनियर सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस
एचपीसी	हाई पावर्ड कमिटी	एसटी	शेड्यूल्ड ट्राइब
आईजीपी	इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	यूएनओडीसी	यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम
आईएलओ	इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन	यूटी	यूनियन टेरिस्ट्री
एलएसआई	लीगल सर्विसेज इंस्टिट्यूशन	यूटीपी	अंडर ट्रायल प्रिजनर्स
एमएचए	मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स	यूटीआरसी	अंडर ट्रायल रिब्यू कमिटी

## राष्ट्रीय निष्कर्ष

सर्वाधिकार (कॉपीराइट) और उद्धरण (साइटशन्स)	ii
शीर्षक पृष्ठ	iii
रिपोर्ट और टीम के सदस्यों के बारे में	iv
साझेदारों के बारे में	v
पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित द्वारा प्रस्तावना	vi
अभिस्वीकृति (एक्नोलेजमेंट)	vii
संक्षिप्तिकरण (एब्रीविएशंस)	ix
विश्व में भारत	1
राष्ट्रीय कमियां	2
माया दारूवाला द्वारा परिचय	4

कुल रैंकिंग	10
न्याय के 4 स्तंभों में प्रत्येक श्रेणीबद्ध राज्य	11
आईजेआर 2020 और आईजेआर 2022 के बीच सुधारकार्ड	12
आईजेआर 2019, आईजेआर 2020, आईजेआर 2022 में प्रदर्शन	13
रैंकिंग विविधता	14
स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा	15
महिला पुलिस कर्मियों में हिस्सा 33% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा	16
पुलिस में 'अन्य' की रोचक स्थिति	17
मानव संसाधन की रैंकिंग	18
न्यायधीश और जनसंख्या अनुपात	19
स्तंभों में रिक्तियां	20
रैंकिंग का इरादा	22
न्याय प्रणाली के बजट	23
राज्य का कानूनी सहायता का बजट में हिस्सा	24
राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों का हिस्सा	25
अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लम्बित मामले	26
उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले	27

## पुलिस

पुलिस रैंकिंग	32
उम्मीदें बढ़ाना	33
पुलिस : अक्षमता, एक सतत चुनौती	34
पुलिस में एससी, एसटी, ओबीसी रिक्तियां	38
महिला पुलिसकर्मी: संख्या बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत कम है	40
भारत: पुलिस प्रशिक्षण बजट (2020-21)	43
पुलिस की उपस्थिति: ग्रामीण शहरी विभाजन	44
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	48
राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति	54
पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी	58

## जेल

जेलों की रैंकिंग	62
उम्मीदें बढ़ाना	63
निराशाजनक परिस्थितियों से उबारने की सीमा तक	64
भारतीय जेलों में अधिभोग दर	66

## जेल

जेलों में अत्यधिक भीड़	67
हिरासत अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदी	68
कैदियों की शिक्षक प्रोफाइल और प्रदान की जाने वाली सुविधाएं	70
मानकों को पूरा करना	71
पिछले दशक में जेल बजट उपयोग की राष्ट्रीय प्रवृत्ति राशि	74
प्रति कैदी दैनिक व्यय	76
कर्नाटक में जेलों का सुधार	77
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	78

## न्यायपालिका

न्यायपालिका की रैंकिंग	86
उम्मीदें बढ़ाना	87
न्यायपालिका : संख्याओं को आंकना	88
न्यायाधीशों की रिक्ति एवं केस क्लीयरेंस दर	90
न्यायाधीश की दुविधा	91
अधीनस्थ न्यायालय में एससी, एसटी, और ओबीसी न्यायाधीशों की रिक्ति	93
महिला न्यायाधीश	94
प्रति न्यायाधीश लम्बित मामले	97
केस क्लीयरेंस दर	99
ग्राम न्यायालय: एक अवास्तविक दृष्टिकोण	100
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	102

## कानूनी सहायता

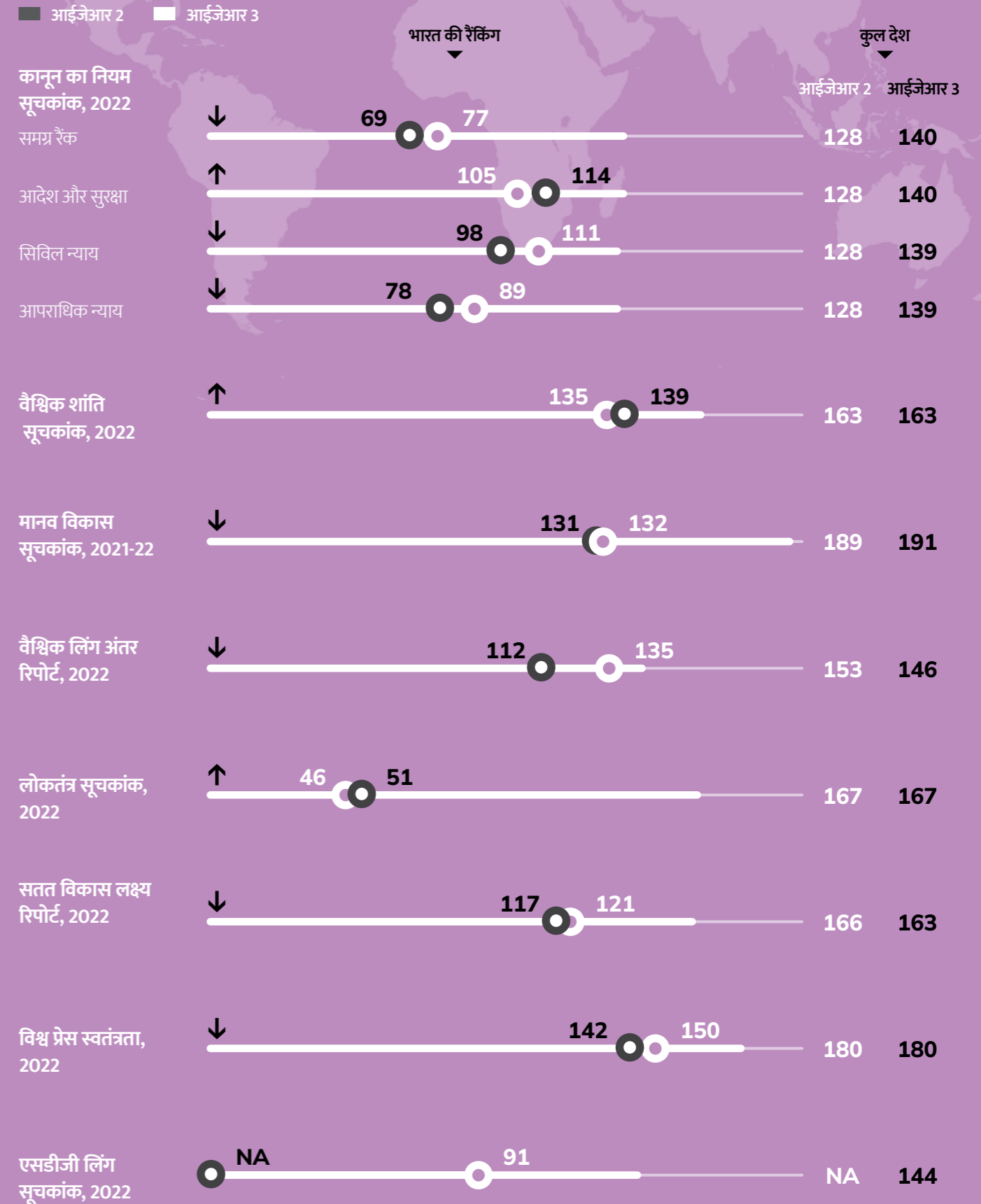
कानूनी सहायता रैंकिंग	110
उम्मीदें बढ़ाना	111
निशुल्क कानूनी सहायता: सभी के लिए न्याय एक दूर के सपने समान	112
पेरालीगल वॉलंटियर्स: संख्याओं का मानचित्रण	114
बजट का उपयोग	116
एक कानूनी सहायता क्लिनिक पर कितने प्रति गांव	118
लोक अदालतों का प्रदर्शन	120
पीड़ित मुआवजा	122
अनावश्यक पूर्व न्यायिक निर्वासन	123
विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों का प्रदर्शन	124
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	125

## राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएचआरसी)

एसएचआरसी रैंकिंग	130
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	131
एचएचआरसी: क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं	132
आयोगों में रिक्तियां	134
तीन वर्षों में एसएचआरसी द्वारा प्राप्त और निपटाए गए मामले	136
राज्य मानवाधिकार आयोगों की वेबसाइटों की स्थिति	138

आईजेआर 2022 के लिए आंकड़ों का संग्रह के लिए आरटीआई का उपयोग करने का अनुभव : एक टिप्पणी	142
आंकड़ों में चुनौतियां	147
कार्यप्रणाली	150
सुझाव	155
शब्दावली (ग्लोसरी)	156
संदर्भ (रेफरेंस)	166
तालिकाओं, मानचित्रों और आंकड़ों की सूची	168

# विश्व में भारत (India in the world)



# सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी



## एससी/एसटी/ओबीसी

हर राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य कोटा है। पुलिस में **केवल कर्नाटक** ही इन आरक्षणों को पूरा कर पाया है।

## महिलाये

एक भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए **अपने स्वयं के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं** करता है।

## ग्रामीण-शहरी विभाजन

19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **शहरी पुलिस स्टेशन अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक आबादी की सेवा करते हैं।**

केरल के शहरी पुलिस स्टेशन ग्रामीण की तुलना में दस गुना और गुजरात के चार गुना आबादी की सेवा करते हैं।

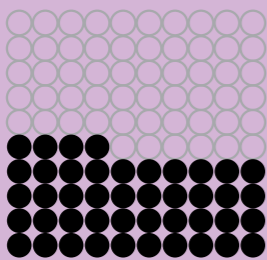


मार्च 2021 में सभी 25 राज्य मानवाधिकार आयोगों में लंबित मामलों की कुल संख्या

# 33,312

25 राज्य मानवाधिकार आयोगों में राष्ट्रीय औसत रिकॉर्ड

# 44%



## सीसीटीवी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन

**केवल अरुणाचल प्रदेश** के सभी 24 पुलिस स्टेशनों के सभी 14 स्थानों (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है) में सीसीटीवी कैमरे होने की सूचना है। केवल 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा) ने नाइट विजन से सज्जित सीसीटीवी होने की सूचना दी।

# सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी



## न्यायाधीश रिकॉर्ड

सिक्किम के उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ में जिला अदालतों को छोड़कर **कोई भी न्यायालय पूर्ण न्यायाधीशों के साथ काम नहीं** करती है।

## एससी/एसटी/ओबीसी

जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका। उच्च न्यायालयों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों पर डेटा उपलब्ध नहीं है।

## प्रकरण निपटान दर

18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, **केवल केरल और पंजाब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों स्तरों पर 100 प्रतिशत** और उससे अधिक की प्रकरण निपटान दर प्राप्त कर सके।



# 9,417

कानूनी सेवा क्लिनिकों की संख्या 14,159 (2020) से घटकर 4,742 (2022) हो गई है।

# ₹7,322 करोड़

2021-2022 के बीच राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा कुल बंदोबस्त राशि



**32** राज्य जहां विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी 60% से अधिक है



**24** 2021 के दौरान 5% से कम कैदियों को शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश



**5** जिन राज्यों ने 2021 में कैदियों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया



# परिचय

## प्रत्येक प्रणाली को पूरी तरह से परिणाम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### डब्ल्यू. एडवर्ड्स डेमिंग

2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सभी को न्याय देने के लिए अपने प्रमुख न्याय वितरण तंत्र-न्यायपालिका, पुलिस, जेल ( जिसे कारागार भी कहते हैं ) और कानूनी सहायता-को सक्षम बनाने में प्रत्येक राज्य की प्रगति का आकलन और श्रेणीकरण करना जारी रखती है। रिपोर्ट में एक नया खंड राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता को मापता है, जो न्याय तक पहुँचने का एक विशेष साधन है और 25 राज्यों में मौजूद है। हर दिन हजारों लोग उन तक पहुँचते हैं। वे अपने जनादेश को पूरा करने के लिए कितने सुसज्जित हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट 17 नए संकेतकों को जोड़ने के साथ अपने 4 स्तंभ मूल्यांकन को भी गहरा करती है<sup>1</sup>।

यह तीसरा संस्करण 24 महीनों के बाद आया है जिसमें पूरी न्याय प्रणाली को कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन द्वारा बनाई गई असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थितियों से जूझना पड़ा है। महामारी और लॉकडाउन ने मिलकर गंभीर व्यवधान पैदा किए जहां न्याय की पहुंच और वितरण दोनों को नुकसान हुआ।

प्रत्येक भूगोल (Every Geography) में प्रत्येक उप-प्रणाली ने इस अप्रत्याशित समय में पुरानी दुर्बलताओं के साथ प्रवेश किया: लंबे समय से कम धन, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी, और काम का बोझ जो सार्वजनिक सेवा के उचित मानकों को पूरा करने की चुनौती का प्रमाण है।

फिर भी, प्रतिकूलता, खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक चिंताओं और मौतों के इस पैमाने से निपटने में अपने स्वयं के अनुभव की कमी के बावजूद, एक बहुत ही कमजोर बल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस अवधि के दौरान, 23.5 करोड़ मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की गई।<sup>2</sup>

भीड़भाड़ कम करने के प्रयासों से अधिकांश राज्यों में जेलों में कैदियों की संख्या कम हो सकती है।<sup>3</sup> एक लड़खड़ाती शुरुआत के बावजूद, पुलिस कर्मियों ने अपनी सहायता के लिए सार्वजनिक प्रशंसा प्राप्त की और कानूनी सहायता अधिकारियों ने हजारों लोगों को मानवीय

सहायता प्रदान करने के लिए अपने पारंपरिक जनादेश से परे चले गए।

## रैंकिंग

इस असाधारण समय से बाहर निकलते हुए, कई राज्यों ने रैंक में नाटकीय बदलाव देखे हैं। कुछ अच्छे के लिए और कुछ बुरे के लिए। कर्नाटक, 2020 में 14वें स्थान पर, तेरह स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश 16वें से 8वें और आंध्र प्रदेश 12वें से 5वें स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम दूसरे से पहले और अरुणाचल प्रदेश पांचवें से दूसरे स्थान पर आ गया है।

इसके विपरीत, महाराष्ट्र आई. जे. आर. 2019 और आई. जे. आर. 2020 दोनों में शीर्ष स्थान से 11वें स्थान पर पहुँचकर हार गया। पंजाब आठ पायदान नीचे गिरकर चौथे से 12वें स्थान पर आ गया है। छोटे राज्यों में राजस्थान पांच स्थान गिरकर 15वें और गोवा तीसरे स्थान से गिरकर अंतिम स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु और तेलंगाना ने बढ़े और मध्यम आकार के राज्यों में दूसरा और तीसरा स्थान बनाए रखा, जबकि उत्तर प्रदेश लगातार तीसरी बार तालिका में सबसे नीचे रहा।

स्थान परिवर्तन की एक बारीकी से जांच एक बार फिर दर्शाती है कि छोटे लेकिन लगातार सुधार भी काफी नाटकीय वृद्धि का कारण बन सकते हैं। एक संकेतक में सुधार, जैसे कि एक रिक्ति को भरना या एक प्रणाली में अधिक विविधता का निर्माण करना, अन्य संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और समग्र रूप से समग्र रैंकिंग को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जेल स्तंभ में गुजरात का उदय रिक्तियों को कम करने और जाति और लिंग विविधता में सुधार के प्रयासों के कारण है। इससे काम का बोझ कम हुआ और आवंटित बजट के उपयोग में वृद्धि हुई, इन सभी ने राज्य के रैंक में वृद्धि में योगदान दिया।

हालाँकि, नीचे की ओर बदलाव आवश्यक रूप से राज्य में गिरावट के कारण नहीं हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अन्य राज्यों में सुधार हुआ है और स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष स्थानांतरित हो गई है। समान रूप से, एक सकारात्मक रैंक बनाए रखने का कभी-कभी न केवल एक राज्य के अपने सुधारों से बल्कि अन्य राज्यों में क्षमता सुधार की धीमी गति से भी लेना पड़ता है।

कुल मिलाकर, 1 से 10 के पैमाने पर, बोर्ड भर में अंकों में सुधार हुआ। आई. जे. आर. 2020 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला राज्य

महाराष्ट्र 5.77 अंक के साथ आया, जबकि आई. जे. आर. 2022 में तालिका में शीर्ष पर रहने वाले कर्नाटक ने 6.38 अंक प्राप्त किए हैं। यहां तक कि सबसे खराब स्कोर करने वालों ने भी 3.15 से 3.78 तक सुधार दिखाया।

फिर भी, दशकों से जारी अव्यवस्था समय पर न्याय देने में न्याय वितरण प्रणाली की असमर्थता को तेज कर रही है-जिसमें सबसे अधिक नुकसान न्याय उपयोगकर्ता पर पड़ रहा है।

## बजट

पुलिस और न्यायपालिका पर राज्यों के खर्च ने राज्य के समग्र खर्च के साथ तालमेल बनाए रखा है। जेल, पड़ोस का गरीब बच्चा, जिसने पहले आवंटन में गिरावट देखी थी, ने 2020 और 2021 के बीच धन में सुधार देखा। कानूनी सहायता में भी हाल ही में केंद्र और राज्य के खजाने से निवेश में वृद्धि देखी गई है।

यदि धन की कमी है, तो जो उपलब्ध है उसे अक्सर कम उपयोग में छोड़ दिया जाता है। 2020-2021 में केंद्र के आधुनिकीकरण अनुदान का केवल 47 प्रतिशत उपयोग किया जा सका। अक्सर प्रक्रिया, शर्त, समय, योजना में अति-केंद्रीकरण और आवश्यकता और अनुदान के बीच बेमेल होने के कारण यह सुनिश्चित होता है कि जो कुछ भी है, उसे तर्कसंगत रूप से खर्च या पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय आवंटन के संदर्भ में कम उपयोग को देखते हुए कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभागीय स्थायी समिति की 123वीं रिपोर्ट में बाधाओं की पहचान करने और उन उपायों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिनकी लंबे समय से "उन प्रणालियों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है जो उनकी उपयोगिता को खत्म कर चुके हैं।"<sup>4</sup> केरल में प्रचलित स्थानीय स्वशासन के स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना इनमें से कुछ मुद्दों से निपटने के लिए एक उपयोगी उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।<sup>5</sup>

## मानव संसाधन

रिक्तियां न्याय प्रणाली के सभी क्षेत्रों को परेशान कर रही हैं और लद्दाख में जेल कर्मचारियों की तरह 83 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं। उच्च न्यायालय और जिला दोनों न्यायालयों में पूर्ण न्यायाधीशों के साथ काम करने का लाभ किसी भी क्षेत्राधिकार को नहीं मिलता है। न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या अब प्रति दस लाख (दस लाख) आबादी पर 15 है।<sup>6</sup>

"स्वीकृत संख्या" और वास्तविक कर्मियों की उपलब्धता के बीच की

खाई एक बारहमासी समस्या बनी हुई है। हालांकि स्वीकृत बल को हर साल जमीनी जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए फिर से समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन यह साल-दर-साल बहुत कम बदलता है और अक्सर वास्तविकता से पीछे रहता है। उदाहरण के लिए, हालांकि जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच स्वीकृत पुलिस बल 26.3 लाख से बढ़कर 26.9 लाख हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर 20.9 लाख कर्मी थे।<sup>7</sup>

बिना संबोधित किए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरानी कमी खतरनाक रूप से तीव्र हो जाती है और आदर्श से बहुत दूर हो जाती है। 2020 और 2021 के बीच जेल डॉक्टरों की वास्तविक संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे रिक्तियों को 300 कैदियों के बेंचमार्क के बजाय लगभग 50 प्रतिशत या 842 कैदियों के लिए एक डॉक्टर तक ले जाया गया। इन रिक्तियों को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आँकड़े यह इंगित नहीं करते हैं कि क्या चिकित्सा अधिकारी स्थायी, निवासी, पूर्णकालिक या केवल एक जेल के लिए अनन्य हैं, या क्या वे केवल अनुबंध पर उपलब्ध हैं या आवधिक या अंशकालिक आधार पर उपलब्ध हैं, या केवल बुलाए जाने पर उपस्थिति में हैं।

बिना संबोधित किए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरानी कमी खतरनाक रूप से तीव्र हो जाती है और आदर्श से बहुत दूर हो जाती है। 2020 और 2021 के बीच जेल डॉक्टरों की वास्तविक संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे रिक्तियों को 300 कैदियों के बेंचमार्क के बजाय लगभग 50 प्रतिशत या 842 कैदियों के लिए एक डॉक्टर तक ले जाया गया। इन रिक्तियों को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आँकड़े यह इंगित नहीं करते हैं कि क्या चिकित्सा अधिकारी स्थायी, निवासी, पूर्णकालिक या केवल एक जेल के लिए अनन्य हैं, या क्या वे केवल अनुबंध पर उपलब्ध हैं या आवधिक या अंशकालिक आधार पर उपलब्ध हैं, या केवल बुलाए जाने पर उपस्थिति में हैं।

रिक्तियों को भरने के प्रयास मिश्रित हैं। डी. एल. एस. ए. ने सचिव रिक्तियों को भरने में काफी प्रगति की और बिहार जैसे कुछ ने जेल अधिकारियों की रिक्तियों को 66 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया। लेकिन पंजाब जैसे अन्य राज्यों में, जहां 2019 में स्वीकृत की तुलना में अधिक चिकित्सा कर्मचारी थे, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में रिक्तियों को बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया।

1 अधिक जानकारी के लिए कार्यप्रणाली पर निबंध देखें।

2 समाचार पत्र, ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिसंबर 2020 और नवंबर 2021:

3 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, महामारी का जवाब देना: जेल और भीड़भाड़, (राज्यों के भीड़भाड़ कम करने के प्रयास), 2020। <https://humanrightsinitiative.org/download/Responding%20to%20the%20Pandemic%20Prisons%20&%20Overcrowding%20Vol%201.pdf> पर उपलब्ध है।

4 कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। यहाँ उपलब्ध है: [https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee\\_site/Committee\\_File/रिपोर्टफाइल/18/171/123\\_2022\\_12.पी.डी.एफ.,पृष्ठ15,पैरा24](https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/रिपोर्टफाइल/18/171/123_2022_12.पी.डी.एफ.,पृष्ठ15,पैरा24)

5 "पुलिस के लिए बजट", लाइव मिंट, 11 अप्रैल 2017। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.livemint.com/Opinion/DR8kPY8VKUDyMlkr2OHUfM/Budgeting-for-the-police.html>

6 न्यायपालिका पर निबंध का संदर्भ लें।

7 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2021 और 2022।

## विविधता

राज्य के प्रयासों के सभी क्षेत्रों में विविधता और प्रतिनिधित्व हमारे बहुलवादी लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। विशेष रूप से न्याय क्षेत्र का इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने का नैतिक कर्तव्य है।

उपलब्ध आँकड़े इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्धता के स्तर को इंगित करते हैं। परंपरागत रूप से, आँकड़े केवल जाति और लिंग विविधताओं को ध्यान में रखते हैं। सक्रिय नागरिकों द्वारा वर्षों की वकालत में विकलांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की एक स्वागत योग्य गणना देखी गई है। लेकिन विविधता सूची अभी भी धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय विविधताओं की गणना को छोड़ती है। आधिकारिक आँकड़े पदानुक्रम के सभी स्तरों पर विश्लेषण करने के बजाय निचले स्तरों पर जाति और लिंग का अधिक आसानी से आकलन करने तक ही सीमित रहते हैं।

प्रत्येक राज्य के अपने मानक और वास्तविकताएँ होती हैं-आई. जे. आर. जो डेटा अनुमति देता है उसे पकड़ता है। चाहे वह जाति हो या लिंग, हर जगह समावेश में कमी है और मरम्मत की गति हिमनदीय बनी हुई है। दशकों की गरमागरम बहस के बावजूद, जबकि अलग-अलग राज्य एक या दूसरी श्रेणी को पूरा कर सकते हैं, कोई भी राज्य सभी उप-प्रणालियों में तीनों कोटा को पूरा नहीं करता है। न ही महिलाएं कहीं भी समानता के करीब हैं। जनवरी 2007 से जनवरी 2022 तक पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी को 3.3 प्रतिशत<sup>8</sup> से बढ़कर 11.8 प्रतिशत होने में पंद्रह साल लग गए हैं।

जाति और लिंग दोनों कांच की छत के खिलाफ आए। उदाहरण के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों में 35 प्रतिशत महिलाएँ हैं जबकि उच्च न्यायालयों में केवल 13 प्रतिशत हैं। इसी तरह, अधिकारी स्तर पर पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, जबकि सिपाही स्तर पर यह 12 प्रतिशत है। अधिकारी स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पुलिस की हिस्सेदारी क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है, जो कांस्टेबुलरी के भीतर 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 32 प्रतिशत से बहुत कम है।

जाति और लिंग दोनों कांच की छत के खिलाफ आए। उदाहरण के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों में 35 प्रतिशत महिलाएँ हैं जबकि उच्च न्यायालयों में केवल 13 प्रतिशत हैं। इसी तरह, अधिकारी स्तर पर पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, जबकि सिपाही स्तर पर यह 12 प्रतिशत है। अधिकारी स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पुलिस की हिस्सेदारी क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है, जो कांस्टेबुलरी के भीतर 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 32 प्रतिशत से बहुत कम है।

प्रतिनिधित्व और समानता के सिद्धांतों से दूरी का सबसे अच्छा उदाहरण शायद राज्यों के मानवाधिकार आयोगों की संरचना से मिलता है। पूरे एस. एच. आर. सी. समूह में महिलाएं केवल 17 प्रतिशत हैं। 25 आयोगों में से केवल 3 में एक-एक महिला सदस्य है। बाकियों के पास कोई नहीं है।

## बुनियादी ढांचा

पिछले दशक में और यहां तक कि रिपोर्टों के बीच भी, न्याय वितरण का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में धीरे-धीरे लेकिन लगातार सुधार हुआ है, विशेष रूप से न्यायपालिका और पुलिस के लिए और शायद पहले-उत्तरदाता स्तर की तुलना में उच्च स्तर पर। भले ही स्थानीय कमी बनी हुई है<sup>9</sup>, वर्तमान में देश भर में न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त अदालत कक्ष हैं। इस दशक में देश भर में लगभग एक चौथाई और पुलिस स्टेशन जोड़े गए हैं, हालांकि औसतन 1 187 वर्ग किलोमीटर के कवरेज के साथ 78,000 से अधिक लोगों की सेवा करता है। सभी पुलिस थानों में से 72 प्रतिशत में अब महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क हैं।

जेल का बुनियादी ढांचा हालांकि पूरी तरह से अपर्याप्त है। 1, 314 जेलों में से 391 में 50 प्रतिशत से अधिक भीड़ है। अनिवार्य शैक्षिक सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास में सहायता के लिए सुविधाएं प्राथमिक बनी हुई हैं। महामारी के दौरान तेजी से भीड़भाड़ कम करने के प्रयासों के एक छोटे अंतराल के बाद, जेलों को फिर से भरने की अनुमति दी गई है-ज्यादातर विचाराधीन कैदियों के साथ।

भौतिक बुनियादी ढांचे और कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी, संपर्क, कम्प्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय प्राप्त करने और प्रदान करने के तरीकों पर दृढ़ता से भरोसा किया जा रहा है और इन प्रयासों ने पहले की तरह गति प्राप्त की है। ई-भुगतान और ई-सेवा केंद्रों सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित पोर्टलों के माध्यम से सूचना और सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक समन और राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रेकिंग (एन. एस. टी. ई. पी.) जैसे ट्रेकिंग ऐप के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाया है। अधिक जेलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं में वृद्धि की है और परमवीर फैसले के बाद, पुलिस थानों के अंदर गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं।

उद्देश्य, सुरक्षा, निजीकरण, स्थानीयकरण, एकीकरण, अप-स्किलिंग, पुराने वातावरण, प्रारूपों और रूपों के तर्कसंगतकरण, प्रतिरोध और परिवर्तनों की स्वीकृति के मुद्दे बने हुए हैं। कम से कम पहुंच का सवाल नहीं है-क्या प्रौद्योगिकी न्याय की उपलब्धता के अंतर को बढ़ाएगी या विशेषाधिकार और बहिष्करण के अधिक अंतःक्षेत्र बनाएगी।

## निष्कर्ष में

उप-प्रणालियों के पांच साल के आकलन ने रुझानों और प्रतिमानों को आगे बढ़ाया है। बहुत अधिक, जैसे रिक्तियां और अदालती मामलों का संचय, लगातार नीचे की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अन्य जैसे बेहतर मामले निकासी दर और लिंग अनुपात और प्रतिक्रिया में धीमी लेकिन निरंतर सुधार, सभी बाधाओं के खिलाफ सुधार के लिए संकेत निर्धारण। कुल मिलाकर, वित्तपोषण में मामूली वृद्धि हुई है। कानूनी सहायता में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश और प्रयोग जरूरतमंदों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व में वृद्धि का वादा करते हैं।

महामारी के दौरान, न्याय वितरण प्रणाली के सामने चुनौती एक अभूतपूर्व स्थिति के माध्यम से काम करने के तरीके खोजना और नवीन प्रतिक्रियाओं को विकसित करना था, भले ही हर उप-प्रणाली जबरदस्त दबाव में थी। महामारी के बाद, यह चुनौती बढ़े हुए रूप में जारी है।

महामारी के दौरान, न्याय वितरण प्रणाली के सामने चुनौती एक अभूतपूर्व स्थिति के माध्यम से काम करने के तरीके खोजना और नवीन प्रतिक्रियाओं को विकसित करना था, भले ही हर उप-प्रणाली जबरदस्त दबाव में थी। महामारी के बाद, यह चुनौती बढ़े हुए रूप में जारी है।

भीड़भाड़ 120 प्रतिशत से बढ़कर 130 प्रतिशत हो गई। 77 प्रतिशत पर, पहले से कहीं अधिक विचाराधीन कैदी कैदी आबादी बनाते हैं-औसतन पहले से कहीं अधिक समय जेल में बिताते हैं। कानूनी सहायता संस्थान,

सर्वोत्तम प्रयासों के साथ भी, अपने संभावित ग्राहकों के केवल एक अंश तक ही पहुंच सके। लगभग 5 करोड़ (5 मिलियन) कुल लंबित मामलों के आंखों में पानी लाने वाले आंकड़ों के नीचे निराशाजनक स्थिति है जो समाधान तक पहुंचने में लगने वाले समय की लगातार बढ़ती अवधि को दर्ज करती है।

स्पष्ट रूप से संकट की यह स्थिति, जहां अधिकारियों से असंभव स्तरों पर काम करने की उम्मीद की जाती है और जिससे न्याय चाहने वालों को बहुत कम उम्मीद होती है, तत्काल मरम्मत के लिए चिल्लाती है।

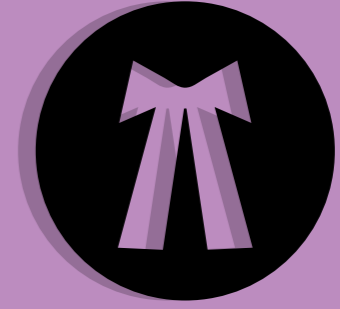
अपनी तुलनाओं और प्रवृत्ति विश्लेषणों के साथ रिपोर्ट का उद्देश्य उन लोगों से आग्रह करना है जो टिलर पर अपना हाथ रखते हैं कि वे तत्काल मरम्मत के लिए इसके निर्देशों को समझें, प्राथमिकताएं निर्धारित करें, रणनीतिक पुनर्निवेश और संसाधनों की पुनः तैनाती की संभावना की जांच करें, और तेजी से और सस्ते में न्याय देने में अपने स्वयं के प्रयासों का आकलन करें, विशेष रूप से सबसे दूरदराज और कमजोर समुदायों में। हर महीने की देरी समाधान को कठिन बनाती है।

सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 16 के तहत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में, भारत "शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों के निर्माण" के लिए प्रतिबद्ध है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में लोकतंत्र का पालन करने का वादा इस आश्वासन पर आधारित है कि गुणवत्तापूर्ण न्याय-निष्पक्ष और सुलभ-हर किसी के लिए प्रदान किया जाएगा। बर्बाद करने के लिए बहुत कम समय है।

## माया दारुवाला

संपादक और संयोजक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

8 जनवरी 2007 के आंकड़ों में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल नहीं हैं। चूंकि वास्तविक पुलिस कर्मियों का डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।  
9 न्यायपालिका पर निबंध का संदर्भ लें।



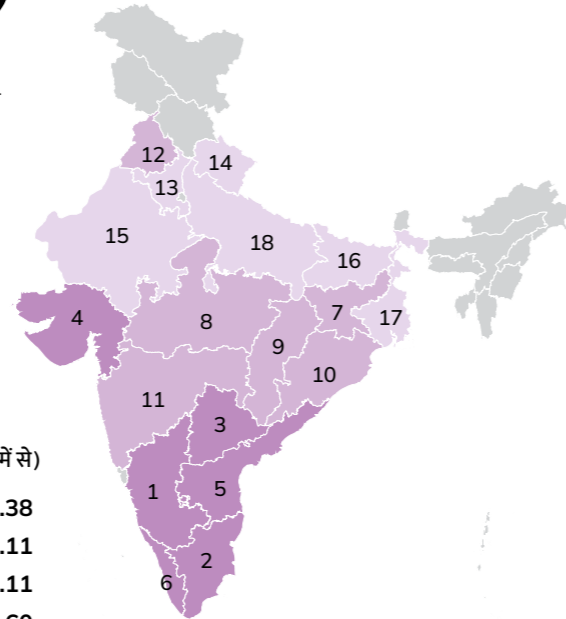
**राष्ट्रीय निष्कर्ष**

# कुल रैंकिंग (Overall Ranking)

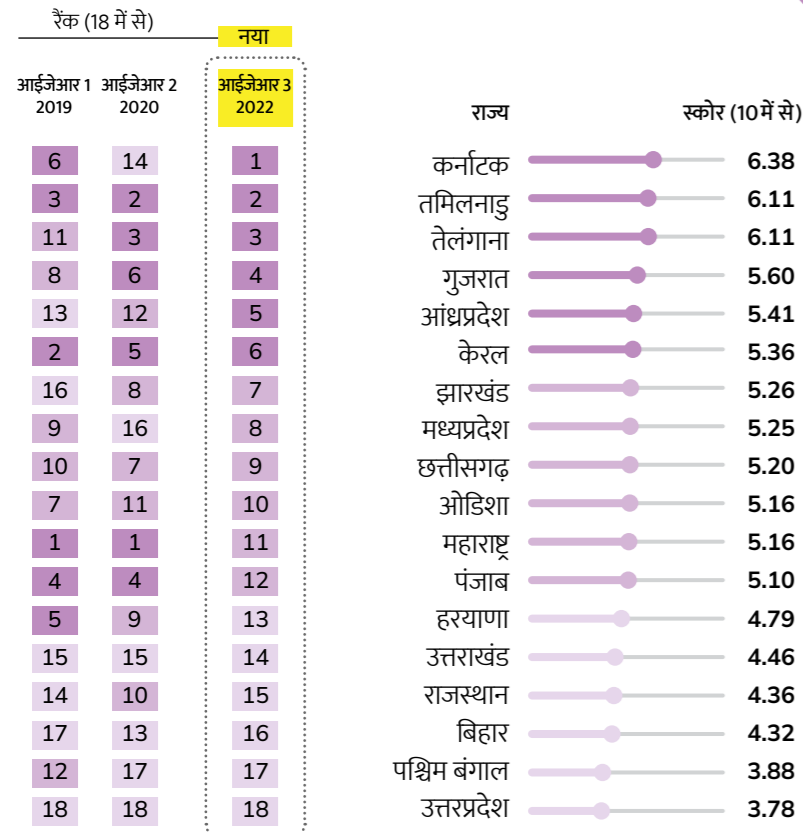
रंग गाइड  
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक (IJR 3) **102**

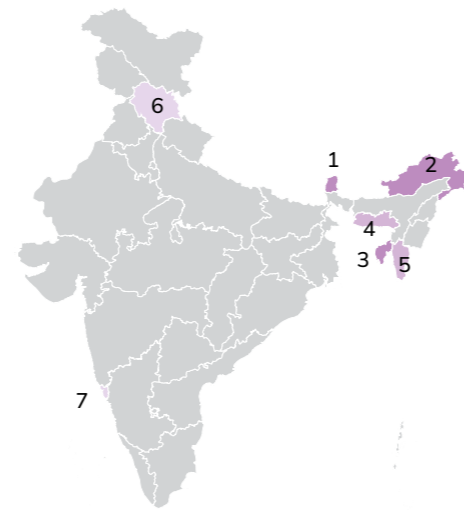
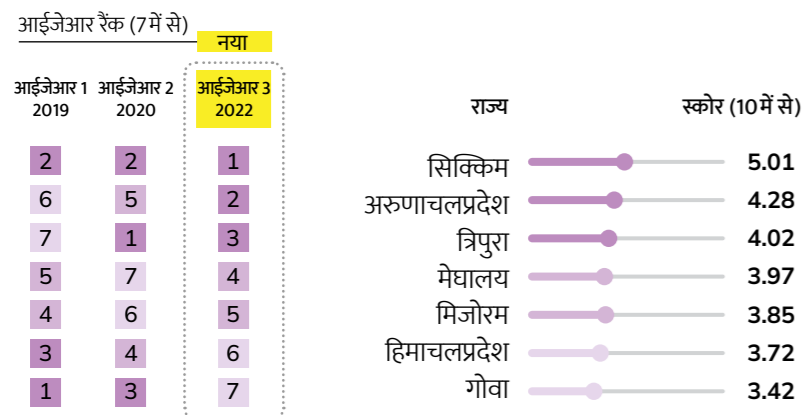
समूह (क्लस्टर)  
 I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)  
 II. 7 छोटे आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ तक)



## मानचित्र 1: 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य



## मानचित्र 2: छोटे राज्य



\*पुलिस, कारागार, न्यायिक प्रणाली और कानूनी सहायता में योग्यता का संयुक्त रैंकिंग  
 नोट: अंक 2 दशमलव तक दिखाए जाते हैं। जबकि वे दोनों समान अंक दिखाते हैं, तमिलनाडु तीसरे दशमलव (6.112 बनाम 6.105) पर तेलंगाना से ऊपर है और ओडिशा महाराष्ट्र (5.159 बनाम 5.157) से ऊपर है।

## न्याय के 4 स्तंभों में प्रत्येक श्रेणीबद्ध राज्य ने अपने समूह में कैसे प्रदर्शन किया

तालिका 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए श्रेणी और अंक

■ रैंक 1 से 6 ■ रैंक 7 से 12 ■ रैंक 13 से 18

	समग्र रैंक IJR 3 2022	पुलिस			जेल			न्यायपालिका			कानूनी सहायता		
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022
कर्नाटक	1	6	1	2	3	14	2	16	12	2	7	16	2
तमिलनाडु	2	1	5	6	10	6	1	1	1	1	12	11	12
तेलंगाना	3	11	10	1	13	2	3	11	6	5	4	6	5
गुजरात	4	12	8	8	9	10	6	7	8	9	6	9	3
आंध्रप्रदेश	5	5	4	3	15	7	5	13	14	11	10	14	13
केरल	6	13	14	17	1	5	4	5	3	4	1	7	6
झारखंड	7	9	6	11	18	15	14	14	9	7	14	4	1
मध्यप्रदेश	8	15	18	7	7	8	7	6	11	10	9	12	14
छत्तीसगढ़	9	10	2	9	8	11	12	12	4	6	8	15	11
ओडिशा	10	7	3	4	5	9	11	9	15	13	15	8	10
महाराष्ट्र	11	4	13	10	2	4	10	4	5	12	5	1	7
पंजाब	12	3	12	13	16	13	15	2	2	3	3	3	9
हरयाणा	13	8	9	12	11	16	16	3	7	14	2	5	4
उत्तराखंड	14	2	7	5	17	18	18	15	13	8	17	10	8
राजस्थान	15	17	16	14	12	1	8	8	10	17	11	13	17
बिहार	16	14	11	16	6	3	9	18	18	16	16	2	16
पश्चिमबंगाल	17	16	17	18	4	12	13	10	16	18	13	17	15
उत्तरप्रदेश	18	18	15	15	14	17	17	17	17	15	18	18	18

राज्यों को IJR 3 में समग्र रैंक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया।

## तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए श्रेणी और अंक

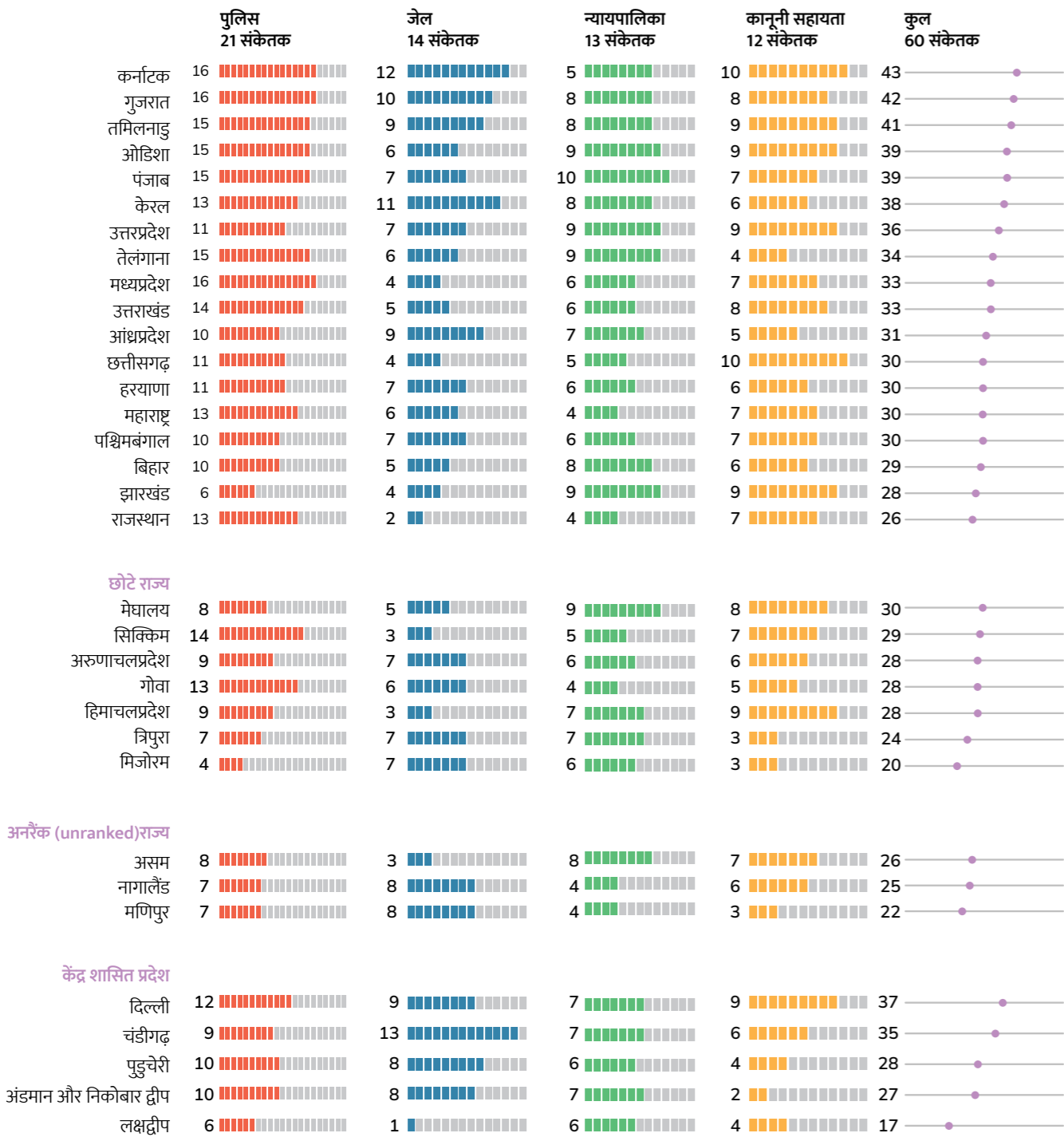
■ रैंक 1 से 6 ■ रैंक 7 से 12 ■ रैंक 13 से 18

	समग्र रैंक IJR 3 2022	पुलिस			जेल			न्यायपालिका			कानूनी सहायता		
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022
सिक्किम	1	1	1	1	7	6	4	1	1	1	4	3	1
अरुणाचलप्रदेश	2	2	4	2	3	3	1	7	5	4	7	7	7
त्रिपुरा	3	4	5	7	5	2	5	6	6	2	5	2	4
मेघालय	4	5	3	3	2	5	6	4	7	5	6	5	3
मिजोरम	5	7	6	4	4	7	3	5	3	3	2	4	6
हिमाचलप्रदेश	6	6	2	5	6	1	2	3	2	6	3	6	5
गोवा	7	3	7	6	1	4	7	2	4	7	1	1	2

राज्यों को IJR 3 में समग्र रैंक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया।

### चित्र 1: IJR 2020 और IJR 2022 के बीच सुधार स्कोरकार्ड

इसके और आई. जे. आर. 2020 के लिए सामान्य 60 स्थिर संकेतकों में से कितने में एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सुधार हुआ?



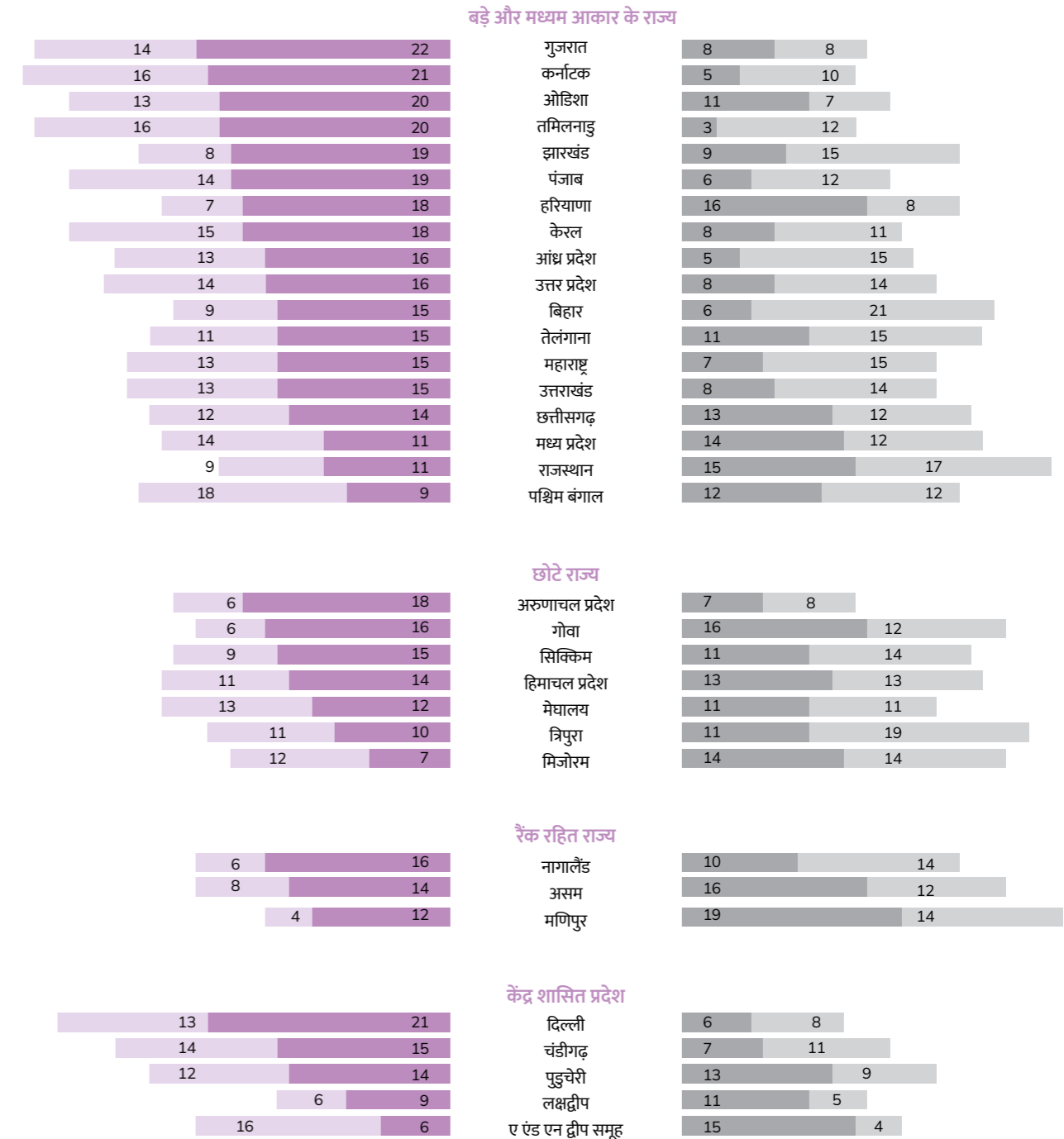
मैथडोलॉजी: कार्यप्रणाली: उन संकेतकों की गिनती जिन पर किसी राज्य ने आई. जे. आर. 2 की तुलना में सुधार किया है। आई. जे. आर. 2 और आई. जे. आर. 3 दोनों में मौजूद केवल गैर-प्रवृत्ति और तुलनीय संकेतकों पर विचार किया गया है। बेंचमार्क वाले संकेतकों के लिए, यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा करता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही बेंचमार्क के भीतर इसके मूल्य में गिरावट आई हो। यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है, लेकिन इसके मूल्य में सुधार होता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है। जहां एक या दोनों वर्षों के लिए एक संकेतक मूल्य उपलब्ध नहीं था, उस संकेतक पर विचार नहीं किया गया था। उनकी प्रशासनिक स्थिति में बदलाव को देखते हुए, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मूल्यों की तुलना आईजेआर 2 के मूल्यों से नहीं की जा सकती है, और इसलिए उन पर यहां विचार नहीं किया गया है।

### चित्र 2: आईजेआर 2019, आईजेआर 2020 और आईजेआर 2022 में प्रदर्शन

आई. जे. आर. 2019 को आधार रेखा के रूप में लेते हुए, नीचे दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि कैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने तीनों आई. जे. आर. के लिए 52 से अधिक संकेतकों का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु केवल 3 संकेतकों में सुधार नहीं कर सका, जबकि हरियाणा के लिए यह संख्या 16 थी। इसी तरह, गुजरात ने आई. जे. आर. 3 में 22 संकेतकों में सुधार किया, जबकि पश्चिम बंगाल केवल 9 में सुधार कर सका।

#### संकेतकों की संख्या में सुधार (अधिकतम: 52) \*

आईजेआर 2 और आईजेआर 3 दोनों में सुधार | आईजेआर 2 में गिरावट आई, आईजेआर 3 में सुधार हुआ  
आईजेआर 2 और आईजेआर 3 दोनों में गिरावट आई | आईजेआर 2 में सुधार, आईजेआर 3 में गिरावट



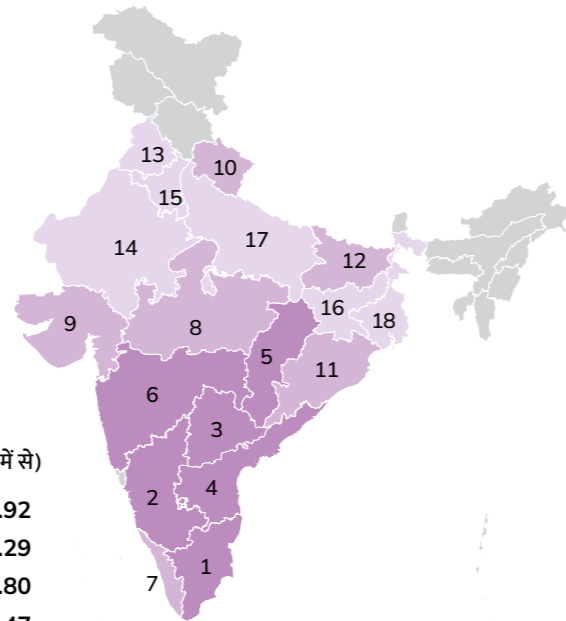
\*4 स्तंभों में 52 गैर-प्रवृत्ति संकेतकों के लिए डेटा, जो तीनों आईजेआर में मौजूद थे।  
नोट: 1. दोनों आई. जे. आर. में संकेतकों के अवरोही क्रम में समूह के भीतर व्यवस्थित राज्यों में सुधार हुआ है। 2. प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आंकड़ों की तुलना आईजेआर में नहीं की जा सकती है, और इसलिए उन्हें इस गणना से बाहर रखा गया है।

# रैंकिंग विविधता\*

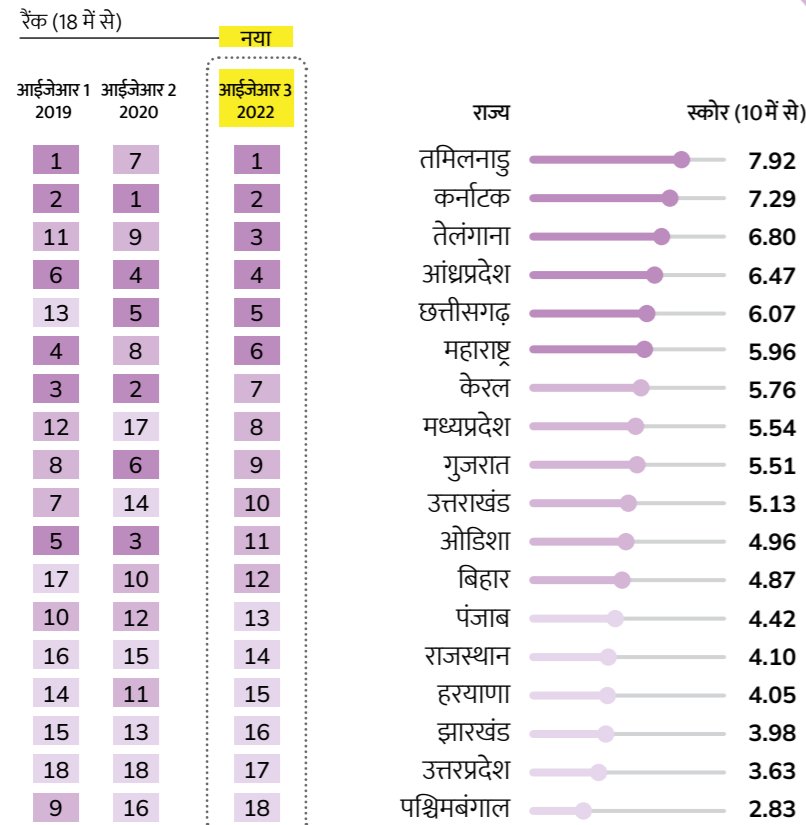
रंग गाइड  
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक (IJR 3) **16**

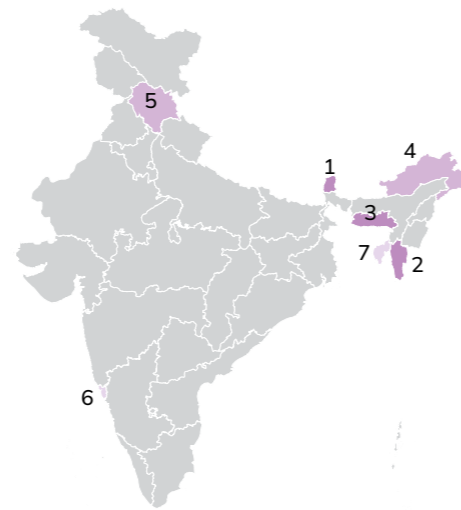
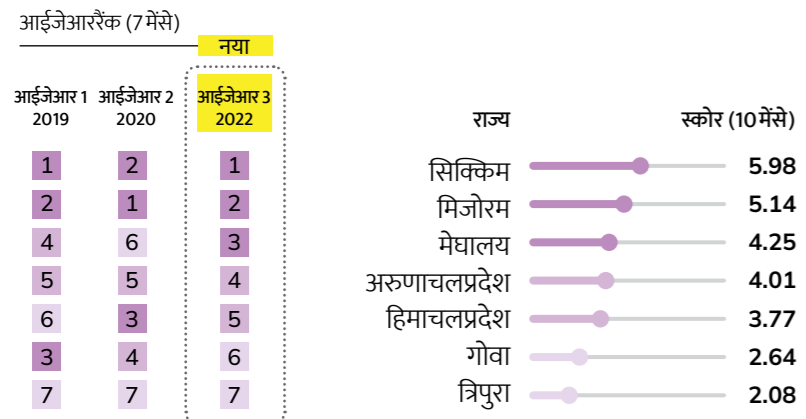
समूह  
 I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)  
 II. 7 छोटे आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ तक)



## मानचित्र 3: 18 बड़े और मध्यम राज्य



## मानचित्र 4: छोटे राज्य



\*पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के 16 विविधता संकेतकों पर राज्यों की स्थिति क्या है? पृष्ठ 28 पर सूचीबद्ध संकेतक।

## चित्र 3: स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा

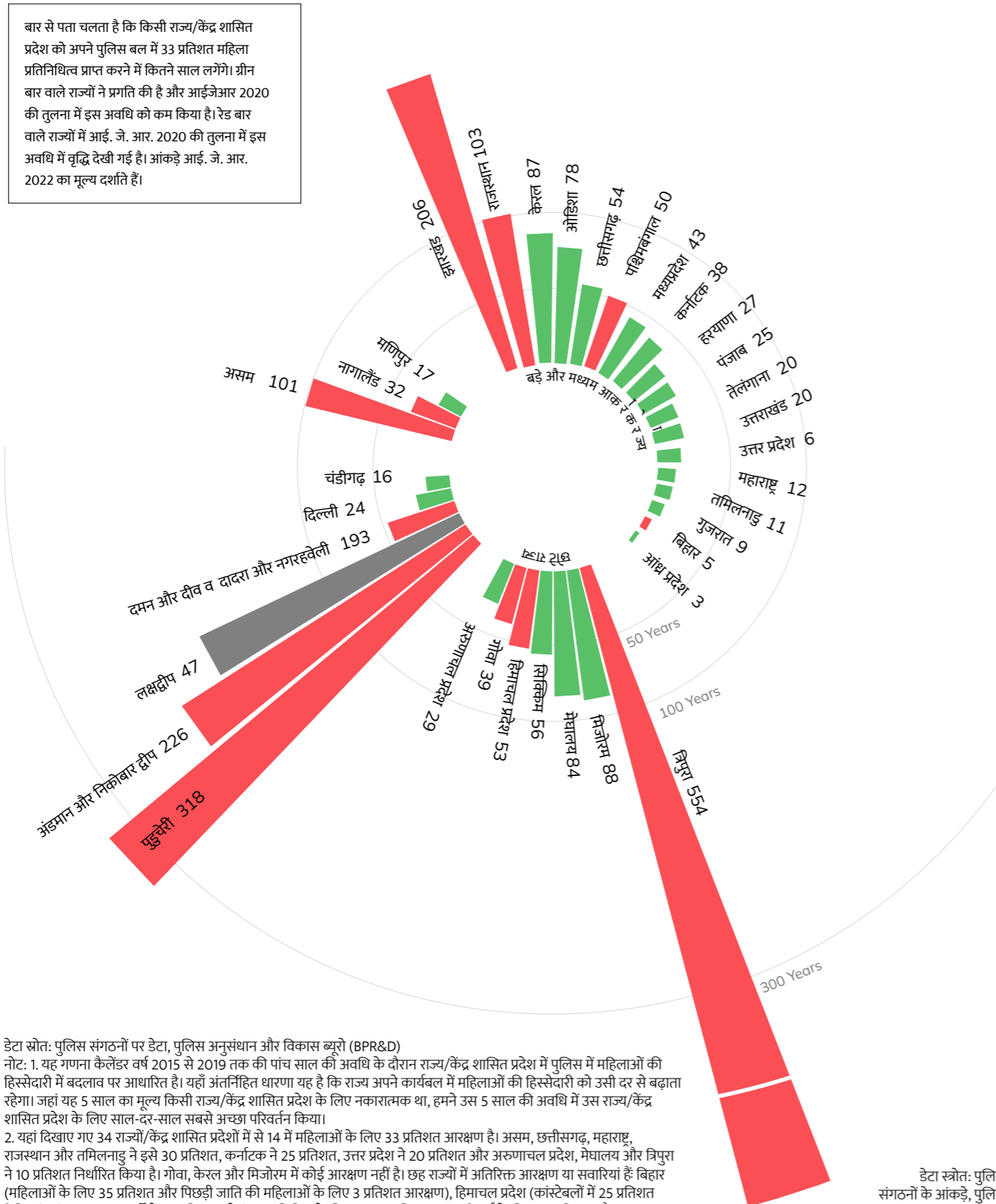
महिलाओं की हिस्सेदारी असमान बनी हुई है और उनका प्रतिनिधित्व निचले स्तर पर केंद्रित है।

	पुलिस		कारागार	न्यायपालिका		कानूनी सहायता	
	पुलिस में महिलाओं का हिस्सेदारी (%)	अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सेदारी (%)	जेल स्टाफ में महिलाएं (% दिसंबर 2016)	महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (%)	महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (%)	महिला पैनाल अधिवक्ता (%)	महिला पैरा लीगल वॉलंटियर (%)
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	11.8	8	13.8	13.1	35.1	24.7	40.3
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>							
आंध्रप्रदेश	21.8	5.4	8.4	6.7	46.2	16.1	38.0
बिहार	21.2	10.6	21.5	0.0	24.2	18.6	26.6
छत्तीसगढ़	7.1	9.3	10.4	7.1	41.7	14.9	40.6
गुजरात	16.3	10.0	7.2	21.4	19.5	24.4	43.5
हरयाणा	8.2	12.2	6.2	19.7	38.4	21.5	41.4
झारखंड	6.2	4.3	9.3	4.8	23.0	15.6	32.9
कर्नाटक	8.6	6.4	32.0	10.2	33.6	38.8	58.4
केरल	7.8	2.4	10.0	16.2	43.1	42.4	62.6
मध्यप्रदेश	7.4	11.5	18.6	9.7	34.8	15.1	35.6
महाराष्ट्र	17.8	7.7	14.8	12.1	30.8	28.2	40.8
ओडिशा	10.5	12.9	12.5	4.5	44.4	26.1	37.6
पंजाब	9.9	8.3	9.4	19.7	45.8	18.6	37.1
राजस्थान	10.4	6.8	19.4	7.7	40.2	8.6	27.1
तमिलनाडु	19.1	17.9	14.1	20.4	39.9	24.4	48.7
तेलंगाना	8.5	7.5	10.5	27.3	52.8	18.2	41.9
उत्तरप्रदेश	10.7	5.1	9.9	7.0	31.7	10.5	24.9
उत्तराखंड	12.8	18.1	3.6	0.0	39.1	21.8	44.2
पश्चिमबंगाल	9.9	4.0	10.9	14.8	35.9	26.2	40.0
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचलप्रदेश	10.7	5.7	18.2	16.7	34.3	22.1	46.3
गोवा	10.6	15.6	1.8	12.1	70.0	45.3	59.3
हिमाचलप्रदेश	14.0	4.9	8.4	20.0	34.0	24.9	27.2
मेघालय	6.0	8.5	14.8	0.0	62.7	60.4	41.7
मिजोरम	7.1	21.4	25.0	16.7	51.2	37.8	32.6
सिक्किम	9.0	7.5	23.2	33.3	52.4	44.7	76.0
त्रिपुरा	5.3	5.9	5.4	0.0	34.9	28.7	24.7

नोट: 1. समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 2. पुलिस सूचकों के लिए 2022 जनवरी तक का डेटा; कारागार सूचकों के लिए 2021 दिसंबर तक का डेटा; उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए 2022 दिसंबर 1; उपन्यायाधीशों के लिए 2022 जुलाई 25; कानूनी सहायता सूचकों के लिए 2022 जून का डेटा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, जनवरी 2022; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, कारागार सांख्यिकी भारत, दिसंबर 2021; न्याय विभाग; लोक सभा के अस्तित्व प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022 और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण।

### चित्र 4: महिला पुलिस कर्मियों में हिस्सा 33% तक पहुँचने में कितना समय लगेगा?

आई. जे. आर. 2020 की तुलना में, 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आई. जे. आर. 2022 में अपने पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार किया है। 5 साल के औसत के आधार पर भी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत तक पहुँचने में सुधार हुआ है।



डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)  
 नोट: 1. यह गणना कैलेंडर वर्ष 2015 से 2019 तक की पांच साल की अवधि के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी में बदलाव पर आधारित है। यहाँ अंतर्निहित धारणा यह है कि राज्य अपने कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को उसी दर से बढ़ाता रहेगा। जहाँ यह 5 साल का मूल्य किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए नकारात्मक था, हमने उस 5 साल की अवधि में उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए साल-दर-साल सबसे अच्छा परिवर्तन किया।  
 2. यहाँ दिखाए गए 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने इसे 30 प्रतिशत, कर्नाटक ने 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 20 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा ने 10 प्रतिशत निर्धारित किया है। गोवा, केरल और मिजोरम में कोई आरक्षण नहीं है। छह राज्यों में अतिरिक्त आरक्षण या सवारियाँ हैं: बिहार (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण), हिमाचल प्रदेश (कांस्टेबलों में 25 प्रतिशत रिक्तियाँ), पंजाब (प्रत्यक्ष भर्ती में 33 प्रतिशत), तेलंगाना (सिविल के लिए 33.3%, जिला सशस्त्र रिजर्व के लिए 10 प्रतिशत और राज्य सशस्त्र रिजर्व के लिए 0 प्रतिशत), उत्तराखंड (30 प्रतिशत क्षैतिज) और पश्चिम बंगाल (शून्य, उत्तरोत्तर 33 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा)। मिजोरम के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आँकड़े, पुलिस अनुसंधान एव विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.)

### चित्र 5: पुलिस में 'अन्य' की रोचक स्थिति

बी. पी. आर. एंड डी. रैंक के आधार पर कर्मियों के डेटा का विवरण प्रदान करता है और इसमें "अन्य यदि कोई हो" का एक अनिर्धारित कॉलम शामिल होता है। 2019 से, 2022 में अन्य लोगों की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है।

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	पुलिस कर्मचारियों में 'अन्य' का हिस्सा (%)			
	जनवरी 2019	जनवरी 2020	जनवरी 2021	जनवरी 2022
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	32.9
बिहार	0.0	0.3	0.5	0.5
छत्तीसगढ़	7.1	5.7	6.4	6.2
गुजरात	0.0	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	13.9
झारखंड	0.0	0.0	0.4	1.9
कर्नाटक	0.0	18.1	6.2	5.6
केरल	0.0	7.5	7.2	7.2
मध्य प्रदेश	0.0	0.3	0.3	4.6
महाराष्ट्र	0.0	0.0	0.2	1.5
ओडिशा	0.0	0.0	0.0	0.0
पंजाब	0.0	1.4	1.6	1.5
राजस्थान	0.0	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	0.0	0.0	3.6	3.6
तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	4.3	5.6
उत्तराखंड	7.3	7.3	5.6	5.3
पश्चिम बंगाल	5.5	15.4	2.7	2.7
<b>छोटे राज्य</b>				
अरुणाचल प्रदेश	5.9	5.7	5.8	10.5
गोवा	9.5	12.2	14.6	14.1
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	3.2	18.6	4.4	4.4
मिजोरम	14.9	13.8	15.6	14.0
सिक्किम	8.1	7.9	9.1	11.0
त्रिपुरा	7.3	16.2	14.8	14.8
<b>रैंक रहित राज्य</b>				
असम	0.9	4.5	5.5	5.1
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0
नागालैंड	0.0	0.2	0.0	0.0
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>				
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.8	10.9	9.9	9.8
चंडीगढ़	0.0	2.6	2.9	3.8
दमन और दीव	6.6	7.1	4.5	4.9
दिल्ली	1.7	1.6	1.9	1.9
जम्मू और कश्मीर	6.0	6.4	7.8	6.4
लद्दाख	NA	2.7	3.3	32.6
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	3.2	2.7	2.6	2.6
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>1.2</b>	<b>2.9</b>	<b>2.8</b>	<b>5.0</b>

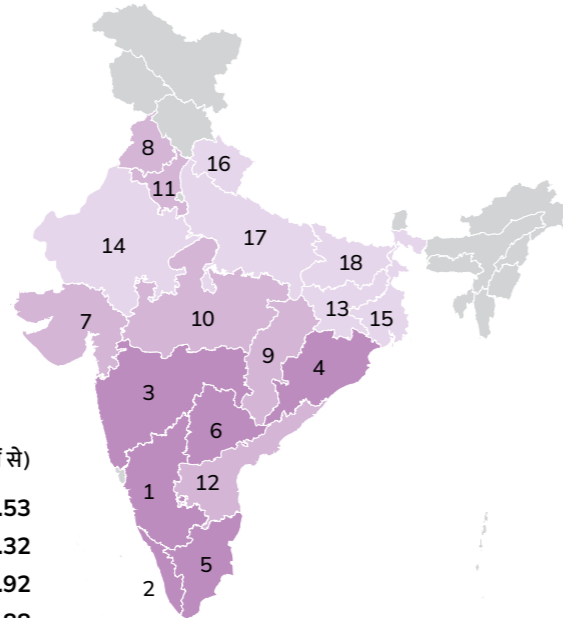
नोट: 1. समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

# रैंकिंग मानव संसाधन\*

रंग गाइड  
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक (IJR 3) **17**

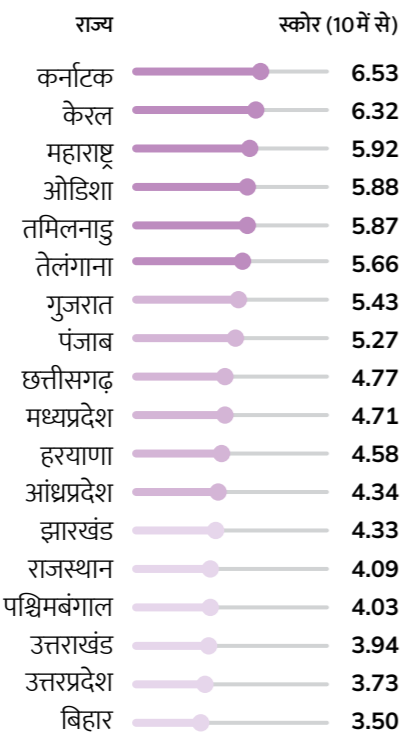
समूह  
 I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (10 लाख से ऊपर की आबादी)  
 II. 7 छोटे आकार के राज्य (10 लाख तक की आबादी)



## मानचित्र 5: 18 बड़े और मध्यम राज्य

रैंक (18 में से) नया

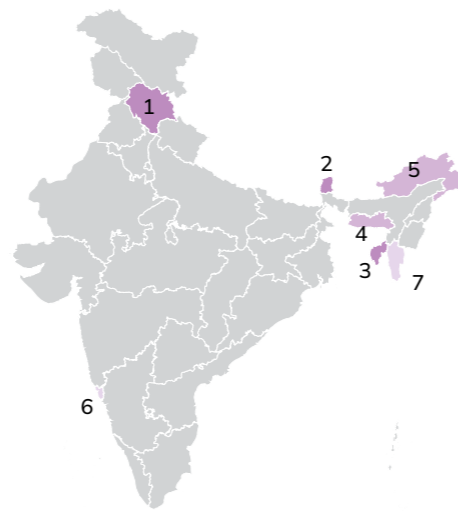
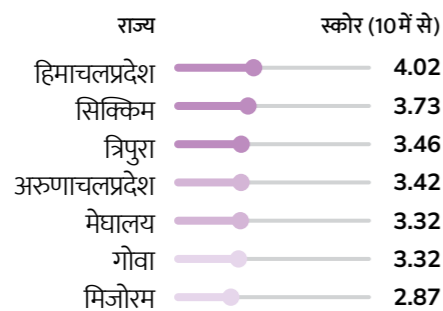
आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
6	11	1
1	3	2
2	1	3
3	4	4
4	2	5
12	5	6
10	8	7
7	6	8
14	14	9
5	9	10
9	12	11
13	16	12
16	10	13
8	7	14
11	17	15
15	13	16
18	18	17
17	15	18



## मानचित्र 6: छोटे राज्य

आईजेआररैंक (7 में से) नया

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
4	3	2
5	4	3
6	2	4
3	5	5
2	7	6
7	6	7



पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के 17 मानव संसाधन संकेतकों पर राज्यों की स्थिति कैसी है? पृष्ठ 28 पर सूचीबद्ध संकेतक।  
 नोट: अंक 2 दशमलव तक दिखाए जाते हैं। जबकि वे दोनों समान अंक दिखाते हैं, मेघालय तीसरे दशमलव (3.324 बनाम 3.320) पर गोवा से ऊपर है।

## चित्र 6: न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात

1987 में विधि आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड ने प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। वास्तव में, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस संख्या को पूरा करने से बहुत दूर हैं।

राष्ट्रीय औसत	प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीश		
	अधीनस्थ न्यायालय	उच्च न्यायालय	कुल
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	14.0	0.6	14.6
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>			
आंध्र प्रदेश	9.1	0.6	9.7
बिहार	10.8	0.3	11.1
छत्तीसगढ़	14.7	0.5	15.2
गुजरात	16.6	0.4	17.0
हरियाणा	15.8	1.1	16.9
झारखंड	15.0	0.5	15.5
कर्नाटक	15.8	0.7	16.6
केरल	13.4	1.0	14.5
मध्य प्रदेश	18.0	0.4	18.4
महाराष्ट्र	15.5	0.5	16.0
ओडिशा	17.5	0.5	18.0
पंजाब	19.6	1.1	20.7
राजस्थान	15.7	0.3	16.1
तमिलनाडु	14.0	0.7	14.7
तेलंगाना	10.8	0.9	11.7
उत्तर प्रदेश	10.8	0.4	11.2
उत्तराखंड	23.5	0.6	24.1
पश्चिम बंगाल	9.3	0.5	9.9
<b>छोटे राज्य</b>			
अरुणाचल प्रदेश	22.6	0.6	23.2
गोवा	25.5	0.5	26.0
हिमाचल प्रदेश	21.8	1.3	23.1
मेघालय	15.4	0.9	16.3
मिजोरम	33.4	0.6	34.0
सिक्किम	30.7	4.4	35.1
त्रिपुरा	26.5	0.7	27.3
<b>रैंक रहित राज्य</b>			
असम	12.2	0.6	12.7
मणिपुर	13.1	0.9	14.1
नागालैंड	10.8	0.6	11.4
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.3	0.5	32.9
चंडीगढ़	24.6	1.1	25.7
दमन और दीव	7.0	0.5	7.5
दिल्ली	32.6	2.1	34.7
जम्मू और कश्मीर	17.5	1.1	18.6
लद्दाख	30.1	1.1	31.2
लक्षद्वीप	29.4	1.0	30.4
पुडुचेरी	6.8	0.7	7.5

नोट: 1. राज्यों को उनके संबंधित समूह में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
 स्रोत: न्याय विभाग; लोक सभा के अस्तित्व प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022।



## चित्र 7: स्तंभों में रिक्तियाँ

हमने 4 स्तंभों में 11 प्रमुख कार्मिक रैंक पर रिक्तियों को देखा। कई राज्यों में सभी आकारों की रिक्तियाँ हैं जो राज्य की अपनी स्वीकृत संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक हैं।

■ 25% तक ■ 25% से 50% ■ 50% से ऊपर

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	पुलिस रिक्ति (%)		न्यायपालिका रिक्ति (%)		
	कांस्टेबल जनवरी 2022	अधिकारी जनवरी 2022	उच्च न्यायालय न्यायाधीश दिसंबर 2022	अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश जुलाई 2022	उच्च न्यायालय कर्मचारी 2021-22
आंध्रप्रदेश	20.0	9.8	18.9	20.4	51.2
बिहार	30.0	53.8	35.8	30.7	52.8
छत्तीसगढ़	21.2	26.0	36.4	8.9	32.6
गुजरात	26.9	22.1	46.2	23.0	24.3
हरयाणा	32.0	25.3	22.4	39.0	23.1
झारखंड	23.9	32.8	16.0	13.6	16.9
कर्नाटक	12.0	10.8	21.0	21.9	26.0
केरल	4.6	23.9	21.3	16.0	17.3
मध्यप्रदेश	13.9	20.8	41.5	23.8	14.6
महाराष्ट्र	28.2	25.3	29.8	11.4	11.3
ओडिशा	13.3	28.4	33.3	20.7	28.5
पंजाब	12.6	22.4	22.4	13.3	23.1
राजस्थान	8.3	45.6	48.0	20.1	37.0
तमिलनाडु	10.9	9.1	28.0	19.2	13.7
तेलंगाना	26.1	7.1	21.4	19.7	33.8
उत्तरप्रदेश	26.0	42.5	37.5	31.0	21.1
उत्तराखंड	6.4	7.2	36.4	9.4	21.1
पश्चिमबंगाल	44.1	25.2	25.0	9.5	31.5
छोटे राज्य					
अरुणाचलप्रदेश	27.8	34.7	0.0	14.6	7.9
गोवा	17.2	23.6	29.8	20.0	11.3
हिमाचलप्रदेश	5.1	16.0	41.2	7.4	15.0
मेघालय	16.9	21.2	25.0	48.5	13.2
मिजोरम	34.2	26.6	0.0	36.9	7.9
सिक्किम	4.6	-4.2	0.0	25.0	11.5
त्रिपुरा	23.7	40.1	40.0	10.7	5.3

नोट: 1. समूह के भीतर राज्यों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
 स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.), पुलिस संगठनों के आंकड़े (डी.ओ.पी.ओ.), जनवरी 2022; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), कारागार सांख्यिकी (पी.एस.आई.), दिसंबर 2021; न्याय विभाग, लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।

## चित्र 7: स्तंभों में रिक्तियाँ

हमने 4 स्तंभों के मुख्य कर्मचारीगण 11 कर्मियों की पद रिक्तियों की जांच की। बहुत सारे राज्य, सभी आकारों के, उनके अपने स्वीकृत संख्या के 25% से अधिक रिक्तियों के साथ हैं। सबसे अधिक रिक्तियाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कारागारों में सुधारी कर्मचारियों में हैं और सबसे कम न्याय सेवा प्राधिकरण के सचिवों में दिखाई देती हैं।

■ 25% तक ■ 25% से 50% ■ 50% से ऊपर

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	कारागार रिक्ति (%)					कानूनी सहायता रिक्ति (%)
	अधिकारी दिसंबर 2021	कांडर कर्मचारी दिसंबर 2021	सुधारक कर्मचारी, दिसंबर 2021	चिकित्सा कर्मचारी, दिसंबर 2021	चिकित्सा अधिकारी, दिसंबर 2021	डी.एल.एस.ए. सचिव मार्च 2022
आंध्र प्रदेश	23.2	26.8	NA <sup>2</sup>	26.7	13.6	0.0
बिहार	25.8	41.4	32.9	49.8	62.4	0.0
छत्तीसगढ़	64.7	27.7	49.5	51.7	56.5	0.0
गुजरात	30.0	34.0	44.4	14.7	12.5	12.5
हरयाणा	34.6	28.8	100.0	50.5	47.2	0.0
झारखंड	67.6	60.3	66.7	59.7	83.7	0.0
कर्नाटक	14.5	21.3	20.7	61.3	66.7	0.0
केरल	6.9	11.4	3.6	23.5	16.7	0.0
मध्यप्रदेश	41.4	15.4	18.8	47.2	72.4	31.4
महाराष्ट्र	22.0	11.2	46.0	27.0	20.5	0.0
ओडिशा	23.3	21.3	41.6	46.3	61.7	0.0
पंजाब	29.3	47.3	100.0	37.4	33.3	0.0
राजस्थान	37.3	22.8	87.5	22.9	35.1	0.0
तमिलनाडु	11.0	9.8	15.0	7.8	11.6	9.4
तेलंगाना	8.0	13.5	0.0	53.4	45.5	18.2
उत्तरप्रदेश	36.1	19.4	37.1	52.3	36.0	28.2
उत्तराखंड	77.1	37.1	NA <sup>2</sup>	56.3	90.0	0.0
पश्चिमबंगाल	24.3	19.2	31.3	66.8	77.3	0.0
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	43.8	3.1	NA <sup>2</sup>	10.0	0.0	100.0
गोवा	29.6	31.5	100.0	84.6	83.3	0.0
हिमाचल प्रदेश	36.4	17.1	69.2	52.2	50.0	0.0
मेघालय	31.6	25.5	NA <sup>2</sup>	10.0	0.0	72.7
मिजोरम	45.9	25.5	NA <sup>2</sup>	40.0	100.0	100.0
सिक्किम	40.7	56.2	NA <sup>2</sup>	28.6	50.0	100.0
त्रिपुरा	65.6	38.4	0.0	29.4	0.0	60.0

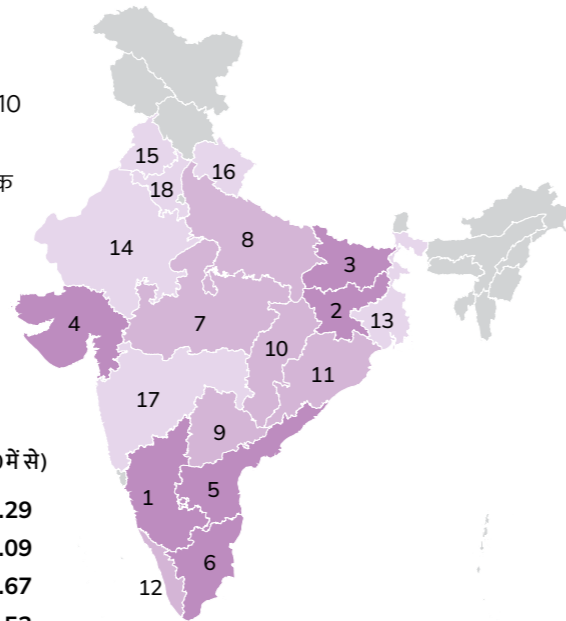
नोट: 1. समूह के अंदर राज्यों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। 2. उन राज्यों के लिए जहाँ सुधारी गई कर्मचारी डेटा उपलब्ध नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि PSI में 0 स्वीकृत और वास्तविक सुधारी कर्मचारी दिखाता है।  
 स्रोत: पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, कारागार सांख्यिकी भारत, दिसम्बर 2021; न्याय विभाग; लोक सभा के अस्तित्व प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022 और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण।

# रैंकिंग का इरादा\*

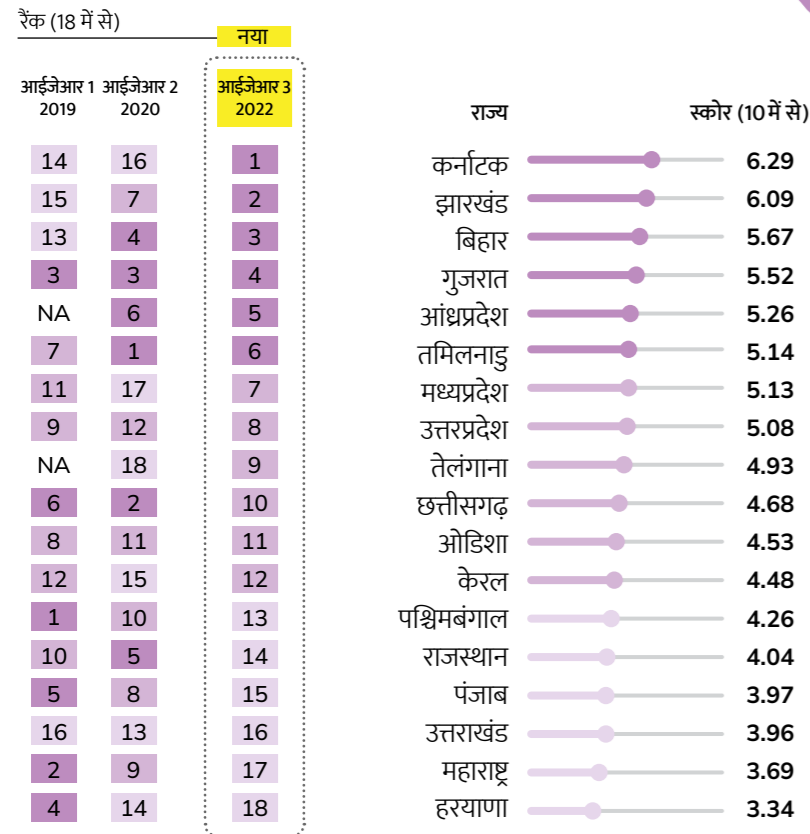
रंग गाइड  
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक (IJR 3) **23**

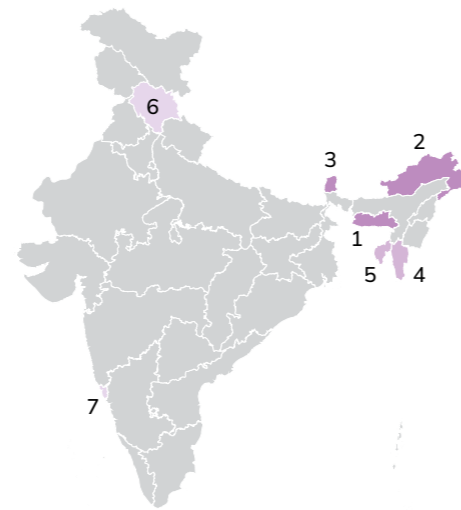
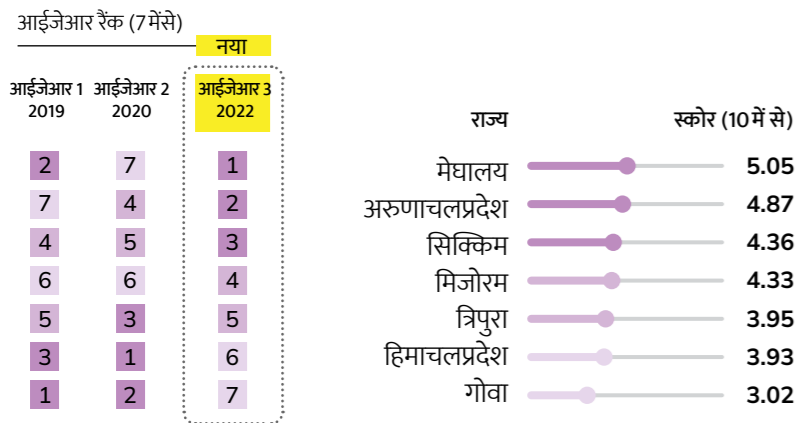
समूह  
 I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (10 लाख से ऊपर की आबादी)  
 II. 7 छोटे आकार के राज्य (10 लाख तक की आबादी)



## मानचित्र 7: 18 बड़े और मध्यम राज्य



## मानचित्र 8: छोटे राज्य



वे प्रवृत्तियाँ जो 23 सूचकों पर पुलिस, कारागार और न्यायिक प्रणाली में 5 वर्ष के डेटा पर आधारित हैं। सूचकों की सूची पृष्ठ 28 पर दी गई है।  
 नोट: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 2019 में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इन राज्यों के लिए 5 वर्ष का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था।

## चित्र 8: न्याय प्रणाली के बजट

नीचे दिया गया चित्र पुलिस, जेलों और न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन में 5 साल की औसत वृद्धि को दर्शाता है, और क्या उन्होंने राज्य के कुल खर्च में वृद्धि के साथ तालमेल रखा है। 25 रैंक वाले राज्यों में, पुलिस बजट में वृद्धि 12 राज्यों में कुल बजट में वृद्धि, 17 राज्यों में जेलों और 10 राज्यों में न्यायपालिका में वृद्धि से पीछे है।

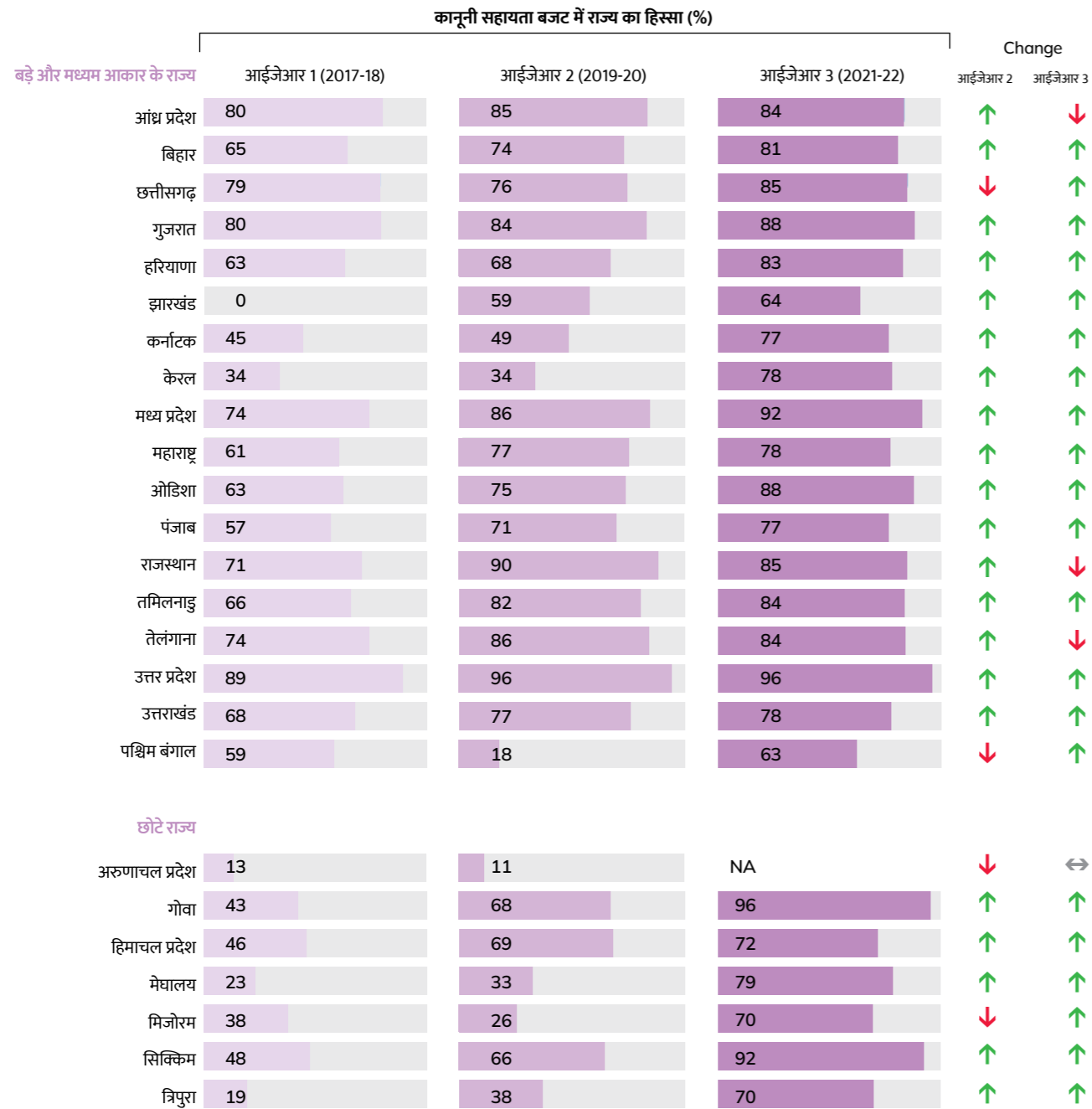
■ स्तंभों के व्यय में वृद्धि, कुल राज्य व्यय में वृद्धि की तुलना में अधिक  
 ■ स्तंभों के व्यय में वृद्धि, कुल राज्य व्यय में वृद्धि की तुलना में कम

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	2015-16 और 2020-21 के बीच व्यय में औसत परिवर्तन (%)				खर्च में अंतर: पिलर बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)		
	राज्य	पुलिस	कारागार	न्यायपालिका	पुलिस	कारागार	न्यायपालिका
आंध्रप्रदेश	12.6	9.9	4.0	8.5	-2.7	-8.6	-4.1
बिहार	8.2	9.1	9.8	10.0	0.9	1.6	1.8
छत्तीसगढ़	9.1	10.8	15.2	9.4	1.7	6.1	0.3
गुजरात	8.2	9.6	24.9	8.4	1.3	16.7	0.2
हरयाणा	8.0	10.1	7.4	9.4	2.1	-0.6	1.4
झारखंड	9.1	13.0	14.9	8.5	3.9	5.8	-0.6
कर्नाटक	10.1	9.5	16.3	18.3	-0.5	6.3	8.2
केरल	9.9	5.7	9.2	6.4	-4.2	-0.8	-3.6
मध्यप्रदेश	11.1	9.8	9.1	12.3	-1.3	-2.0	1.3
महाराष्ट्र	9.9	10.0	8.3	9.3	0.1	-1.6	-0.6
ओडिशा	8.6	7.8	0.7	9.3	-0.8	-7.9	0.7
पंजाब	11.6	6.2	3.0	8.3	-5.5	-8.6	-3.3
राजस्थान	8.7	10.2	4.3	12.9	1.5	-4.5	4.2
तमिलनाडु	11.1	8.2	8.0	10.0	-2.8	-3.0	-1.1
तेलंगाना	10.9	6.8	-2.3	4.5	-4.1	-13.2	-6.4
उत्तरप्रदेश	5.2	11.2	-6.2	10.1	6.0	-11.4	5.0
उत्तराखंड	9.8	10.0	1.5	11.2	0.2	-8.3	1.4
पश्चिमबंगाल	7.9	12.5	10.0	9.3	4.6	2.1	1.4
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचलप्रदेश	13.1	8.5	8.4	23.6	-4.6	-4.6	10.6
गोवा	7.3	10.8	-11.9	9.3	3.4	-19.2	2.0
हिमाचलप्रदेश	9.1	10.2	11.2	8.3	1.0	2.0	-0.8
मेघालय	13.4	11.5	3.1	18.7	-1.9	-10.3	5.3
मिजोरम	9.6	6.8	2.0	9.3	-2.8	-7.6	-0.4
सिक्किम	13.2	11.5	25.9	10.4	-1.7	12.7	-2.8
त्रिपुरा	6.7	10.2	-2.6	15.5	3.5	-9.3	8.8

नोट: समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
 स्रोत: भारतीय संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, भारतीय लेखा और महालेखा नियंत्रक।

### चित्र 9: राज्य का कानूनी सहायता बजट में हिस्सा

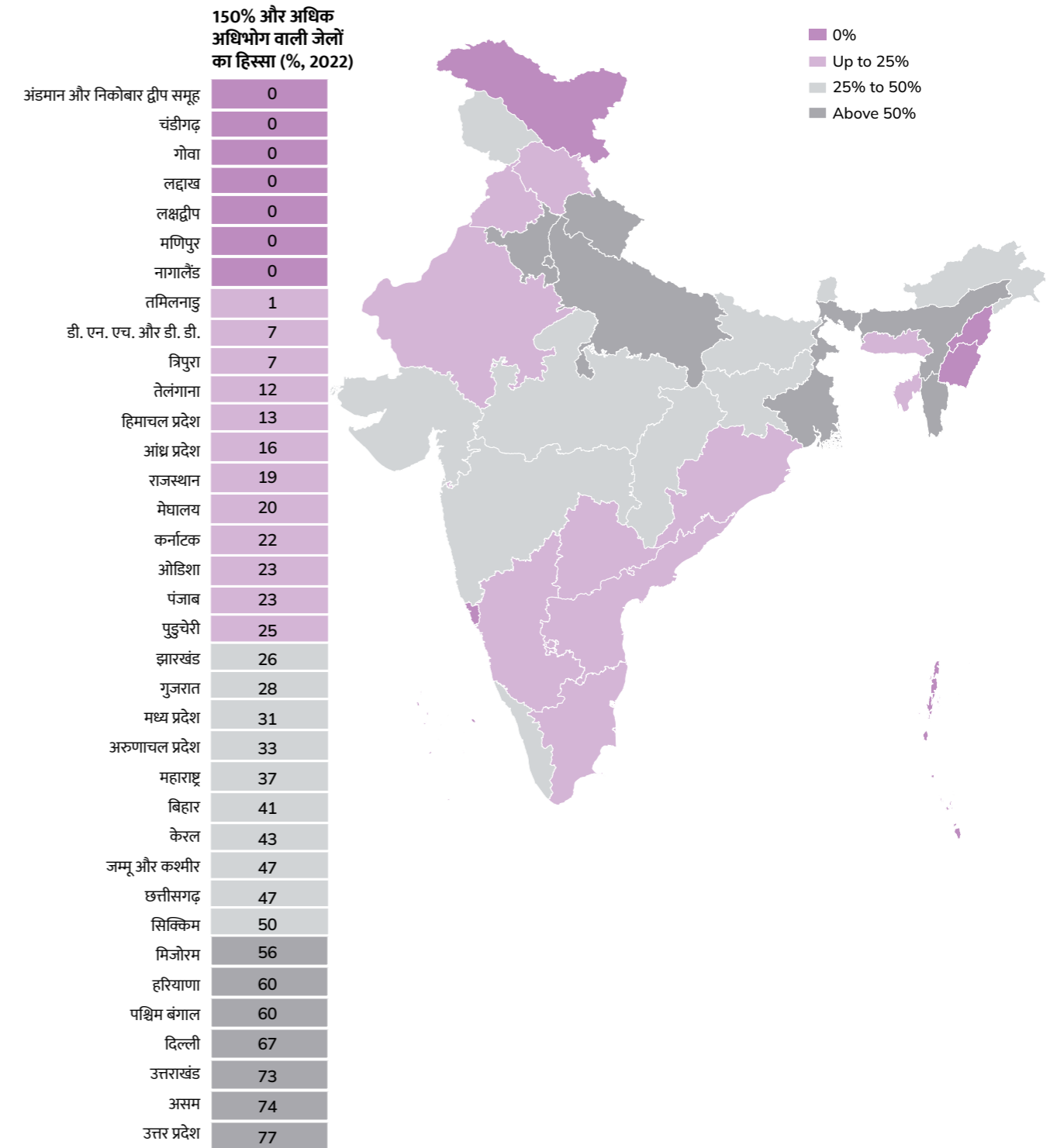
एक राज्य के कानूनी सहायता बजट में दो स्रोत होते हैं: केंद्र में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और स्वयं राज्य। 2017-18 और 2021-22 के बीच, अपने कानूनी सहायता बजट में राज्यों का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ा है। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से 13 में और 7 छोटे राज्यों में से 5 में, दोनों अनुवर्ती समय अवधि में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।



नोट: 1. राज्यों को उनके संबंधित समूह में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
 स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़ और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

### चित्र 10: राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों का हिस्सा

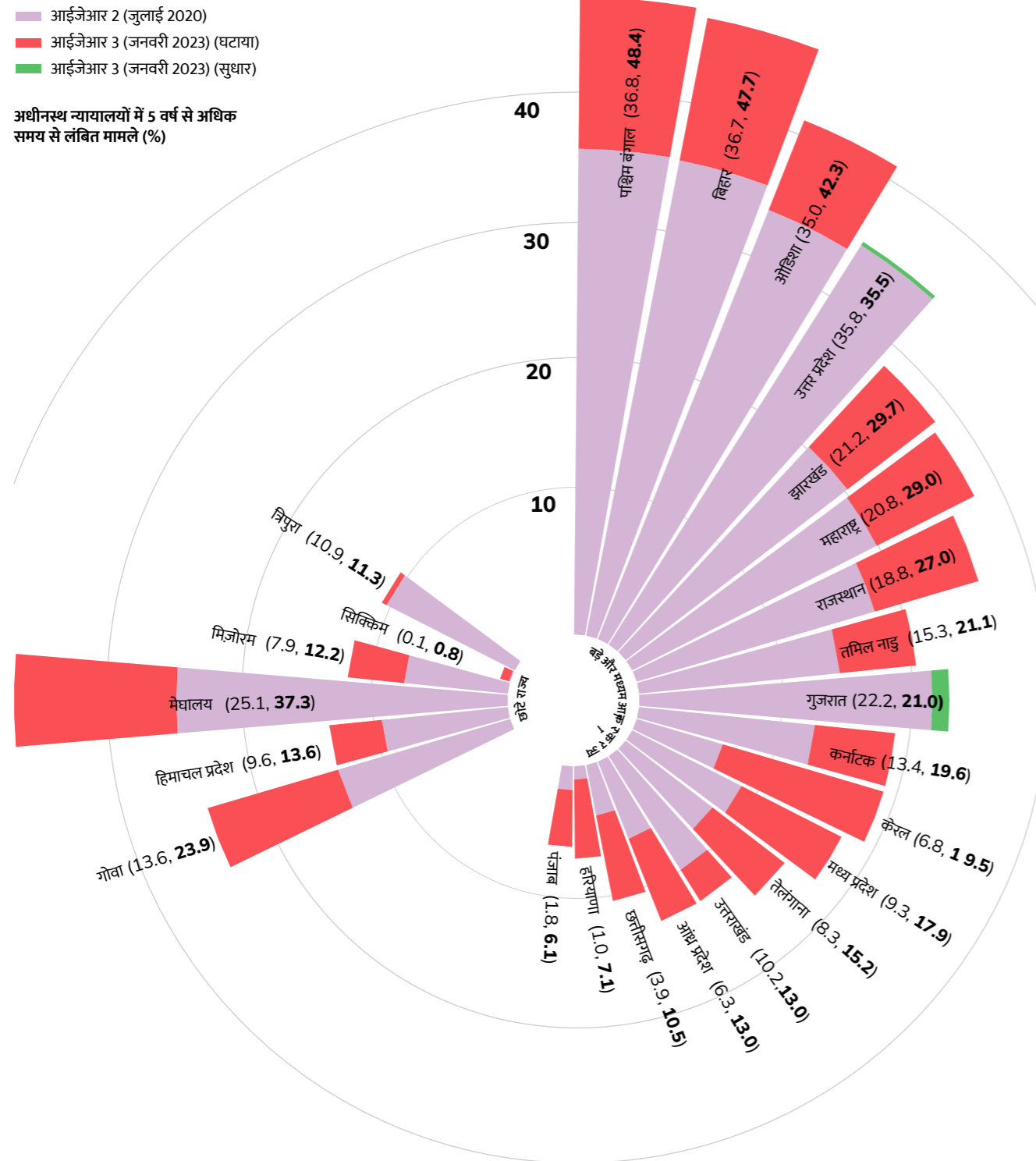
ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 120% भीड़भाड़ को 'गंभीर' और 150% को 'चरम' के रूप में वर्गीकृत करता है। 2021 के अंत में, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में औसत अधिभोग दर महत्वपूर्ण थी। छह में, यह 150% को पार कर गया था। औसत, हालांकि, इस तथ्य को छिपाते हैं कि कई जेलों में, भीड़ 150% को पार कर जाती है।



स्रोत: ई-कैदी पोर्टल

### चित्र 11: अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले

25 में से 23 राज्यों में, अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों में पिछले 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। 8 राज्यों में ऐसे मामले 25 प्रतिशत से अधिक लंबित हैं। ग्रीन और रेड बार इस बात को दर्शाते हैं कि आईजेआर 2020 की तुलना में राज्यों में अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की हिस्सेदारी या तो कम हुई है या बढ़ी है।

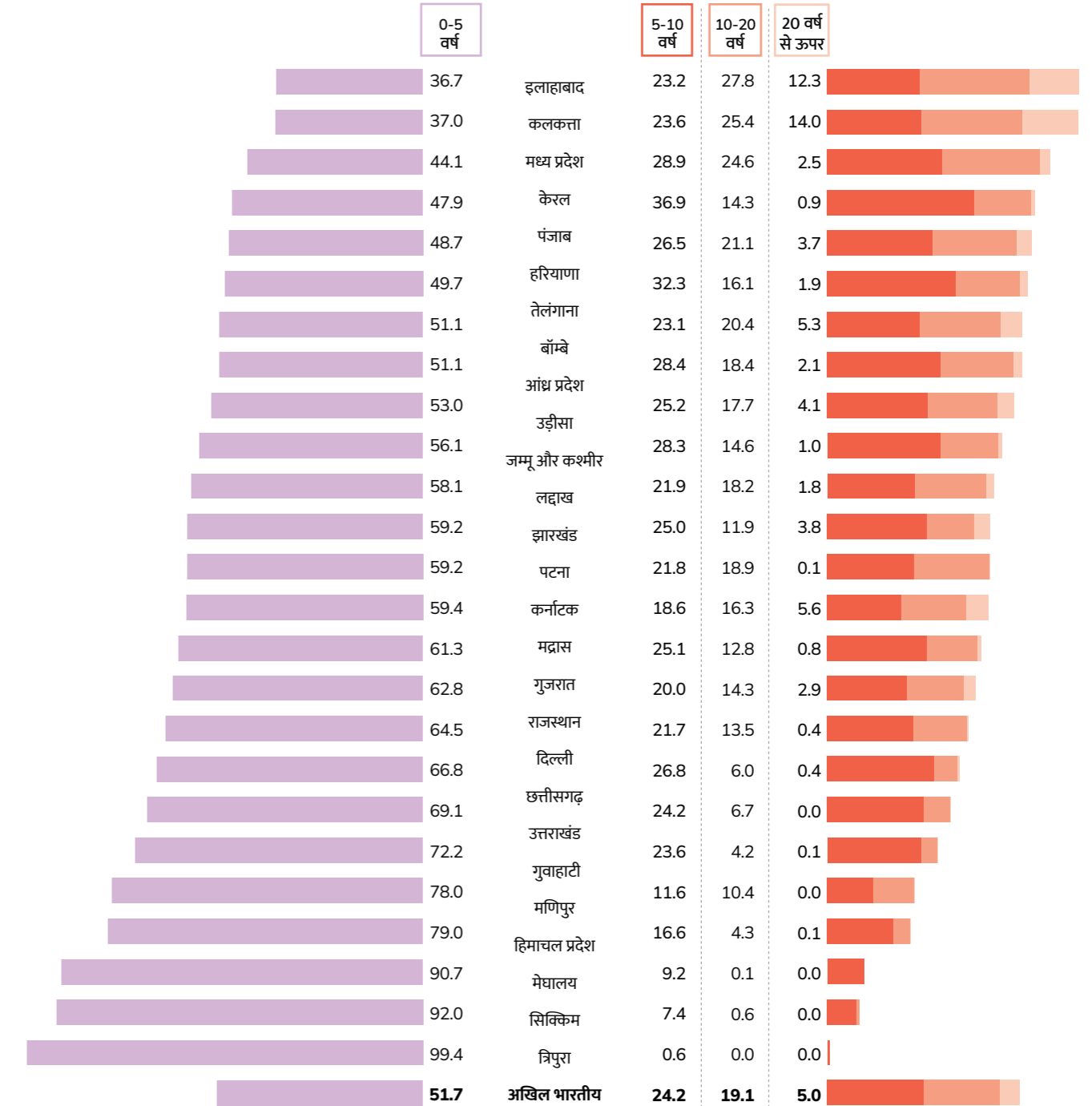


नोट: 1. आई. जे. आर. 3 मूल्य के अवरोही क्रम में संबंधित समूह में व्यवस्थित राज्य। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।  
 स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

### चित्र 12: उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

उच्च न्यायालयों में विचाराधीनता का स्तर अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में बदतर है। सभी 25 उच्च न्यायालयों में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों की हिस्सेदारी 48.3% है। जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य इस मीट्रिक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) और कलकत्ता (पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) सबसे खराब हैं, जहां पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है।

अवधि के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित मामले (%), 2 जनवरी, 2023)



नोट: 1. उच्च न्यायालयों को 0-5 वर्षों के मूल्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
 स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड





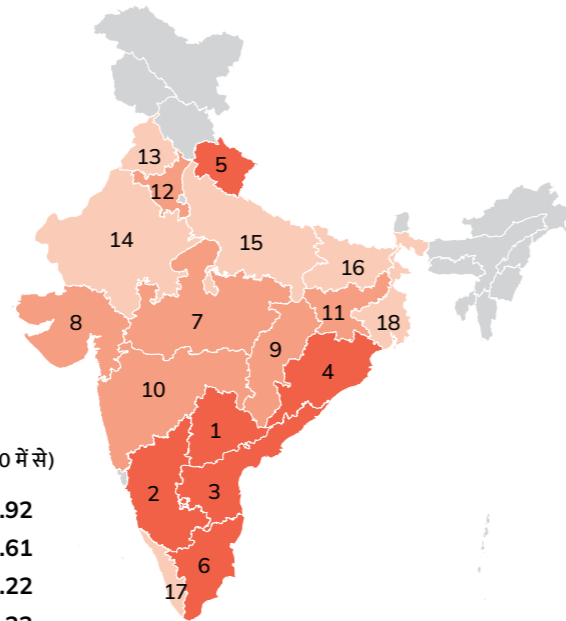
पुलिस

# रैंकिंग

**कलर गाइड**  
■ सर्वश्रेष्ठ ■ बीच का ■ सबसे खराब

संकेतक (आईजेआर 3 में) **30**

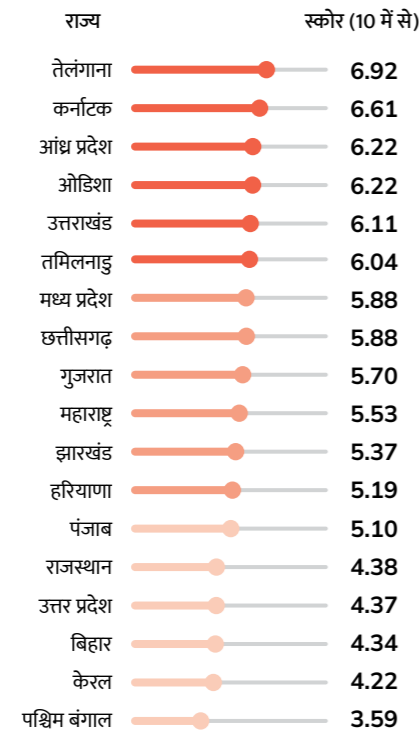
**समूह**  
 1. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (जनसंख्या 10 लाख से अधिक)  
 2. 7 छोटे आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ तक)



## मानचित्र 9: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

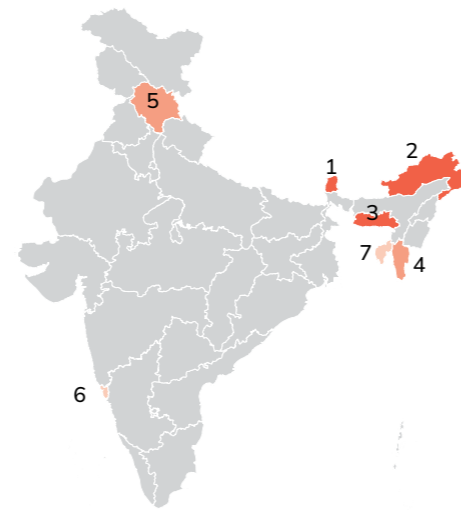
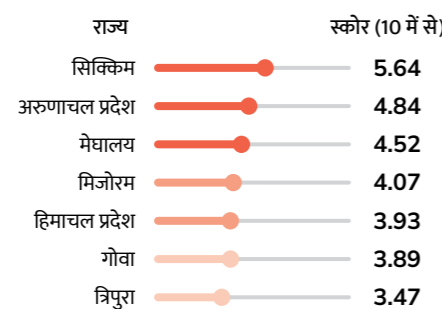
आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
11	10	1
6	1	2
5	4	3
7	3	4
2	7	5
1	5	6
15	18	7
12	8	8
10	2	9
4	13	10
9	6	11
8	9	12
3	12	13
17	16	14
18	15	15
14	11	16
13	14	17
16	17	18



## मानचित्र 10: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
2	4	2
5	3	3
7	6	4
6	2	5
3	7	6
4	5	7



नोट: अंक 2 दशमलव तक दिखाए जाते हैं। जबकि वे दोनों समान अंक दिखाते हैं, आंध्र प्रदेश तीसरे दशमलव (6.218 बनाम 6.217) पर ओडिशा से ऊपर है और मध्य प्रदेश चौथे दशमलव (5.8762 बनाम 5.8758) पर गुजरात से ऊपर है।

# उम्मीदें बढ़ाना

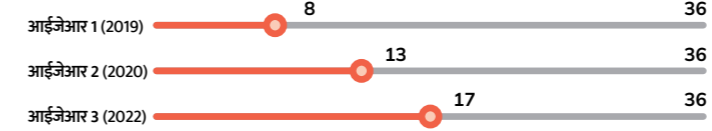
## आधुनिकीकरण कोष

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने अपने आधुनिकीकरण कोष का पूरी तरह से उपयोग किया। कुल राज्य \*



## महिला कर्मचारी

ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक है।



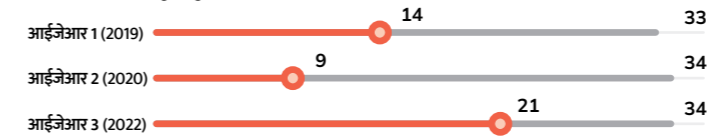
## एससी/एसटी/ओ. बी. सी. कोटा

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने अपने घोषित कोटे का कम से कम 80 प्रतिशत पूरा किया है।



## बजट

5 वर्षों में ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, जिनके पुलिस खर्च में उनके राज्य के खर्च से अधिक वृद्धि हुई है।



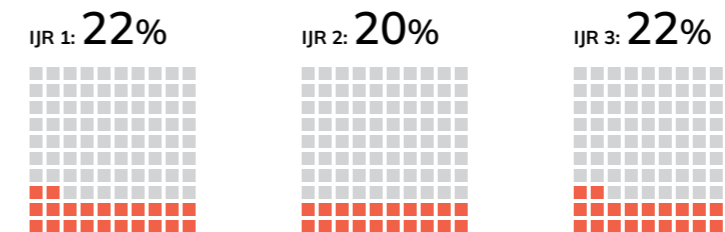
## क्षेत्र का दायरा

1981 के 150 वर्ग किलोमीटर के मानक को पूरा करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में एक पुलिस स्टेशन के लिए।



\*राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या (36 में से) जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे।

## पुलिस बल में रिक्रिया



## बुनियादी ढांचा सीसीटीवी



## 1 in 4

पुलिस थानों में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है।

## महिला सहायता डेस्क



## 3 in 10

पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क नहीं है।

## प्रशिक्षण

कुल पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का अखिल भारतीय हिस्सा **1.3%** है, केवल 5 राज्यों में यह 2 प्रतिशत से अधिक है।



## पुलिस में 'अन्य'

कुल पुलिस में 'अन्य' यदि कोई हो' का **5%** हिस्सा



आंध्र प्रदेश में **33%** पुलिस कर्मी 'अन्य' यदि कोई हो' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।





## आंध्र प्रदेश में 'महिला पुलिस'

पुलिस कर्मियों की संख्या की गणना करते समय, पुलिस संगठन 2022-पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का डेटा रैंक के आधार पर कर्मियों की श्रेणियों को सारणीबद्ध करता है। इसके अलावा, "अन्य यदि कोई हो" शीर्षक वाला एक अपरिभाषित कॉलम भी है। ये सब मिलकर एक राज्य की कुल पुलिस बनाते हैं। "अन्य यदि कोई है" आम तौर पर उन भूमिकाओं में कार्यरत लोगों की श्रेणी को इंगित करता है जो सहायक क्षमताओं में पुलिस के काम में सहायता करते हैं। इसमें अल्पकालिक टाइपिस्ट और मशीन ऑपरेटर से लेकर मैसेंजर बॉय, मुखबिर, सफाई कर्मचारी और अन्य अस्थायी या संविदात्मक मंत्रालयिक (contractual ministerial) और नौकर कर्मचारी (menial staff) शामिल हो सकते हैं।

जनवरी 2022 तक, 'अन्य' श्रेणी की कुल स्वीकृत ताकत लगभग 1.3 लाख है, जबकि वास्तविक ताकत 1.1 लाख है। इस श्रेणी की संख्या ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान में शून्य से लेकर आंध्र प्रदेश में 29,179 और उत्तर प्रदेश में 17,295 तक है। राष्ट्रीय स्तर पर, वास्तविक संख्या कुल (20.9 लाख) का 5% है।

आंध्र प्रदेश के लिए, 547 महिला अधिकारी, 3172 कांस्टेबल हैं और 'अन्य यदि कोई' श्रेणी में 15,580 महिलाओं को 'महिला पुलिस' के रूप में शामिल किया गया है।<sup>18</sup> इसने कुल पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इसे 21.8% तक बढ़ा देती है। जनवरी 2020 में 5.8 प्रतिशत से जनवरी 2022। फिर भी क्या 'महिला पुलिस'<sup>18</sup> दल को पुलिस कर्मी माना जा सकता है या मंडल स्तर पर ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता हैं, यह अनिश्चित और विवादास्पद बना हुआ है।

दिनांक 10.10.2019 के एक सरकारी आदेश ने कर्मियों का एक वर्ग बनाया, जिसे ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी / वार्ड महिला संरक्षण कार्यदर्शी के रूप में जाना जाता है, जिसमें मामलों की जांच में SHO की सहायता करना और आईओ के आगमन से पहले अपराध स्थल की सुरक्षा करना आदि शामिल थे। बाद में, एक संशोधन अधिसूचना G.O.Ms.No 59 दिनांक 23.06.2021 ने ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी/वार्ड

महिला संरक्षण कार्यदर्शी को 'महिला पुलिस' से प्रतिस्थापित कर दिया। इस आदेश में उनके प्रशिक्षण को 'प्रचलन' के रूप में प्रदान किया गया, महिला कांस्टेबलों के समान वर्दी और विभिन्न अधिनियमों के तहत समान अधिकार और शक्तियाँ जो कांस्टेबलों को दी गई हैं। हेड कांस्टेबलों के पद और पदोन्नति के रास्ते भी उपलब्ध कराए गए।

एक जनहित याचिका (पीआईएल) ने इस सरकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी। 15,000 महिलाओं के पुलिस कर्मी होने के विवरण में चुनौतियाँ उन्हें शामिल करने के तरीके (बल में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले सख्त नियमों का पालन किए बिना) से लेकर, उनके कार्यों में स्वतंत्र हस्तक्षेपों के बारे में चिंताएं, जिन्हें 'पुलिस' कहा जाता है और शामिल हैं। वर्दी में उपस्थिति का मतलब।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सवालों का सामना करते हुए, दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपमानजनक आदेश वापस ले लिया और इसके बजाय इसे आंध्र प्रदेश महिला पुलिस (अधीनस्थ सेवा नियम, 2021) दिनांक 12.01.2022 के साथ संशोधित किया। इस बार इस स्थिति की फिर से पुष्टि हुई कि ये पुलिस विभाग के भीतर एक अलग कार्यक्षेत्र बनने जा रहे थे। अब सहायक कर्मियों का नाम बदलकर महिला पुलिस कर दिया गया। जीओ ने उनकी विशिष्ट वर्दी और प्रतीक चिन्ह का विवरण दिया; उनकी शक्तियों और कार्यों को परिभाषित किया; नियुक्ति निकाय और प्रक्रियाएं निर्धारित कीं; और प्रशिक्षण, परिवीक्षा की अवधि की रूपरेखा, रैंक, पदोन्नति के रास्ते और पर्यवेक्षण पदानुक्रम निर्दिष्ट करता है।

जनहित याचिका लिखे जाने तक, इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था कि महिला पुलिस को पुलिस कर्मी माना जाएगा या नहीं। हालाँकि, आंध्र योजना और अन्य राज्यों में 'अन्य' की बढ़ती संख्या बाहरी भर्ती के माध्यम से पुलिसिंग कार्यों को बढ़ाने की बढ़ती राष्ट्रीय प्रवृत्ति को इंगित करती है, जो पुलिस भर्ती अनुशासन और जवाबदेही मानकों को पूरा नहीं करती है, फिर भी 'के तहत कार्य करती प्रतीत होती है। 'पुलिसिंग' पुलिस अधिनियम में निर्धारित है।

**जनसंख्या/सिविल पुलिस:** जनवरी 2022 तक, देश भर में 831 लोगों की सेवा के लिए एक पुलिस व्यक्ति उपलब्ध था (सिविल और जिला सशस्त्र पुलिस को मिलाकर)। यह जनवरी 2020 में 858 से थोड़ा सुधार है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों<sup>19</sup> में, पुलिस-से-जनसंख्या अनुपात में कमी आई है (इस कमी को समझने के लिए 'अन्य' पर बॉक्स देखें)। पंजाब में प्रत्येक 500 लोगों पर एक पुलिसकर्मी का अनुपात सबसे अच्छा है, जबकि बिहार का अनुपात 146 तक खराब होकर प्रति 1,695 लोगों पर एक पुलिसकर्मी पर पहुंच गया है।

## विविधता<sup>25</sup>

एससी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

एससी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

एसटी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

एसटी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

ओबीसी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

ओबीसी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022)

अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022) कुल पुलिस में महिलाएं (पीपी, CY'17-'21)

**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण<sup>26</sup>:** संवैधानिक समानता सभी राज्यों को जाति कोटा आरक्षित करने का आदेश देती है। इस मानक के पीछे की आकांक्षा सभी क्षेत्रों में लगातार कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रतिनिधित्व में अंतर को दूर करना है - जिसका नेतृत्व सरकारें कर रही हैं। जनवरी 2022 तक, अनुसूचित जाति कुल कार्यरत पुलिस बल का 15.99 प्रतिशत<sup>27</sup> (जनसंख्या में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले), अनुसूचित जनजाति

## संस्वीकृत कार्मिक संख्या

रक्तियों का जटिल प्रश्न न्याय प्रणाली पर कुठाराघात करता है। स्वीकृत संख्या में कमी से रक्ति के स्तर में कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, दो वर्षों<sup>20</sup> में केरल ने नागरिक पुलिस की स्वीकृत संख्या में 239 कर्मियों की कमी कर दी। नतीजतन, रक्तियां कम हो गई हैं (10% से 8.8%) लेकिन 'कार्यभार' (जनसंख्या-से-पुलिस अनुपात) बढ़ गया है (773 व्यक्तियों से 776 व्यक्तियों तक)।

प्रशासन समय-समय पर स्वीकृत शक्ति को संशोधित करता है, हालांकि 'आदर्श' अनिश्चित रहता है। सुझाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानक 222 प्रति लाख जनसंख्या है।<sup>21</sup> राज्य और शहर स्तर पर आधिकारिक और नागरिक समाज के अध्ययनों ने इष्टतम मानव संसाधन आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने का प्रयास किया है जो वर्तमान ताकत से 457% से 621% तक की वृद्धि का सुझाव देता है।<sup>22</sup> 2014 ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अध्ययन ने तीन शिफ्ट पुलिसिंग के आधार पर गणना की कि 61% अधिक कर्मियों की आवश्यकता थी।<sup>23</sup> 1982 से केरल ने एक पुलिस स्टेशन की न्यूनतम शक्ति के रूप में 1SI:1 ASI: 5HC: 25 PC का मानदंड निर्धारित किया है, लेकिन पुलिस स्टेशनों में वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय बाधाएं इस मानदंड को बनाए रखने में एक चुनौती पैदा करती हैं, जिससे इस मानदंड को बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। भारत - दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश - प्रति लाख जनसंख्या पर 152.8 पुलिसकर्मी हैं।<sup>24</sup>

11.77 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 30.79 प्रतिशत और महिलाएं 11.75 प्रतिशत हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रतिनिधित्व पर डेटा 2014 से अनुपलब्ध है।<sup>28</sup> उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद, पुलिस विभागों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती शुरू कर दी है, लेकिन विस्तृत राज्य-वार डेटा अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

18 'सरकार ने एपी महिला पुलिस विंग के लिए नियमों को अधिसूचित किया', द हिंदू, 13 जनवरी 2022। यहां उपलब्ध है: <https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/govt-notify-rules-for-ap-mahila-pulis-ving/article38261660.ece>

19 आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़।  
 20 जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक  
 21 पीआरएस विधायी अनुसंधान, भारत में पुलिस सुधार। यहां उपलब्ध है: <https://prsindia.org/policy/analytical-reports/police-reforms-india>  
 22 नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केंद्र, जनशक्ति आवश्यकता अध्ययन, बैंगलोर सिटी पुलिस, 2014। यहां उपलब्ध है: <https://www.janaagraha.org/files/publications/Manpower-Requirements-Study-March-2014.pdf>  
 23 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस स्टेशनों में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए जनशक्ति की राष्ट्रीय आवश्यकता; अगस्त 2014  
 24 कुल वास्तविक पुलिस संख्या (सिविल + डीएआर + विशेष सशस्त्र + आईआरबी) के मुकाबले पुलिस-प्रति-लाख-जनसंख्या अनुपात (पीपीआर), पुलिस संगठन पर डेटा, 2022, पी। 76.  
 25 विविधता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं शामिल हैं।  
 26 आरक्षण पर बीपीआरडी डेटा छह रैंकों के लिए डेटा की गणना करता है: एसपी/उप. एसपी/सहायक. कमांडेंट, इंस्पेक्टर/रिजर्व इंस्पेक्टर, एस.आई/रिजर्व सब-इंस्पेक्टर (एसआई), एसआई/एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल।  
 27 भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत की जनगणना, 2011। यहां उपलब्ध है: <https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>  
 28 एनएएलएसए बनाम भारत संघ, 2014, '[टी] उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर और अन्य लिंग गैर-अनुरुप व्यक्तियों को कानूनी मान्यता दी। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्राप्त करने की अनुमति दें।

गुजरात और मणिपुर अधिकारी और कांस्टेबल दोनों स्तरों पर अपने एससी कोटा को पूरा करने के लिए अग्रणी हैं, जबकि बिहार, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश अपने एसटी कोटा को पूरा करने के लिए हैं। जब ओबीसी की बात आती है तो राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर होता

है। कम से कम 9 राज्यों (कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु और केरल) ने अपना ओबीसी कोटा पूरा कर लिया है।

### चित्र 13 पुलिस में एससी, एसटी, ओबीसी रिक्तियां



टिप्पणी: 1. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए संयुक्त एससी/एसटी/ओ. बी. सी. आरक्षण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 3. मेघालय में अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 4. बी. पी. आर. एंड डी. अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड के लिए 0 प्रतिशत अनुसूचित जाति आरक्षण दिखाता है। 5. बी. पी. आर. एंड डी. लद्दाख के लिए 0 अनुसूचित जाति अधिकारी के आंकड़े दिखाता है। 6. बी. पी. आर. एंड डी. ने मिजोरम, चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए 0 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आरक्षण दिखाया है। 7. बी. पी. आर. एंड डी. ने अरुणाचल प्रदेश, एल. के लिए 0 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण दिखाया।

कुछ राज्यों में, आरक्षित समूहों का प्रतिशत हिस्सा अधिकारी और कांस्टेबल स्तर के बीच काफी भिन्न होता है। उत्तराखंड में एससी के लिए 19 फीसदी आरक्षण के मुकाबले कांस्टेबल स्तर पर एससी के लिए आरक्षित 98 फीसदी पद भरे जा चुके हैं, जबकि अधिकारियों के लिए यह सिर्फ 54 फीसदी है। उत्तराखंड में, एसटी के लिए 4 प्रतिशत कोटा के मुकाबले, 132 प्रतिशत कांस्टेबल पद भरे गए, लेकिन केवल 55 प्रतिशत अधिकारी ही भरे गए। इसके विपरीत, गोवा में अधिकारी स्तर पर एससी की हिस्सेदारी कांस्टेबलरी (43 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है (110 प्रतिशत)।

आरक्षण लक्ष्य पूरा करने में असम और जम्मू-कश्मीर का प्रदर्शन सबसे खराब है।

अधिक राज्य अधिकारी स्तर के बजाय कांस्टेबलरी के भीतर कोटा पूरा करने में सक्षम हैं। जबकि 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने एससी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, केवल 5 ने एससी अधिकारियों के कोटा को पूरा किया। बारह राज्यों ने एसटी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, जबकि केवल 7 ने अपने अधिकारी कोटा को पूरा किया। ओबीसी कोटा 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिकारी कोटा में भरे गए। स्तर पर और 13 कांस्टेबलरी स्तर पर।<sup>34</sup>

**लिंग:** पुलिस बल में कितनी महिलाएँ होनी चाहिए, इसके लिए अधिकांश राज्यों का अपना विशिष्ट कोटा है। जबकि 6 केंद्रशासित प्रदेशों<sup>35</sup> और 9 राज्यों<sup>36</sup> का लक्ष्य 33 प्रतिशत है, अन्यत्र, लक्ष्य बिहार के 35 प्रतिशत से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में 10 प्रतिशत तक है। केरल और मिजोरम सहित<sup>38</sup> राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोई आरक्षण नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में कांस्टेबल स्तर पर महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की हैं।

जनवरी 2022 तक, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था। 21.8 प्रतिशत के साथ आंध्र प्रदेश में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसने हाल ही में 'महिला पुलिस' नामक 15,000 महिला-सशक्त सहायक बल बनाया है।

29 सिक्किम, कर्नाटक, मणिपुर, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु  
30 गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश।  
31 बिहार, लक्षद्वीप, कर्नाटक, लद्दाख, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश।  
32 लद्दाख, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप  
33 पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल  
34 ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, पुडुचेरी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरल, तमिलनाडु, गुजरात।  
35 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, डीएनएच एवं डीडी, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़।  
36 आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब।  
37 बिहार सरकार के नियम के मुताबिक महिलाओं के लिए 35 फीसदी और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 3 फीसदी आरक्षण है।  
38 जम्मू और कश्मीर, केरल, मिजोरम, गोवा, लद्दाख।

39 राज्यसभा अतारिक्त प्रश्न संख्या 701 दिनांक 8 फरवरी 2023। यहां उपलब्ध है: <https://pqars.nic.in/annex/259/AU701.pdf>

40 यह मानते हुए कि बल में शामिल सभी महिलाएं केवल पुलिस स्टेशनों पर तैनात हैं, जो अक्सर मामला नहीं होता है।

41 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, नागालैंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, असम, लद्दाख, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, डीएनएच और डीडी

अधिक राज्य अधिकारी स्तर के बजाय कांस्टेबलरी के भीतर कोटा पूरा करने में सक्षम हैं। जबकि 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>29</sup> ने अपने एससी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, केवल 5 ने एससी अधिकारियों के कोटा को पूरा किया।<sup>30</sup> बारह राज्यों<sup>31</sup> ने एसटी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, जबकि केवल 7 ने अपने अधिकारी कोटा को पूरा किया। ओबीसी कोटा<sup>32</sup> 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>33</sup> द्वारा अधिकारी कोटा में भरे गए। स्तर पर और 13 कांस्टेबलरी स्तर पर।<sup>34</sup>

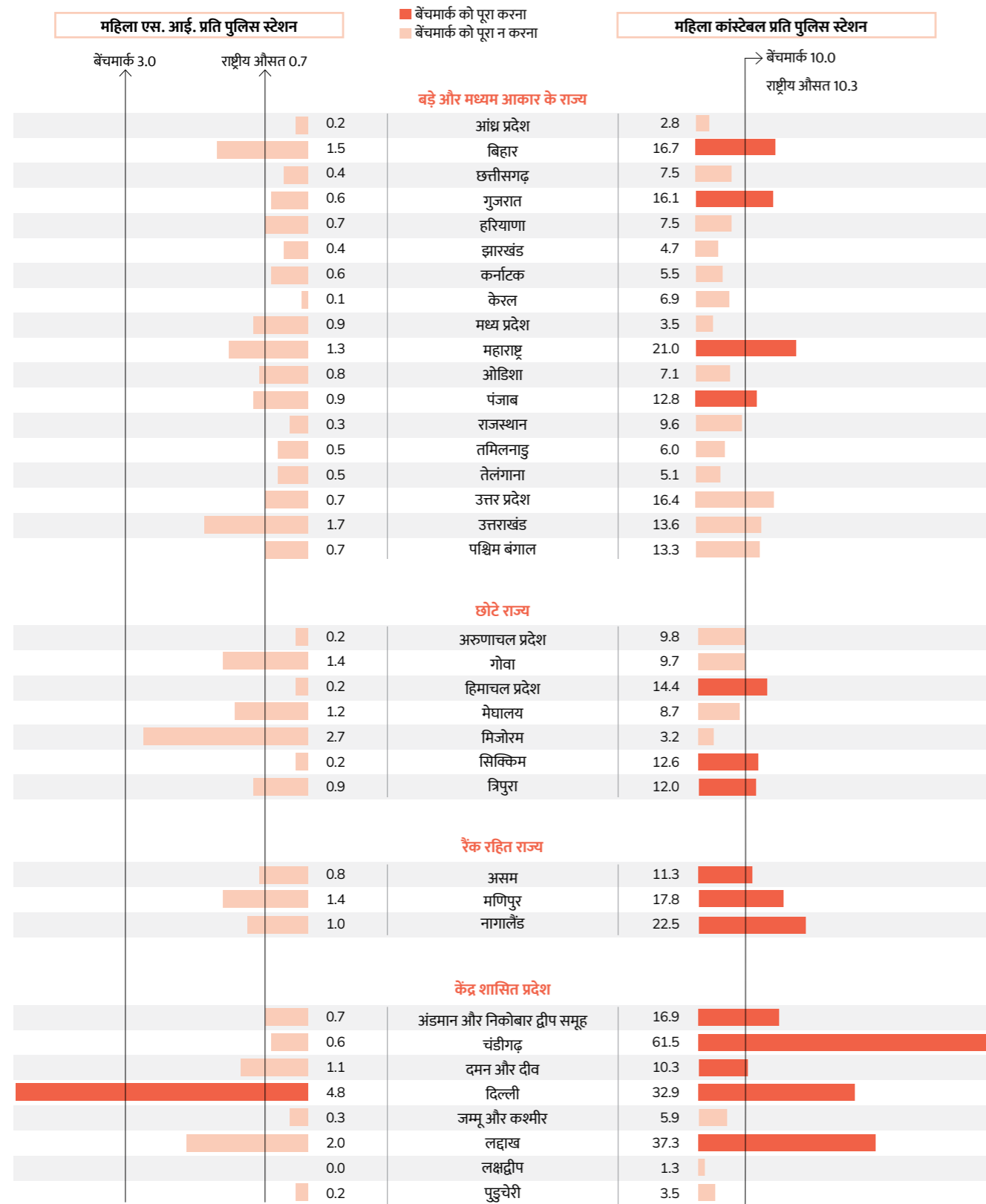
### महिलाओं के लिए पर्याप्त महिलाएं?

“गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व 33% तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021 और 13.04.2022 को सलाह जारी की है। कुल ताकत. सभी राज्य सरकारों से कांस्टेबल/उप-निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल/उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों, ताकि एक महिला हेल्प डेस्क चौबीसों घंटे तैनात रहे।”<sup>39</sup>

जनवरी 2022 में देश में 17,535 पुलिस स्टेशन और 13,146 महिला एसआई थीं। लक्ष्य पूरा करने के लिए अन्य 39,459 महिला एसआई की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, केवल दिल्ली, 225 पुलिस स्टेशनों और 1,086 महिला एसआई के साथ, और मिजोरम, 44 पुलिस स्टेशनों और 119 एसआई के साथ, आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखते हैं।<sup>40</sup> जनवरी 2022 तक देश में रिकॉर्ड पर 180,685 महिला कांस्टेबल थीं। यदि इन्हें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समान रूप से तैनात किया जाता है, तो 18 में सलाहकार बेंचमार्क को पूरा करने के लिए पर्याप्त महिला कांस्टेबल<sup>41</sup> होंगी।

### चित्र 14 महिला पुलिसकर्मी: संख्या बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत कम है

गृह मंत्रालय के कई सलाहकारों ने सिफारिश की है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सब-इंस्पेक्टर (एस. आई.) और 10 महिला कांस्टेबल हों। दिल्ली को छोड़कर, कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एस. आई. के लिए इस मानदंड को पूरा नहीं करता है।



नोट: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
 स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.)

राज्य में महिला कांस्टेबलों की वास्तविक संख्या 3,172 है ('अन्य यदि कोई हो' बॉक्स देखें)। लेकिन एपी अभी भी 33 प्रतिशत के अपने आरक्षण लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है। बिहार (21.2 प्रतिशत) और तमिलनाडु (19.1 प्रतिशत) में भी महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन वे क्रमशः 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के अपने घोषित लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। झारखंड में 33 प्रतिशत कोटा है, लेकिन 6.2 प्रतिशत के साथ, महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (7.1 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (7.4 प्रतिशत) का स्थान है। महिलाएं पुलिस पदानुक्रम में निचले पायदान पर हैं। महिला अधिकारी उस कैडर में केवल 8 प्रतिशत हैं: 21.4 प्रतिशत के साथ मिजोरम, 18.1 प्रतिशत के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत के साथ सबसे कम है। लक्षद्वीप, जिसमें 16 पुलिस अधिकारी हैं, के पुलिस बल में कोई महिला अधिकारी नहीं है।

### बजट

प्रति व्यक्ति पुलिस पर खर्च (₹, 2020-21)  
 आधुनिकीकरण निधि का उपयोग (% , 2020-21) (संशोधित)  
 प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर व्यय (₹, 2020-21) (संशोधित)  
 कुल पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (प्रतिशत, 2020-21) (संशोधित) **नया**  
 प्रशिक्षण बजट उपयोग (% , ₹, 2020-21) (संशोधित) **नया**  
 खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-21)

प्रभावी प्रशासन और इष्टतम कार्य क्षमताएं काफी हद तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और योजना पर निर्भर करती हैं। परिवर्तन कैसे आगे बढ़ता है, इस पर इन दोनों कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2016-17 और 2020-21 के बीच पुलिस पर राष्ट्रीय खर्च 35 फीसदी बढ़ गया। अधिकांश राज्यों में पुलिस व्यय में वृद्धि राज्य व्यय में वृद्धि से अधिक है। 2016-17 और 2020-21 के बीच, 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>42</sup> के लिए पुलिस व्यय में वृद्धि कुल राज्य व्यय में समग्र वृद्धि से अधिक है। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश के कुल राज्य व्यय में 5.16 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, लेकिन पुलिस पर व्यय 11.16 प्रतिशत अंक तक बढ़ गया। गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित दिल्ली पुलिस ने अपने बजट में 37 प्रतिशत की वृद्धि की। पुलिसिंग पर पांच साल की सबसे बड़ी

बजट व्यय वृद्धि झारखंड (70 प्रतिशत के साथ) और पश्चिम बंगाल (67 प्रतिशत) में देखी गई।

**प्रति व्यक्ति पुलिस खर्च:** 2020-21 में केरल<sup>43</sup> को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति पुलिस व्यक्ति खर्च में वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय औसत रु. 1,151- रुपये से वृद्धि। पिछले साल 911.5. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से ग्यारह<sup>44</sup> राज्य राष्ट्रीय औसत से कम खर्च करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>45</sup> में प्रति व्यक्ति खर्च सबसे अधिक है, उनमें से 5 केंद्रशासित प्रदेश हैं, 2 एफएएसपीए-राज्य हैं और शेष 3 छोटे राज्य हैं। प्रति पुलिस व्यक्ति का औसत खर्च भी नाटकीय रूप से भिन्न होता है; बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से, जबकि पंजाब रुपये खर्च करता है। प्रति व्यक्ति 2,055 रुपये खर्च करता है बिहार 641. सिक्किम जैसा छोटा राज्य (6,559 रुपये) अपने घनी आबादी वाले पड़ोसी पश्चिम बंगाल की तुलना में पुलिस पर काफी अधिक खर्च करता है, जो केवल रुपये खर्च करता है। 909.

**आधुनिकीकरण निधि का उपयोग:** 1969-1970 के बाद से, राज्य पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सशर्त वित्तीय सहायता के पात्र रहे हैं, मुख्य रूप से अत्याधुनिक हथियार और संचार/फोरेसिक उपकरण, प्रशिक्षण सहायता, साइबर पुलिसिंग आदि के अधिग्रहण के लिए। अपना वित्तीय योगदान भी देते हैं। अनुपात 90:10 (उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर के लिए) से लेकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 60:40 तक है।<sup>46</sup>

2016-17 और 2020-21 के बीच, राज्यों को कुल केंद्रीय निधि आवंटन रुपये से 46 प्रतिशत कम हो गया। 2,066.27 करोड़ रु. 1,123.05 करोड़, और उपयोग 75 प्रतिशत<sup>47</sup> से घटकर 47 प्रतिशत<sup>48</sup> हो गया।

**उपयोग एक चुनौती बनी हुई है।** 2020-2021 तक, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से, जिनके लिए डेटा उपलब्ध था, केवल गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी ने अपने संपूर्ण आधुनिकीकरण अनुदान का उपयोग करने की सूचना दी। आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 50 प्रतिशत से कम उपयोग किया। सबसे कम उपयोग करने वाले राज्यों में मणिपुर (1.5 प्रतिशत), असम (11.5 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (24.5 प्रतिशत) थे।

**प्रशिक्षण बजट और उपयोग:** देश भर में संचयी रूप से देखा जाए तो, कुल पुलिस बजट (1.78 लाख करोड़ रुपये) का केवल 1.3 प्रतिशत

42 उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, त्रिपुरा, गोवा, पुदुचेरी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र  
 43 डीएनएच और डीडी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की तुलना नहीं की गई।  
 44 बिहार, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।  
 45 लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, चंडीगढ़  
 46 गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। यहां उपलब्ध है: [https://www.mha.gov.in/vision\\_of\\_mha/Police%20Modernisation%20Division/modernisation-of-state-police-forces-mpf-sch](https://www.mha.gov.in/vision_of_mha/Police%20Modernisation%20Division/modernisation-of-state-police-forces-mpf-sch)  
 47 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2017।  
 48 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2022।  
 49 तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर

(2020-21)<sup>50</sup> प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया गया था। प्रशिक्षण बजट में से रु. 2,253.09 करोड़ में से केवल 84 प्रतिशत का उपयोग किया गया, जिससे वास्तविक खर्च 1.1 प्रतिशत या दूसरे शब्दों में, रुपये से थोड़ा अधिक हो गया। 9,000 प्रति पुलिस व्यक्ति प्रति वर्ष।

उत्तीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>51</sup> ने राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। 2016-17<sup>52</sup> से प्रशिक्षण के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है लेकिन 2 प्रतिशत तक नहीं पहुंची है। जिन राज्यों ने प्रशिक्षण पर अपना आवंटन लगातार बढ़ाया है उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है - जहां यह रुपये से बढ़ा है। 144.9 करोड़ (2016-17) से रु. 283.46 करोड़ (2020-21)—96 प्रतिशत की छलांग, जिससे यह चार वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी वृद्धि है। इसी अवधि में तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने वास्तव में अपने बजट में क्रमशः 9.8 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 52.9 प्रतिशत की कमी की है।<sup>53</sup>

चौदह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों,<sup>54</sup> ने प्रशिक्षण के लिए अपने कुल पुलिस बजट का 1 प्रतिशत से भी कम आवंटित किया, जिसमें से केवल गुजरात ही पूरी राशि का उपयोग करने में सक्षम था। सर्वाधिक 5.4 प्रतिशत आवंटन के साथ अरुणाचल प्रदेश ने अपने प्रशिक्षण बजट का 96 प्रतिशत उपयोग किया। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः 0.04 और 0.05 प्रतिशत के साथ सबसे कम प्रशिक्षण बजट था।

### आधारभूत संरचना

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या: पुलिस स्टेशन के स्थान जनसंख्या, अपराध प्रोफ़ाइल, स्थलाकृति और वित्त और मानव संसाधन उपलब्धता सहित कई अन्य विचारों से तय होते हैं। 2012 से 2022 के बीच पुलिस स्टेशनों की संख्या में 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रव्यापी, 17,535 पुलिस स्टेशन 1.37 अरब की आबादी और 3,287,469 वर्ग किमी क्षेत्र की सेवा करते हैं। इसका औसत लगभग 78,344 लोगों के लिए एक पुलिस स्टेशन और 187 वर्ग किमी का कवरेज है।

कुल मिलाकर, भले ही भारत की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, क्षेत्र-वार पुलिसिंग मशीनरी शहरी क्षेत्रों में कहीं अधिक केंद्रित है।

औसतन, एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 337.4 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है - इसका मतलब शहरी पुलिस स्टेशन (20.2 वर्ग किमी) द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का 16.7 गुना है।

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (ग्रामीण) (जनवरी 2022)
प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (शहरी) (जनवरी 2022)
प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग किमी, जनवरी 2022)
प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (शहरी) (वर्ग किमी, जनवरी 2022)
प्रति प्रशिक्षण संस्थान पुलिस कर्मी (संख्या, जनवरी 2022)
राज्यों के नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (% , 2022)
सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशनों की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022) <b>नया</b>
महिला हेल्प डेस्क वाले पुलिस स्टेशनों की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022) <b>नया</b>

सभी तीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस स्टेशन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बड़े क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों की तुलना में 118 गुना अधिक क्षेत्र कवर करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह क्रमशः 41 और 36 गुना है। केरल और पुदुचेरी एकमात्र ऐसे भूगोल हैं जहां अंतर मामूली है।<sup>56</sup> बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, राजस्थान प्रति ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए सबसे बड़े क्षेत्र (684 वर्ग किमी प्रति पीएस) और केरल में प्रति शहरी पुलिस स्टेशन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र (74 वर्ग किमी) है। किमी प्रति पीएस)।

औसतन, ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों (94,683) की तुलना में थोड़ी बड़ी और शायद अधिक बिखरी हुई आबादी (97,362) की सेवा करते हैं। हालाँकि, शहरों और कस्बों में आबादी की संकेंद्रित प्रकृति के कारण, 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>57</sup> में शहरी पुलिस स्टेशन अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं: केरल के शहरी पुलिस स्टेशन ग्रामीण की तुलना में दस गुना अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं, जबकि गुजरात में चार गुना। तेलंगाना में, ग्रामीण और शहरी दोनों स्टेशन लगभग समान संख्या में सेवा प्रदान करते हैं। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, प्रति

### चित्र 15: भारत: पुलिस प्रशिक्षण बजट (2020-21)

लगभग 21 लाख की संख्या वाले बल के लिए प्रशिक्षण पर कुल खर्च 2,253 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि प्रति पुलिस कर्मी का राष्ट्रीय वार्षिक औसत खर्च मात्र 9,000 रुपये है।

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	पुलिस बजट (करोड़ रुपये)	पुलिस प्रशिक्षण बजट (करोड़ रुपये)	कुल पुलिस (वास्तविक संख्या)	कुल पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (%)	प्रशिक्षण बजट उपयोग (%)	प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर खर्च (रु.)
आंध्र प्रदेश	5,490.62	57.21	88,689	1.04	99.5	6,417
बिहार	9,991.23	142.17	93,313	1.42	71.8	10,944
छत्तीसगढ़	4,897.61	62.46	64,573	1.28	53.5	5,179
गुजरात	5,379.80	52.53	89,846	0.98	100.0	5,847
हरियाणा	5,043.11	43.12	59,078	0.86	95.8	6,991
झारखंड	5,003.19	46.00	63,077	0.92	89.2	6,506
कर्नाटक	6,934.31	85.05	95,516	1.23	90.2	8,031
केरल	3,780.53	0.00	53,216	NA <sup>2</sup>	NA <sup>2</sup>	NA <sup>2</sup>
मध्य प्रदेश	7,451.94	184.18	103,642	2.47	87.9	15,629
महाराष्ट्र	16,996.90	159.86	170,570	0.94	84.2	7,887
ओडिशा	4,130.66	49.46	56,227	1.20	85.7	7,541
पंजाब	6,387.42	78.68	72,210	1.23	87.0	9,479
राजस्थान	6,621.30	126.95	96,058	1.92	100.0	13,216
तमिलनाडु	8,434.30	157.72	118,057	1.87	86.0	11,493
तेलंगाना	7,260.52	193.48	62,731	2.66	91.2	28,126
उत्तर प्रदेश	27,285.74	283.46	310,955	1.04	55.6	5,070
उत्तराखंड	2,038.13	16.78	20,359	0.82	63.9	5,270
पश्चिम बंगाल	11,403.54	4.78	96,104	0.04	61.3	305
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	1,021.73	55.10	12,100	5.39	96.4	43,901
गोवा	653.17	2.27	7,903	0.35	94.3	2,708
हिमाचल प्रदेश	1,414.74	0.65	17,133	0.05	89.2	339
मेघालय	1,067.79	6.52	13,881	0.61	96.8	4,546
मिजोरम	708.60	18.25	7,567	2.58	89.5	21,594
सिक्किम	495.37	4.75	5,868	0.96	85.1	6,885
त्रिपुरा	1,634.27	15.00	21,990	0.92	99.5	6,785
<b>रैंक रहित राज्य</b>						
असम	5,004.71	44.83	61,868	0.90	71.3	5,167
मणिपुर	2,119.49	34.54	28,631	1.63	79.6	9,608
नागालैंड	1,457.71	14.86	26,201	1.02	100.0	5,672
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार	398.90	3.99	4,331	1.00	100.0	9,213
द्वीप समूह	499.10	2.00	5,903	0.40	23.5	796
चंडीगढ़	69.08	-	1,179	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>
दमन और दीव	8,273.48	190.76	79,489	2.31	100.0	23,989
दिल्ली	8,419.26	117.67	79,464	1.40	88.9	13,171
जम्मू और कश्मीर	279.58	-	2,452	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>
लद्दाख	32.00	-	262	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>
लक्षद्वीप	258.65	-	3,390	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>	NA <sup>4</sup>
पुडुचेरी						
	178,338.47	2,253.09	2,093,833	1.26	84.0	9,043

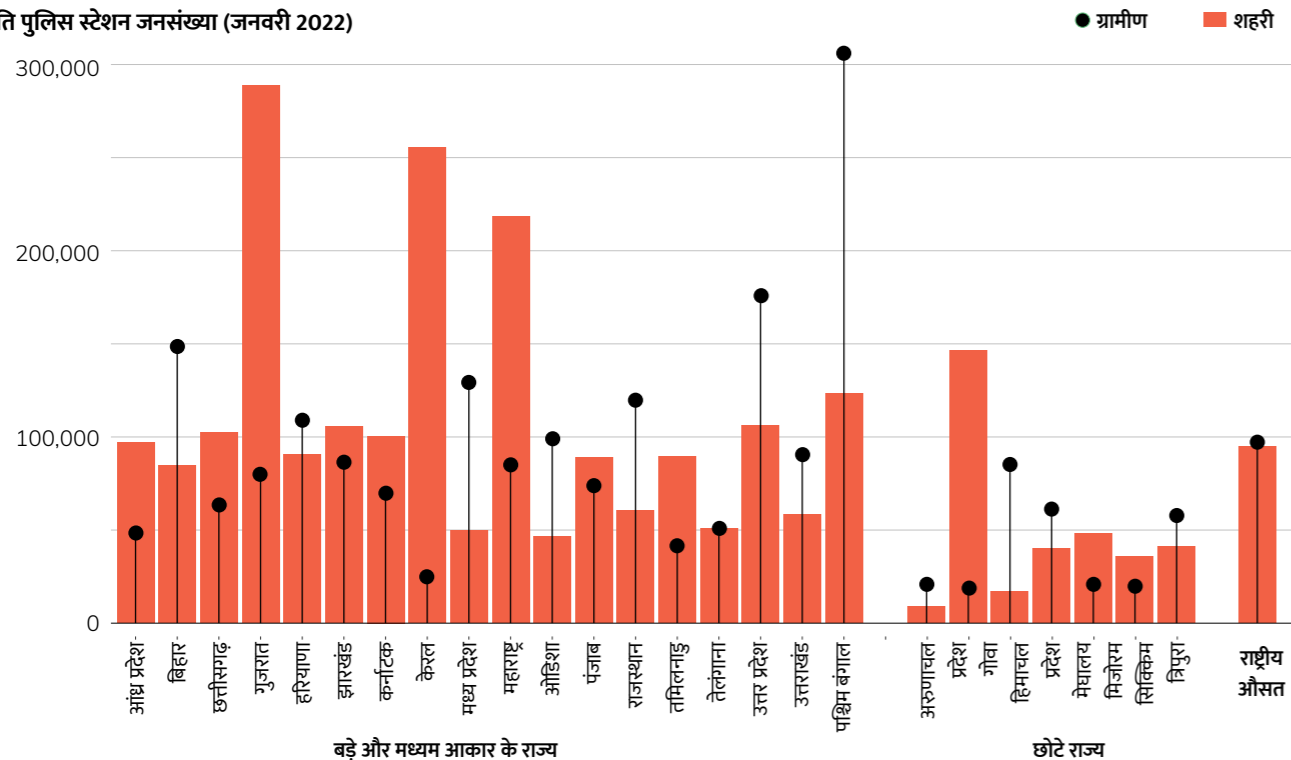
सामान्य टिप्पणियाँ: 2020-21 के लिए बजट डेटा, जनवरी 2022 के लिए कार्मिक आंकड़े। अंतिम तीन कॉलम में दिखाए गए प्रत्येक मेट्रिक्स के लिए, अलग-अलग तराजू का उपयोग किया गया है। राज्य टिप्पणियाँ: 1. बी. पी. आर. एंड डी. पुलिस प्रशिक्षण बजट को खाली बताता है। 2. बी. पी. आर. एंड डी. शून्य पुलिस प्रशिक्षण बजट दिखाता है। स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.)

50 पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी)  
 51 कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल।  
 52 BPR&D ने DoPO 2018 रिपोर्ट से पुलिस प्रशिक्षण बजट पर डेटा प्रदान करना शुरू किया।  
 53 तमिलनाडु से रु. 174.76 करोड़ से 157.72 करोड़, त्रिपुरा रु. 23.08 करोड़ से 15 करोड़ और पश्चिम बंगाल रु. 10.15 करोड़ से 4.78 करोड़  
 54 केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, मेघालय, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, गुजरात।  
 55 अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है  
 56 केरल के शहरी और ग्रामीण पुलिस स्टेशन लगभग समान क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं, शहरी में (74 वर्ग किमी) और ग्रामीण में (82 वर्ग किमी)। इसी तरह, पुदुचेरी का शहरी पुलिस स्टेशन भी ग्रामीण (21 वर्ग किमी) की तुलना में थोड़ा छोटा (11 वर्ग किमी) क्षेत्र में कार्य करता है।  
 57 तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, डीएनएच और डीडी, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल।

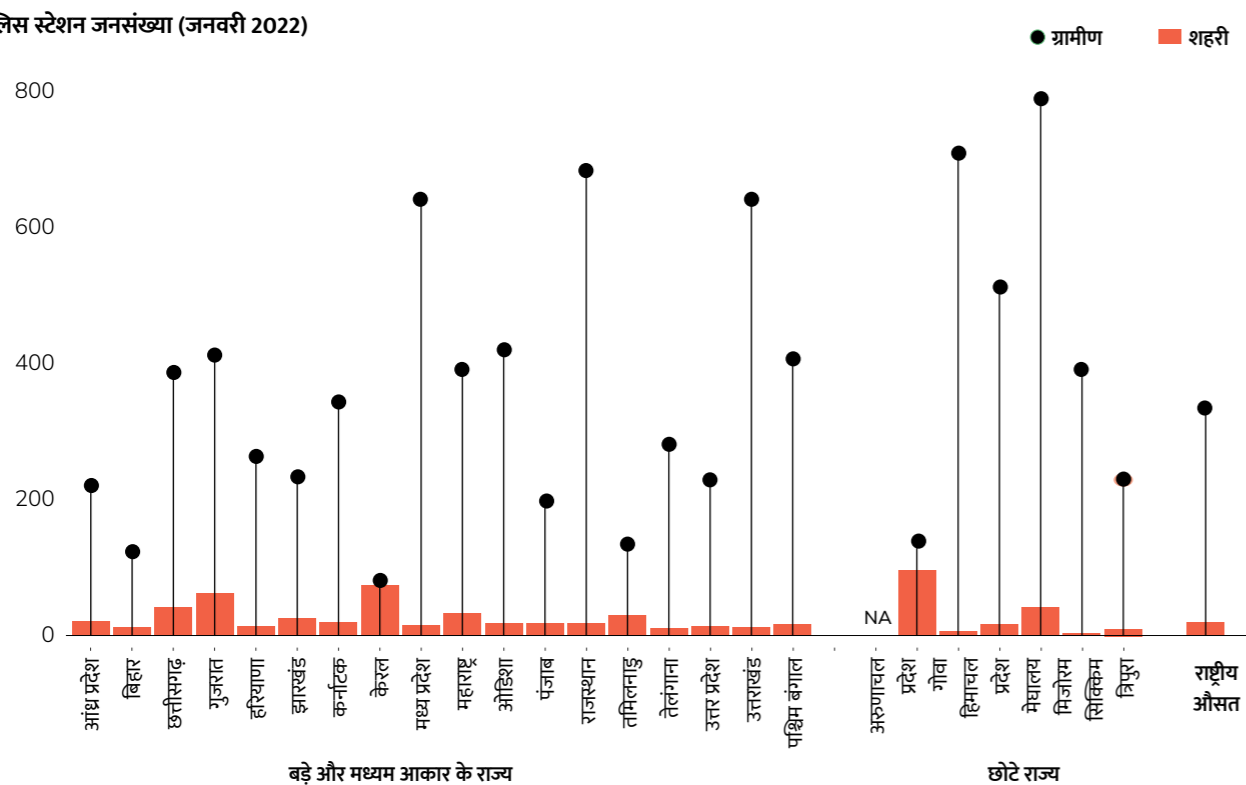
### चित्र 16: पुलिस की उपस्थिति: ग्रामीण-शहरी विभाजन

भारत की 60% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। पुलिस तंत्र शहरी क्षेत्रों में कहीं अधिक केंद्रित है। नीचे दिया गया ग्राफ दोनों सेटिंग्स में जनसंख्या और पुलिस स्टेशनों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों को दर्शाता है।

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (जनवरी 2022)



प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (जनवरी 2022)



नोट: 2011 की जनगणना अरुणाचल प्रदेश के लिए ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का विभाजन नहीं देती है। स्रोत: पुलिस संगठनों पर आंकड़े, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.); जनगणना 2011; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019

ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल (321,677) में है, जबकि शहरी पुलिस स्टेशनों में सबसे बड़ी आबादी गुजरात (288,788) में है।

केवल 6 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-गोवा (140), तमिलनाडु (137), बिहार (125), केरल (82), पुदुचेरी (21) और लक्षद्वीप (1)-राष्ट्रीय पुलिस आयोग के 1981 के 150 वर्ग किमी के अनुशासित क्षेत्र कवरेज को पूरा करते हैं। एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए।

प्रति प्रशिक्षण संस्थान पुलिसकर्मी<sup>58</sup>: दुनिया भर में संगठनात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि प्रेरण या बुनियादी प्रशिक्षण से परे संस्थागत समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास (Manpower Development) पर खर्च किया जाना चाहिए। बीपीआरडी का सुझाव है, "पुलिस के लिए आवश्यकता निश्चित रूप से सेवा अवधि के 5 प्रतिशत से अधिक होगी, हालांकि फिलहाल हम इसे केवल 5 प्रतिशत पर बेंचमार्क करते हैं।<sup>59</sup>

इसका अर्थ है नई पदोन्नति जिम्मेदारियों के लिए कर्मियों को तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमताएं उपलब्ध होना; संस्थागत मानदंडों पर पुनश्चर्या, संवैधानिक अनिवार्यताओं का पालन, अनिवार्य प्रक्रियाएं और संरक्षक पर्यवेक्षण; विशेषज्ञता के लिए पाठ्यक्रम, कानून में बदलाव, नए प्रकार के अपराध और प्रौद्योगिकी से अवगत रहना; मनोवैज्ञानिक तीक्ष्णता (Psychological acuity) और सामुदायिक विश्वास का निर्माण; कमजोर समूहों और आकस्मिक स्थितियों से निपटना; और कई अन्य पहलुओं में कौशल बढ़ाना जो लोकतंत्र में दिन-प्रतिदिन की पुलिसिंग संस्था की मांग है।

प्रशिक्षण स्कूलों और अकादमियों की सामान्य स्थिति यह है कि उनके पास अल्प संसाधन और काम की अधिकता है। जनवरी 2022 तक, प्रति प्रशिक्षण संस्थान का औसत कार्यभार<sup>60</sup> 12,744 व्यक्ति था। 26.88 लाख स्वीकृत पुलिस कर्मियों के लिए, भारत में कुल 211 प्रशिक्षण संस्थान हैं, जनवरी 2020 से 8 की वृद्धि हुई है। केरल में 2 से 3, हरियाणा में 3 से 4, तमिलनाडु में 23 से 24 और पश्चिम बंगाल में 10 से 16 हो गए हैं। 11 प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण कार्यभार औसतन 38,382 प्रति संस्थान है, जो राष्ट्रीय औसत

से लगभग तीन गुना है। मणिपुर का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान लगभग 35,000 पुलिस कर्मियों के कार्यभार से निपट रहा है। तमिलनाडु के 24 संस्थान औसतन 5,480 कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं।

सीसीटीवी कैमरों वाले पुलिस स्टेशनों का हिस्सा: 2020 में, परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020)<sup>61</sup> में उच्चतम न्यायालय ने सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना के संबंध में कई निर्देश पारित किए। जनवरी 2022 तक, राष्ट्रीय स्तर पर, 17,535 पुलिस स्टेशनों में से केवल 73.5 प्रतिशत (12,893) ने कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया था।<sup>62</sup>

पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटक सहित आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>63</sup> के सभी पुलिस स्टेशनों में कम से कम एक सीसीटीवी था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितने या वे उन विशिष्ट स्थानों पर स्थित हैं या नहीं, जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें स्थापित करने की मांग की थी।

चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (राजस्थान, मणिपुर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप) ने बताया कि उनके 1 प्रतिशत से भी कम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी हैं। राजस्थान में शहरी पुलिस स्टेशन में केवल एक ही प्रबंधित किया गया था; मणिपुर, पुदुचेरी और लक्षद्वीप ने कोई रिपोर्ट नहीं की।

नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>64</sup> के आधे ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नहीं हैं। केवल 7 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>65</sup> ने सभी विशेष प्रयोजन पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी स्थापित किए हैं।<sup>66</sup>

महिला सहायता डेस्क: न्याय तक पहुंच में सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा की डिग्री को देखते हुए, पुलिस में प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। गृह मंत्रालय की समय-समय पर सलाह ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है।<sup>67</sup>

जनवरी 2022 तक, देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में से 72 प्रतिशत ने इन विशेष सुविधाओं की सूचना दी। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क हैं। बिहार के 47 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क हैं। मेघालय में कोई महिला हेल्प डेस्क नहीं है।

58 वर्तमान बीपीआरडी डेटा प्रशिक्षण को प्रेरण, मध्य-कैरियर या पदोन्नति प्रशिक्षण, न ही प्रत्येक पर खर्च किए गए समय में विभाजित नहीं करता है।  
 59 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, प्रशिक्षण मास्टर प्लान, 2009। यहाँ उपलब्ध है: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/CMS/File1336.pdf>  
 60 कार्यभार की गणना पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या को प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।  
 61 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020) [https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346\\_2020\\_33\\_1501\\_24909\\_Judgement\\_02-Dec-2020.pdf](https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf)  
 62 पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी)  
 63 कर्नाटक, तेलंगाना, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, गोवा, पश्चिम बंगाल  
 64 राजस्थान, लक्षद्वीप, मणिपुर, पुदुचेरी, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम।  
 65 तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, डीएनएच और डीडी  
 66 विशेष प्रयोजन पुलिस स्टेशन वे हैं जो एससी/एसटी/कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार विरोधी/सतर्कता, तटीय सुरक्षा, अपराध जैसे विशेष अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किए जाते हैं।  
 67 जांच विभाग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, नशीले पदार्थ, नशीली दवाओं की तस्करी, आदि।  
 68 नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, केरल, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा

झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड में भी 50 प्रतिशत से कम पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क हैं। इक्कीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों<sup>68</sup> ने शहरी क्षेत्रों में सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर महिला सहायता डेस्क स्थापित करने की रिपोर्ट दी है; ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17 में है।<sup>69</sup> छब्बीस प्रतिशत विशेष प्रयोजन पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए सहायता डेस्क शामिल है।

इसके अलावा, कई राज्यों ने सभी महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए, कुल 745 महिला पुलिस स्टेशनों में से, तमिलनाडु में 202 सबसे अधिक हैं, जबकि उत्तराखंड में केवल 2 हैं।

राज्यों के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: राज्य-स्तरीय नागरिक पोर्टलों को आसान पहुँच के लिए नौ बुनियादी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करना आवश्यक है (अगले कॉलम में बॉक्स देखें)। पोर्टल के कामकाज में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक इन नौ सेवाओं की दो बार जांच करके प्रत्येक राज्य नागरिक पोर्टल<sup>70</sup> के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया था।

आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>71</sup> ने अनुपालन के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में खराब प्रदर्शन किया, जबकि 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रतिशत में वृद्धि की। पांच राज्यों में नागरिक सेवा पोर्टल निष्क्रिय थे: 2020 में 9 थे।<sup>74</sup> प्रगति डैशबोर्ड स्थिति के विपरीत, किसी भी राज्य ने सभी सेवाएं प्रदान नहीं कीं, जो इंगित करता है कि 97% राज्य ऐसा करते हैं। 91 प्रतिशत के साथ गुजरात और 90 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश अधिकतम अनुपालन दर्शाते हैं जबकि मिजोरम और मणिपुर कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं।<sup>75</sup>

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य अधिकांश सेवाएं प्रदर्शित करते हैं, फिर भी लॉगिन और साइन अप की समस्याओं जैसी तकनीकी त्रुटियों के कारण पहुंच योग्य नहीं हैं। झारखंड के पोर्टल तक कई लॉगिन प्रयासों के बाद ही पहुंचा जा सका।

जबकि मेघालय जैसे कुछ राज्यों ने इस वर्ष अधिक सेवाएँ जोड़कर अपने पोर्टल में सुधार किया है, केरल जैसे अन्य राज्यों ने कुछ सुविधाएँ

## राज्यों के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

1. संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना।
2. शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना।
3. एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करना।
4. गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण।
5. लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से उनका मिलान।
6. चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण।
7. विभिन्न एनओसी जारी/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।
8. नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध।
9. जानकारी साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल।

वैश्विक पर्यटन केंद्र गोवा ने 133 भाषाओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें उनकी राज्य भाषा (कोंकणी) भी शामिल है, जो पिछले साल वहां नहीं थी।

हटा दी हैं। अधिकांश साइटें अंग्रेजी या हिंदी में उपलब्ध थीं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे राज्य भाषा में हों; उदाहरण के लिए, ओडिशा की साइट अंग्रेजी में है, उड़िया में नहीं। केरल ने मलयालम को जोड़ा है। राजस्थान की वेबसाइट एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो अंग्रेजी के लिए विकल्प प्रदान नहीं करती है।

## साइबर अपराध: केरल मॉडल

पिछले 2 वर्षों में पूरे भारत में साइबर अपराध में 6% की वृद्धि हुई है।<sup>76</sup> अपराधों में लोगों से पैसे की धोखाधड़ी (60%) से लेकर पहचान की चोरी, बाल अक्षीलता (child pronography), दुर्भावनापूर्ण प्रणाली के व्यवधान, आतंकवादी संचार, अवैध निगरानी (Illegal surveillance), औद्योगिक जासूसी (Industrial espionage), सोशल मीडिया और शामिल हैं। डार्कनेट और साइबरयुद्ध के बाजारों से उभरते खतरे।

2016 में, साइबर अपराध के लगातार बदलते खतरे<sup>77</sup> ने केरल पुलिस के अनुसंधान और विकास प्रभाग को साइबर अपराध को रोकने, बचाव करने और उसका पता लगाने के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र साइबरडोम<sup>78</sup> स्थापित करने के लिए प्रेरित किया; केरल पुलिस की क्षमताओं और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना; साथ ही प्रौद्योगिकी के गतिशील, चुनौतीपूर्ण वातावरण से निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना; और पुलिस और जनता को इसे पहचानने, रिपोर्ट करने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करें।

पारंपरिक स्व-निहित कानून प्रवर्तन तरीकों से आगे बढ़ते हुए, यह सक्रिय रूप से पुलिस जांच को फोरेंसिक सहायता प्रदान करता है और साइबर खतरों को पहचानने और खत्म करने में मदद

करने के लिए अन्य राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तलाश करता है और बाहरी शैक्षणिक अनुसंधान समूहों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत विशेषज्ञों और एथिकल हैकर्स के योगदान को प्रोत्साहित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केरल पुलिस एक दशक पहले अनसुने अपराधों का जवाब देने के लिए नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित और अद्यतित है। काफी विशिष्ट रूप से, इसका साइबरडोम वालंटियर फ्रेमवर्क दस्तावेज<sup>79</sup> स्पष्ट करता है कि योगदान और सहयोग - यहां तक कि लाभकारी उद्यमों के साथ भी - सख्ती से स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए। सीख और संयुक्त रूप से विकसित नवाचारों को बाद में व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है। इससे पुलिस को विविध विशेषज्ञता और कानून प्रवर्तन सहायकों का एक 'गर्वित' समूह मिला है। साइबर अपराध की सीमा पार प्रकृति की पहचान में साइबरडोम ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के साथ जुड़ाव किया है।

अब 6 साल पुराने, साइबरडोम के मूल्य को कई हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, यह विशेष रूप से आसन्न रैंसमवेयर हमले के बारे में सरकार को चेतावनी देने में सक्षम था<sup>80</sup> और, एक अन्य अवसर पर, राज्य के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन की सुरक्षा भेद्यता में खामियों को उजागर किया। वह प्रणाली जो कर प्रेषण सहित सार्वजनिक धन की पर्याप्त मात्रा को संभालती है।

देविका प्रसाद, स्वतंत्र शोधकर्ता  
देवयानी श्रीवास्तव, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल  
राधिका झा, कॉमन कॉज  
डॉ. रेहाना मंज़ूर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट  
लखविंदर कौर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

68 नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा

69 असम, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा।

70 गृह मंत्रालय की स्मार्ट पुलिसिंग पहल के तहत राज्यों को राज्य नागरिक पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की सलाह दी जाती है: <https://digitalpolice.gov.in/>

71 असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पंजाब, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश

72 हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, गोवा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप

73 मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।

74 अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

75 दोनों राज्यों की वेबसाइट लोड नहीं हो रही है: <https://mnpccitizenportal.gov.in/> और <http://www.cctns.mizoram.gov.in/>

76 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध, 2021

77 केरल पुलिस साइबर अपराध आँकड़े

78 केरल सरकार द्वारा आदेश, दिनांक 22 अगस्त 2014। यहां उपलब्ध है:

<https://keralapolice.gov.in/storage/pages/custom/ckFiles/file/Cp8ecEJSSmrtRBaCjQO47NSOZKO1yc4tvEiFG.pdf>

79 केरल पुलिस, साइबरडोम वालंटियर फ्रेमवर्क। यहां उपलब्ध है: [https://www.cyberdome.kerala.gov.in/assets/policy/cyberdome\\_volunteer\\_framework.pdf](https://www.cyberdome.kerala.gov.in/assets/policy/cyberdome_volunteer_framework.pdf)

80 'केरल पुलिस साइबरडोम वानाक्राई रैंसमवेयर हमले के खिलाफ अलर्ट', इंडियन एक्सप्रेस, 15 मई 2017। यहां उपलब्ध है: <https://Indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/kerala-cyberdome-alerts-again/>

### तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

राज्य	समूह में रैंक			आईजेआर 3 स्कोर (10 में से)	संकेतक सुधार (21 में से)¹	बजट		
	आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2021			प्रति व्यक्ति पुलिस पर खर्च (रुपये, 2020-21)	पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (% 2020-21)	
<b>राष्ट्रीय औसत</b>						1.151	1.26	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>								
आंध्र प्रदेश	5	4	3	6.22		1.133	1.04	
बिहार	14	11	16	4.34		641	1.42	
छत्तीसगढ़	10	2	9	5.70		1,362	1.28	
गुजरात	12	8	8	5.88		761	0.98	
हरियाणा	8	9	12	5.19		1,621	0.86	
झारखंड	9	6	11	5.37		1,432	0.92	
कर्नाटक	6	1	2	6.61		943	1.23	
केरल	13	14	17	4.22		936	0.00³	
मध्य प्रदेश	15	18	7	5.88		816	2.47	
महाराष्ट्र	4	13	10	5.53		1,234	0.94	
ओडिशा	7	3	4	6.22		763	1.20	
पंजाब	3	12	13	5.10		2,055	1.23	
राजस्थान	17	16	14	4.38		813	1.92	
तमिलनाडु	1	5	6	6.04		1,009	1.87	
तेलंगाना	11	10	1	6.92		1,601	2.66	
उत्तर प्रदेश	18	15	15	4.37		857	1.04	
उत्तराखंड	2	7	5	6.11		1,607	0.82	
पश्चिम बंगाल	16	17	18	3.59		909	0.04	
<b>छोटे राज्य</b>								
अरुणाचल प्रदेश	2	4	2	4.84		6,552	5.39	
गोवा	3	7	6	3.89		3,615	0.35	
हिमाचल प्रदेश	6	2	5	3.93		1,641	0.05	
मेघालय	5	3	3	4.52		2,864	0.61	
मिजोरम	7	6	4	4.07		5,193	2.58	
सिक्किम	1	1	1	5.64		6,559	0.96	
त्रिपुरा	4	5	7	3.47		3,416	0.92	
<b>रैंक रहित राज्य</b>								
असम	Not ranked					8	1,169	0.90
मणिपुर	Not ranked					7	5,936	1.63
नागालैंड	Not ranked					7	7,989	1.02
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>								
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Not ranked					10	8,798	1.00
चंडीगढ़	Not ranked					9	4,458	0.40
दमन और दीव	Not ranked					NA	796	NA²
दिल्ली	Not ranked					12	4,041	2.31
जम्मू और कश्मीर	Not ranked					NA	5,427	1.40
लद्दाख	Not ranked					NA	6,437	NA²
लक्षद्वीप	Not ranked					6	9,406	NA²
पुडुचेरी	Not ranked					10	1,501	NA²

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. D&N/D&D, J&K and Ladakh values are not comparable with IJR 2, and so have not been considered. 2. BPR&D shows police training budget as blank. 3. BPR&D shows zero police training budget.

### तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

राज्य	संकेतक	बजट			मानव संसाधन		
		प्रशिक्षण बजट उपयोग (% 2020-21)	प्रति कार्मिक पर प्रशिक्षण खर्च (रुपये, 2020-21)	आधुनिकीकरण निधि का उपयोग (% 2020-21)	कांस्टेबल, रिक्ति (% जनवरी 2022)	अधिकारी, रिक्ति (% जनवरी 2022)	सिविल पुलिस में अधिकारी (% जनवरी 2022)
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	स्कोरिंग गाइड	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा
<b>राष्ट्रीय औसत</b>		84.0	9,043	47	21.6	28.6	16.6
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>							
आंध्र प्रदेश	99.5	6,417	NA⁴	20.0	9.8	11.1	
बिहार	71.8	10,944	NA⁴	30.0	53.8	23.4	
छत्तीसगढ़	53.5	5,179	58	21.2	26.0	12.7	
गुजरात	100.0	5,847	100	26.9	22.1	18.2	
हरियाणा	95.8	6,991	85	32.0	25.3	15.3	
झारखंड	89.2	6,506	NA⁵	23.9	32.8	25.4	
कर्नाटक	90.2	8,031	99	12.0	10.8	17.2	
केरल	NA³	NA³	76	4.6	23.9	9.5	
मध्य प्रदेश	87.9	15,629	NA⁵	13.9	20.8	19.7	
महाराष्ट्र	84.2	7,887	96	28.2	25.3	18.2	
ओडिशा	85.7	7,541	NA⁵	13.3	28.4	21.8	
पंजाब	87.0	9,479	33	12.6	22.4	11.6	
राजस्थान	100.0	13,216	53	8.3	45.6	11.5	
तमिलनाडु	86.0	11,493	NA⁵	10.9	9.1	12.4	
तेलंगाना	91.2	28,126	43	26.1	7.1	17.0	
उत्तर प्रदेश	55.6	5,070	24	26.0	42.5	12.8	
उत्तराखंड	63.9	5,270	93	6.4	7.2	10.3	
पश्चिम बंगाल	61.3	305	42	44.1	25.2	31.5	
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचल प्रदेश	96.4	43,901	100	27.8	34.7	13.6	
गोवा	94.3	2,708	NA⁴	17.2	23.6	17.7	
हिमाचल प्रदेश	89.2	339	90	5.1	16.0	15.0	
मेघालय	96.8	4,546	91	16.9	21.2	15.3	
मिजोरम	89.5	21,594	42	34.2	26.6	27.4	
सिक्किम	85.1	6,885	88	4.6	-4.2	23.1	
त्रिपुरा	99.5	6,785	67	23.7	40.1	15.0	
<b>रैंक रहित राज्य</b>							
असम	71.3	5,167	11	23.0	26.6	16.7	
मणिपुर	79.6	9,608	2	9.5	36.5	15.4	
नागालैंड	100.0	5,672	NA⁵	-2.0	6.0	17.4	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0	9,213	NA⁵	13.7	25.5	10.5	
चंडीगढ़	23.5	796	NA⁵	17.3	12.5	13.2	
दमन और दीव	NA²	NA²	NA⁵	20.1	25.2	11.1	
दिल्ली	100.0	23,989	NA⁵	19.7	2.4	23.0	
जम्मू और कश्मीर	88.9	13,171	25	3.6	28.6	17.3	
लद्दाख	NA²	NA²	NA⁵	29.1	6.6	14.0	
लक्षद्वीप	NA²	NA²	NA⁵	16.3	40.7	6.1	
पुडुचेरी	NA²	NA²	200	24.4	32.9	15.2	

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. Where an indicator value was not available for one or both years, that indicator was not considered. 2. BPR&D shows police training budget as blank. 4. Expenditure data not provided. 5. No modernisation grant received.

### तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	विविधता					
	पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), जनवरी 2022)	अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), जनवरी 2022)	एससी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	एससी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	एसटी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	एसटी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)
राष्ट्रीय औसत	11.8	8.0	NA	NA	NA	NA
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>						
आंध्र प्रदेश	21.8 ●	5.4	84	99	99	87
बिहार	21.2	10.6	51	90	116	278 ●
छत्तीसगढ़	7.1	9.3	94	95	70	109
गुजरात	16.3	10.0	131 ●	109	95	86
हरियाणा	8.2	12.2	63	63 ●	NA <sup>10</sup>	NA <sup>10</sup>
झारखंड	6.2 ●	4.3	71	93	59	70
कर्नाटक	8.6	6.4	116	116 ●	176 ●	169
केरल	7.8	2.4 ●	78	96	81	73
मध्य प्रदेश	7.4	11.5	101	80	64	83
महाराष्ट्र	17.8	7.7	87	81	96	99.7
ओडिशा	10.5	12.9	80	86	64	112
पंजाब	9.9	8.3	82	108	0 ●	0.01 ●
राजस्थान	10.4	6.8	54	87	62	110
तमिलनाडु	19.1	17.9	78	104	87	117
तेलंगाना	8.5	7.5	94	80	139	138
उत्तर प्रदेश	10.7	5.1	43 ●	75	27	53
उत्तराखंड	12.8	18.1 ●	54	98	55	132
पश्चिम बंगाल	9.9	4.0	65	72	52	82
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	10.7	5.7	NA <sup>9</sup>	NA <sup>9</sup>	78	101
गोवा	10.6	15.6	110 ●	43 ●	74	47 ●
हिमाचल प्रदेश	14.0 ●	4.9 ●	72	91	115 ●	127 ●
मेघालय	6.0	8.5	NA <sup>7</sup>	NA <sup>7</sup>	79	89
मिजोरम	7.1	21.4 ●	NA <sup>8</sup>	NA <sup>8</sup>	NA <sup>10</sup>	NA <sup>10</sup>
सिक्किम	9.0	7.5	84	171 ●	83	81
त्रिपुरा	5.3 ●	5.9	64 ●	78	57 ●	75
<b>रैंक रहित राज्य</b>						
असम	6.8	6.5	57	23	55	23
मणिपुर	6.9	6.6	117	114	54	73
नागालैंड	9.9	8.5	NA <sup>8</sup>	NA <sup>8</sup>	67	73
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.7	14.1	NA	NA	76	90
चंडीगढ़	21.6	7.9	48	84	NA <sup>10</sup>	NA <sup>10</sup>
दमन और दीव	8.8	8.5	NA <sup>6</sup>	NA <sup>6</sup>	NA <sup>6</sup>	NA <sup>6</sup>
दिल्ली	12.9	11.0	94	73	106	86
जम्मू और कश्मीर	3.3	1.4	30	43	46	63
लद्दाख	28.3	6.4	NA <sup>9</sup>	NA <sup>9</sup>	214	153
लक्षद्वीप	10.3	0.0	NA <sup>8</sup>	NA <sup>8</sup>	103	182
पुडुचेरी	7.6	4.5	75	68	0	3

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

6. Combined reservation data not available. 7. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 8. BPR&D shows 0% SC reservation. 9. BPR&D shows SC figures as 0. 10. BPR&D shows 0% ST reservation.

### तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	विविधता			बुनियादी ढांचा		
	ओबीसी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	ओबीसी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	थाना जनसंख्या (ग्रामीण) प्रति पुलिस (संख्या, जनवरी 2022)	थाना जनसंख्या प्रति पुलिस (शहरी) (संख्या, जनवरी 2022)	थाना क्षेत्र प्रति पुलिस (ग्रामीण) (वर्ग कि. मी., जनवरी 2022)	
राष्ट्रीय औसत	NA	NA	97,362	94,683	337	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>						
आंध्र प्रदेश	135	167	48,393	96,939	222	
बिहार	58	120	149,020	84,667	125	
छत्तीसगढ़	117	156	64,047	102,513	387	
गुजरात	76	111	80,200	288,788 ●	414	
हरियाणा	77	72	109,113	90,423	264	
झारखंड	122	131	86,855	105,552	233	
कर्नाटक	148	140	70,108	100,510	345	
केरल	104	114	25,010 ●	255,676	82 ●	
मध्य प्रदेश	85	82	129,721	49,517	641	
महाराष्ट्र	98	81	85,159	218,484	392	
ओडिशा	120	200 ●	99,191	46,376 ●	421	
पंजाब	154 ●	149	74,479	89,155	199	
राजस्थान	34 ●	76	120,031	60,450	684 ●	
तमिलनाडु	119	112	42,160	89,659	137	
तेलंगाना	145	128	50,581	50,787	281	
उत्तर प्रदेश	74	129	175,995	106,332	231	
उत्तराखंड	53	84	90,707	58,286	641	
पश्चिम बंगाल	37	55 ●	306,063 ●	123,234	408	
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	NA <sup>11</sup>	NA <sup>11</sup>	21,389	8,733 ●	NA <sup>17</sup>	
गोवा	33	27 ●	18,857 ●	146,375 ●	140 ●	
हिमाचल प्रदेश	29 ●	73 ●	85,474 ●	16,978	710	
मेघालय	NA <sup>13</sup>	NA <sup>13</sup>	61,256	40,235	515	
मिजोरम	NA <sup>11</sup>	NA <sup>11</sup>	21,346	48,000	788 ●	
सिक्किम	88 ●	67	20,111	35,667	392	
त्रिपुरा	NA <sup>11</sup>	NA <sup>11</sup>	57,818	41,184	229	
<b>रैंक रहित राज्य</b>						
असम	65	23	321,677	25,055	830	
मणिपुर	14	26	40,130	60,412	410	
नागालैंड	0.1	1	23,226	51,684	308	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29	30	12,611	58,333	456	
चंडीगढ़	55	93	NA <sup>14</sup>	76,125	NA <sup>14</sup>	
दमन और दीव	NA <sup>6</sup>	NA	233,000	312,333	508	
दिल्ली	24	96	NA <sup>14</sup>	106,938	NA <sup>14</sup>	
जम्मू और कश्मीर	NA <sup>12</sup>	NA <sup>12</sup>	64,048	75,741	NA <sup>16</sup>	
लद्दाख	NA <sup>11</sup>	NA <sup>11</sup>	52,250	45,000	NA <sup>16</sup>	
लक्षद्वीप	NA <sup>11</sup>	NA <sup>11</sup>	111	NA <sup>15</sup>	1	
पुडुचेरी	142	134	30,063	80,500	21	

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

6. Combined reservation data not available. 11. BPR&D shows 0% OBC reservation. 12. OBC reservation data not available. 13. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 14. BPR&D shows 0 rural police stations. 15. BPR&D shows 0 urban police stations. 16. Disaggregated data for rural and urban areas for Jammu & Kashmir and Ladakh not available. 17. Census 2011 does not give rural/urban area break-up.



### तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	बुनियादी ढांचा						कार्यभार
	थाना क्षेत्र (शहरी) प्रति पुलिस (वर्ग कि.मी., जनवरी 2022)	राज्य के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (% 2022)	कार्मिक प्रति प्रशिक्षण संस्थान (संख्या, जनवरी 2022)	नया		प्रति नागरिक पुलिस जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2022)	
				सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन (% जनवरी 2022)	महिला सहायता डेस्क वाले पुलिस स्टेशन (% जनवरी 2022)		
स्कोरिंग गाइड	जितना कम उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	20.2	NA	12,744	74	72.2	835	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>							
आंध्र प्रदेश	21.0	85.6	26,519	58	83.3	661	
बिहार	12.9	21.6	35,718	91	47.0	1,695	
छत्तीसगढ़	41.7	87.6	6,558	97	80.5	756	
गुजरात	62.8	91.0	24,516	83	67.1	991	
हरियाणा	14.4	79.6	20,848	96	61.0	565	
झारखंड	25.2	72.6	13,809	22	42.6	874	
कर्नाटक	20.5	57.3	7,905	99.7	75.8	823	
केरल	74.5	55.0	20,491	95	94.5	776	
मध्य प्रदेश	15.5	89.6	6,962	74	60.4	1,051	
महाराष्ट्र	32.8	87.6	19,414	57	89.0	813	
ओडिशा	18.8	84.6	5,647	91	94.6	1,227	
पंजाब	17.7	79.6	14,222	99	90.7	500	
राजस्थान	18.9	79.6	10,141	0.1	99.5	1,006	
तमिलनाडु	30.0	66.0	5,484	69	34.9	739	
तेलंगाना	10.6	70.7	13,770	99.9	77.1	712	
उत्तर प्रदेश	14.4	85.1	38,382	86	88.8	864	
उत्तराखंड	12.9	77.6	5,601	98	98.8	740	
पश्चिम बंगाल	17.6	41.6	9,887	100	100.0	1,331	
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचल प्रदेश	NA <sup>17</sup>	82.6	15,287	93	100.0	264	
गोवा	95.6	80.6	10,749	100	72.7	274	
हिमाचल प्रदेश	6.0	22.0	19,300	90	92.1	625	
मेघालय	16.6	82.6	5,508	33	0.0	422	
मिजोरम	41.9	0.0	11,301	91	81.8	386	
सिक्किम	4.3	5.0	3,532	43	93.3	233	
त्रिपुरा	10.3	5.0	7,402	89	100.0	448	
<b>रैंक रहित राज्य</b>							
असम	5.8	82.6	16,344	100	60.8	1,306	
मणिपुर	10.6	0.0	35,099	0	66.7	211	
नागालैंड	12.8	82.6	8,903	33	32.6	268	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.6	87.6	5,078	100	95.8	118	
चंडीगढ़	6.8	79.6	7,010	94	94.4	302	
दमन और दीव	31.4	79.6	1,396	100	100.0	1,688	
दिल्ली	5.9	77.6	15,709	88	85.8	299	
जम्मू और कश्मीर	NA <sup>16</sup>	77.6	13,029	20	60.0	280	
लद्दाख	NA <sup>16</sup>	77.6	NA <sup>19</sup>	100	100.0	166	
लक्षद्वीप	NA <sup>15</sup>	87.6	NA <sup>19</sup>	0	56.3	260	
पुडुचेरी	11.0	87.6	4,462	0	60.0	826	

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्गानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

15. BPR&D shows 0 urban police stations. 16. Disaggregated data for rural and urban areas for Jammu & Kashmir and Ladakh not available. 17. Census 2011 does not give rural/urban area break-up. 18. Quantitative assessment of state police citizen portals on 10 counts: whether they include each of the 9 services listed by the Ministry of Home Affairs and whether the portal was available in a state language (other than English). 19. BPR&D shows 0 training institutes.

### तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	रूझान (ट्रेंड्स)					
	कुल पुलिस में महिलाएं (पीपी, सीवाई '17-' 21)	कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (पीपी, सीवाई '17-' 21)	कांस्टेबल रिक्ति (पीपी, सीवाई '17-' 21)	अधिकारी रिक्ति (पीपी, सीवाई '17-' 21)	खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (पीपी, वित्त वर्ष '17-' 21)	स्कोरिंग गाइड
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	0.90	0.49	0.07	0.21	0.75	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>						
आंध्र प्रदेश	3.52	0.35	0.17	0.25	0.40	
बिहार	2.47	1.58	-0.04	3.06	0.87	
छत्तीसगढ़	0.48	1.00	2.49	-1.21	1.71	
गुजरात	1.82	0.90	-0.94	-0.92	1.33	
हरियाणा	-0.19	0.53	1.06	-1.93	2.12	
झारखंड	0.13	0.26	-1.51	-2.34	3.94	
कर्नाटक	0.65	0.48	-1.71	-0.68	-0.54	
केरल	0.29	0.07	1.57	-0.03	-4.20	
मध्य प्रदेश	0.59	1.02	0.75	0.39	-1.26	
महाराष्ट्र	1.24	0.45	4.81	3.42	0.06	
ओडिशा	0.29	0.91	1.22	0.21	-0.76	
पंजाब	0.92	0.81	0.63	2.46	-5.47	
राजस्थान	0.22	0.38	-1.09	3.06	1.46	
तमिलनाडु	1.24	-0.35	3.55	-1.82	-2.84	
तेलंगाना	1.21	1.21	0.27	-1.28	-2.92	
उत्तर प्रदेश	1.39	0.40	-5.40	-4.02	6.01	
उत्तराखंड	1.02	1.83	-0.16	-1.53	-0.02	
पश्चिम बंगाल	0.46	0.18	2.56	-0.17	4.63	
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	0.78	0.08	3.65	3.37	-4.61	
गोवा	-0.05	0.60	2.18	0.59	3.42	
हिमाचल प्रदेश	0.36	0.29	0.37	0.90	1.04	
मेघालय	0.32	0.58	0.27	2.46	-1.85	
मिजोरम	-0.12	0.25	2.75	2.32	-2.82	
सिक्किम	0.43	0.00	0.54	1.39	-1.73	
त्रिपुरा	0.05	-0.03	1.41	3.71	3.51	
<b>रैंक रहित राज्य</b>						
असम	0.26	0.62	0.49	2.04	-3.58	
मणिपुर	-0.25	-0.19	-5.72	2.16	0.50	
नागालैंड	0.72	0.16	2.11	-0.02	0.53	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.07	3.99	-6.18	4.01	
चंडीगढ़	0.71	0.43	0.98	0.58	0.43	
दमन और दीव	-0.90	-1.68	1.20	0.00	7.38	
दिल्ली	0.85	0.23	4.32	-1.23	5.28	
जम्मू और कश्मीर	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	
लद्दाख	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	NA <sup>20</sup>	
लक्षद्वीप	0.48	-0.63	-0.87	-4.97	1.68	
पुडुचेरी	0.08	0.03	3.17	-1.06	2.36	

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्गानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

20. For trend indicators, Jammu & Kashmir and Ladakh are excluded as their data was not available separately for 5 years.

### चित्र 17: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति

आईजेआर राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति पर नज़र रखना जारी रखता है। 2022 में, केवल गुजरात और महाराष्ट्र ने अधिकतम अनुपालन दिखाया जबकि मिजोरम और मणिपुर ने कोई अनुपालन नहीं किया।

राज्य के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (%)	2020 में बदलाव	पोर्टल की उपलब्धता	क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41सी का पालन करना है? (Y/N)				
			1. संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना	2. शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना	3. एफ. आई. आर. की प्रतियाँ प्राप्त करना	4. गिरफ्तार व्यक्तियों/ वांछित अपराधियों का विवरण	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	87.6	↓	✓	✓	✓	✓	✗
आंध्र प्रदेश	85.6	↔	✓	✓	✓	✓	✗
अरुणाचल प्रदेश	82.6	↑	✓	✓	✓	✓	NA
असम	82.6	↓	✓	✓	✓	✓	NA
बिहार	21.6	↓	✗ 1	✗	✗	✗	NA
चंडीगढ़	79.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗
छत्तीसगढ़	87.6	↔	✓	✓	✓	✓	✗
दादरा नगर हवेली	79.6	NA	✓	✓	✓	✓	NA
दिल्ली	77.6	↓	✓	✓	✓	✓	✗
गोवा	80.6	↑	✓	✓	✓	✓	NA
गुजरात	91.0	↑	✓	✓	✓	✓	✗
हरियाणा	79.6	↑	✓	✓	✓	✓	NA
हिमाचल प्रदेश	22.0	↓	✓ 2	✗	✗	✗	NA
जम्मू और कश्मीर	77.6	NA	✓	✓	✓	✓	—
झारखंड	72.6	↔	✓	✓	✓	✓	NA
कर्नाटक	57.3	↔	✓	✓	✓	✓	✗
केरल	55.0	↓	✓	✓	✓	✓	NA
लद्दाख	77.6	NA	✓	✓	✓	✓	NA
लक्षद्वीप	87.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗
मध्य प्रदेश	89.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗
महाराष्ट्र	87.6	↔	✓	✓	✓	✓	✗
मणिपुर	0.0	↓	Not loading				NA
मेघालय	82.6	↑	✓	✓	✓	✓	NA
मिजोरम	0.0	↔	Unable to access portal				NA
नागालैंड	82.6	↔	✓	✓	✓	✓	NA
ओडिशा	84.6	↑	✓	✓	✓	✓	✓
पुडुचेरी	87.6	↔	✓	✓	✓	✓	✗
पंजाब	79.6	↓	✓	✓	✓	✓	—
राजस्थान	79.6	↑	✓	✓	✓	✓	NA
सिक्किम	5.0	↔	Unable to sign up				NA
तमिलनाडु	66.0	↔	✓	✓	✓	✓	✗
तेलंगाना	70.7	↑	✓	✓	✓	✓	✗
त्रिपुरा	5.0	↔	Unable to sign up				NA
उत्तर प्रदेश	85.1	↔	✓	✓	✓	✓	✗
उत्तराखंड	77.6	↑	✓	✓	✓	✓	NA
पश्चिम बंगाल	41.6	↔	Unable to sign up				✗

नोट: 1. बिहार में नागरिक पुलिस पोर्टल नहीं है। 2. हिमाचल प्रदेश पोर्टल में उपलब्ध सेवाएं, लेकिन यह लॉगिन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो रही है। ओडिशा को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आई. पी. सी. की धारा 41सी में उल्लिखित गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रदान नहीं करता है। - धारा 41सी के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब के अनुपालन की जांच करने में असमर्थ। धारा 41सी गिरफ्तारी प्रथाओं की सार्वजनिक निगरानी को प्रोत्साहित करती है, जिसमें कुछ जानकारी सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, सी. आर. पी. सी. की धारा 41सी निम्नलिखित तीन अनिवार्य आवश्यकताओं को निर्धारित करती है: 1) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर और प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी. सी. आर.) स्थापित करना चाहिए; 2) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जिले के बाहर नोटिस बोर्ड पी. सी. आर. प्रदर्शित हों; 3) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते और (बी) गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम; और 3) राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष को नियमित रूप से डेटा एकत्र करना चाहिए।

### चित्र 17: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति

आईजेआर राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति पर नज़र रखना जारी रखता है। 2022 में, केवल गुजरात और महाराष्ट्र ने अधिकतम अनुपालन दिखाया जबकि मिजोरम और मणिपुर ने कोई अनुपालन नहीं किया।

राज्य के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (%)	2020 में बदलाव	पोर्टल की उपलब्धता	क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41सी का पालन करना है? (Y/N)				
			5. लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण और गिरफ्तार, अज्ञात व्यक्तियों और शर्तों के साथ उनका मिलान	6. चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण	7. विभिन्न एन. ओ. सी. जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना	8. सेवकों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध	9. जानकारी साझा करने और नागरिकों को आवश्यक प्रपत्र डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			✓	✓	✓	✓	✓
आंध्र प्रदेश			✓	✓	✓	✓	✓
अरुणाचल प्रदेश			✓	✓	✓	✓	✓
असम			✓	✓	✓	✓	✓
बिहार			✗	✗	✗	✗	✗
चंडीगढ़			✓	✓	✓	✓	✓
छत्तीसगढ़			✓	✓	✓	✓	✓
दादरा नगर हवेली			✓	✓	✓	✓	✓
दिल्ली			✓	✓	✓	✓	✓
गोवा			✓	✓	✓	✓	✓
गुजरात			✓	✓	✓	✓	✓
हरियाणा			✓	✓	✓	✓	✓
हिमाचल प्रदेश			✗	✗	✗	✗	✗
जम्मू और कश्मीर			✓	✓	✓	✓	✓
झारखंड			✓	✓	✓	✓	✓
कर्नाटक			✗	✗	✗	✗	✗
केरल			✓	✓	✓	✓	✓
लद्दाख			✓	✓	✓	✓	✓
लक्षद्वीप			✓	✓	✓	✓	✓
मध्य प्रदेश			✓	✓	✓	✓	✓
महाराष्ट्र			✓	✓	✓	✓	✓
मणिपुर			Not loading				
मेघालय			✓	✓	✓	✓	✓
मिजोरम			Unable to access portal				
नागालैंड			✓	✓	✓	✓	✓
ओडिशा			✓	✓	✓	✓	✓
पुडुचेरी			✓	✓	✓	✓	✓
पंजाब			✓	✓	✓	✓	✓
राजस्थान			✓	✓	✓	✓	✓
सिक्किम			Unable to sign up				
तमिलनाडु			✓	✓	✓	✓	✓
तेलंगाना			✓	✓	✓	✓	✓
त्रिपुरा			Unable to sign up				
उत्तर प्रदेश			✓	✓	✓	✓	✓
उत्तराखंड			✓	✓	✓	✓	✓
पश्चिम बंगाल			✗	✗	✗	✗	✗

नोट: 1. बिहार में नागरिक पुलिस पोर्टल नहीं है। 2. हिमाचल प्रदेश पोर्टल में उपलब्ध सेवाएं, लेकिन यह लॉगिन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो रही है। ओडिशा को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आई. पी. सी. की धारा 41सी में उल्लिखित गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रदान नहीं करता है। - धारा 41सी के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब के अनुपालन की जांच करने में असमर्थ। धारा 41सी गिरफ्तारी प्रथाओं की सार्वजनिक निगरानी को प्रोत्साहित करती है, जिसमें कुछ जानकारी सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, सी. आर. पी. सी. की धारा 41सी निम्नलिखित तीन अनिवार्य आवश्यकताओं को निर्धारित करती है: 1) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर और प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी. सी. आर.) स्थापित करना चाहिए; 2) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जिले के बाहर नोटिस बोर्ड पी. सी. आर. प्रदर्शित हों; 3) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते और (बी) गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम; और 3) राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष को नियमित रूप से डेटा एकत्र करना चाहिए।

# पुलिस स्टेशनों में सी.सी.टी.वी

## समय

3 अप्रैल 2018

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को अपराध स्थल की वीडियोग्राफी के लिए कार्य योजना की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी निकाय बनाने का आदेश दिया।

9 मई 2018

गृह मंत्रालय ने सीओबी का गठन किया है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपराध स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के प्रभावी उपयोग को लागू करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

16 जुलाई 2020

SC ने अपराध स्थल पर पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के सवाल पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

16 सितंबर 2020

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की सटीक स्थिति का पता लगाने और निरीक्षण समितियों के गठन का निर्देश दिया।

2 दिसंबर 2020

परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर (यानी 13 जनवरी 2021 तक) पूर्ण और विस्तृत अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और एक राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (एसएलओसी) के गठन का आदेश दिया। (डीएलओसी)।

24 नवंबर 2020 तक

उच्चतम न्यायालय के शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्देशों के अनुसार 14 राज्यों ने अधूरे अनुपालन हलफनामा और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कीं।



## उच्चतम न्यायालय: "सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने"

देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर आरटीआई अध्ययन के निष्कर्ष

## मुख्य निष्कर्ष

केवल अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सभी स्थापित सीसीटीवी में 18 महीने की भंडारण क्षमता होने की सूचना दी।

→ 7 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>81</sup> ने बताया कि सभी स्थापित सीसीटीवी में ऑडियो और वीडियो क्षमता है

→ 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>82</sup> ने बताया कि सभी स्थापित सीसीटीवी में नाइट विजन सुविधा है

→ 17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश<sup>83</sup> सीसीटीवी के लिए बजट आवंटन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या

→ 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश<sup>84</sup> जिला स्तरीय निगरानी समितियां (डीएलओसी) बनाने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या

→ 23 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश<sup>85</sup> राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलओसी) का गठन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या

पहले के फैसले<sup>86</sup> और 239वें विधि आयोग की सिफारिश<sup>87</sup> पर अमल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह<sup>88</sup> मामले में सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

न्यायालय को चौदह स्थानों पर 12 से 18 महीने की भंडारण क्षमता वाले ऑडियो-विजुअल और नाइट-विजन कैमरे स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिसमें प्रवेश बिंदु, लॉक-अप, गलियारे, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर कमरे के अंदर और सभी पुलिस के पीछे शामिल थे। स्टेशन: सभी न्यायक्षेत्रों को आदेश की तारीख से छह सप्ताह में (यानी 13 जनवरी 2021 तक) स्थिति रिपोर्ट करनी होगी। फैसले में निम्नलिखित की स्थापना जैसे अनुपालन के लिए विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किए गए:

### 1. राज्य स्तरीय निगरानी समिति में शामिल हैं:

- सचिव/अपर सचिव, वित्त विभाग
- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक; और
- राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष/सदस्या

### 2. जिला स्तरीय निगरानी समिति में शामिल हैं:

- जिले के मंडलायुक्त/मंडलायुक्त/क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व आयुक्त मंडल (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)
- जिले का जिला मजिस्ट्रेट
- उस जिले का एक पुलिस अधीक्षक
- जिले के भीतर एक नगर पालिका का मेयर/ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत का एक प्रमुख।

2 दिसंबर 2020 को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह फैसले में उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुलिस स्टेशनों में कैमरों और उनके प्लेसमेंट पर विस्तृत जानकारी मांगी। इसने यह भी पूछा कि क्या निरीक्षण समितियाँ-राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति (एसएलओसी) और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (डीएलओसी) स्थापित की गई थीं।

अप्रैल 2022 में, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रासंगिक जानकारी मांगने के लिए आवेदन दायर किए। पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी की संख्या, प्लेसमेंट और तकनीकी क्षमता और एसएलओसी और डीएलओसी के गठन के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 31 अगस्त 2022 तक कुल 426 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई थीं। मणिपुर को छोड़कर सभी 36 न्यायक्षेत्रों ने जवाब दिया, लेकिन अपूर्णता की अलग-अलग डिग्री के साथ। हरियाणा, ओडिशा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना जैसे राज्यों में आरटीआई को डीजीपी कार्यालय द्वारा विभिन्न जिला पुलिस मुख्यालयों में पी. आई. ओ. को भेज दिया गया था। उदाहरण के तौर पर, हिमाचल प्रदेश में आरटीआई को प्रशासनिक श्रृंखला से नीचे उप-मंडलों और पुलिस स्टेशनों तक भेजा गया था। ऐसे राज्यों की प्रतिक्रियाएँ केवल उन्हीं जिलों, उप-प्रभागों और पुलिस स्टेशनों से मिल खाती हैं जिन्होंने आरटीआई का जवाब दिया था। इसमें देशभर के 58 पुलिस स्टेशनों के जवाबों को शामिल किया गया है। केवल अरुणाचल प्रदेश ने ही राज्य मुख्यालय को सारी जानकारी मुहैया कराई।

81 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा।  
 82 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा।  
 83 तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम, दिल्ली, मिजोरम, असम, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक।  
 84 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, चंडीगढ़, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल।  
 85 कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड।  
 86 शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018)। यहां उपलब्ध है: [https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/6212/6212\\_2017\\_Judgement\\_30-Jan-2018.pdf](https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/6212/6212_2017_Judgement_30-Jan-2018.pdf)  
 87 भारत का 239वां विधि आयोग, 2012. यहां उपलब्ध है: <https://indiankanoon.org/doc/39463074/>  
 88 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020)। [https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346\\_2020\\_33\\_1501\\_24909\\_Judgement\\_02-Dec-2020.pdf](https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf)

### चित्र 18: पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी: एक अनुपालन रिपोर्ट

ग्रिड 2020 में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अनुपालन को दिखाने का प्रयास करता है। यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से आरटीआई प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कई मामलों में जिलों से आरटीआई के जवाब मिले और उन्हें दर्शाया भी गया है।

Yes Information not provided

राज्य स्तरीय निगरानी समिति	जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया	2021-22 के लिए बजट आवंटित	से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 3/3
आंध्र प्रदेश	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; Districts: 26/26
अरुणाचल प्रदेश	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 27/27
असम	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 14/31
बिहार	NP	NP	Yes	DIGP; Districts: 38/38
चंडीगढ़	NR	Yes	NP	SP Chandigarh; 1/1
छत्तीसगढ़	Yes	NP	NP	HQ: 1
दादरा नगर हवेली	NP	NP	Yes <sup>2</sup>	PIO logistics and provisional; Districts: 14/15
दिल्ली	Yes	NP	NP	PIO home dept
गोवा	NP	NP	NP	Sub Divisions: 6/8; Districts: 2/2
गुजरात	NP	NP	NP	Home Dept: 1; Districts:33/33
हरियाणा	NP	NP	NP	HQ: 1; Districts: 22/22
हिमाचल प्रदेश	Yes	Yes	NP	HQ: 1; Districts: 12/12
जम्मू और कश्मीर	Yes	Yes	Yes	HQ: 1; Districts: 19/20
झारखंड	Yes <sup>1</sup>	Yes <sup>1</sup>	NP	Districts: 5/24
कर्नाटक	Yes <sup>1</sup>	Yes <sup>1</sup>	Yes	Home dept: 1; Districts: 31/31
केरल	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 14/14
लद्दाख	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 2/2
लक्षद्वीप	NP	NP	NP	0
मध्य प्रदेश	Yes	Yes	Yes	PHQ: 1; Districts: 50/50
महाराष्ट्र	Yes	Yes	Yes	HQ: 1; Districts: 35/35
मणिपुर	NP	NP	NP	0
मेघालय	NP	NP	NP	Addl.DGP: 1; Home dept: 1; Districts: 1/12
मिजोरम	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 11/11
नागालैंड	NP	NP	NP	DGP Police: 1; Districts: 12/16
ओडिशा	NP	NP	NP	DSP: 1; Districts: 30/30
पुडुचेरी	Yes	NP	Yes	PHQ: 1
पंजाब	NP	NP	NP	0
राजस्थान	Yes	Yes	Yes	Police SCRB: 2; Asst commissioner Jaipur: 1; Districts: 1/33
सिक्किम	NP	NP	Yes	PHQ-1; Secretariat finance dept: 1; Districts:6/6
तमिलनाडु	Yes	Yes	Yes	Police HQ planning: 1; Districts: 38/38
तेलंगाना	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; Districts: 24/33
त्रिपुरा	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; District Magistrate: 1; Districts: 8/8
उत्तर प्रदेश	Yes	NP	NP	Home dept: 1; Districts: 75/75
उत्तराखंड	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; DGP office: 1; Districts: 13/13
पश्चिम बंगाल	Yes <sup>1</sup>	Yes <sup>1</sup>	NP	Police directorate: 1; Asst. IGP: 1; Districts: 23/23

संक्षेप एन. पी.: प्रदान नहीं किया गया है। एनआर: आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी: 1. जानकारी आर. टी. आई. से नहीं, बल्कि आई. जे. आर. दल द्वारा प्राप्त अनुपालन शपथ पत्रों से ली गई है। 2. 9. 68 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 3. प्रक्रिया में है। 4. पूर्वी खासी पहाड़ियों में। 5. जिलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार (21.1.2021 पर 2,959)। 6. यह सुनिश्चित किया जाएगा।

### चित्र 18: पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी: एक अनुपालन रिपोर्ट

ग्रिड 2020 में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अनुपालन को दिखाने का प्रयास करता है। यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से आरटीआई प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कई मामलों में जिलों से आरटीआई के जवाब मिले और उन्हें दर्शाया भी गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	आर. टी. आई. जवाबों के अनुसार सीसीटीवी जानकारी				डीओपीओ 2022 डेटा		
	कुल सीसीटीवी कैमरे	ऑडियो और वीडियो के साथ सीसीटीवी कैमरे	नाइट विजन के साथ सीसीटीवी कैमरे	कैमरों की संख्या के अनुसार भंडारण क्षमता	कम से कम एक सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन	कुल पुलिस स्टेशन	कम से कम एक सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	527	527	527	527: 18 months	24	24	24
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP	1,027	599
अरुणाचल प्रदेश	1,485	1,485	1,485	1,485: 18 months	99	107	99
असम	299	63	112	103: below 12 months	125	329	329
बिहार	11,081	NP	NP	NP	952	1,056	957
चंडीगढ़	510 <sup>1</sup>	115 (video only)	0	66: 40-45 days; 16: 15-20, 33: about 30 days	17	18	17
छत्तीसगढ़	1,772	NP <sup>3</sup>	NP <sup>3</sup>	NP <sup>3</sup>	443	456	443
दादरा नगर हवेली	1,941	NP	1,941	1,941: 12 months	197	225	197
दिल्ली	18	NA <sup>6</sup>	NA <sup>6</sup>	DNH: 25 days; Daman: 30 days; Diu: Nil	7	8	8
गोवा	259	259	259	236: 18 months; 23: below 12 months	17	44	44
गुजरात	7,354	NP	NP	NP	NP	745	622
हरियाणा	NP <sup>3</sup>	NP	NP	NP	NP	397	381
हिमाचल प्रदेश	1,530	711	838	525: 18 months; 298: 12 months; 223: below 12 months	NP	151	136
जम्मू और कश्मीर	306	NP	55	112: below 12 months	112	250	51
झारखंड	169	4 (video only), 8 (audio only)	69	8: 12 months; 62: below 12 months	113	564	126
कर्नाटक	4,176 <sup>1</sup>	4,176 <sup>1</sup>	4,176 <sup>1</sup>	4,176: one year <sup>1</sup>	1049*	1,055	1,052
केरल	1,936	1,936 (video only)	1,936	15-20 days to 45 days	523	564	538
लद्दाख	56	56	56	56: 12-18 months	7	7	7
लक्षद्वीप	NP	NP	NP	NP	NP	16	0
मध्य प्रदेश	3,436	3,436	3,436	3,436: below 12 months	NP	1,159	859
महाराष्ट्र	6,363	NP	NP	NP	1113	1,168	663
मणिपुर	0	NP	NP	NP	NP	84	0
मेघालय	44 <sup>4</sup>	6	27	27: 12 months; 4: below 12 months; 6: 1 month	14	76	25
मिजोरम	465	430	430	430: 12 months; 35: below 12 months	40	44	40
नागालैंड	70	36 (video only)	58	41: below 12 months; 1: 2 months	66 replied, 43 have CCTVs	86	28
ओडिशा	NP	NP	NP	NP	NP	643	584
पुडुचेरी	0	NP	NP	NP	0	55	0
पंजाब	NP	NP	NP	NP	NP	431	425
राजस्थान	33	NP	NP	NP	NP	917	1
सिक्किम	317	23	325	145: 18 months; 75: 12 months; 41: below 12 months; 64: NP	29	30	13
तमिलनाडु	8,748	All cameras in 1,327 PS	All cameras in 1,578 PS	1,578 PS: below 12 months	1,578	2,292	1,578
तेलंगाना	3,849 <sup>5</sup>	NP	NP	NP	567	843	842
त्रिपुरा	308	308	308	308: above 1 month	72	82	73
उत्तर प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP	1,783	1,533
उत्तराखंड	960	632	632	632: 12 months	160	162	159
पश्चिम बंगाल	2,623	NP	No night vision	12 months	NP	637	637

संक्षेप एन. पी.: प्रदान नहीं किया गया है। एनआर: आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी: 1. जानकारी आर. टी. आई. से नहीं, बल्कि आई. जे. आर. दल द्वारा प्राप्त अनुपालन शपथ पत्रों से ली गई है। 2. 9. 68 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 3. प्रक्रिया में है। 4. पूर्वी खासी पहाड़ियों में। 5. जिलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार (21.1.2021 पर 2,959)। 6. यह सुनिश्चित किया जाएगा।



जेल

# जेलों की रैंकिंग

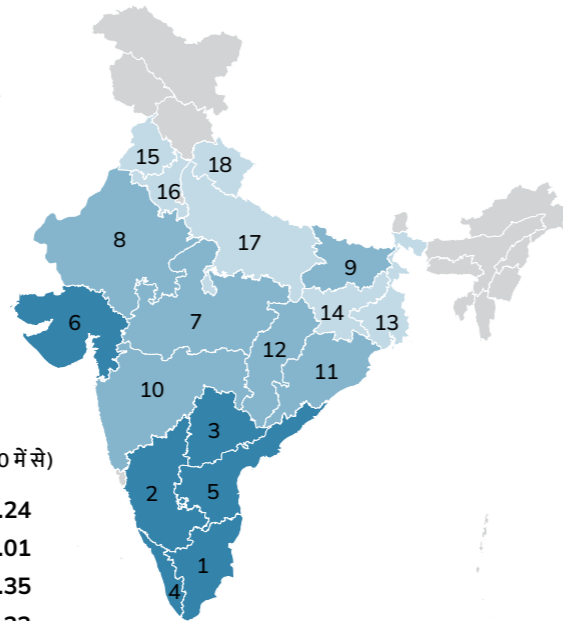
रंग गाइड

- श्रेष्ठ
- मध्य
- खराब

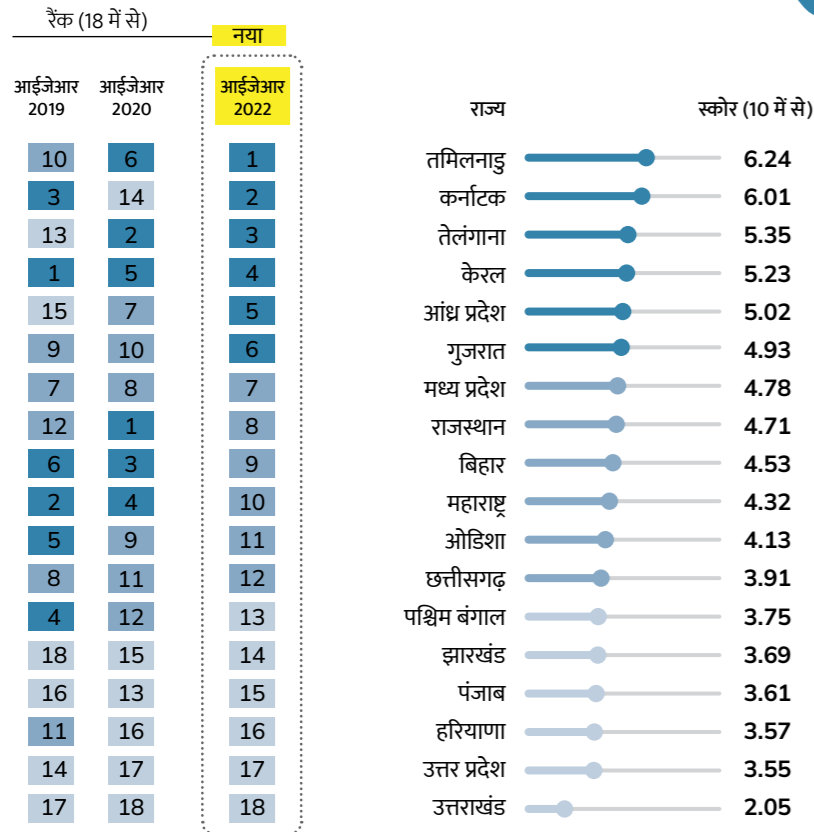
संकेतक (IJR 3) **29**

समूह (क्लस्टर)

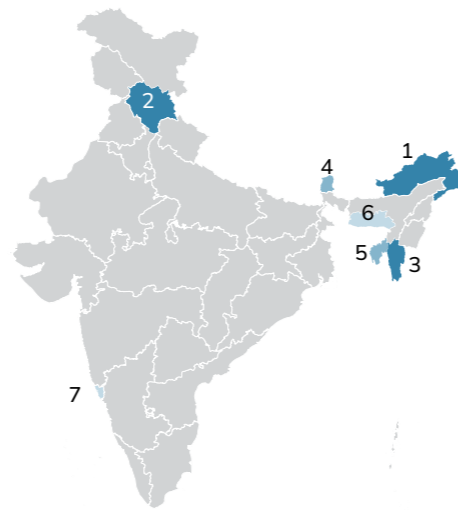
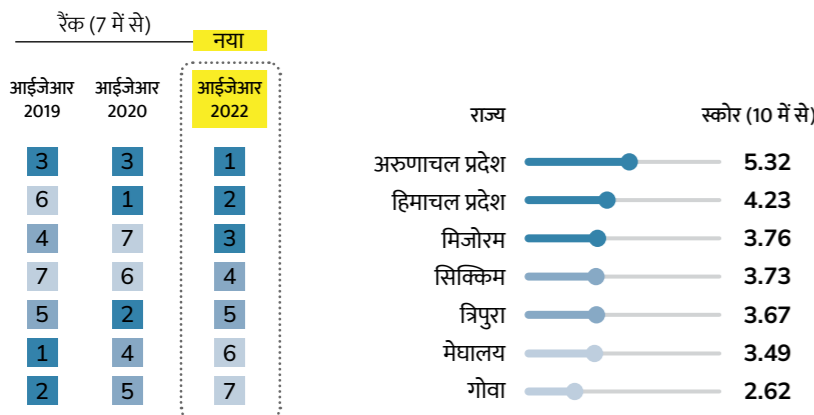
- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- 7 छोटे आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ तक)



## मानचित्र 11: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

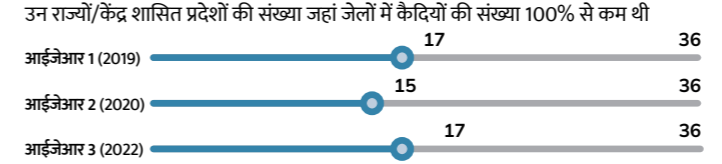


## मानचित्र 12: छोटे राज्य

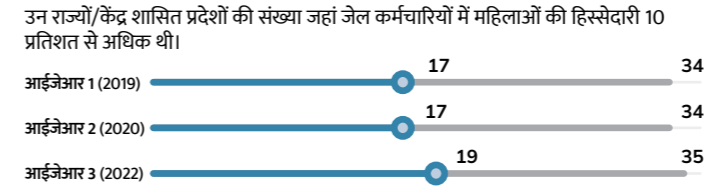


# उम्मीदें बढ़ाना

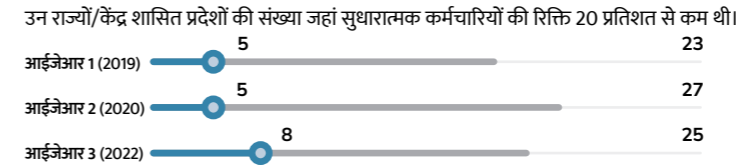
## भीड़भाड़



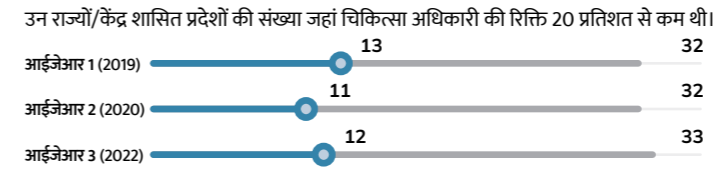
## महिला कर्मचारी



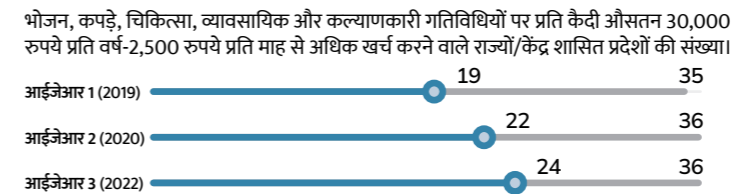
## सुधारक कर्मचारी



## चिकित्सा अधिकारी



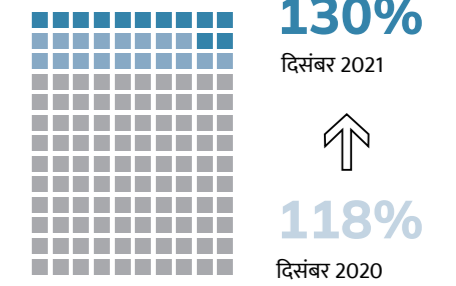
## कैदियों पर खर्च



\* Number of states/UTs (out of 36) for which data was available.

## बुनियादी ढांचा

### राष्ट्रीय जेल अधिवास



उत्तराखंड की जेलों में 3,741 कैदियों की क्षमता है। दिसंबर 2021 तक, 6,921 कैदी थे, और, 185% अधिवास।

भारत में जेलों में **54%** भीड़भाड़ है।

## चिकित्सा अधिकारी

उत्तराखंड, 11 जेलों में 6,921 कैदियों के साथ, **10 स्वीकृत पदों के खिलाफ केवल 1 डॉक्टर दर्ज करता है।**



**11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सुधारात्मक कर्मचारियों के लिए किसी भी पद को मंजूरी नहीं दी है।**

## जेलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग

राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाली जेलों की हिस्सेदारी **दिसंबर 2019 में 60 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2021 में 84 प्रतिशत हो गई है।**



अध्याय 2

# जेल: निराशाजनक परिस्थितियों से उबारने की सीमा तक

## परिचय

2021 में, दुनिया भर में 11.5 मिलियन (1.15 करोड़) से अधिक लोगों के जेलों में होने का अनुमान है - जो अब तक की सबसे अधिक और 2000 के बाद से 24 प्रतिशत की वृद्धि है।<sup>1</sup> भारत इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2010 और 2021 के बीच, भारत में जेलों की आबादी लगभग दोगुनी हो गई, 3.7 लाख से 5.5 लाख हो गई। 2021 में राष्ट्रीय अधिभोग दर 130 प्रतिशत तक पहुंच गई - एक साल पहले की तुलना में 12 प्रतिशत अंक की वृद्धि।<sup>2</sup>

विभिन्न मानकों के आधार पर जेल प्रशासन की क्षमता का आकलन करते हुए, आईजेआर 5 नए पैरामीटर जोड़ता है और रैंकिंग में काफी सुधार पाता है। अत्यधिक भीड़भाड़, स्थिर या बढ़ती रिक्तियों और बिगड़ते बजट उपयोग के गंभीर स्तर ने रैंकिंग में गिरावट में योगदान दिया है।

तमिलनाडु पहले स्थान पर है, 2019 में दसवें स्थान से बारिशत और 2020 में छठे स्थान पर पहुंची। कर्नाटक सबसे उच्च उछाल दर्ज करता है, चौदहवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर 5 सूचकांकों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। राजस्थान, जो 2020 में पहले स्थान पर था, आठ स्थानों तक गिर गया, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीचे के तीन स्थानों में बने रहे। महाराष्ट्र भी चौथे से दसवें स्थान पर गिर गया बजट उपयोग में गिरावट और रिक्ति के स्तर में वृद्धि के कारण।

सात छोटे राज्यों में, गोवा ने अपनी गिरावट जारी रखी, 2019 में पहले स्थान से, 2020 में चौथे स्थान से, अब सातवें स्थान पर पहुंची। हालांकि, मिजोरम ने सातवें से तीसरे और अरुणाचल प्रदेश ने पहले स्थान से तीसरे स्थान पर बदलाव किया है 2019 और 2020 में।

## आधारभूत संरचना

जेल अधिभोग (%), दिसंबर 2021)	
100% और अधिक क्षमता वाली जेलों का हिस्सा (%), 2022)	नया
150% और अधिक क्षमता वाली जेलों का हिस्सा (%), 2022)	नया
1-3 साल के लिए हिरासत में लिए गए विचाराधीन कैदी (%), दिसंबर 2021)	नया
वी-सी सुविधा वाली जेलें (%), दिसंबर 2021)	
शैक्षिक सुविधाओं से लाभान्वित कैदी (%), दिसंबर 2021)	नया
कैदियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया (%), दिसंबर 2021)	नया
विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (पीपी, CY '17-'21)	

**अधिग्रहण (ऑक्यूपेंसी):** पूरे देश में, अधिक भरपूरी एक सामान्य और स्थायी स्थिति है। कारागार स्टैटिस्टिक्स इंडिया के नवीनतम डेटा (2021 के 31 दिसंबर के रूप में) के अनुसार, राष्ट्रीय औसत ऑक्यूपेंसी दर को 130 प्रतिशत पर प्रिकट किया गया है। इस वृद्धि का समर्थन करता है, जो पूर्व वर्षों के विरुद्ध है, जिसमें ऑक्यूपेंसी कम हो गई, भले ही थोड़ी सी, 2019 में 120 प्रतिशत से 2020 में 118 प्रतिशत तक। ऑक्यूपेंसी के बढ़ते स्तर कारागार आबादी में वृद्धि के परिणामस्वरूप आते हैं। कारागार जनसंख्या 2019 में 4.81 लाख से 2020 में 4.89 लाख तक और 2021 में 5.54 लाख तक स्थिर रूप से बढ़ी है: जबकि 2021 में 1,319 कारागार में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या 10.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ 18.1 लाख से बढ़कर 16.3 लाख से बढ़ गई थी।

सोलह राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी कुल क्षमता<sup>7</sup> से अधिक कैदी हैं। 7 पिछले वर्ष की तुलना में पंद्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि दर्ज की गई है<sup>8</sup>, जिसमें बिहार में 2020 में 113 प्रतिशत से 2021 में 140 प्रतिशत तक की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखंड में 185 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उच्चतम औसत अधिभोग दर.

यहां तक कि कोविड अवधि (2020-2021) की विकृतियों को ध्यान में रखते हुए, 2017 से 2021 तक के 5 साल के आंकड़े राज्यों में भीड़भाड़ की लगातार बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। अस्थायी जमानत या आपातकालीन पैरोल पर कैदियों की रिहाई के बावजूद, जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि के लिए दो कारक जिम्मेदार हो सकते हैं - गिरफ्तारियों में वृद्धि और अदालतों का काम न करना (तत्काल जमानत सुनवाई को छोड़कर)।

**जेलों में भीड़भाड़:** संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के ड्रग्स और अपराध (यूएनओडीसी) की 'गंभीर' और 'अत्यधिक' भीड़भाड़ की परिभाषा के खिलाफ जांच की गई, यह रिपोर्ट डेटा के माध्यम से प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 150 प्रतिशत से अधिक अधिभोग दर वाली जेलों की हिस्सेदारी का आकलन करती है। जुलाई से अक्टूबर 2022 की तीन महीने की अवधि में ई-प्रिजन पोर्टल पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्तर पर, लगभग 30 प्रतिशत (391 जेलें) 150 प्रतिशत और उससे अधिक की अधिभोग दर दर्ज करती हैं, और 54 प्रतिशत (709 जेलें) 100 प्रतिशत क्षमता से ऊपर चलती हैं।<sup>15</sup> 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की आधे से अधिक जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं।<sup>16</sup> उदाहरण के तौर पर, 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से, हरियाणा में भीड़भाड़ वाली जेलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसकी 20 में से अठारह जेलें 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चलती हैं: बारह या 60 प्रतिशत में 150 प्रतिशत से अधिक की अधिभोग दर दर्ज की गई है। तमिलनाडु में, कुल 139 जेलों में से 15 जेलों में 100 प्रतिशत से अधिक भीड़भाड़ है और 2 में 150 प्रतिशत से अधिक भीड़ है।

## महामारी और कारागार

मार्च 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों के कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश करने के लिए विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ<sup>4</sup> गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने जेलों में भीड़ कम करने के उपाय करने के लिए अंडर ट्रायल समीक्षा समितियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और आदेश पारित किए। अप्रैल और जून 2020 के बीच के चार महीनों में, 20 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में जेलों में कैदियों की कुल संख्या घटकर 93.3%<sup>5</sup> हो गई। सबसे बड़ी कटौती पंजाब में हुई, जिससे इसकी औसत कैदियों की संख्या 91.5% से घटकर 74% हो गई, और महाराष्ट्र में जहां ऑक्यूपेंसी 150% से घटकर 118% हो गई।<sup>6</sup>

## दीर्घकालिक भीड़ (क्रोनिक ओवर क्रौडिंग)

संयुक्त राष्ट्र औषधियों और अपराध कार्य कार्यालय 120% भरपूरी को 'महत्वपूर्ण' और 150% को 'अत्यंत'<sup>9</sup> वर्ग में श्रेणीबद्ध करता है। 2021 के अंत में, 13<sup>10</sup> राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में औसत ऑक्यूपेंसी दरें महत्वपूर्ण थीं।<sup>11</sup> 6<sup>11</sup> में यह 150%<sup>12</sup> से ज्यादा हो गई थी। औसत, हालांकि, यह छिपाने में मदद करती है कि कई कारागारों में भरपूरी 150% से ज्यादा है। 22 प्रिजनों में ऑक्यूपेंसी दरें 500%<sup>13</sup> से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। व्यक्तिगत कारागार अधिक भयानक कारागार स्थितियों को प्रकट करते हैं: छत्तीसगढ़ के डांटेवाड़ा में जिला कारागार की औसत ऑक्यूपेंसी 4,963% है—उसकी क्षमता की तुलना में लगभग 50 गुना ज्यादा। उसी तरह, असम के नालबाड़ी जिला कारागार में औसत आवासी क्षमता के खिलाफ 4,500 कारागारियों को बनाया जाता है, जो कि 155<sup>14</sup> की उपलब्ध क्षमता के खिलाफ है।

1 पेनल रिफॉर्म इंटरनेशनल के वैश्विक जेल रुझान, 2022। यहां उपलब्ध है: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

2 दो प्रतिशत के बीच का अंतर जो वृद्धि या कमी को उजागर करता है।

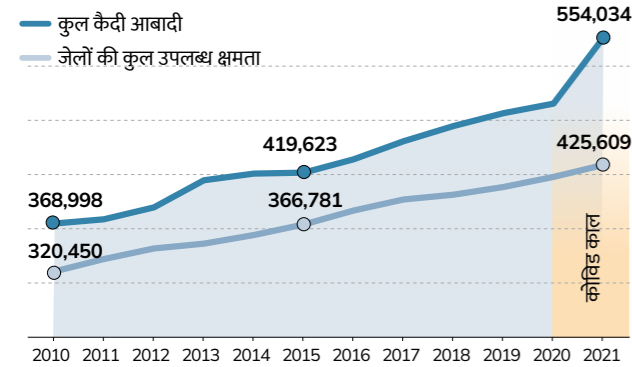
3 जेल और जेल शब्द दो अलग-अलग अवधारणाएँ बनाते हैं। अमेरिका में, जेल और जेल के बीच मूलभूत अंतर रहने की अवधि के संदर्भ में है, जहां जेल एक अल्पकालिक सुविधा है और जेलें लम्बी सजाओं के लिए होती हैं। IJR जेल और जेल शब्द का परस्पर उपयोग करता है।

4 पुनर्जेलों में COVID 19 वायरस का संक्रमण (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 1/2020) दिनांक 23 मार्च 2020 के आदेश द्वारा।  
 5 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की महामारी पर प्रतिक्रिया: जेलें और भीड़भाड़, 2020; राज्यों के भीड़भाड़ कम करने के प्रयास। उपलब्ध है: <https://humanrightsinitiative.org/download/Responding%20to%20the%20Pandemic%20Prisons%20&%20Overcrowding%20Vol%201.pdf>  
 6 Ibid  
 7 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।  
 8 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।  
 9 ई/सीएन.15/2016/10, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग का पच्चीसवां सत्र, 2016। यहां उपलब्ध है: [https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/25\\_Session\\_2016/session-25-of-the-ccpcj.html](https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/25_Session_2016/session-25-of-the-ccpcj.html)  
 10 बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।  
 11 दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।  
 12 जेल सांख्यिकी भारत, 2021  
 13 रिपोर्ट में तीन महीने की अवधि (जुलाई-अक्टूबर 2022) में ई-प्रिजन पोर्टल पर दर्ज 1,314 जेलों में जेल की क्षमता और आबादी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। यहां उपलब्ध है: <https://eprisons.nic.in/public/ePrisonsLiveStatus>  
 14 Ibid  
 15 भीड़भाड़ वाली जेलों के संकेतकों के लिए, रिपोर्ट ने ई-प्रिजन पोर्टल पर दर्ज कुल 1,314 जेलों का विश्लेषण किया। पोर्टल में 1,367 जेलों की सूची है, जिनमें से 53 जेलों को कुल संख्या में नहीं माना गया, क्योंकि वे कार्यात्मक नहीं हैं या संबंधित जेल विभागों के पास जेलों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, या राजस्व विभाग के अंतर्गत आती हैं।  
 16 अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डीएनएच और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

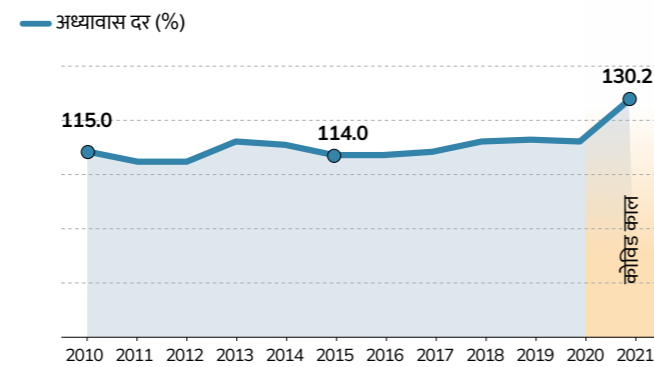
### चित्र 19: भारतीय जेलों में अधिभोग दर

निम्नलिखित ग्राफ राज्यों में बढ़ती जेल आबादी और दशक के दौरान अनिवार्य रूप से बढ़ती राष्ट्रीय अधिभोग दर को दर्शाता है।

19 ए. भारत: जेलों की क्षमता और जनसंख्या



19 बी. राष्ट्रीय जेल अधिभोग

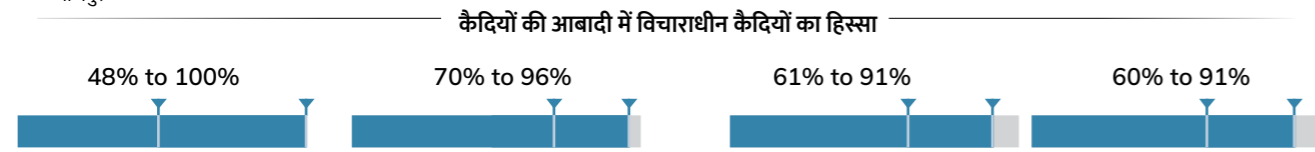


### 19 सी. दिसंबर 2021 तक जेल अधिभोग और विचाराधीन कैदी

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) 120% भीड़भाड़ को 'गंभीर' और 150% को 'अत्यधिक' के रूप में वर्गीकृत करता है। यह तालिका देश की जेलों में कैदियों की संख्या को दर्शाती है। नीचे दी गई पट्टियाँ विभिन्न राज्यों में अधिभोग की विभिन्न श्रेणियों में विचाराधीन कैदियों की उच्च हिस्सेदारी को दर्शाती हैं।



श्रेणी	अधिभोग दर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सीमा के भीतर	100% तक अधिभोग	17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, गोवा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, लद्दाख, तेलंगाना, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मणिपुर
उच्च	100% से 120% अधिभोग	7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र असम, दमन और दीव व दादरा और नगरहवेली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
बहुत अधिक	120% से 150% अधिभोग	6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र
गंभीर	150% से 185% अधिभोग	6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

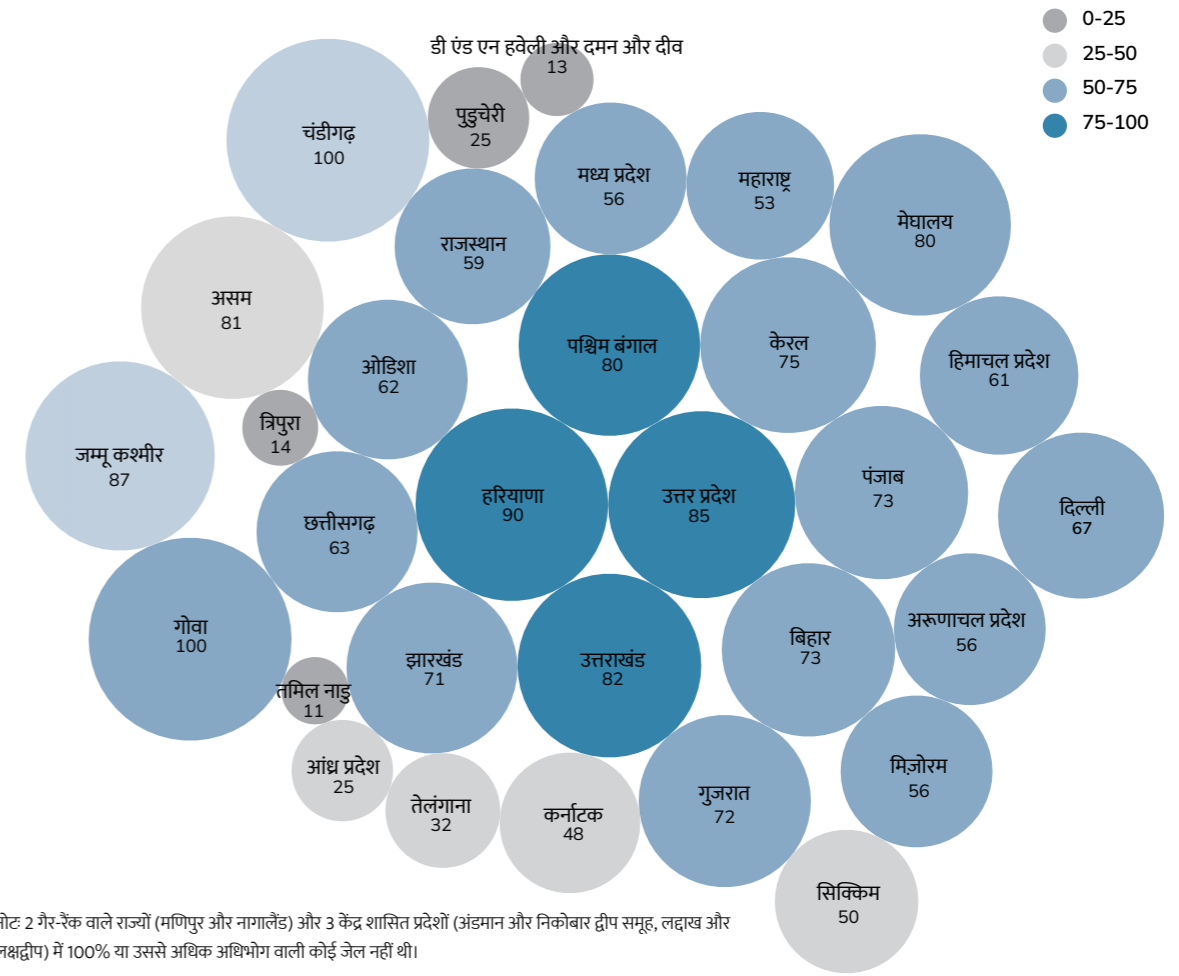


नोट: श्रेणी के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।  
स्रोत: कारागार सांख्यिकी (पी.एस.आई.)

### चित्र 20: जेलों में अत्यधिक भीड़

देश की आधी से ज्यादा जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं। नीचे दिया गया आंकड़ा राज्यों में भीड़भाड़ वाली जेलों का प्रतिशत

20 ए. 100% या अधिक क्षमता वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जेलों का हिस्सा (%), (2022)



नोट: 2 गैर-रैंक वाले राज्यों (मणिपुर और नागालैंड) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप) में 100% या उससे अधिक अधिभोग वाली कोई जेल नहीं थी।

### 20 बी. 2022 में 150% से अधिक क्षमता वाली जेलों की संख्या

भारत की 1,314 जेलों में से, 2022 में 391 जेलों में कैदियों की संख्या 150% से अधिक थी। 13 राज्य जहां ये संख्या दोहरे अंक में थी. नीचे दिया गया ग्राफ राज्यों में जेलों की कुल संख्या के मुकाबले 150% से अधिक क्षमता वाली जेलों की संख्या दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश	57/74
मध्य प्रदेश	40/131
पश्चिम बंगाल	36/60
राजस्थान	27/143
बिहार	24/59
केरल	24/56
असम	23/31
महाराष्ट्र	22/60
ओडिशा	20/87
छत्तीसगढ़	15/32
आंध्र प्रदेश	14/87
कर्नाटक	13/60
हरियाणा	12/20



स्रोत: ई-जेल पोर्टल



## दुनिया भर में विचाराधीन कैदी

वैश्विक स्तर पर, जेल में बंद तीन में से लगभग एक व्यक्ति को परीक्षण-पूर्व हिरासत<sup>17</sup> में रखा जा रहा है। 2000 के बाद से, एशिया और अफ्रीका में परीक्षण-पूर्व हिरासत में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। 17 भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील<sup>18</sup> के बाद चौथे स्थान पर है। 18 अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में, केवल बांग्लादेश, जहां 80% कैदी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, से अधिक हैं। भारत के बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या पाकिस्तान (70%), श्रीलंका (60%) और नेपाल (54%) है। ब्रिक्स साझेदारों-दक्षिण अफ्रीका (32.9%), ब्राजील (27.2%), रूस (24.6%) और चीन (12.7%) में भी भारत का प्रतिशत सबसे अधिक है।<sup>19</sup>

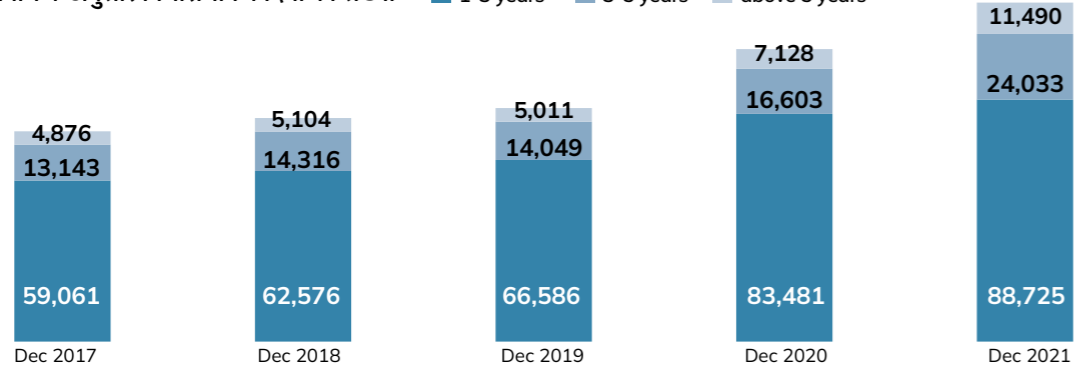
छोटे राज्यों में, मेघालय की 5 जेलों में से 4 में क्षमता से अधिक कैदी हैं, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, जहां 23 में से 14 जेलें 100 प्रतिशत क्षमता से अधिक चल रही हैं। गोवा की एकल जेल भी क्षमता से 33 प्रतिशत अधिक थी।

यहां तक कि कोविड अवधि (2020-2021) की विकृतियों को ध्यान में रखते हुए, 2017 से 2021 तक के 5 साल के आंकड़े राज्यों में भीड़भाड़ की लगातार बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। अस्थायी जमानत या आपातकालीन पैरोल पर कैदियों की रिहाई के बावजूद, जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि के लिए दो कारक जिम्मेदार हो सकते हैं - गिरफ्तारियों में वृद्धि और अदालतों का काम न करना (तत्काल जमानत सुनवाई को छोड़कर)।

## चित्र 21: हिरासत अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदी दर्शाता है।

पिछले कुछ वर्षों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 में, विचाराधीन कैदी पूरी जेल की आबादी का 77% थे। नीचे दिया गया आंकड़ा विचाराधीन कैदियों द्वारा पांच वर्षों में जेलों में बिताई गई विभिन्न अवधियों को दर्शाता है।

निरोध अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदियों की संख्या



स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

17 पेनल रिफॉर्म इंटरनेशनल के वैश्विक जेल रूडमैप, 2022. यहां उपलब्ध है: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

18 दुनिया भर की जेल प्रणालियों पर वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ का डेटाबेस। यहां उपलब्ध है: [https://www.prisonestudies.org/highest-to-lowest/pre-trial-detainees?field\\_region\\_taxonomy\\_tid=16](https://www.prisonestudies.org/highest-to-lowest/pre-trial-detainees?field_region_taxonomy_tid=16)

19 Ibid

20 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, राजस्थान और सिक्किम।

**विचाराधीन कैदियों की आबादी:** जेल की आबादी में से केवल 22 प्रतिशत ही दोषी हैं जबकि 77 प्रतिशत 'विचाराधीन कैदी' या जांच या मुकदमे के पूरा होने का इंतजार कर रहे लोग हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या 2010 के बाद से सबसे अधिक है, जो 2010 में 2.4 लाख से लगभग दोगुनी होकर 2021 में 4.3 लाख हो गई है: 78 प्रतिशत की वृद्धि। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की आबादी 60 प्रतिशत से अधिक है।

2017 और 2021 के बीच, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और पुद्दुचेरी में विचाराधीन कैदियों की आबादी में वृद्धि देखी गई। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से, पंजाब में 3.75 प्रतिशत अंक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सात छोटे राज्यों में, गोवा में 5.23 प्रतिशत अंक की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।

**हिरासत की अवधि:** विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखना इस बात का संकेत है कि मुकदमे पूरे होने में अधिक समय लग रहा है। इससे प्रशासनिक कार्यभार बढ़ता है, अल्प बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और प्रति कैदी खर्च पर असर पड़ता है। आईजेआर का नया संकेतक 1 से 3 साल के बीच हिरासत में लिए गए विचाराधीन कैदियों की अवधि को रिकॉर्ड करता है।

पीएसआई, 2021 से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, 88,725 (20.8 प्रतिशत) विचाराधीन कैदियों ने 1 से 3 साल जेल में बिताए।<sup>20</sup> दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 25 प्रतिशत से अधिक को 1 से 3 साल के लिए हिरासत में रखा गया था। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, 28 प्रतिशत के साथ राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी जबकि

छोटे राज्यों में, 47 प्रतिशत के साथ गोवा की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। पूर्ण संख्या के अनुसार, उत्तर प्रदेश (21,244 कैदी) में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, इसके बाद बिहार (8,365), महाराष्ट्र (7,599) और मध्य प्रदेश (6,778) हैं।

2021 के अंत में, देश भर में बड़ी संख्या में (11,490) कैदी 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे, जो 2020 में 7,128 और 2019 में 5,011 से काफी अधिक है। हालांकि, वर्ष के दौरान रिहा किए गए कुल विचाराधीन कैदियों में से 96.7 प्रति सेंट ने एक वर्ष के भीतर या तो जमानत पर या बरी/मुक्ति पर जेल छोड़ दी, या मुकदमा पूरा होने पर दोषी में परिवर्तित हो गया।<sup>21</sup>

**वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग:** वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग: रिमांड और सुनवाई के दौरान कैदियों को अदालत से आगे-पीछे लाने-ले जाने में होने वाली लागत और मानव संसाधनों को कम करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में अपनाया गया। इसके प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप देशी में कमी आई है, विशेषकर रिमांड चरण में, जहां अन्यथा अदालतें मुकदमा शुरू होने के बाद भौतिक उत्पादन को प्राथमिकता देती हैं। इस सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके की गई सुनवाई की संख्या, या उत्पादन लागत में बचत पर बहुत कम डेटा है। महामारी की शुरुआत से ठीक पहले, 2019 में, केवल 60 प्रतिशत जेलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी। 2019 और 2021 के बीच, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं 808 जेलों से बढ़कर 1,102 या 84 प्रतिशत हो गईं।<sup>22</sup> 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत कवरेज दर्ज किया,<sup>23</sup> लेकिन केवल 4 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आधे से भी कम कवर कर सके।<sup>24</sup> लक्षद्वीप की 4 जेलों में से कोई भी इस सुविधा से सुसज्जित नहीं है। पंजाब, झारखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग कवरेज में गिरावट दर्ज की गई।<sup>25</sup>

**कैदियों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाएँ:** 2011 में, कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयास में, गृह मंत्रालय ने राज्यों को जेलों में विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा बोर्ड और द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)।<sup>26</sup> मॉडल जेल मैनुअल, 2016 अनपढ़ युवा अपराधियों और वयस्क कैदियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है और प्रत्येक जेल में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शैक्षिक कर्मचारियों और कक्षाओं और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह विचाराधीन कैदियों के लिए शैक्षिक कक्षाओं का भी

प्रशासनिक दक्षता और लागत में कमी के आधार पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग उचित है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि, इसका उपयोग मुख्य रूप से रिमांड बढ़ाने के लिए किया जाता है, यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों की कीमत पर है। यद्यपि जेल मैनुअल में कैदियों और उनके परिवारों के साथ-साथ उनके वकीलों के बीच बैठकों की सुविधा के प्रावधान हैं, व्यवहार में, सुरक्षा चिंताओं और प्रतिबंधात्मक वातावरण का मतलब है कि ऐसे अवसर बहुत सीमित हैं। वकील शायद ही कभी ग्राहकों से निर्देश लेने के लिए जेलों में जाते हैं और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप, अक्सर विचाराधीन कैदियों - जिनमें से अधिकांश सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं - को ऐसी अदालत का सामना करना पड़ता है जिसकी कार्यवाही उनके लिए अपारदर्शी होती है और/या जब उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाता है तो वे अपने वकीलों को जानकारी देने में असमर्थ होते हैं।

प्रावधान करता है।<sup>27</sup> आईजेआर वर्ष के दौरान भरती किए गए कैदियों की संख्या को मापता है जिन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

यह देखते हुए कि जेल की 65 प्रतिशत आबादी कम शिक्षित है,<sup>28</sup> साक्षरता और अप-कौशल सुविधाएं एक अमूल्य सुधारात्मक और पुनर्वास उपाय हैं। वार्षिक जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट में विभिन्न राज्य जेल विभागों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत की गई शिक्षा सुविधाओं के बारे में विस्तृत डेटा की कमी बनी हुई है। शैक्षिक सुविधाओं की श्रृंखला में शिक्षित कैदियों या साक्षरता कर्मचारियों की मदद से चलाए जाने वाले साक्षरता अभियान, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तदर्थ कक्षाएं और कुछ केंद्रीय जेलों में स्थापित अध्ययन केंद्रों के माध्यम से मुक्त विद्यालयी शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालयों तक पहुंच शामिल है। इसी प्रकार, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में रसोई, बढ़ईगीरी, कपड़ा, कालीन बनाने और ऐसे अन्य उद्योगों में 'करके सीखना' के साथ-साथ वायरिंग, प्लंबिंग, बुनियादी कंप्यूटर कौशल आदि जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं, जो इसके साथ चलाए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों या सरकारी एजेंसियों की मदद। शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन के बारे में स्पष्ट मानकों की अनुपस्थिति

21 जेल सांख्यिकी भारत, 2021, पृष्ठ 172। यहां उपलब्ध है: [https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2021/PSI\\_2021\\_as\\_on\\_31-12-2021.pdf](https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2021/PSI_2021_as_on_31-12-2021.pdf)

22 जेल सांख्यिकी भारत, 2021।

23 अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, मेघालय, पुद्दुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

24 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर और नागालैंड।

25 तेलंगाना को छोड़कर, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जेलों की संख्या में वृद्धि के कारण वीसी कवरेज में गिरावट दर्ज की गई।

26 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सलाहकार संख्या V-17013/01/2011-PR. यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvEducationProg15062011.pdf>

27 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय XIV। यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

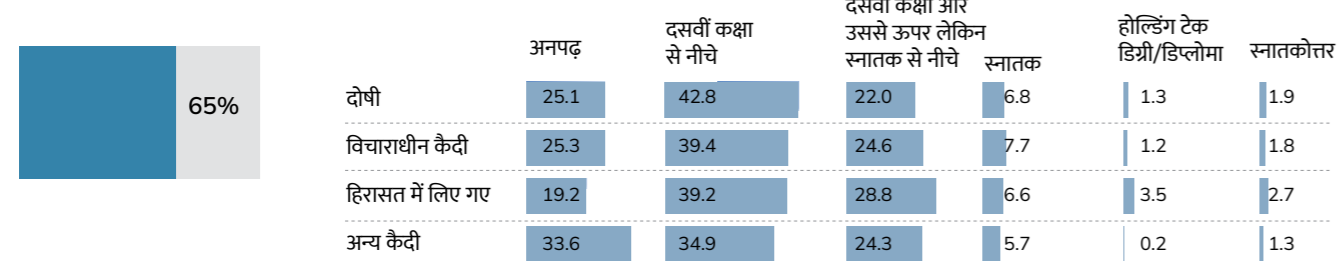
28 भारत के जेल सांख्यिकी में निरक्षर, 10 वीं कक्षा से नीचे, 10 वीं कक्षा और उससे ऊपर लेकिन स्नातक स्तर से नीचे, स्नातक, स्नातकोत्तर, होल्डिंग वाले कैदियों की शैक्षिक प्रोफाइल शामिल की गई है। तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा, और अन्य।

## चित्र 22: कैदियों की शैक्षिक प्रोफाइल और प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

दिसंबर 2021 तक, 5.5 लाख कैदियों में से लगभग 65% या तो निरक्षर थे या दसवीं कक्षा तक पढ़े थे। फिर भी, 2021 के दौरान जेलों में भर्ती किए गए 18 लाख कैदियों के मुकाबले गणना की गई, केवल 89,761 या 5% ने किसी न किसी रूप में शिक्षा प्राप्त की।

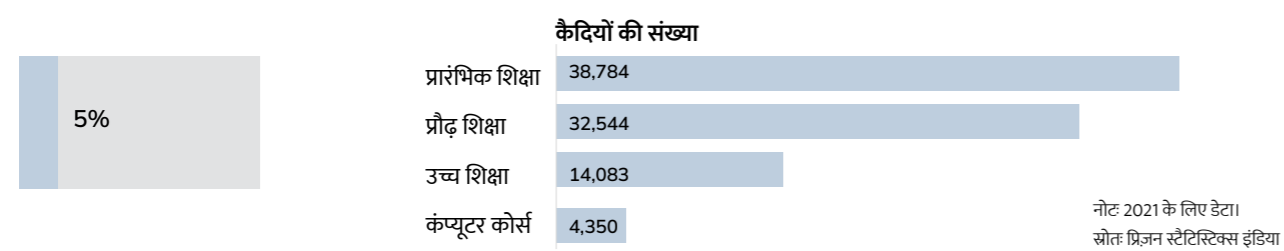
### कैदियों की शैक्षिक प्रोफाइल

31 दिसंबर 2021 को निरक्षर या दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की



### जेल में प्राप्त शैक्षिक सुविधाएँ

इस वर्ष के दौरान भर्ती 18 लाख कैदियों के प्रति शिक्षा प्राप्त करने वाले कैदियों की संख्या



कैदियों को बाहरी दुनिया में बेहतर करने के लिए तैयार करने में उनकी प्रभावकारिता का आकलन करने की अनुमति नहीं देती है।

**व्यावसायिक प्रशिक्षण:** मॉडल जेल मैनुअल, 2016 में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुधारात्मक कार्यक्रमों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक केंद्रीय और जिला जेल में रोजगार योग्य दोषियों और स्वेच्छा से काम करने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।<sup>29</sup> कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य "उनकी इच्छाशक्ति को मजबूत करना" है। काम करने के लिए और उनकी आर्थिक सुरक्षा की भावना के लिए।"<sup>30</sup>

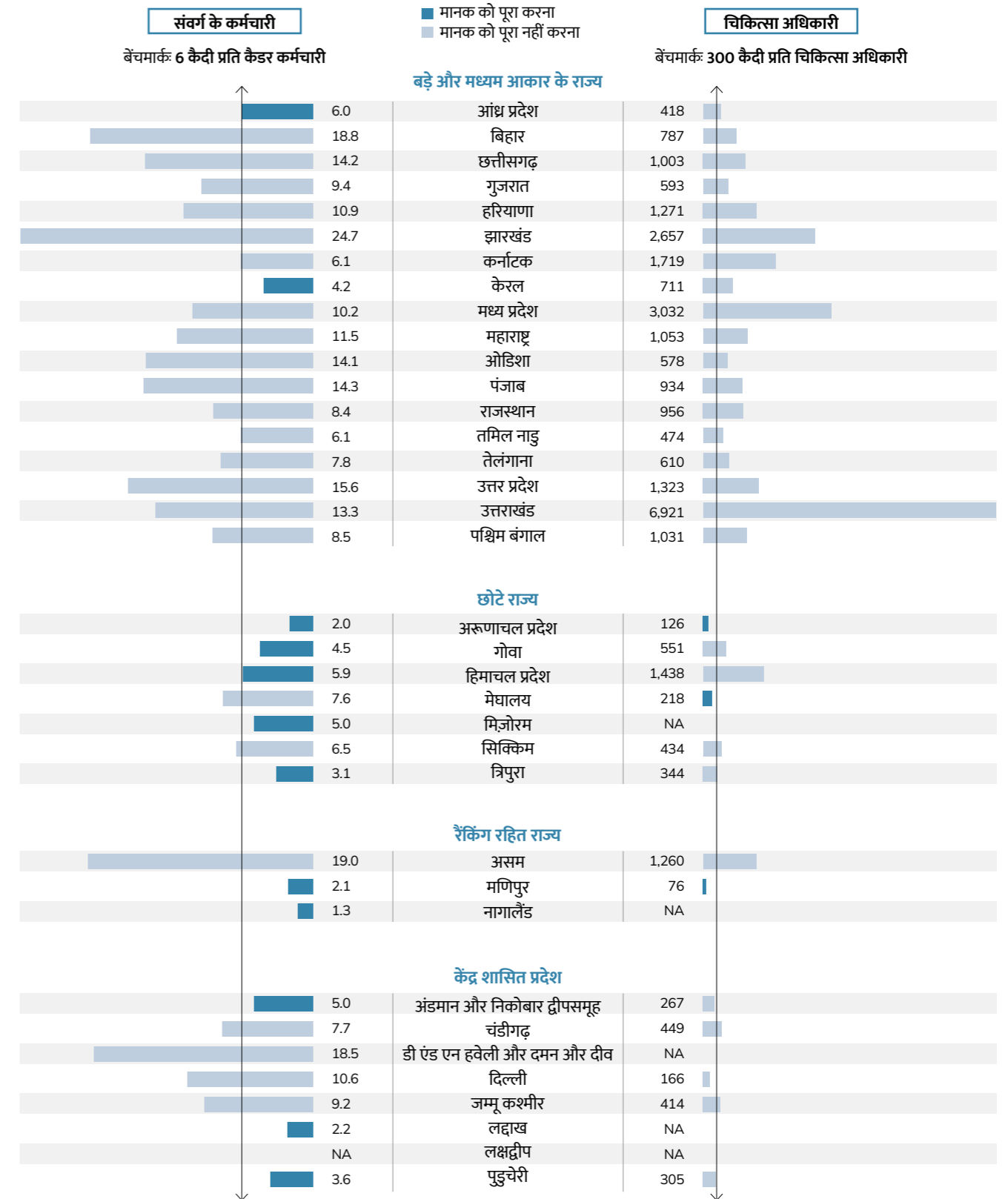
वर्ष के दौरान प्रवेशित 18 लाख कैदियों के मुकाबले शिक्षा प्राप्त करने वाले कैदियों की संख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण को कृषि, बढ़ईगरी, सिलाई, साबुन और फिनाइल बनाना, हथकरघा और 'अन्य' में वर्गीकृत किया गया है, और यह उन दोषियों और विचाराधीन कैदियों के लिए उपलब्ध है जो स्वेच्छा से काम करते हैं। सिक्किम (29 प्रतिशत) को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 2021 के दौरान 20 प्रतिशत से अधिक कैदियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। पश्चिम बंगाल एक प्रतिशत (0.14 प्रतिशत) तक भी नहीं पहुंच सका जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप और दमन और दीव ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया।

29 Ibid.

30 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय XVI। यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

## चित्र 23: मानकों को पूरा करना

मॉडल कारागार मैनुअल, 2016 का उद्देश्य कारागारों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन में समानता लाना है। अधिकांश राज्य निर्धारित मानकों को पूरा करने में कमी कर गए हैं।



नोट: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

## मानव संसाधन और कामकाज

कैदियों के साथी के रूप में डॉक्यूमेंटेड कर्मचारी अधिकारी, कैडर कर्मचारी, सुधार कर्मचारी, चिकित्सा और मंत्रालयी कर्मचारी के रूप में हैं। स्टाफ की रिक्तियों को स्वीकृत संख्या के खिलाफ मापा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, स्वीकृत संख्या सालों-सालों स्थिर रहती है और अक्सर वर्तमान आवश्यकताओं से पिछड़ सकती है। पिछले दशक के दृष्टिकोण से देखा जाता है, कुल रिक्तियाँ लगभग 30 प्रतिशत के आस-पास हैं। इस स्थिति में सजा यात्रियों के रूप में मासिक वार्डर्स, चौकीदार, आदि के रूप में नियुक्ति की जाती है और रोजमर्रा के कामों को प्रबंधित करने के लिए वेतन दिया जाता है। 2021 के अंत में, राष्ट्रीय औसत रिक्तियाँ 28 प्रतिशत पर थीं। आधे से अधिक राज्य/संघ अपने स्टाफ पदों के चौथाई हिस्से की रिक्तियों के साथ काम कर रहे थे। महान राज्यों में, झारखंड ने सबसे अधिक रिक्ति स्तर (59.3 प्रतिशत) को दर्ज किया और छोटे राज्यों और संघों में यह लद्दाख (83.1 प्रतिशत) और सिक्किम (52.3 प्रतिशत) था।

**चिकित्सा कर्मचारी:** कारागार स्वास्थ्य कर्मचारी को चिकित्सा अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका मतलब प्रमाणित चिकित्सक होते हैं, साथ ही चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल होते हैं, जिनमें प्रयोगशाला प्राविधिकों, फार्मासिस्ट्स और कॉम्पाउंडर्स शामिल हैं। 2016 का मॉडल कारागार मैनुअल आवश्यकता है कि प्रत्येक 300 कैदियों के लिए एक चिकित्सक हो। वर्षों-वर्षों, प्रमाणित डॉक्टरों की अवशोषित कमी की समस्या केवल और अधिक गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय रूप से, रिक्तियाँ 2020 में 34 प्रतिशत से 2021 में 48.2 प्रतिशत तेजी से बढ़ गईं। 1,270 की स्वीकृत संख्या के खिलाफ, 2020 में सेवा में पहले ही कम संख्या 797 से 2020 में और कम हो गई और 658 हो गई। 554,034 कैदियों के जनसंख्या के खिलाफ, इससे प्रत्येक 842 कैदियों के लिए एक प्रमाणित चिकित्सक होता है, इसका सूचित करते हैं कि हर कारागार में एक चिकित्सक नहीं होता है और चिकित्सा आपातकालिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसी भी उपलब्ध जिला स्वास्थ्य पेशेवर पर निर्भर करना पड़ता है।

चिकित्सा के अलावा मेडिकल कर्मचारी की कमी और भी गंभीर है। निर्धारित 3,497 के खिलाफ केवल 2,080 वास्तविक मेडिकल स्टाफ है, जो राष्ट्रीय रूप से निर्वाचित हैं, रिक्तियाँ 2021 में 32.7 प्रतिशत से बढ़कर 40.5 प्रतिशत तक बढ़ गईं। 15 राज्य/संघ अध्यापन करते हैं कि 40 प्रतिशत से अधिक रिक्तियाँ हैं,<sup>31</sup> जिनमें गोवा (84.6 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (66.8 प्रतिशत) और कर्नाटक (61.3 प्रतिशत) सबसे अधिक स्तर पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। बारह राज्यों<sup>32</sup> ने पिछले साल के अधिक रिक्तियों को दर्शाया और केवल 3 राज्य/संघ (नागालैंड, एंडमैन और निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी) ने कोई रिक्ति नहीं दर्शाई।

31 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

32 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

33 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

34 मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय IV, ऑप. सिट., पी 42.

35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम,

पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

36 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी और त्रिपुरा।

## सुधारात्मक प्रभाग

2021 के अंत में, 1,319 जेलों में 658 डॉक्टर प्रति जेल में आधे डॉक्टर का संकेत देते हैं। वर्ष के अंत में जेल में बंद कैदियों की संख्या 554,034 के मुकाबले प्रत्येक 842 कैदियों के लिए 1 डॉक्टर और 266 महिला कैदियों के लिए 1 महिला डॉक्टर थी।

**कैडर कर्मचारी:** 2016 का मॉडल कारागार मैनुअल प्रावधान करता है कि प्रत्येक 6 कैदियों<sup>33</sup> के लिए 1 गार्डिंग/कैडर स्टाफ हो। कारागारों का प्रतिदिन प्रबंधन कैडर स्टाफ के साथ होता है:

जेलों का रोजमर्रा का प्रबंधन कैडर कर्मचारियों पर निर्भर करता है: वार्डर, मैट्रन और सुरक्षा कर्मी, जो तीन शिफ्टों में कैदियों के साथ सीधे काम करते हैं। उनके कार्यों में सुरक्षा और संतरी कर्तव्यों, दिन में तीन बार रोल कॉल, कमिश्नरी की खरीद, लेखांकन और वितरण, कैदियों को अदालत में जाने के लिए तैयार करना, अंदर आने या बाहर जाने वालों के रजिस्टर को बनाए रखना, स्वच्छता की निगरानी करना, काम और घरेलू गतिविधियों का वितरण करना शामिल है।<sup>34</sup>

उन्नीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 4 में से 1 कैडर स्टाफ गायब है।<sup>35</sup> रिक्तियों में 2020 में 29 प्रतिशत से मामूली कमी आई है और 2021 में 26 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, लद्दाख (80 प्रतिशत) में सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की गईं, जबकि नागालैंड (0.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की गईं। सेंट) सबसे कम। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, झारखंड (60 प्रतिशत) में सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की गईं, जबकि तमिलनाडु (9.8 प्रतिशत) में सबसे कम रिक्तियां दर्ज की गईं।

तीन साल की अवधि (2019-2021) में, झारखंड और सिक्किम क्रमशः 40 प्रतिशत और 44 प्रतिशत से कम कर्मचारियों के साथ काम करते रहे। पंजाब (47.3 प्रतिशत), बिहार (41.4 प्रतिशत) और गुजरात (34 प्रतिशत) ने 2019 के बाद से रिक्तियों में पर्याप्त वृद्धि दिखाई है। केवल चार राज्य-अरुणाचल प्रदेश (3.1 प्रतिशत), मणिपुर (4.8 प्रतिशत), नागालैंड (0.3 प्रतिशत) और तमिलनाडु (9.8 प्रतिशत)-रिकार्ड रिक्तियों 10 प्रतिशत से कम।

36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 12<sup>36</sup> ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक छह कैदियों के लिए एक कैडर स्टाफ के बेंचमार्क को पूरा कर पाए हैं। 21,000 से अधिक कैदियों की आबादी वाले झारखंड में प्रति

कैडर स्टाफ 25 कैदियों का कार्यभार है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है।

**सुधार अधिकारी:** मैनुअल द्वारा निर्धारित किए गए 1,200 कैदियों के लिए 1 सुधार अधिकारी और 1 मानसिक चिकित्सक/सलाहकार के लिए 1,500 कैदियों के लिए है।

कारागार के मार्गदर्शन का तत्व है कि दंड देने के बजाय पुनर्वास की दिशा में किया जा रहा है,<sup>37</sup> सुधार अधिकारी की अभाव—जो प्रायः परिवीक्षण या कल्याण अधिकारियों, मानसिक और भौतिक रूप से कैदियों के साथ और समाज में उनके समावेश के मानसिक और भौतिक वेबिंग के बारे में प्रमुख रूप से चिंतित हैं—विशेष रूप से स्पष्ट है। वर्षों से रिक्तियां गंभीर रही हैं, बोझ अधिक है और संस्थानिक क्षमताएँ बिना मूल्य हैं।

प्रत्येक 200 कैदियों के लिए 1 सुधार अधिकारी के मानक को पूरा करने के लिए, देश भर में सुधार कर्मचारियों के कम से कम 2,770 स्वीकृत पद होने चाहिए। हकीकत में, 2021 में 1,391 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 886 सुधारात्मक कर्मचारी थे। राष्ट्रीय स्तर पर, औसतन, 1 सुधारात्मक स्टाफ सदस्य 625 कैदियों की सेवा करता है; और रिक्तियां 36 प्रतिशत रहीं, जो 2020 में 40 प्रतिशत और 2019 में 42 प्रतिशत से मामूली कमी है।

तमिलनाडु और चंडीगढ़ को छोड़कर, कोई भी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 200 कैदियों<sup>38</sup> के लिए 1 सुधार अधिकारी के बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है। 22,938 कैदियों के लिए 1 स्टाफ सदस्य के साथ राजस्थान और 21,257 कैदियों के लिए 1 स्टाफ सदस्य के साथ झारखंड में सबसे अधिक कार्यभार दर्ज किया गया है। क्रमशः 7,316 और 1,033 कैदियों की आबादी वाले तेलंगाना और त्रिपुरा ने अपनी जेलों में केवल 1 सुधार अधिकारी को मंजूरी दी है। पंजाब, हरियाणा और गोवा में 2017 से 100 प्रतिशत रिक्तियां जारी हैं।

## विविधता

जेल स्टाफ में महिलाएँ (% , दिसंबर 2021)

जेल स्टाफ में महिलाओं की हिस्सेदारी (पीपी, CY 2017-2021)

हालाँकि मॉडल जेल मैनुअल कोई बेंचमार्क प्रदान नहीं करता है, नीति दस्तावेज महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव देते हैं। 2021 तक, किसी भी राज्य ने इस कोटा को पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर, कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 13.8 प्रतिशत है, जो 2020 में 13.7 प्रतिशत और 2019 में 12.8 प्रतिशत से मामूली वृद्धि है। ग्लास सीलिंग यथावत बनी हुई है और लैंगिक असमानता बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9.6 प्रतिशत है।

कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य था जहां कुल जेल कर्मचारियों में 32 प्रतिशत महिलाएँ थीं। सत्रह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।<sup>39</sup> पांच वर्षों (2017-2021) को देखें, तो इक्कीस राज्यों/केंद्रशासित<sup>40</sup> प्रदेशों ने धीमे लेकिन स्थिर बदलाव किए हैं, जिनमें से बिहार में 3.26 प्रतिशत अंकों के साथ सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में जबकि उत्तराखंड में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।

मॉडल जेल मैनुअल महिला कैदियों की देखभाल के लिए महिला चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था करता है, जो कुल कैदी आबादी का 4 प्रतिशत (22,918) हैं। हालाँकि महिला चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मैनुअल जेल प्रशासन को संबंधित जिला सरकारी अस्पतालों से अंशकालिक महिला चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश देता है। सत्रह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>42</sup> में किसी भी महिला चिकित्सा अधिकारी का रिकॉर्ड नहीं है। उदाहरण के लिए, सर्वाधिक महिला कैदियों (4,995) वाले उत्तर प्रदेश में राज्य की सभी जेलों में केवल 3 महिला चिकित्सा अधिकारी दर्ज हैं।<sup>43</sup>

## बजट

बजट और व्यय

खर्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-'21)

उपयोग किया गया जेल बजट (% , 2021-22)

उपयोग किया गया बजट (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

प्रति कैदी खर्च (रुपये, 2021-22)

प्रति कैदी खर्च (% , वित्तीय वर्ष '18-'22)

37 'केंद्र सरकार मॉडल जेल अधिनियम लागू: अमित शाह', हिंदुस्तान टाइम्स, 5 सितंबर 2021। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.hindustantimes.com/india-news/centre-to-bring-model-prisons-act-amit-शाह-101662315982981.html>

38 मॉडल जेल मैनुअल, 2016 में कहा गया है कि प्रत्येक 200 कैदियों पर एक सुधार अधिकारी होना चाहिए। हालाँकि, पीएसआई परिवीक्षा अधिकारियों/कल्याण अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए सुधारात्मक कर्मचारियों के डेटा को अलग करता है। इस रिपोर्ट में मॉडल जेल मैनुअल में निर्धारित बेंचमार्क के मुकाबले पीएसआई में दर्ज कुल सुधारात्मक स्टाफ के हिसाब से कैदियों को मापा गया है।

39 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लद्दाख, पुदुचेरी, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

40 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

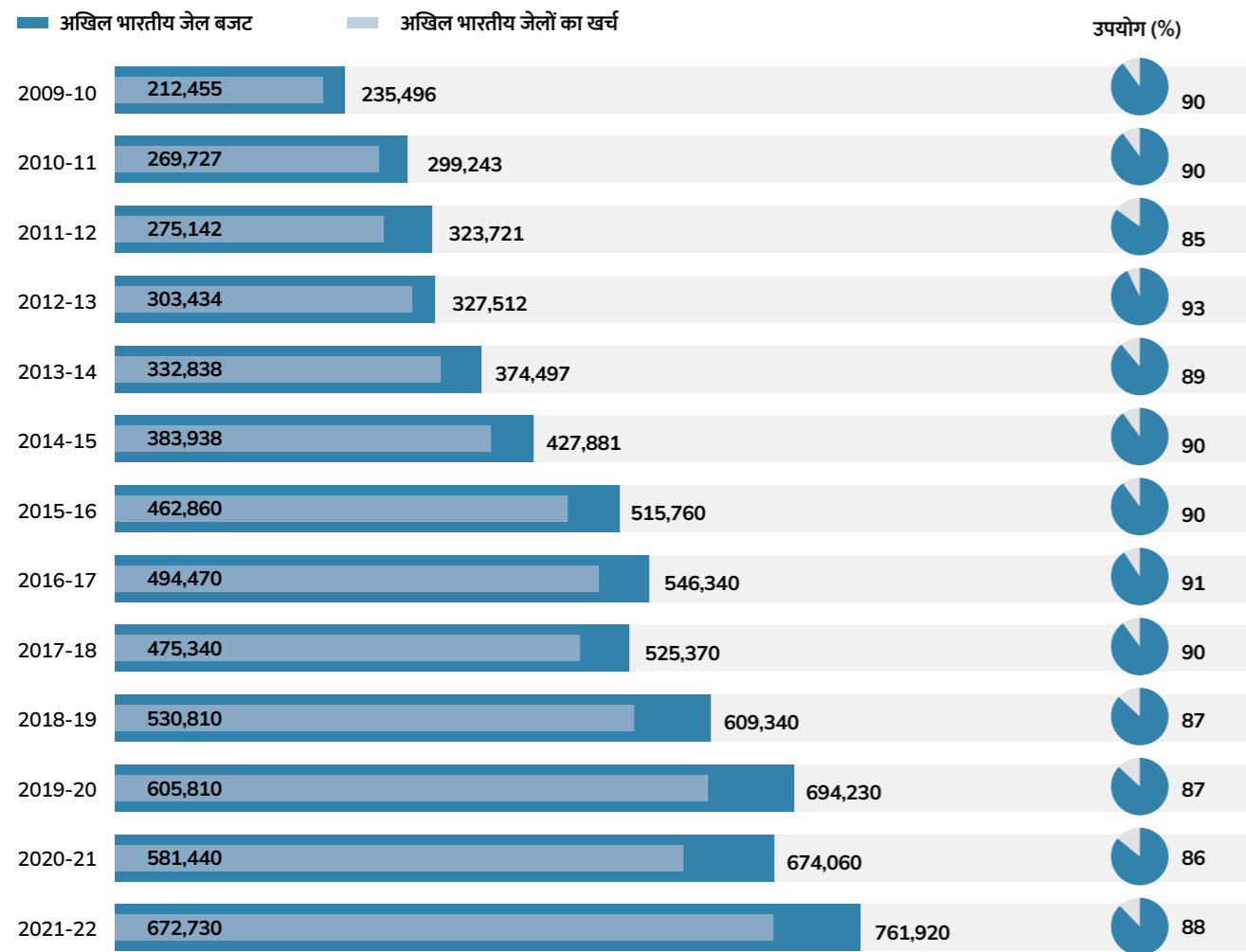
41 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016; अध्याय 26, नियम 26.25, पृ.243। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

42 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, डीएनएच और डीडी, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

43 जेल सांख्यिकी भारत, ऑप. सिट., पी. 261.

## चित्र 24: पिछले दशक में जेल बजट उपयोग की राष्ट्रीय प्रवृत्ति राशि (लाख रु.)

राशि (लाख रुपये)



स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

**प्रति कैदी बजट और खर्च:** 2020-21 में, देश भर की जेलों के लिए कुल स्वीकृत बजट 6740.6 करोड़ (₹67.4 बिलियन) से बढ़कर 7619.2 करोड़ (₹76.19 बिलियन) हो गया, जो एक साल पहले की तुलना में 13.03 प्रतिशत की वृद्धि सात को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने स्वीकृत बजट में वृद्धि दर्ज की। त्रिपुरा का स्वीकृत बजट 162 प्रतिशत बढ़ गया, जो 2020-21 में 13.7 करोड़ से बढ़कर 35.9 करोड़ हो गया, जबकि उत्तराखंड 31.2 करोड़ से घटकर 4.6 करोड़ या 85 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों ने अपने कुल स्वीकृत बजट में से औसतन 88 प्रतिशत का उपयोग किया - 2020 में 86 प्रतिशत से मामूली वृद्धि। अधिकांश राज्यों ने 90 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया। लद्दाख

(61 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (71 प्रतिशत) और बिहार (74 प्रतिशत) में सबसे कम उपयोग दर्ज किया गया है जबकि लक्षद्वीप में कोई उपयोग नहीं होने की रिपोर्ट है।<sup>46</sup>

केवल पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम और तमिलनाडु - ने अपने पूरे बजट का उपयोग किया। तेलंगाना ने अपनी आवंटित राशि से 14 प्रतिशत अधिक का उपयोग किया।

2020 और 2021 के बीच, दस बड़े और मध्यम आकार के राज्यों सहित बीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बजट उपयोग में वृद्धि देखी।<sup>47</sup> 2018 से 2022 की पांच साल की अवधि में, तेलंगाना (4.43 प्रतिशत

अंक), आंध्र प्रदेश (3.96 प्रतिशत अंक) और झारखंड (2.33 प्रतिशत अंक) में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश (-3.42 प्रतिशत अंक), बिहार (-2.16 प्रतिशत अंक) और छत्तीसगढ़ (-1.16 प्रतिशत अंक) ने बजट उपयोग में गिरावट देखी।

प्रति कैदी खर्च: 2021-22 में जेलों के लिए आवंटित 7,619.2 करोड़ बजट में से, राज्य 6,727.3 करोड़ (67.27 बिलियन) या 88 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 'प्रति कैदी खर्च' को भोजन, कपड़े, चिकित्सा आवश्यकताओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और कल्याण गतिविधियों के खर्चों को पूरा करने पर किए गए व्यय के रूप में परिभाषित करती है।

इसमें से 31 प्रतिशत या 2,106.86 करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर भोजन, कपड़े, चिकित्सा आवश्यकताओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किए गए।

राष्ट्रीय स्तर पर, 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>48</sup> ने रुपये से कम खर्च किया। कैदियों पर सालाना 35,000 या रुपये से कम। प्रति दिन 100. बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, 106 जेलों और 7,950 कैदियों के साथ आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक (लगभग 580 रुपये प्रति दिन) खर्च किया, जबकि उत्तराखंड (6,112 रुपये), जहां 11 जेलों में 6,921 कैदी हैं, ने सबसे कम खर्च किया। रु. 17 प्रति दिन. पांच वर्षों (2018-22) में बीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>49</sup> में प्रति कैदी खर्च में वृद्धि देखी गई है। 20 जेलों वाले हरियाणा ने 2018-22 के बीच प्रति कैदी खर्च में 117 प्रतिशत अंक की वृद्धि की, जो उच्चतम दर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 75 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। असम (-7.2 पीपी), हिमाचल प्रदेश (-7.6 पीपी), महाराष्ट्र (-5.8 पीपी), पुडुचेरी (-7.4 पीपी), उत्तराखंड (-10.6 पीपी) और गोवा (-20.6 पीपी) ने प्रति कैदी अपने औसत खर्च में कमी की।

जेलों पर खर्च में औसत पांच साल का बदलाव प्रत्येक राज्य द्वारा इस उपग्रहणी को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है। 2015-16 और 2020-21 के बीच पांच साल की अवधि में उन्नीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जेल व्यय कुल राज्य बजट व्यय,<sup>50</sup> से पीछे रहा। उदाहरण के लिए, गोवा का कुल राज्य बजट औसतन 7.33 प्रतिशत अंक की दर से बढ़ा, जबकि इसके जेल बजट में 11.87 प्रतिशत अंक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई; इसका तात्पर्य यह है कि जेल का बजट राज्य के समग्र बजट के समान गति से नहीं बढ़ा। इसी तरह, तेलंगाना के समग्र राज्य बजट में 9.74 प्रतिशत अंक की औसत वृद्धि दर देखी गई, जबकि इसी अवधि में जेल बजट में 2.25 प्रतिशत अंक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई।

बिहार (1.57 पीपी), पश्चिम बंगाल (2.12 पीपी), गुजरात (16.66 पीपी), कर्नाटक (6.26 पीपी), छत्तीसगढ़ (6.08 पीपी) और झारखंड (5.79 पीपी) सहित<sup>51</sup> राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, जेल बजट का उपयोग जारी रखा गया है। राज्य के समग्र बजट व्यय के साथ तालमेल बिठाना। पांच वर्षों में राज्य के बजट के समग्र उपयोग की तुलना में गोवा (-19.20 प्रतिशत अंक) और तेलंगाना (-11.99 प्रतिशत अंक) में जेल बजट उपयोग में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।

**प्रो. विजय राघवन**, टीआईएसएस-प्रयास  
**मधुरिमा धानुका**, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल  
**सुगंधा माथुर**, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल  
**नयनिका सिंघल**, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट  
**लखविंदर कौर**, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

44 जेल भारत सांख्यिकी, 2021; तालिका 12.2, पृ. 274.

45 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

46 जेल सांख्यिकी भारत, 2021 राज्य जेल विभागों के लिए करोड़ों का बजट दर्ज करता है और जबकि लक्षद्वीप 0.1 करोड़ का स्वीकृत बजट दर्ज करता है, यह कोई व्यय दर्ज नहीं करता है। इसका कारण लाखों का खर्च हो सकता है।

47 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

48 असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

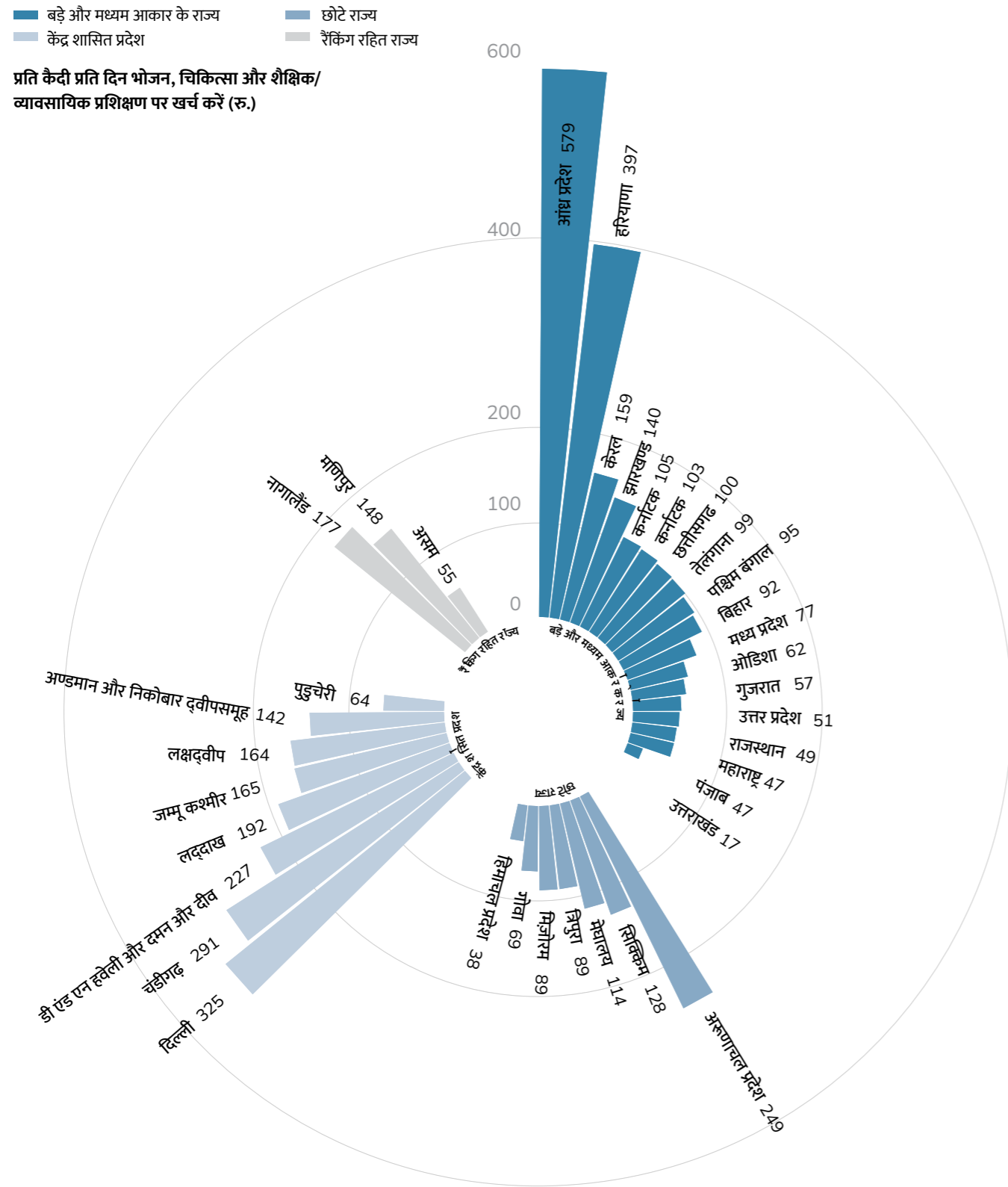
49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, डीएनएच और डीडी, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा।

50 अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, डीएनएच और डीडी, गोवा, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

51 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

### चित्र 25: प्रति कैदी दैनिक व्यय

पांच वर्षों (2018-2022) में पंद्रह राज्यों ने कैदियों के भोजन, चिकित्सा आवश्यकताओं और व्यावसायिक और शैक्षणिक सुविधाओं पर खर्च में वृद्धि देखी है। निम्नलिखित आंकड़ा राज्य-वार प्रति कैदी दैनिक खर्च को दर्शाता है।



नोट: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समूह के भीतर खर्च के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

### कर्नाटक में जेलों का सुधार

कर्नाटक में 51 परिचालन जेलों पर सीएचआरआई का 2019 का अध्ययन<sup>52</sup> दर्शाता है कि राज्य तंत्र - इस मामले में जेल विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और कर्नाटक उच्च न्यायालय - द्वारा एक समन्वित प्रयास वास्तव में सुधार को उत्प्रेरित कर सकता है।

खोज	प्रभाव
<ol style="list-style-type: none"> <li>कर्नाटक जेल मैनुअल और नियम राजस्व जेलों को नियंत्रित नहीं करते हैं। यहां हालात बेहद खराब हैं और कैदियों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>राजस्व जेलों में कैदियों को नजदीकी सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। सभी राजस्व जेलों को कारागार एवं सुधार सेवा विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लंबित है।</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2000 के बाद 51 में से केवल 18 जेलों का निर्माण किया गया। इमारतों को उन्नयन और डिजाइन की आवश्यकता है जो कानूनी सहायता क्लिनिक, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और पश्चिमी शौचालय जैसी नई आवश्यकताओं को समायोजित करते हैं।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कर्नाटक के जेल विभाग ने रुपये की लागत से 5,500 की अतिरिक्त कैदी क्षमता का निर्माण किया है। नई जेलों के निर्माण और पुरानी जेलों के नवीनीकरण की योजना के साथ 450 करोड़।</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच को सीमित करने वाले मॉडल जेल मैनुअल 2016 मानकों का अनुपालन न करना। दो उप-कारागारों में शौचालय-कैदी अनुपात 1:200 था।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अप्रैल 2022 तक रु. मॉडल जेल मैनुअल, 2016 मानकों के अनुरूप, 60 अतिरिक्त शौचालय और 322 बाथरूम के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>नियमित डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और लैब तकनीशियनों की कमी के कारण प्रत्येक 250-300 कैदियों पर विजिटिंग मेडिकल अधिकारियों सहित एक चिकित्सा कर्मी की कमी हो गई है।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है।</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>बुनाई जैसे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण और उनकी उपयोगिता के किसी भी सर्वेक्षण के बिना बढ़ईगिरी रिहा होने के बाद कैदियों के लिए अवसरों को सीमित कर देती है। इसके अलावा, जिन कैदियों के पास बैंक खाता खोलने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे, उनके लिए वेतन सुरक्षित करना मुश्किल था।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कर्नाटक देश के उन कुछ राज्यों में से एक है, जिसने अक्टूबर 2021 में जेल विकास बोर्ड अधिनियम लागू किया है। सभी जेलों में सभी दोषियों के लिए जन धन खाते खोले गए हैं और कैदियों की मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य के पास लंबित है। सरकार।</li> </ol>

52 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, कर्नाटक की जेलों के अंदर, 2019। यहां उपलब्ध है: <https://kslsa.kar.nic.in/library.html>

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

Table with columns: State, AIJ 2019, AIJ 2020, AIJ 2022, AIJ 2022 Score, Improvement, Significance, Prisoners, Budget (Per inmate and Jail budget), and Score. Sub-headers: राष्ट्रीय औसत, बड़े और मध्यम आकार के राज्य, छोटे राज्य, रैंक रहित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश.

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

Table with columns: State, Indicator, Score, and Rank. Sub-headers: राष्ट्रीय औसत, बड़े और मध्यम आकार के राज्य, छोटे राज्य, रैंक रहित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश.

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्यों। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्व

1. उन संकेतकों की गिनती जिन पर किसी राज्य ने आईजेआर से बेहतर प्रदर्शन किया है 2. केवल आईजेआर 2 और आईजेआर 3 दोनों में मौजूद गैर-प्रवृत्ति संकेतकों पर विचार किया गया है। बेंचमार्क वाले संकेतकों के लिए, यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा करता है, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही बेंचमार्क के भीतर उसके मूल्य में गिरावट आई हो। यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है लेकिन उसके मूल्य में सुधार होता है, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया था। D&NH/D&D, J&K और लद्दाख के मान IJR 2 के साथ तुलनीय नहीं हैं, और इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया है।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्यों। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्व

2. भारत के जेल आँकड़े (Prison Statics of India या पीएसआई) स्वीकृत और वास्तविक अधिकारी और कैडर स्टाफ दिखाता है। 3. पीएसआई 0 स्वीकृत और अधिकारियों को दर्शाता है। 6. पीएसआई 0 स्वीकृत और वास्तविक कुल स्टाफ दिखाता है।

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

श्रीम संकेतक	विधिता	बुनियादी ढांचा					
		जेल कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या (%), दिसंबर 2021)	जेल अधिभोग (%), दिसंबर 2021)	नया 100% और अधिक अधिभोग वाली जेलों का हिस्सा (%), 2022)	नया 150% और अधिक अधिभोग वाली जेलों का हिस्सा (%), 2022)	नया 1-3 साल (%), दिसंबर 2021) के लिए हिरासत में लिए गए विचाराधीन कैदी	नया कैदियों (भारती) ने शैक्षिक पाठ्यक्रम का लाभ उठाया (%), दिसंबर 2021)
स्कोरिंग गाइड	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	Higher, the better	
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	13.8	130.2	54	30	20.8	4.97	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>							
आंध्र प्रदेश	8.4	90.7	25	16	5.2	2.21	
बिहार	21.5	140.1	73	41	14.0	6.40	
छत्तीसगढ़	10.4	148.6	63	47	26.9	5.86	
गुजरात	7.2	118.6	72	28	23.5	3.84	
हरियाणा	6.2	120.8	90	60	23.4	7.46	
झारखंड	9.3	121.5	71	26	21.9	5.97	
कर्नाटक	32.0	100.6	48	22	20.4	8.07	
केरल	10.0	89.8	75	43	7.2	1.83	
मध्य प्रदेश	18.6	164.1	56	31	23.3	4.76	
महाराष्ट्र	14.8	148.8	53	37	23.9	2.34	
ओडिशा	12.5	99.1	62	23	22.1	2.49	
पंजाब	9.4	98.5	73	23	20.5	0.48	
राजस्थान	19.4	100.2	59	19	27.5	2.08	
तमिलनाडु	14.1	76.4	11	1	6.8	7.88	
तेलंगाना	10.5	91.5	32	12	6.7	21.52	
उत्तर प्रदेश	9.9	184.8	85	77	23.4	5.18	
उत्तराखंड	3.6	185.0	82	73	22.9	0.52	
पश्चिम बंगाल	10.9	120.0	80	60	24.6	1.46	
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचल प्रदेश	18.2	75.4	56	33	19.0	0.00	
गोवा	1.8	88.3	100	0	47.2	0.78	
हिमाचल प्रदेश	8.4	119.0	61	13	30.2	0.11	
मेघालय	14.8	160.1	80	20	27.5	0.00	
मिजोरम	25.0	78.6	56	56	11.4	0.10	
सिक्किम	23.2	166.9	50	50	37.1	0.25	
त्रिपुरा	5.4	46.9	14	7	11.5	0.00	
<b>रैंक रहित राज्य</b>							
असम	12.8	112.8	81	74	4.0	10.04	
मणिपुर	10.7	48.0	0 <sup>7</sup>	0 <sup>7</sup>	16.8	0.00	
नागालैंड	22.5	34.5	0	0	14.7	0.00	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.9	83.7	0	0	41.8	0.90	
चंडीगढ़	6.4	80.1	100	0	26.6	6.81	
दमन और दीव	0.0	108.8	67	67	35.0	0.00	
दिल्ली	12.5	182.5	13	7	22.7	6.17	
जम्मू और कश्मीर	8.1	138.6	87	47	27.2	8.68	
लद्दाख	8.3	12.9	0	0	25.0	0.00	
लक्षद्वीप	NA <sup>6</sup>	7.8	0 <sup>8</sup>	0 <sup>8</sup>	0.0	0.00	
पुडुचेरी	9.5	73.3	25	25	8.6	0.00	

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के निबंधक और महालेखा परीक्षक;

केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पंक्त

6. पीएसआई स्वीकृत और वास्तविक कुल स्टाफ दिखाता है। 7. ई-प्रिजन वेबसाइट मणिपुर की 5 जेलों की क्षमता प्रदान नहीं करती है। लेकिन पीएसआई के अनुसार, इन 5 जेलों में अत्यधिक भीड़ नहीं है, और इसलिए हमने मान लिया है कि किसी भी जेल में अत्यधिक भीड़ नहीं है। 8. ई-प्रिजन वेबसाइट लक्षद्वीप की 4 जेलों की क्षमता प्रदान नहीं करती है। लेकिन पीएसआई के अनुसार, इनमें 8% की क्षमता है, और इसलिए हमने माना है कि किसी भी जेल में अत्यधिक भीड़ नहीं है।

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

श्रीम संकेतक	बुनियादी ढांचा		कार्यभार		
	कैदी (भारती) ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया (%), दिसंबर 2021)	वी-सी सुविधा वाली जेलें (%), दिसंबर 2021)	प्रति अधिकारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)	प्रति संवर्ग कर्मचारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)	प्रति सुधारात्मक कर्मचारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)
स्कोरिंग गाइड	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	2.18	84	105	11.2	625
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>					
आंध्र प्रदेश	0.83	74	33	6.0	NA <sup>10</sup>
बिहार	1.09	97	253	18.8	256
छत्तीसगढ़	2.57	94	264	14.2	436
गुजरात	1.78	94	55	9.4	3,319
हरियाणा	5.14	100	163	10.9	NA <sup>11</sup>
झारखंड	7.67	91	443	24.7	21,257
कर्नाटक	2.88	68	49	6.1	673
केरल	4.01	96	31	4.2	263
मध्य प्रदेश	1.63	94	199	10.2	746
महाराष्ट्र	0.55	75	72	11.5	365
ओडिशा	1.19	83	83	14.1	221
पंजाब	1.42	92	168	14.3	NA <sup>11</sup>
राजस्थान	4.53	64	112	8.4	22,938
तमिलनाडु	1.05	82	21	6.1	198
तेलंगाना	2.26	57	46	7.8	7,316
उत्तर प्रदेश	2.65	96	287	15.6	2,677
उत्तराखंड	2.00	100	532	13.3	NA <sup>10</sup>
पश्चिम बंगाल	0.14	100	134	8.5	560
<b>छोटे राज्य</b>					
अरुणाचल प्रदेश	0.00	100	28	2.0	NA <sup>10</sup>
गोवा	0.00	100	32	4.5	NA <sup>11</sup>
हिमाचल प्रदेश	5.05	94	115	5.9	719
मेघालय	3.99	100	99	7.6	NA <sup>10</sup>
मिजोरम	0.62	70	62	5.0	NA <sup>10</sup>
सिक्किम	28.78	100	31	6.5	NA <sup>10</sup>
त्रिपुरा	1.13	100	103	3.1	1,033
<b>रैंक रहित राज्य</b>					
असम	1.53	100	88	19.0	593
मणिपुर	1.94	40	15	2.1	NA <sup>10</sup>
नागालैंड	5.69	45	14	1.3	250
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.85	25	53	5.0	267
चंडीगढ़	19.74	100	90	7.7	64
दमन और दीव	0.00	100	46	18.5	NA <sup>10</sup>
दिल्ली	5.10	100	58	10.6	832
जम्मू और कश्मीर	5.23	93	155	9.2	262
लद्दाख	0.00	50	20	2.2	NA <sup>10</sup>
लक्षद्वीप	0.00	0	NA <sup>9</sup>	NA <sup>9</sup>	NA <sup>10</sup>
पुडुचेरी	1.14	100	34	3.6	NA <sup>10</sup>

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के निबंधक और महालेखा परीक्षक;

केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पंक्त

9. पीएसआई 0 स्वीकृत और वास्तविक अधिकारियों और कैद कर्मचारियों को दर्शाता है। 10. पीएसआई 0 स्वीकृत और वास्तविक सुधारात्मक स्टाफ दिखाता है। 11. पीएसआई 0 सुधारात्मक स्टाफ दिखाता है

## तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	थीम	कार्यभार		रुझान (ट्रेंड्स)		
		नया				
	प्रति चिकित्सा अधिकारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)	अधिकारी रिक्ति (पीपी, सीवाई '17-' 21)	संवर्ग कर्मचारी रिक्ति (पीपी, सीवाई '17-' 21)	जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (पीपी, सीवाई '17-' 21)	प्रति जेल अधिकारी कैदी (% सीवाई '17-' 21)	
स्कोरिंग गाइड	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	842	-2.13	-1.55	0.83	-1.9	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>						
आंध्र प्रदेश	418 ●	-0.84	0.53	0.53	-0.8	
बिहार	787	-5.38	-4.91	3.26 ●	9.4	
छत्तीसगढ़	1,003	0.53	1.86	0.06	3.4	
गुजरात	593	-1.65	0.36	0.34	-10.8	
हरियाणा	1,271	2.30 ●	2.40 ●	0.11	8.4	
झारखंड	2,657	-0.50	-1.72	0.39	7.7	
कर्नाटक	1,719	-2.24	1.35	2.65	-15.0 ●	
केरल	711	1.48	2.05	-0.19	-2.5	
मध्य प्रदेश	3,032	1.27	-2.91	1.70	7.0	
महाराष्ट्र	1,053	0.63	0.39	0.56	4.2	
ओडिशा	578	-2.72	1.87	0.06	8.7	
पंजाब	934	-2.02	0.74	0.46	-0.8	
राजस्थान	956	-4.45	-4.37	1.77	-6.2	
तमिलनाडु	474	-7.95 ●	-3.82	-0.16	-12.5	
तेलंगाना	610	-1.49	-1.14	1.64	0.0	
उत्तर प्रदेश	1,323	-2.75	-3.82	0.80	-0.9	
उत्तराखंड	6,921 ●	1.82	-6.91 ●	-0.61 ●	23.0 ●	
पश्चिम बंगाल	1,031	1.24	-0.18	0.15	2.7	
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	126 ●	-1.25 ●	-2.00 ●	0.01	3.0	
गोवा	551	3.70	3.56	-0.09	10.1	
हिमाचल प्रदेश	1,438 ●	-0.73	-1.95	0.09	4.3	
मेघालय	218	3.16	3.35	-0.45 ●	10.8	
मिजोरम	NA <sup>13</sup>	1.62	-0.10	2.14 ●	4.5	
सिक्किम	434	1.01	6.08 ●	0.87	-2.7 ●	
त्रिपुरा	344	3.71 ●	2.02	-0.37	17.0 ●	
<b>रैंक रहित राज्य</b>						
असम	1,260	0.88	4.19	0.00	6.0	
मणिपुर	76	-2.88	-4.97	-0.68	-8.9	
नागालैंड	NA <sup>12</sup>	-1.00	0.003	-0.06	5.2	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	267	6.67	3.07	-0.42	8.1	
चंडीगढ़	449	0.00	5.00	-0.29	-6.6	
दमन और दीव	NA <sup>12</sup>	-100.00	5.96	-1.18	17.2	
दिल्ली	166	-5.20	-6.33	-0.54	-4.0	
जम्मू और कश्मीर	414	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	
लद्दाख	NA <sup>13</sup>	NA	NA	NA	NA	
लक्षद्वीप	NA <sup>12</sup>	NA <sup>15</sup>	NA <sup>15</sup>	NA <sup>15</sup>	NA <sup>15</sup>	
पुडुचेरी	305	-5.00	-3.21	0.77	-1.6	

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्क

12. पीएसआई स्वीकृत और वास्तविक चिकित्सा अधिकारी दिखाता है। 13. पीएसआई वास्तविक चिकित्सा अधिकारी दिखाता है। प्रवृत्ति संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बाहर रखा गया है क्योंकि उनका डेटा 5 वर्षों से अलग से उपलब्ध नहीं था। पीएसआई प्रवृत्ति संकेतकों के लिए विचार किए गए सभी 5 वर्षों के लिए 0 स्वीकृत और वास्तविक कुल कर्मचारी दिखाता है।

## तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	थीम	रुझान (ट्रेंड्स)				
	प्रति संवर्ग कर्मचारी कैदी (% सीवाई '17-' 21)	विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (पीपी, सीवाई '17-' 21)	प्रति कैदी खर्च करें (% वित्त वर्ष '18-' 22)	उपयोग किया गया जेल बजट (पीपी, वित्त वर्ष '18-' 22)	खर्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (पीपी, वित्त वर्ष '17-' 21)	
स्कोरिंग गाइड	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	1.3	1.88	5.7	-0.44	-3.82	
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>						
आंध्र प्रदेश	3.9	1.89	75.0	3.96	-5.48	
बिहार	6.1	1.05	-0.3	-2.16	1.57	
छत्तीसगढ़	3.7	1.13	4.1	-1.16	6.08	
गुजरात	4.4	1.25	-2.9	-0.56	16.66 ●	
हरियाणा	8.8 ●	3.28	116.9 ●	-0.85	-0.64	
झारखंड	-0.5	0.43 ●	12.0	2.33	5.79	
कर्नाटक	-9.2 ●	0.96	6.8	0.34	6.26	
केरल	0.4	1.74	9.9	0.13	-0.75	
मध्य प्रदेश	0.7	1.04	-3.2	0.26	-1.97	
महाराष्ट्र	3.8	2.80	-5.8	-0.16	-1.59	
ओडिशा	8.8	2.08	-4.6	-0.15	-7.86	
पंजाब	3.6	3.75 ●	0.8	0.95	-8.61	
राजस्थान	-3.5	1.10	4.8	1.80	-4.49	
तमिलनाडु	2.4	2.06	6.2	1.00	-3.03	
तेलंगाना	4.5	0.49	16.9	4.43 ●	-11.99 ●	
उत्तर प्रदेश	-0.3	1.03	-3.2	-3.42 ●	-11.39	
उत्तराखंड	-0.9	2.92	-10.6 ●	1.65	-8.43	
पश्चिम बंगाल	2.6	3.71	-0.04	-0.39	2.12	
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	1.1	-3.26 ●	30.9	-0.07	-4.65	
गोवा	7.3	5.23 ●	-20.6 ●	5.85 ●	-19.20 ●	
हिमाचल प्रदेश	-2.3 ●	2.10	-7.6	-1.24 ●	2.04	
मेघालय	7.6	-1.93	37.4 ●	1.15	-10.31	
मिजोरम	2.6	1.53	4.3	0.26	-7.65	
सिक्किम	7.8 ●	1.82	3.4	-1.14	12.68 ●	
त्रिपुरा	6.7	3.74	4.6	3.83	-9.26	
<b>रैंक रहित राज्य</b>						
असम	8.8	3.02	-7.2	-1.08	8,061.98	
मणिपुर	4.1	0.03	9.1	-3.47	-3.01	
नागालैंड	6.1	-1.29	-0.5	0.07	1.00	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.4	3.42	17.0	0.00	30.57	
चंडीगढ़	-0.3	5.88	15.6	0.00	3.76	
दमन और दीव	19.2	1.15	22.0	11.43	-4.79	
दिल्ली	-2.3	2.65	30.1	0.00	11.81	
जम्मू और कश्मीर	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	NA <sup>14</sup>	
लद्दाख	NA	NA	NA	NA	NA	
लक्षद्वीप	NA <sup>15</sup>	NA <sup>15</sup>	NA <sup>15</sup>	0.00	NA <sup>16</sup>	
पुडुचेरी	2.8	-0.84	-7.4	0.52	51.25	

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्क

14. प्रवृत्ति संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बाहर रखा गया है क्योंकि उनका डेटा 5 वर्षों से अलग से उपलब्ध नहीं था। पीएसआई प्रवृत्ति संकेतकों के लिए विचार किए गए सभी 5 वर्षों के लिए 0 स्वीकृत और वास्तविक कुल कर्मचारी दिखाता है। 16. विचाराधीन 5 वर्षों में से 2 वर्षों के लिए जेल व्यय 0 दिखाया गया था।





**न्यायपालिका**

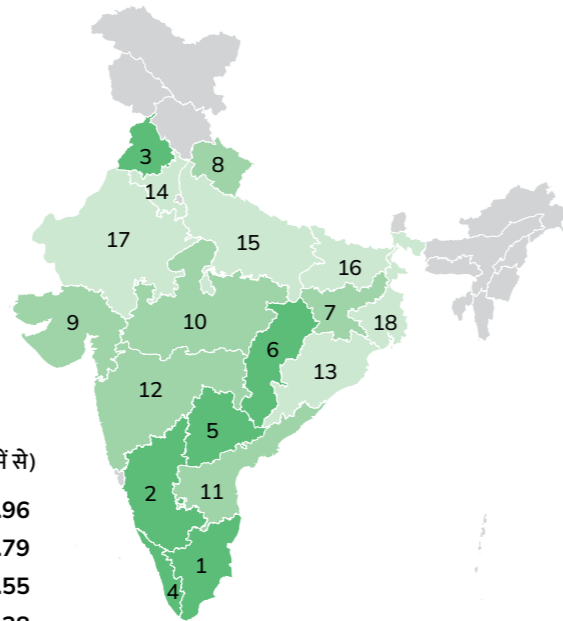
# न्यायपालिका की रैंकिंग

रंग गाइड  
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक (IJR 3) **28**

समूह (क्लस्टर)

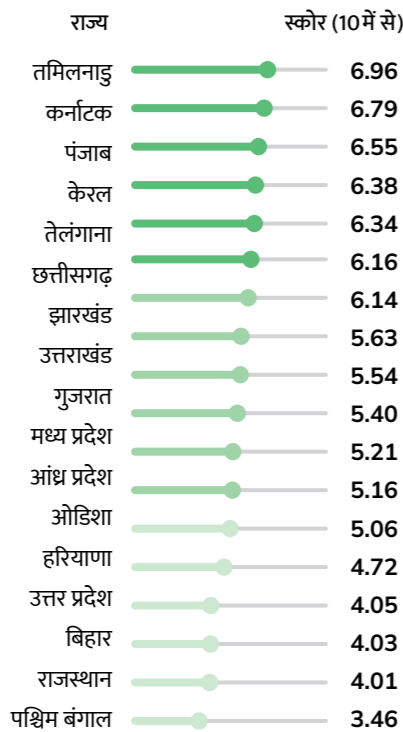
- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ तक)



## मानचित्र 13: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

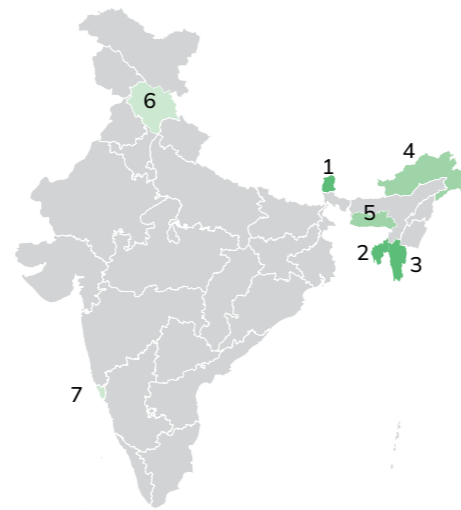
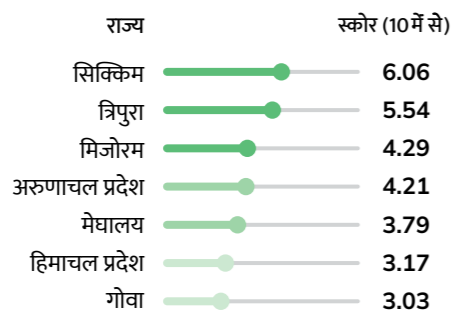
आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
16	12	2
2	2	3
5	3	4
11	6	5
12	4	6
14	9	7
15	13	8
7	8	9
6	11	10
13	14	11
4	5	12
9	15	13
3	7	14
17	17	15
18	18	16
8	10	17
10	16	18



## मानचित्र 14: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
6	6	2
5	3	3
7	5	4
4	7	5
3	2	6
2	4	7



# उम्मीदें बढ़ाना

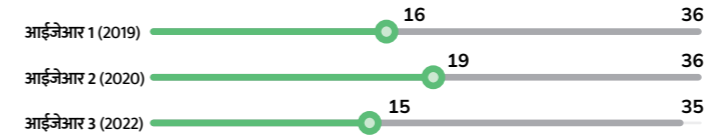
### न्यायाधीश रक्ति: उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयों की संख्या जहां न्यायाधीश रक्ति 20 प्रतिशत से कम है।



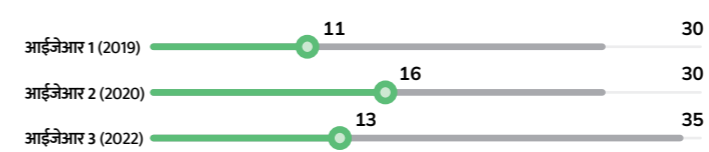
### न्यायाधीश रक्ति: अधीनस्थ न्यायालय

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश की रक्ति 20 प्रतिशत से कम है।



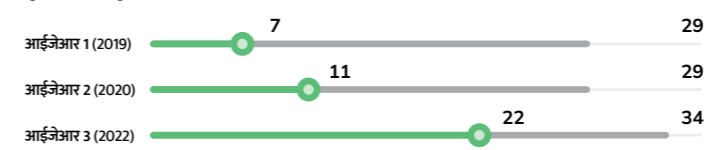
### न्यायालय

उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां स्वीकृत न्यायाधीशों के खिलाफ अदालतों की कमी 10 प्रतिशत से कम है।



### बजट

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां न्यायपालिका द्वारा खर्च में वृद्धि राज्य के कुल खर्च में वृद्धि से अधिक है।



### मामलों के निपटारे की दर

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों स्तरों पर 100% से अधिक मामलों के निपटारे की दर वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या।



\*राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या (36 में से) जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे।

### महिलाएं

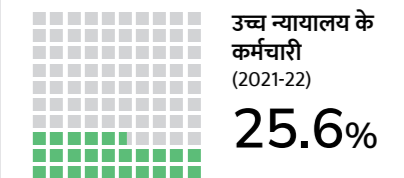
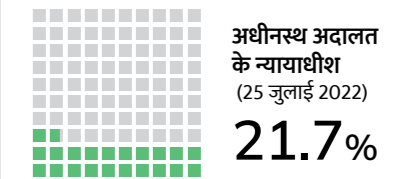
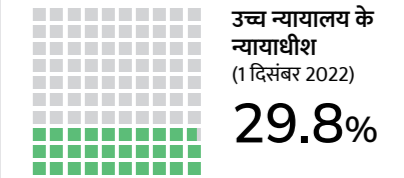
उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का हिस्सा (दिसंबर 2022)

**13.1%**



पाँच राज्यों (बिहार, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय) के उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

### रक्ति: राष्ट्रीय औसत



### जाति विविधता

किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने तीनों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को पूरा नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालयों में **3/10**



उच्च न्यायालयों में **5/10**



अधीनस्थ न्यायालयों में 10 में से लगभग 3 मामले और उच्च न्यायालयों में 10 में से 5 मामले 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

## अध्याय 3

# न्यायपालिका: संख्याओं को आंकना

2022 के अंत में, क्षमता की कमी के कारण न्याय देने के लिए अदालतों की समग्र क्षमता बाधित रही। राज्यों में औसतन उच्च न्यायालय स्तर पर न्यायिक रिक्तियां 29.8 प्रतिशत और उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों की रिक्तियां 25.6 प्रतिशत हैं। जिला अदालतों में 21.7 प्रतिशत न्यायिक पद भरे नहीं गए। 2020 और 2022 के बीच, लंबित मामलों की संख्या 4.1 से बढ़कर 4.9 करोड़ हो गई, जिनमें से 69 प्रतिशत आपराधिक मामले थे। जिला अदालतों में, औसतन मामले निपटारे की दर<sup>1</sup> 3.6 प्रतिशत अंक<sup>2</sup> कम हो गई और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले अदालत कक्ष 14.7 प्रतिशत<sup>3</sup> कम थे। सकारात्मक पक्ष पर, न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति व्यय में थोड़ा सुधार हुआ, उच्च न्यायालयों ने औसत मामले निपटान दरों में सुधार किया 6.1 प्रतिशत अंक<sup>4</sup> और विविधता तथा समावेशन ने धीमी प्रगति पर स्वागत योग्य संकेत दिया।

## रैंकिंग

लगातार तीसरी बार, तमिलनाडु ने बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। कर्नाटक ने सबसे अधिक सुधार किया और बारहवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। राज्य में सुधारों में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की रिक्तियों को 50 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करना, अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी बढ़ाना और प्रति व्यक्ति खर्च में सुधार करना शामिल है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय और जिला अदालत के स्तर पर न्यायाधीशों की लगातार रिक्तियों के कारण, कोर्ट हॉल की कमी के कारण, राजस्थान दसवें से सत्रहवें स्थान पर सात पायदान नीचे चला गया; जबकि उच्च न्यायालय कर्मचारियों की रिक्तियों में वृद्धि के कारण पंजाब एक स्थान फिसलकर दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया।

सात छोटे राज्यों में सिक्किम ने भी अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। जिला अदालतों में न्यायाधीशों की रिक्तियों और उच्च न्यायालयों में कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने में राज्य के प्रयासों, जिला अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और उच्च न्यायालय में मामले निपटारे की दर में वृद्धि के कारण त्रिपुरा छठे से दूसरे स्थान पर

पहुंच गया है। मेघालय ने भी अपने प्रति व्यक्ति खर्च में सुधार करके, न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरकर और जिला अदालतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी रैंक को सातवें से पांचवें स्थान पर सुधार लिया है।

इसके विपरीत, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की रिक्तियों में वृद्धि के साथ-साथ निकासी दरों में कमी और अदालत कक्षों की कमी ने हिमाचल प्रदेश को दूसरे से छठे स्थान पर धकेल दिया, जबकि उच्च न्यायालय और जिला अदालत दोनों स्तरों पर न्यायाधीशों की रिक्तियों में वृद्धि, महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी में कमी और उच्च न्यायालय स्तर पर मामले की निपटान दर में कमी के कारण गोवा चौथे से सातवें स्थान पर खिसक गया।

## बजट

न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति खर्च (₹. 2020-21)  
खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (पीपी,  
वित्तीय वर्ष '17-'21)

बजट में कमी को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस वित्तीय दायित्व का बड़ा हिस्सा राज्यों का है, जबकि केंद्र राज्य न्यायपालिका के बजट में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देता है। दो केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, कोई भी राज्य न्यायपालिका पर अपने कुल वार्षिक व्यय का 1 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करता है। कुल राज्य व्यय के प्रतिशत के रूप में न्यायपालिका पर व्यय का हिस्सा राज्यों में काफी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, पंजाब (0.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (0.6 प्रतिशत) और झारखंड (0.6 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ (0.37 प्रतिशत)<sup>6</sup> की तुलना में दो या तीन गुना अधिक खर्च करते हैं।

## कोविड-19 प्रभाव

“मैं इस रवैये से बहुत व्यथित हूँ... हमने जो भी पैसा खर्च किया है, वे आभासी सुनवाई के लिए हमारे द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे को खत्म कर रहे हैं... आप एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रौद्योगिकी में रुचि ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप न्याय तक पहुंच के मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक धन को खर्च करने के लिए बाध्य हैं... क्षमा करें, प्रौद्योगिकी महामारी के लिए कुछ नहीं है। प्रौद्योगिकी यहाँ भविष्य के लिए, हमेशा के लिए रहने के लिए है।”

—**डी.वाई. चंद्रचूड़**, भारत के मुख्य न्यायाधीश, फरवरी 2023

COVID-19 महामारी और 2020 और 2021 के लॉकडाउन ने पूरे भारत में अदालती प्रणालियों में बड़े व्यवधान पैदा किए। मार्च 2020 के मध्य में, उच्चतम न्यायालय<sup>7</sup> ने निर्देश दिया कि अदालतें केवल अत्यावश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें। हर स्तर पर न्याय तक सीमित पहुंच के परिणामस्वरूप दाखिल याचिकाओं में कमी आई, साथ ही मौजूदा बैकलॉग में भी तेजी से वृद्धि हुई। उदाहरण

के तौर पर, जिला अदालतों में मामलों की स्थापना में पिछले वर्षों की तुलना में 32 प्रतिशत और निपटान में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है। विश्लेषण किए गए 642 जिला अदालतों में से केवल 40 अदालतों में महामारी के वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या में कमी नहीं देखी गई। 9 दूसरी तरफ, महामारी ने न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया: मई 2020 में ई-कोर्ट समिति द्वारा मॉडल ई-फाइलिंग नियमों का मसौदा तैयार किया गया और जून 2020<sup>10</sup> में अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को सूचित किया गया। 1 मार्च 2020 से 21 मई 2021 तक, जिले के माध्यम से ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या अदालत और उच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग आवेदन क्रमशः 90,190 और 11,810 मामले थे।<sup>11</sup> ई-भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक समन और राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रेकिंग (एनएसटीईपी) जैसे ट्रेकिंग ऐप्स संभावित रूप से नई दक्षता दिखाते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल सुनवाई संभव की गई थी। हालांकि, सभी अचानक नवप्रवर्तन के साथ, उठाव असमान था। बार और बेंच प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व के नए तरीकों से अपरिचित थे, और उनकी पहुंच इंटरनेट पहुंच, कनेक्टिविटी और नियमित बिजली आपूर्ति पर निर्भर थी।

**खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य:** वित्त वर्ष 2017-2021 के बीच, 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों<sup>12</sup> में, न्यायपालिका पर व्यय में वृद्धि समग्र राज्य व्यय में वृद्धि के साथ बनी रही। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में क्रमशः 10.57 और 8.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>13</sup> में न्यायपालिका पर खर्च में कमी पाई गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे नवगठित राज्यों में, न्यायपालिका व्यय में वृद्धि क्रमशः 5.2 और 0.97 प्रतिशत अंक से पिछड़ गई।

2022 में, न्यायपालिका पर कुल राष्ट्रीय खर्च औसतन ₹. प्रति व्यक्ति के हिसाब से 146 रुपये की बढ़ोतरी। 2015-16 से 42। ग्यारह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>14</sup> ने राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। सिक्किम, जहां पिछले साल पहले से ही प्रति व्यक्ति खर्च काफी अधिक था - (496 रुपये) - ने इसे और अधिक (139 रुपये) बढ़ाकर 635 रुपये कर दिया। यह पश्चिम बंगाल के खर्च (75 रुपये) से आठ गुना अधिक है। आंध्र प्रदेश (145 रुपये) और बिहार (83 रुपये) ने अपने खर्च में केवल

रुपये 24 और ₹.16 क्रमशः की वृद्धि की।

## मानव संसाधन

उच्च न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या (1 दिसंबर 2022)  
अधीनस्थ न्यायालय के प्रति न्यायाधीश जनसंख्या  
(25 जुलाई 2022)  
हाई कोर्ट में जज की वैकेंसी (%), 1 दिसंबर 2022)  
अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के रिक्त पद  
(%, 25 जुलाई 2022)  
उच्च न्यायालय स्टाफ रिक्ति (%), 2021-22)  
न्यायाधीश रिक्ति (उच्च न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)  
न्यायाधीश रिक्ति (उप न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

न्यायाधीशों की रिक्तियाँ स्थानिक बनी हुई हैं। पांच वर्षों में देखा जाए तो 6 उच्च न्यायालयों<sup>15</sup> और 14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>16</sup> की जिला

1 केस क्लीयरेंस दर एक वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या है, जिसे उस वर्ष दायर की गई संख्या के मुकाबले मापा जाता है।

2 93.0 प्रतिशत से 89.4 प्रतिशत।

3 न्याय विकास पोर्टल, 31.08.2022, 2022 तक कोर्ट हॉल की राज्य-वार उपलब्धता का विवरण। यहां उपलब्ध है: [https://bhuvan-nyayavikas.nrsr.gov.in/assets/files/ch\\_info.pdf](https://bhuvan-nyayavikas.nrsr.gov.in/assets/files/ch_info.pdf)

4 88.5 फीसदी से 94.76।

5 बजट और शासन जवाबदेही केंद्र और दक्ष, भारत में न्यायपालिका के लिए बजट पर पंद्रहवें वित्त आयोग को ज्ञापन, 2019। यहां उपलब्ध है: <https://www.dakshindia.org/wp-content/uploads/2019/06/Memorandum-on-Budgeting-for-Judiciary-in-India-from-CBGA-Website.pdf>

6 भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कुल राज्य व्यय के लिए न्याय प्रशासन का व्यय, 2020-2021।

7 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अधिसूचना दिनांक 13.03.2020, 2020। यहां उपलब्ध है: [https://main.sci.gov.in/pdf/Notification/13032020\\_120544.pdf](https://main.sci.gov.in/pdf/Notification/13032020_120544.pdf)

8 विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, डेटा स्पीक: महामारी के दौरान जिला न्यायालयों के प्रदर्शन पर एक नज़र, 2022। यहां उपलब्ध है: <https://vidihlegalpolicy.in/research/data>

9 पूर्वोक्त

10 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ई-कमेटी न्यूजलेटर, जून 2020। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2020/08/2020081415.pdf>

11 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21। यहां उपलब्ध है: [https://main.sci.gov.in/pdf/AnnualReports/12012022\\_114003.pdf](https://main.sci.gov.in/pdf/AnnualReports/12012022_114003.pdf)

12 मणिपुर, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, नागालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी

13 तेलंगाना, केरल, पंजाब, सिक्किम, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मिजोरम।

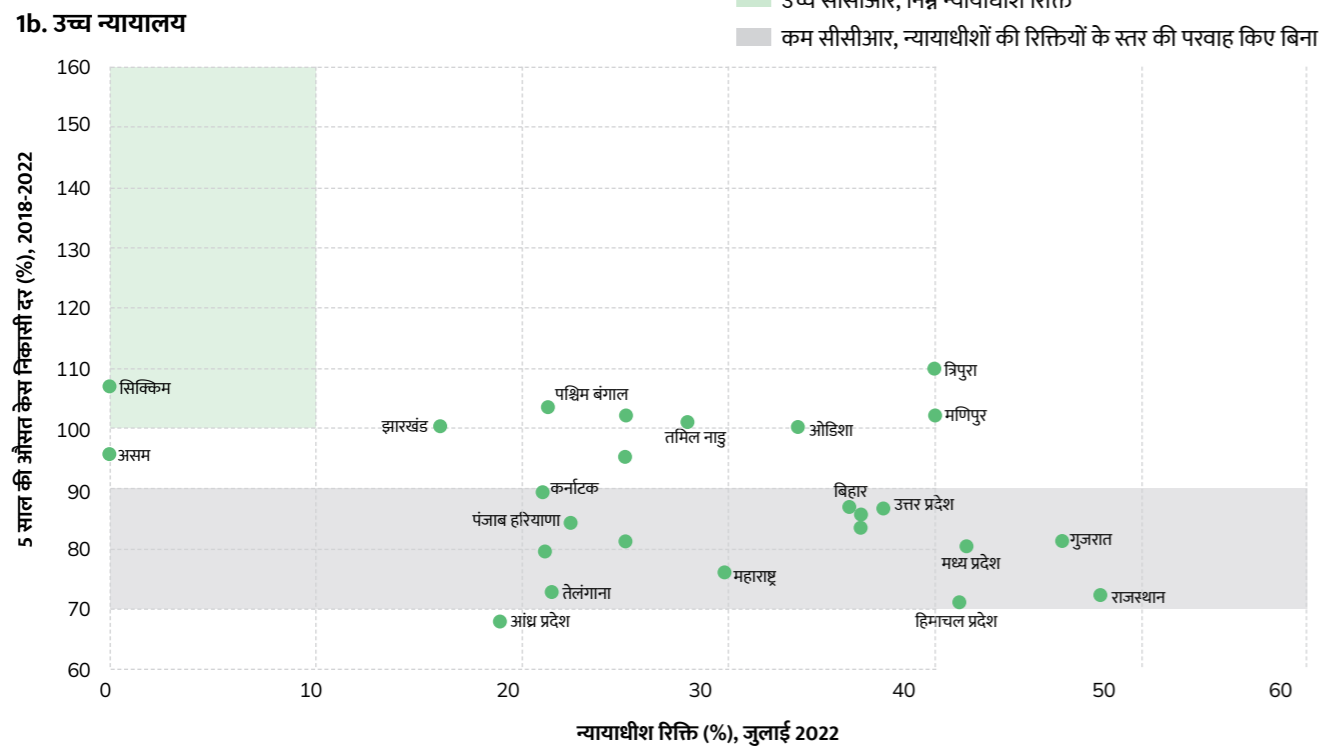
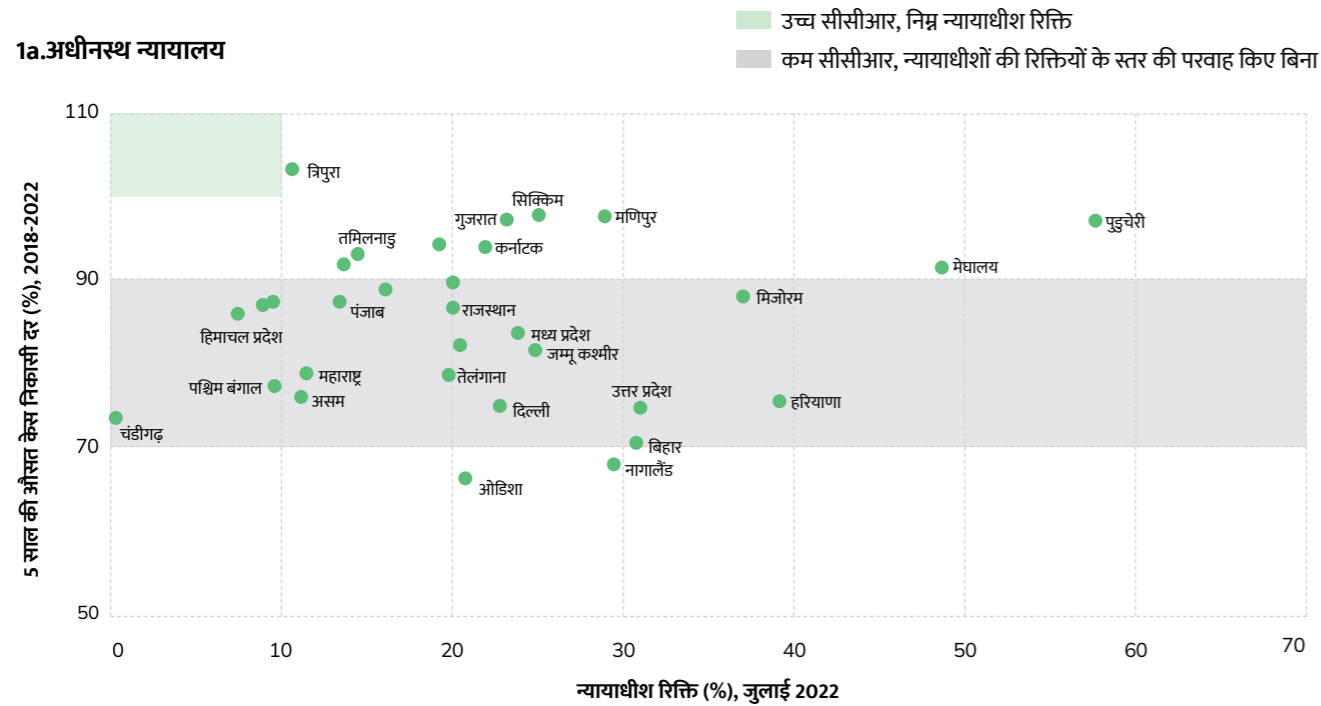
14 आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, डीएनएच और डीडी।

15 पटना, गुजरात, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, उत्तराखंड, राजस्थान।

16 केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश (3-वर्षीय रुझान), डीएनएच और डीडी

### चित्र 26: न्यायाधीशों की रिक्तियां और मामले की मंजूरी दर

भारतीय अदालतों में मुकदमों से खचाखच भरी हुई हैं और उनमें दिन-ब-दिन लंबित मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही वे स्वीकृत संख्या से कम जजों के साथ भी काम कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों दोनों में, जो अदालतें लंबित मामलों में वृद्धि दर्ज कर रही हैं, वे अपने रिक्ति स्तर की परवाह किए बिना ऐसा कर रही हैं।



उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समान मूल्य होगा। चित्र में केवल प्रमुख अवस्था दिखाई गई है। इस प्रकार, असम (लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड नहीं), केरल (लक्षद्वीप), महाराष्ट्र (गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव), पंजाब और हरियाणा (चंडीगढ़), तमिलनाडु (पुडुचेरी), पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) को दिखाया गया है। स्रोत: न्याय विभाग और लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं. 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

अदालतों में रिक्तियां बढ़ी हैं। 2018- 2019 से 2022 तक, राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च न्यायालय की रिक्तियां 37.8 प्रतिशत से 8 प्रतिशत अंक घटाकर 29.8 प्रतिशत हो गईं, लेकिन फिर भी 30 प्रतिशत के आसपास रहीं।

जिला अदालतों में रिक्तियाँ केवल मामूली रूप से कम हुईं - 22.3 से 21.7 प्रतिशत। राज्यवार, प्रवृत्ति एक समान नहीं थी। उच्च न्यायालय स्तर पर सिक्किम अपनी सभी रिक्तियों को भर सकता है जबकि आंध्र प्रदेश ने अपनी रिक्तियों को 70.3 प्रतिशत से घटाकर 18.9 प्रतिशत कर दिया है। हालाँकि, त्रिपुरा और उत्तराखंड में रिक्तियों में क्रमशः 15 और 11.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>17</sup>

में उच्च न्यायालय अपनी स्वीकृत बेंच शक्ति की एक-चौथाई के बिना काम कर रहे थे, जबकि राजस्थान और गुजरात दोनों - क्रमशः 48 प्रतिशत और 46.2 प्रतिशत की कमी के साथ - आधे से अधिक के साथ काम कर रहे थे।

जिला अदालतों में भी रिक्तियाँ पुरानी बनी हुई हैं। 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का 25 प्रतिशत नियुक्त<sup>18</sup> नहीं किया गया था, सबसे अधिक रिक्तियां पुडुचेरी (57.7 प्रतिशत), मेघालय (48.5 प्रतिशत) और हरियाणा (39 प्रतिशत) में हैं।

### न्यायाधीश की दुविधा

प्रश्न यह है कि कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है दशकों तक व्यापक रूप से बहस हुई।

- 1987:** 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट<sup>19</sup> का प्रस्ताव एक विधि के रूप में न्यायाधीश-से-जनसंख्या अनुपात जज की ताकत की गणना करें.
- 2002:** संसदीय स्थिति<sup>20</sup> की 85वीं रिपोर्ट समिति की वृद्धि की सिफारिश करती है न्यायाधीश-जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीश अनुपात।
- 2012:** इम्तियाज अहमद बनाम यूपी राज्य<sup>21</sup>, में उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग से उस आधार पर सिफारिशें देने को कहा जिसके आधार पर बढ़ते बैकलॉग से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- 2014:** विधि आयोग<sup>22</sup> की 245वीं रिपोर्ट निपटान पद्धति की दर प्रस्तावित करता है।
- 2016:** राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस)<sup>23</sup>

न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने की एक विधि के रूप में इकाई प्रणाली पर आधारित एक अंतरिम मॉडल का प्रस्ताव करता है।

**2017:** उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट को खारिज कर दिया और एनसीएमएस इकाई प्रणाली-आधारित मॉडल के अंतरिम कार्यान्वयन का निर्देश दिया।

1987 से, जब भारत का विधि आयोग पहली बार जनसंख्या<sup>24</sup> को एक आवश्यक मीट्रिक के रूप में प्रस्तावित किया गया

पर्याप्त जज संख्या तक पहुंचने के लिए, 'जज-टू- 'जनसंख्या अनुपात' को आम तौर पर स्वीकार किया गया है आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने में मानदंड। 1987 में, आयोग ने सिफारिश की कि प्रति 10 लाख (1 मिलियन) जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीश हों प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों तक की वृद्धि अगले पांच से दस साल<sup>25</sup>. दिसंबर 2022 तक, मार्च 2022<sup>26</sup> के लिए जनसंख्या अनुमान के आधार पर भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 न्यायाधीश हैं प्रति 10 लाख पर 19 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति जनसंख्या और 4.8 करोड़ मामलों का बैकलॉग।

### कुल न्यायाधीश, स्वीकृत और वास्तविक

न्यायाधीशों की संख्या	जिला न्यायालय (जुलाई 2022)		उच्च न्यायालय (दिसंबर 2022)		उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2022)	
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
न्यायाधीशों की संख्या	24,631	19,288	1,108	778	34	27
प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या	17.93	14.04	0.81	0.57	0.02	0.02

नोट: प्रत्येक कोर्ट प्रकार और मीट्रिक के लिए अलग-अलग तराजू का उपयोग किया गया है। स्रोत: न्याय विभाग और लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं। 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

17 पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान।  
 18 पुडुचेरी, मेघालय, हरियाणा, मिजोरम, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम  
 19 भारतीय विधि आयोग, न्यायपालिका में जनशक्ति नियोजन पर एक सौ बीसवीं रिपोर्ट: एक ब्लूप्रिंट, 1987। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf>  
 20 गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति, कानून की देरी पर 85 वीं रिपोर्ट: न्यायालयों में बकाया, 2002। यहां उपलब्ध है: [http://164.100.47.5/rs/book2/reports/home\\_aff/85threport%20.htm](http://164.100.47.5/rs/book2/reports/home_aff/85threport%20.htm)  
 21 इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 254-262, 2012 (43, 36)।  
 22 भारतीय विधि आयोग, बकाया और बैकलॉग: अतिरिक्त न्यायिक (महिला) जनशक्ति का निर्माण, 2014, रिपोर्ट संख्या 245, पृष्ठ। 20. यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081643.pdf>  
 23 राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या की गणना के लिए नोट, 2016। यहां उपलब्ध है: [https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/NCMs\\_1.pdf](https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/NCMs_1.pdf)  
 24 भारतीय विधि आयोग, 120 वीं रिपोर्ट: भारत में जनशक्ति नियोजन: एक न्यायिक खाका, 1987। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf>  
 25 Ibid.  
 26 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, नवंबर 2019 में जुलाई 2020 के लिए भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण (2011 से 2036)। यहां उपलब्ध है: [https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202021-2036%20-%20upload\\_compressed\\_0.pdf](https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202021-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf)

सुचारू न्यायिक कामकाज के लिए न्यायालय कर्मचारी अपरिहार्य हैं और रिक्तियां न्यायिक क्षमता में काफी बाधा डालती हैं। उच्च न्यायालयों में अदालती कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय औसत रिक्ति 25.6 प्रतिशत थी, जो 2018-19 में 23.8 प्रतिशत और 2016-17 में 22.9 प्रतिशत से लगातार वृद्धि है। आंध्र प्रदेश, जिसे 2019 में नया उच्च न्यायालय मिला, वहां 51.2 प्रतिशत रिक्तियां हैं। 2018-19 और 2021-2022 के बीच बिहार के उच्च न्यायालय कर्मचारियों की रिक्तियां 26.3 प्रतिशत से दोगुनी होकर 52.8 प्रतिशत हो गई हैं।

**भूमिकारूप व्यवस्था**

कोर्ट हॉल की कमी(%), 25 जुलाई 2022, 31 अगस्त 2022)

आदर्श रूप से, प्रत्येक न्यायाधीश के लिए एक न्यायालय कक्ष होना चाहिए। अगस्त 2022 में, उस समय स्वीकृत 24,631 न्यायाधीशों के पदों के लिए 21,014 कोर्ट हॉल थे - 14.7 प्रतिशत की कमी, हालांकि 2016-17 के 18.2 प्रतिशत से सुधार हुआ। यदि प्रत्येक राज्य अपने स्वीकृत न्यायाधीशों में से प्रत्येक को नियुक्त करता है, तो केवल 4 राज्यों<sup>27</sup> और 4 केंद्रशासित प्रदेशों<sup>28</sup> में पर्याप्त न्यायालय कक्ष होंगे। 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>29</sup> में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी होगी। अरुणाचल प्रदेश (21 प्रतिशत से 37 प्रतिशत), हरियाणा (16 प्रतिशत से 28 प्रतिशत) और तमिलनाडु (2 प्रतिशत से 9 प्रतिशत) में, कमी मुख्य रूप से स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण बढ़ी। 46.5 प्रतिशत के साथ मेघालय में सबसे अधिक कमी थी।

राष्ट्रीय स्तर पर, न्यायालय कक्षों की संख्या वास्तविक न्यायाधीशों की संख्या के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। हालाँकि, यदि सभी स्वीकृत पद

**डाटा मिसमैच**

जनवरी 2020<sup>30</sup> में सिक्किम में 23 स्वीकृत निचली अदालत के न्यायाधीशों के मुकाबले 25 कोर्ट हॉल थे, लेकिन अगस्त 2022 में 28 स्वीकृत न्यायाधीश थे, लेकिन कोर्ट हॉल की संख्या घटकर 20<sup>31</sup> हो गई। इसी तरह, 2020 में हिमाचल प्रदेश में 162 न्यायाधीशों के लिए 160 कोर्ट हॉल थे। 2022 के मध्य तक, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 175 हो गई लेकिन अदालत कक्षों की संख्या घटकर 151 रह गई।

27 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र।  
 28 चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, लक्षद्वीप, पुदुचेरी  
 29 उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख  
 30 लोकसभा उत्तर, बजट सत्र - 17वीं लोकसभा का तीसरा सत्र, 2020। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbsrs.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2022/09/2022090116.pdf>  
 31 न्याय विकास पोर्टल, 31.08.2022, 2022 तक कोर्ट हॉल की राज्य-वार उपलब्धता का विवरण। यहां उपलब्ध है: [https://shuvan-nyayavikas.nrsnc.gov.in/assets/files/ch\\_info.pdf](https://shuvan-nyayavikas.nrsnc.gov.in/assets/files/ch_info.pdf)  
 32 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 'पिछले 5 वर्षों में उच्च न्यायालयों में पिछड़े समुदायों से केवल 15 प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त किए गए: न्याय विभाग से सममूल्य पैनाल', इकोनॉमिक टाइम्स, 2023। यहां उपलब्ध है: [https://economicstimes.com/news/india/only-15-pc-judges-appointed-to-hcs-in-last-5-yrs-from-backward-communities-dept-of-justice-to-par-panel/articleshow/96661214.cms?utm\\_source=twitter](https://economicstimes.com/news/india/only-15-pc-judges-appointed-to-hcs-in-last-5-yrs-from-backward-communities-dept-of-justice-to-par-panel/articleshow/96661214.cms?utm_source=twitter)  
 33 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित छह समुदाय ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन हैं।

सिक्किम और गौहाटी उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर कोई भी अदालत न्यायाधीशों के पूर्ण पूरक के साथ काम नहीं करती है। औसतन, 17.7 लाख (1.77 मिलियन) लोगों पर एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश और 71000 लोगों पर एक अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश है। जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 9.3 लाख लोगों पर एक न्यायाधीश है, वहीं पटना उच्च न्यायालय में 36.7 लाख लोगों पर एक न्यायाधीश है।

भरे जाते हैं तो जगह की समस्या हो जाएगी। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में क्रमशः 86, 82 और 35 सेवारत न्यायाधीशों के लिए कोई कोर्ट हॉल नहीं थे।

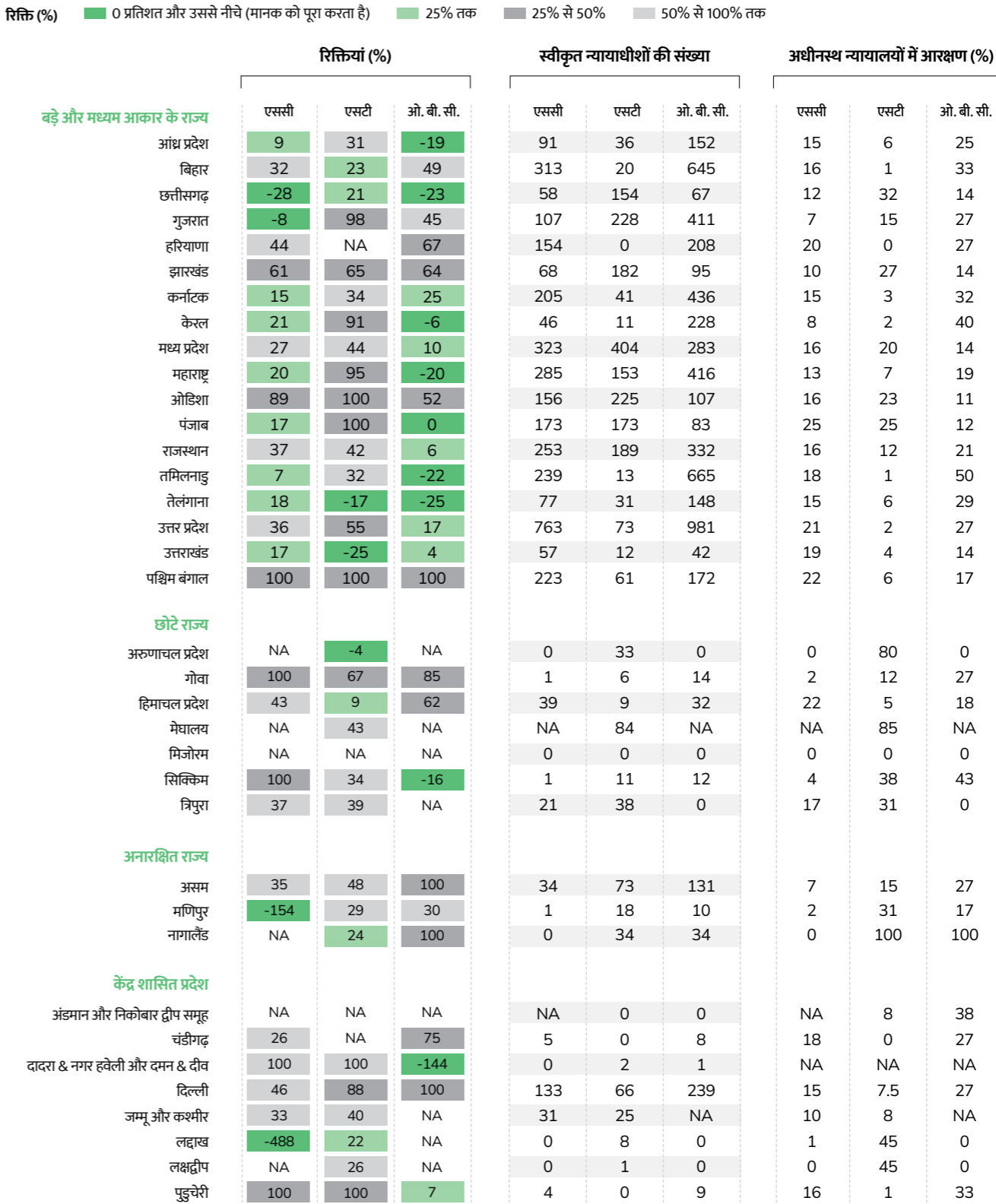
राज्यों के कानून और नीतियां सार्वजनिक संस्थानों में लिंग और जाति के आधार पर और हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करते हैं। जाति-आधारित आरक्षण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है, और नीतिगत प्रावधान महिलाओं को आकांक्षी न्यूनतम 33 प्रतिशत तक शामिल करने का सुझाव देते हैं।

**विविधता**

एससी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय; 25 जुलाई 2022)	<b>नया</b>
एसटी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय; 25 जुलाई 2022)	<b>नया</b>
ओबीसी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय; 25 जुलाई 2022)	<b>नया</b>
महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (%), 1 दिसंबर 2022)	
महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (%), 25 जुलाई 2022)	

उच्च न्यायालयों में जाति विविधता पर राज्य-वार डेटा अनुपलब्ध है। हालाँकि, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति को दी गई न्याय विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "2018 से दिसंबर 2022 तक, उच्च न्यायालयों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से 1.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 2.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 11 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से और 2.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों<sup>33</sup> से थे।"

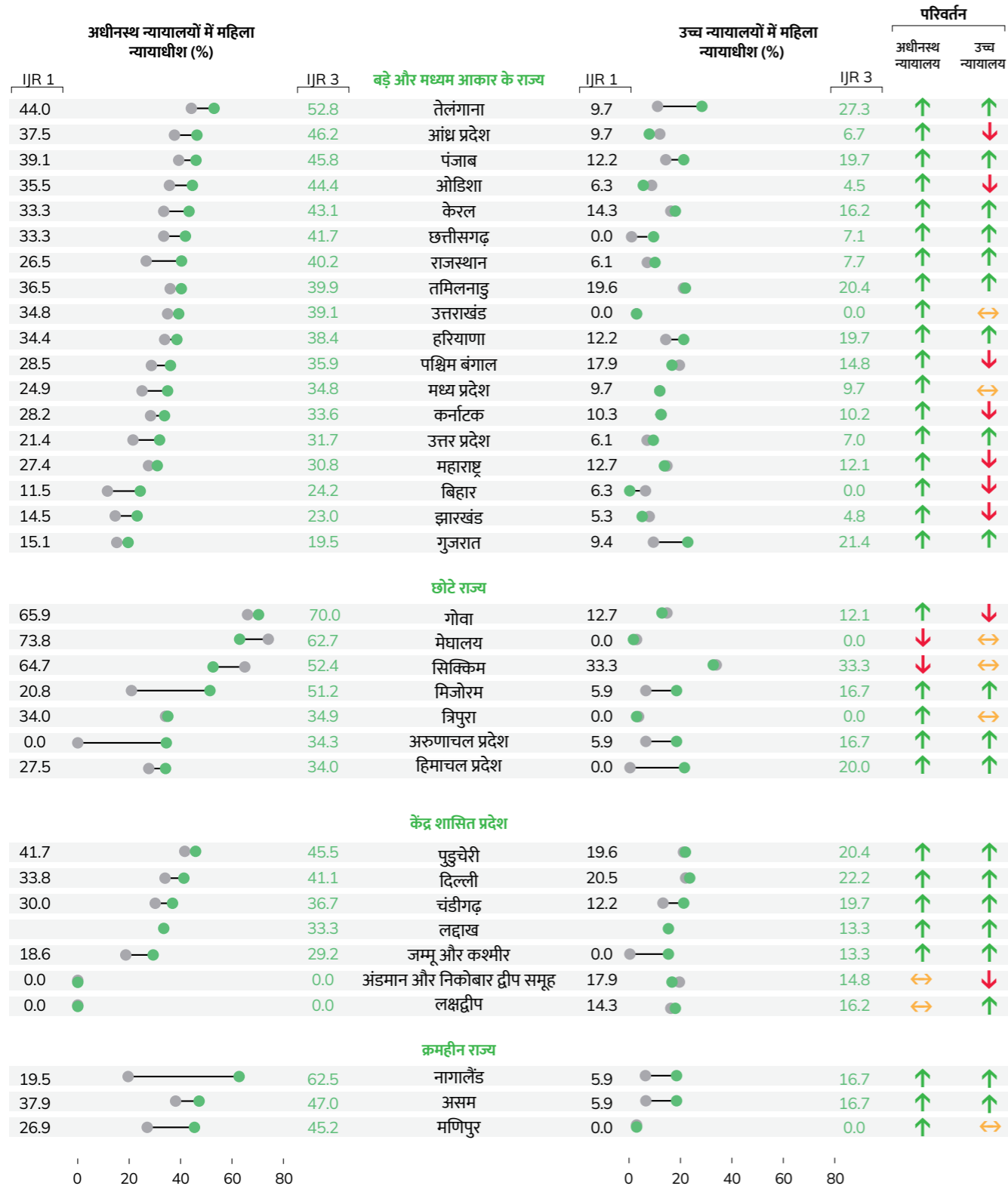
**चित्र 27: अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों की रिक्तियां**



टिप्पणी: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 2. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम में कोई आरक्षण नहीं है और कोई एससी न्यायाधीश नहीं है। 3. मेघालय में अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष आरक्षण स्वीकृत नहीं है। एसटी न्यायाधीश 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जनजाति न्यायाधीश नहीं है। 2. मिजोरम में एसटी आरक्षण नहीं है। 3. चंडीगढ़ और हरियाणा में कोई आरक्षण नहीं है और कोई अनुसूचित जनजाति न्यायाधीश नहीं है। 4. नागालैंड के लिए न्याय विभाग की वेबसाइट से लिया गया एसटी न्यायाधीशों का डेटा। ओ. बी. सी. न्यायाधीश 1. अरुणाचल प्रदेश में ओ. बी. सी. आरक्षण नहीं है। 2. मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप और त्रिपुरा में कोई आरक्षण नहीं है और कोई अन्य पिछड़ा वर्ग न्यायाधीश नहीं है। 3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई ओ. बी. सी. न्यायाधीश नहीं है। 4. जम्मू और कश्मीर में एससी श्रेणी उपलब्ध नहीं है। 4. मेघालय में ओ. बी. सी. के लिए कोई विशेष आरक्षण स्वीकृत नहीं है। डी. एन. एच. और डी. डी.: दादरा और नगर हवेली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 2 प्रतिशत, 43 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। दमन और दीव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 3 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है। स्रोत लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं. 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

### चित्र 28: महिला न्यायाधीश

अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी कम है। सिक्किम में सबसे अधिक 33.3% है।



टिप्पणी: 1. जून 2018 के लिए आई. जे. आर. 1 के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जुलाई 2017 के लिए या अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों के लिए डेटा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जुलाई 2022 के लिए या अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों के लिए दिसंबर 2022 के लिए आईजेआर 3 के लिए डेटा। 2. राज्यों को अधीनस्थ न्यायालयों में हिस्सेदारी के अक्टोबरी मूल्य में संबंधित समूह के भीतर व्यवस्थित किया गया है। 3. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को नहीं दिखाया गया। स्रोत न्याय विभाग और लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं. 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

जिला-अदालत स्तर पर कोई भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका। नौ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>34</sup> ने अपना अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा पूरा कर लिया। 50 प्रतिशत के साथ, तमिलनाडु इस श्रेणी में आरक्षण का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है, जो अपना कोटा पूरी तरह से पूरा करता है। छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपना कोटा पूरा किया और तेलंगाना ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपना कोटा पूरा किया। लद्दाख, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और गुजरात ने अपने अनुसूचित जाति कोटा को पूरा कर लिया।

उत्तराखंड, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश ने अपना अनुसूचित जनजाति कोटा भरा। हिमाचल प्रदेश (91 प्रतिशत) अपनी अनुसूचित जनजाति कोटा आवश्यकताओं को पूरा करने के सबसे करीब है, जबकि गुजरात अपने अनुसूचित जनजाति कोटा का केवल 2 प्रतिशत ही भर सका। आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>35</sup> में अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है और 3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>36</sup> में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

2020 और 2022 के बीच उच्च न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 2 प्रतिशत से थोड़ी कम वृद्धि देखी गई, तेलंगाना में 7.1 से बढ़कर 27.3 फीसदी। हालाँकि, कुछ राज्यों में, उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिशत गिर गया: आंध्र प्रदेश 19 से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 14.3 से गिरकर 7.1 प्रतिशत हो गया। बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों में अभी भी कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

कांच की छत का प्रतीक, उच्च न्यायालय स्तर की तुलना में जिला अदालत स्तर पर अधिक महिला न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्तर पर न्यायाधीशों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35 प्रतिशत है। लेकिन राज्यों में वितरण असमान है। छोटे राज्यों में 70 प्रतिशत के साथ गोवा का प्रतिशत सबसे अधिक है, उसके बाद मेघालय (63 प्रतिशत) और नागालैंड (63 प्रतिशत) का स्थान है। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, गुजरात (19.5 प्रतिशत) में सबसे कम और तेलंगाना (52.8 प्रतिशत) में महिला न्यायाधीशों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

झारखंड और बिहार जैसे अन्य बड़े राज्यों में, सभी न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों की संख्या क्रमशः 23 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है।

लंबित मामले (5-10 वर्ष, उच्च न्यायालय, %, जनवरी 2023) **नया**

लंबित मामले (10+ वर्ष, उच्च न्यायालय, %, जनवरी 2023) **नया**

लंबित मामले (5-10 वर्ष, उप न्यायालय, %, जनवरी 2023)

लंबित मामले (10+ वर्ष, उप न्यायालय, %, जनवरी 2023)

लंबित मामले (प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश) (% , वित्तीय वर्ष '18-'22)

लंबित मामले (प्रति उप न्यायालय न्यायाधीश) (% , वित्तीय वर्ष '18-'22)

कुल लंबित मामले (उच्च न्यायालय) (% , वित्तीय वर्ष '18-'22)

कुल लंबित मामले (उप न्यायालय) (% , वित्तीय वर्ष '18-'22)

केस क्लीयरेंस दर (उच्च न्यायालय) (% , 2022)

केस क्लीयरेंस दर (उप न्यायालय) (% , 2022)

औसत उच्च न्यायालय लंबित (फरवरी 2022)

केस क्लीयरेंस दर (उच्च न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

केस क्लीयरेंस दर (उप न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

दशकों से, लंबित मामलों के मुद्दों से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिन्हें विधि आयोग की 245 वीं रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है, "सभी मामले शुरू किए गए, लेकिन निपटाए नहीं गए, भले ही मामला कब शुरू किया गया था"<sup>37</sup>। 2018 में, 'न्यायिक प्रणाली'<sup>38</sup> में लंबित मामलों और देरी को कम करने की राष्ट्रीय पहल पर उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व वाले सम्मेलन में बेहतर मामले और अदालत प्रबंधन प्रणाली, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया। आधे दशक के बाद, ई-फाइलिंग<sup>39</sup> और न्याय बंधु<sup>40</sup>, टेली-लॉ<sup>41</sup> जैसी योजनाएं जैसे कुछ प्रयास शुरू किए गए हैं, फिर भी सकारात्मक परिणाम अस्पष्ट बने हुए हैं।

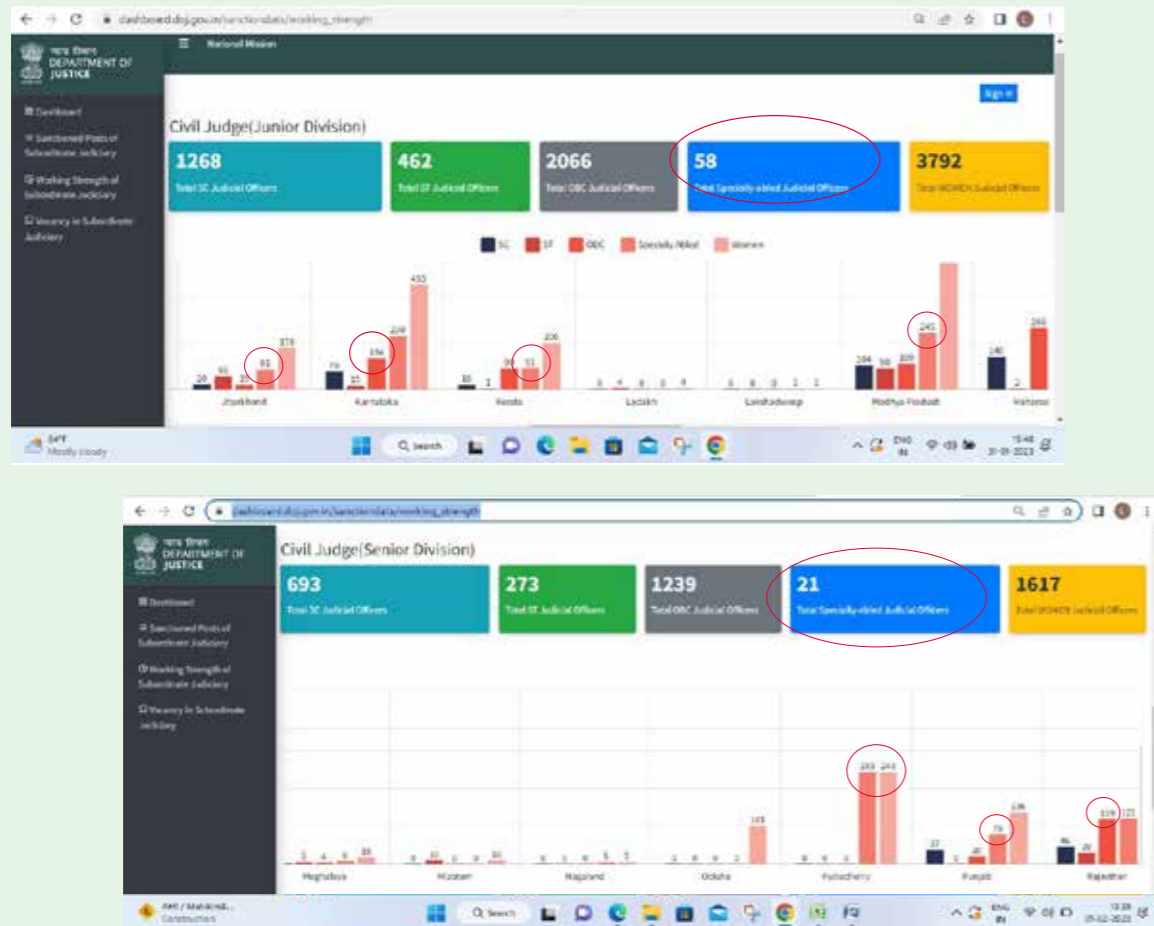
34 डीएनएच और डीडी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, पंजाब।  
 35 नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, डी एंड एनएच और डीडी  
 36 चंडीगढ़, हरियाणा, मिजोरम।  
 37 भारतीय विधि आयोग, 245 वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2014। यहाँ उपलब्ध है: <https://satyamevjayate.info/wp-content/uploads/2017/08/Law-Commission-report-245.pdf>  
 38 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों और देरी को कम करने के लिए राष्ट्रीय पहल की सम्मेलन कार्यवाही, 2018। यहाँ उपलब्ध है: [https://districts.courts.gov.in/sites/default/files/कार्यवाही\\_पुस्तक\\_सुप्रीमकोर्ट1.pdf](https://districts.courts.gov.in/sites/default/files/कार्यवाही_पुस्तक_सुप्रीमकोर्ट1.pdf)  
 39 न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई एक ई-फाइलिंग प्रणाली कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए है। यह वकीलों को किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने की अनुमति देता है 24x7.  
 40 न्याय बंधु के तहत, अपने समय और सेवाओं को स्वेच्छा से देने में रुचि रखने वाले अभ्यास करने वाले वकील पात्र हाशिए पर रहने वाले लाभार्थियों के साथ (मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से) जुड़े हुए हैं।  
 41 टेली-लॉ प्री-लिटिगेशन चरण में कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने के लिए एक ई-इंटरफेस प्रणाली है। यह जरूरतमंद और हाशिये पर मौजूद लोगों को वीडियो के माध्यम से कानूनी सहायता के लिए पैनल वकीलों से जोड़ता है कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाएं।

### डेटा अक्षम

दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत नया आरक्षण<sup>42</sup> बनाता है। यह कानून विशिष्ट विकलांगताओं को कवर करता है, जिसमें शारीरिक (जैसे लोकोमोटिव, दृश्य, या श्रवण हानि, भाषण और भाषा विकलांगता), बौद्धिक विकलांगता और मानसिक व्यवहार शामिल हैं। न्याय विभाग ने जिला अदालतों<sup>43</sup> में राज्य-वार डेटा उपलब्ध कराया है। हालाँकि, इस डेटा की सटीकता पर बहस जारी है। अगस्त और दिसंबर 2022 के बीच एकत्र किए गए दो डेटा सेट महत्वपूर्ण विसंगतियां दिखाते हैं। विशेष रूप से सक्षम न्यायाधीशों की संख्या पांच महीने के भीतर सौ गुना से अधिक बढ़ गई, जो अगस्त 2022 में 60 से बढ़कर दिसंबर 2022 में 6,690 हो गई। अगस्त 2022 में, असम को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 4 प्रतिशत के बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाया, और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>44</sup> में विशेष

रूप से सक्षम न्यायाधीशों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम थी और 20 राज्यों ने किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। इसके विपरीत, दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश<sup>45</sup> 4 प्रतिशत कोटा पूरा करते हैं, केवल 6 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश<sup>47</sup> 1 प्रतिशत से कम हैं और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और मिजोरम में कोई भी नहीं है।

डेटा कई विसंगतियां भी सामने लाता है- शायद गलत डेटा प्रविष्टि के कारण। उदाहरण के तौर पर, पुडुचेरी में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 26 और कामकाजी शक्ति 11 है, लेकिन रिपोर्ट 244 विशेष रूप से सक्षम न्यायाधीश। अगस्त 2022 में, किसी भी राज्य में 10 से अधिक विशेष रूप से सक्षम न्यायाधीश थे, जबकि दिसंबर 2022 में, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 848 और 678 की संख्या बताई गई।



42 च सामाजिक न्याय और अधिकारिता, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016। यहां उपलब्ध है: <https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts.php>

43 [https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/working\\_strength](https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/working_strength)

44 अंडमान मंत्रालय और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, डीएनएच और डीडी, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान।

45 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, डीएनएच और डीडी, पुडुचेरी

46 पुडुचेरी, डीएनएच और डीडी, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, असम, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर।

47 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, तमिलनाडु, मणिपुर।

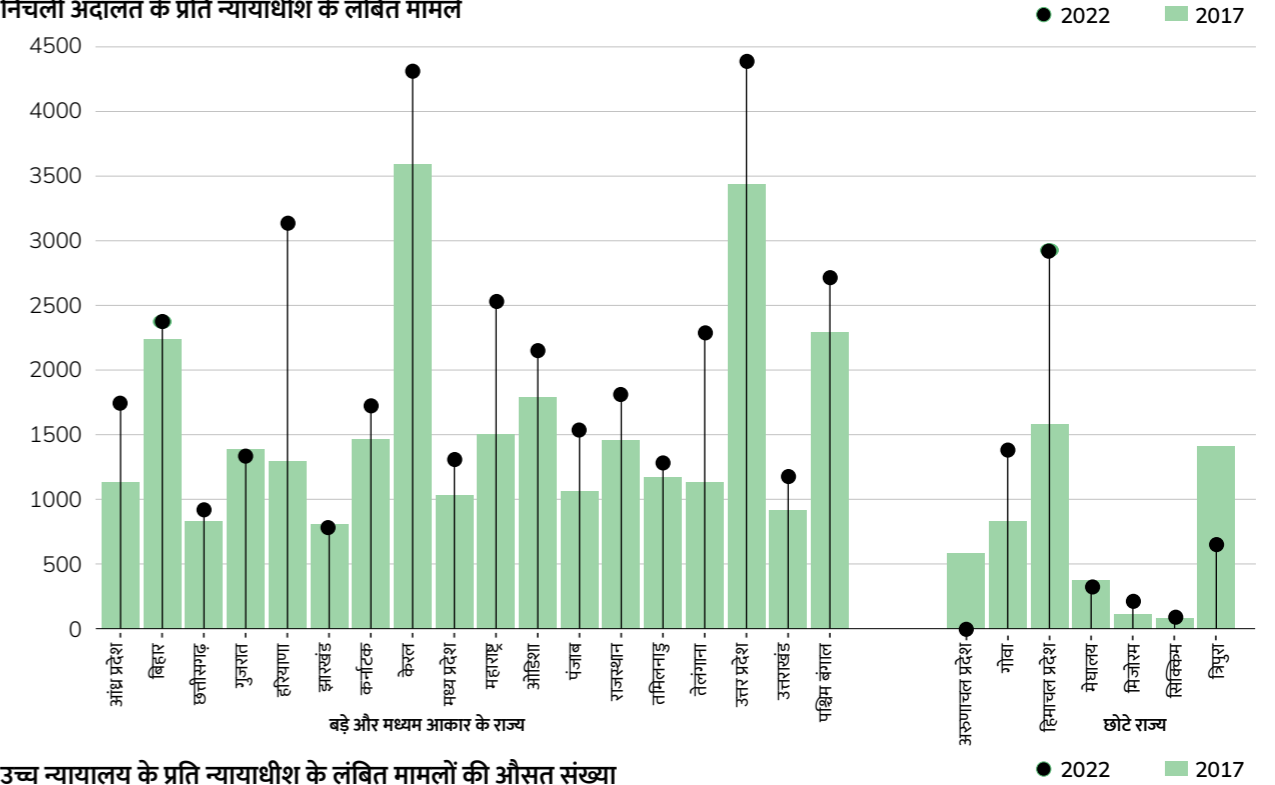
दिसंबर 2022 तक, देश के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में कुल 4.9 करोड़ मामले लंबित थे। कम से कम 1.9 लाख मामले 30 साल से अधिक समय से और 56 लाख मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। औसतन, इनमें से 49 प्रतिशत और 29 प्रतिशत

मामले क्रमशः उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में 5 साल<sup>48</sup> से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में करीब 70,000 मामले लंबित हैं।

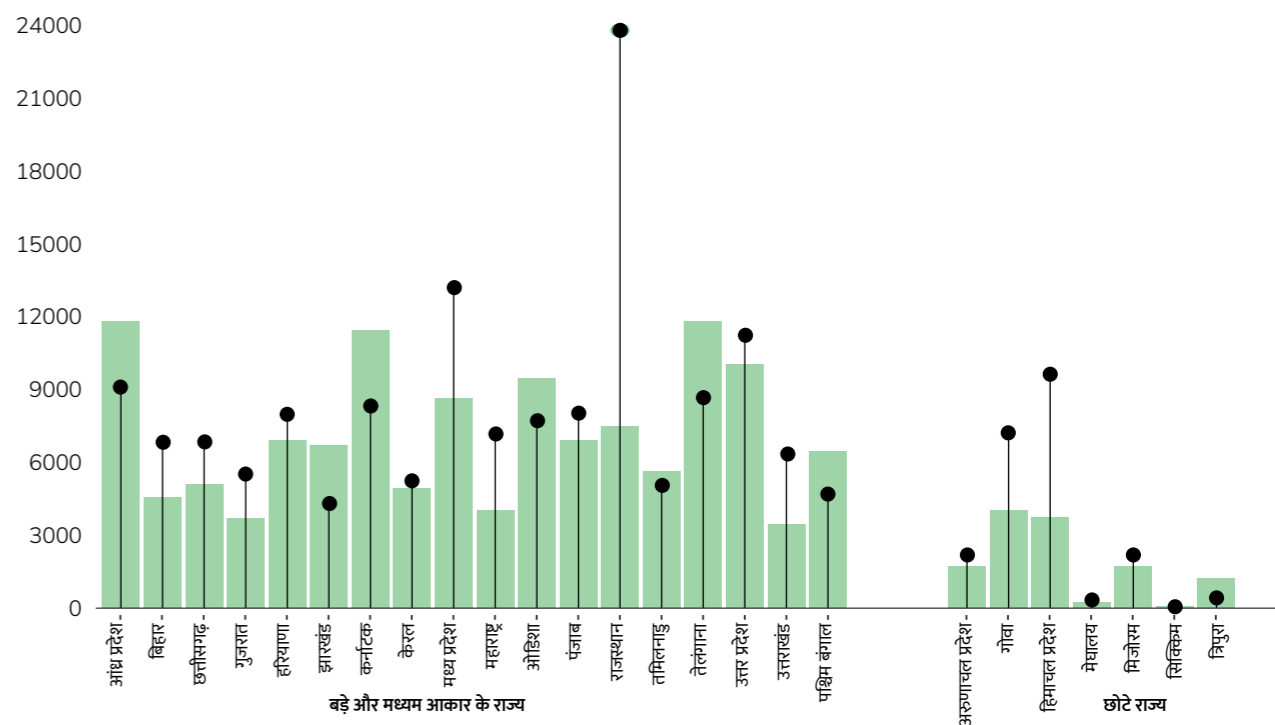
### चित्र 29: प्रति न्यायाधीश लंबित मामले

पिछले 5 वर्षों में अधिकांश राज्यों में प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जबकि स्वीकृत संख्या काफी हद तक समान रही है।

5a. निचली अदालत के प्रति न्यायाधीश के लंबित मामले



5b. उच्च न्यायालय के प्रति न्यायाधीश के लंबित मामलों की औसत संख्या



Note: States that share a High Court have been assigned the same value.  
Source: National Judicial Data Grid

48 इसमें 5-10, 10-20, 20-30 और 30 साल से अधिक समय से लंबित मामले शामिल हैं।

उच्च न्यायालय स्तर पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औसत लंबित मामले हैं; मामले औसतन 11.34 वर्षों तक लंबित रहते हैं, और पश्चिम बंगाल में 9.9 वर्षों तक। सबसे कम औसत उच्च न्यायालय लंबित मामले त्रिपुरा (1 वर्ष), सिक्किम (1.9 वर्ष) और मेघालय (2.1 वर्ष) में हैं।

30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>49</sup> में हर चार उच्च न्यायालयों में से एक मामला 5 साल से अधिक समय से लंबित है: इस श्रेणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे अधिक (63.3 प्रतिशत के साथ) और त्रिपुरा (0.6 प्रतिशत) सबसे कम है। एक न्यायाधीश को जिन मामलों से निपटना पड़ता है उनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। 2018 और 2022 के बीच, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>50</sup> में प्रति न्यायाधीश मुकदमों का भार बढ़ गया।

11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>51</sup> की जिला अदालतों में हर चार में से एक मामला 5 साल से अधिक समय से लंबित है। देश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक हिस्सेदारी सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (53 प्रतिशत) में है, और सबसे कम सिक्किम (0.8 प्रतिशत) में है। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में पश्चिम बंगाल में 48.4 प्रतिशत और बिहार में ऐसे मामले हैं 47.7 फीसदी<sup>52</sup> पांच वर्षों (2018-2022) में, बहुत कम न्यायालयों<sup>53</sup> को छोड़कर, सभी अधीनस्थ न्यायालयों<sup>54</sup> में न्यायाधीशों का कार्यभार बढ़ गया है।

केस क्लियरेंस दर (सीसीआर), या एक वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या, उस वर्ष दायर की गई संख्या के विरुद्ध मापी गई एक सामान्य मीट्रिक है जिसका उपयोग उस दर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जिस पर मामलों का निपटारा किया जाता है<sup>55</sup>। 100% से अधिक का सीसीआर इंगित करता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। 2018-19 और 2022 के बीच, उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय औसत में छह प्रतिशत अंक (88.5 प्रतिशत से 94.6 प्रतिशत) का सुधार हुआ, लेकिन निचली अदालतों में 3.6 अंक की गिरावट (93 प्रतिशत से 89.4 प्रतिशत) हुई।

2018 और 2022 के बीच, त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जहां जिला अदालतों में सीसीआर 100 प्रतिशत से ऊपर रहा; 2020 को छोड़कर, महामारी

का वर्ष, जब यह गिरकर 40 प्रतिशत हो गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय में भी, 2019 से सीसीआर 100 से ऊपर बना हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में सालाना अधिक मामलों का निपटारा करते हैं। 2018-19 में केवल 4 उच्च न्यायालयों<sup>56</sup> में सीसीआर 100 प्रतिशत या उससे अधिक था। 2022 में यह दोगुना से भी अधिक बढ़कर 12 उच्च न्यायालयों<sup>57</sup> हो गया। केरल और ओडिशा के उच्च न्यायालयों में मामला निपटान दर क्रमशः 156 प्रतिशत और 131 प्रतिशत अधिक है, जबकि राजस्थान (65 प्रतिशत) और बॉम्बे (72 प्रतिशत) के उच्च न्यायालयों में मामला निपटान दर सबसे कम है। पांच वर्षों में, 16 उच्च न्यायालयों में मामले निपटान दर में वृद्धि हुई और 9 में कमी आई।

2018-19 में 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 2022 में केवल 9 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>60</sup> अपने अधीनस्थ न्यायालयों में 100 प्रतिशत या उससे अधिक की सीसीआर दर हासिल कर सके<sup>61</sup>। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश में सीसीआर सबसे कम, 72 प्रतिशत और गुजरात में सबसे अधिक, 117 प्रतिशत है। पांच वर्षों में, 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>62</sup> ने अपनी केस क्लियरेंस दरों में सुधार किया है, जिसमें केरल में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जिसमें 5.12 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई है। 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>63</sup> में केस क्लियरेंस दर में कमी आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 13.67 प्रतिशत की कमी आई है।

बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, केरल और पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दोनों जगह अदालतों में स्तर 100 की केस क्लियरेंस दर प्राप्त कर सकता है प्रतिशत और अधिक।

पांच वर्षों में 9 उच्च न्यायालयों<sup>64</sup> में निपटान दरों के साथ-साथ लंबित मामलों में भी वृद्धि देखी गई। इसी तरह की प्रवृत्ति 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>65</sup> की अधीनस्थ अदालतों में भी देखी गई, जहां सीसीआर में वृद्धि के बावजूद, लंबित मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

49 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख।  
50 राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, डीएनएच और डीडी।  
51 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पुडुचेरी, नागालैंड।  
52 इन राज्यों में कुल लंबित मामले क्रमशः 24 लाख और 32 लाख मामले हैं।  
53 त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप और झारखंड।  
54 लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।  
55 दक्ष, डिक्टोरिंग विलंब: उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में विलंब का विश्लेषण। यहां उपलब्ध है: [https://www.dakshindia.org/Daksh\\_Justice\\_in\\_India/19\\_chapter\\_01.xhtml](https://www.dakshindia.org/Daksh_Justice_in_India/19_chapter_01.xhtml)  
56 झारखंड, मद्रास, उड़ीसा, मणिपुर।  
57 सिक्किम, मद्रास, झारखंड, पटना, कलकत्ता, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, पंजाब और हरियाणा, तेलंगाना।  
58 गुजरात, मद्रास, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, सिक्किम, पटना, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तेलंगाना, केरल, पंजाब और हरियाणा।  
59 राजस्थान, उत्तराखंड, बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इलाहाबाद, गौहाटी, दिल्ली, मध्य प्रदेश।  
60 पंजाब, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, केरल, पुडुचेरी, गुजरात।  
61 छत्तीसगढ़, झारखंड, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, गुजरात, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा।  
62 कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, बिहार, तेलंगाना (3-वर्षीय रुझान), केरल।  
63 पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश (3-वर्ष प्रवृत्ति), मणिपुर, राजस्थान, डीएनएच और डीडी।  
64 केरल, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, पंजाब और हरियाणा, पटना, कर्नाटक और गुजरात।  
65 कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, बिहार, तेलंगाना, केरल।

## चित्र 30: केस क्लियरेंस दर

भारत में एक वर्ष में अदालतों को मिलने वाले प्रत्येक 100 मामलों में से वे कितने का निपटारा करते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो यह केस क्लियरेंस रेट (सीसीआर) है। यदि अदालतें प्राप्त प्रत्येक 100 मामलों में से 100 से कम का निपटारा करती हैं, तो कमी बैकलॉग में जुड़ जाती है - और तदनुसार उनके लंबित मामलों में भी वृद्धि होती है। पिछले पांच वर्षों में, अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों दोनों के स्तर पर अधिकांश अदालतों ने, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, 100% से कम सीसीआर दर्ज किया है, और इस प्रकार उनकी लंबितता में वृद्धि हुई है।

केस क्लियरेंस दर (%) ■ Below 70% ■ 70% to 100% ■ Above 100%

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केस क्लियरेंस रेट (उच्च न्यायालय)					केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ अदालतों)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	85	110	83	111	121	88	91	117	317	76
2 आंध्र प्रदेश	69	54	74	69	73	96	90	68	66	90
3 अरुणाचल प्रदेश	142	83	79	84	90	108	NA	NA	NA	NA
4 असम	142	83	79	84	90	95	96	48	68	72
5 बिहार	90	86	88	57	113	73	73	47	67	93
6 चंडीगढ़	85	87	73	73	103	90	91	50	60	76
7 छत्तीसगढ़	90	87	78	86	77	105	95	66	81	89
8 दादरा & नगर हवेली और दमन & दीव	87	83	69	69	72	96	106	69	96	97
9 दिल्ली	91	87	66	73	88	90	77	68	70	71
10 गोवा	87	83	69	69	72	91	86	59	99	113
11 गुजरात	75	82	75	82	92	114	105	55	96	117
12 हरियाणा	85	87	73	73	103	88	83	52	72	82
13 हिमाचल प्रदेश	83	61	53	79	80	94	92	58	90	95
14 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	88	76	287	194	127	NA	NA	NA	NA	NA
15 जम्मू और कश्मीर	NA	NA	NA	NA	NA	99	87	64	85	74
16 झारखंड	102	110	88	100	101	106	100	78	77	96
17 कर्नाटक	75	94	89	107	82	95	98	84	96	95
18 केरल	85	94	76	107	156	97	95	39	100	113
19 लद्दाख	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	77	90	81
20 लक्षद्वीप	85	94	76	107	156	96	NA	NA	NA	NA
21 मध्य प्रदेश	82	81	75	80	84	98	89	62	78	91
22 महाराष्ट्र	87	83	69	69	72	92	84	48	79	92
23 मणिपुर	132	130	66	83	99	115	98	89	82	103
24 मेघालय	90	100	69	90	128	116	85	62	92	103
25 मिजोरम	142	83	79	84	90	93	74	76	88	111
26 नागालैंड	142	83	79	84	90	96	97	28	56	63
27 ओडिशा	101	114	73	82	131	64	69	42	67	90
28 पुडुचेरी	106	99	93	98	107	98	91	80	102	114
29 पंजाब	85	87	73	73	103	96	94	60	87	100
30 राजस्थान	82	86	59	71	65	94	93	70	81	96
31 सिक्किम	78	111	96	138	111	109	99	92	92	97
32 तमिलनाडु	106	99	93	98	107	98	96	84	94	98
33 तेलंगाना	69	64	58	70	103	96	81	49	71	95
34 त्रिपुरा	92	113	111	127	107	163	101	40	107	104
35 उत्तर प्रदेश	91	94	72	82	96	85	81	66	69	72
36 उत्तराखंड	83	93	88	83	81	93	120	60	80	86
37 पश्चिम बंगाल	85	110	83	111	121	87	89	66	63	80
38 अखिल भारत	88	108	77	83	95	93	89	62	80	89

नोट: उच्च न्यायालय को साझा करने वाले राज्यों को समान मूल्य सौंपा गया है।  
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड



## ग्राम न्यायालय: एक अवास्तविक दृष्टिकोण

1986<sup>66</sup> की शुरुआत में, 66 ग्राम न्यायालयों की परिकल्पना उन समुदायों के लिए न्याय वितरण को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए की गई थी जहां वे रहते थे। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009 में लागू हुआ। हालाँकि, एक दशक से अधिक समय के बाद भी, ग्राम न्यायालय अभी भी विवाद समाधान के लिए एक उपयोगी स्थानीय मंच के रूप में विकसित नहीं हुआ है। केवल 15 राज्यों ने उन्हें अधिसूचित किया है। 24 जनवरी 2023 तक, 476 अधिसूचित ग्राम न्यायालय हैं, जिनमें से केवल 264 चालू हैं<sup>67</sup>। इन संस्थानों की धीमी वृद्धि के कारणों की समीक्षा करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय<sup>68</sup> पर संसदीय स्थायी समिति ने मुख्य चुनौतियों का उल्लेख किया: राज्य सरकारों द्वारा उन्हें स्थापित करने की गैर-अनिवार्य प्रकृति, बुनियादी ढांचे की कमी, स्वतंत्र 'न्यायाधिकारी' या निर्णायकों की रिक्तियां, मोबाइल अदालतों की कमी, और सामान्य पुलिस और अन्य पदाधिकारियों की उनके सामने पेश होने में अनिच्छा।

राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित

करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सहायता के रूप में, केंद्र सरकार रुपये प्रदान करती है। 27.60 लाख<sup>69</sup> प्रति ग्राम न्यायालय और अधिकतम रु. इसके संचालन के बाद तीन साल तक 3.2 लाख प्रति वर्ष, जिसके बाद राज्य सरकारों को इन संस्थानों के प्रावधान की लागत वहन करनी होगी। योजना की शुरुआत से अब तक ग्राम न्यायालयों के लिए न्याय विभाग द्वारा कुल 8,340 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राशि या रुपये मिले हैं। 2,456 लाख, और कर्नाटक, गोवा, पंजाब और हरियाणा को केवल रु. 25 लाख प्रत्येक। 2021-22 में, ओडिशा को 19 परिचालन ग्राम न्यायालयों के साथ रु. 107 लाख और शून्य परिचालन वाले ग्राम न्यायालय (55 अधिसूचित) वाले तेलंगाना को रु. 693 लाख।

24 जनवरी 2023 तक, कुल प्राप्त 2.16 लाख मामलों (दीवानी और आपराधिक) में से केवल 6289 का निपटारा किया गया था। इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रगति से पता चलता है कि अधिक जनशक्ति, वित्त और नियमित कामकाज के बिना, ये संस्थान जल्द ही अभिभूत हो जाएंगे और अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों पर बोझ को कम करने के लिए दरवाजे पर न्याय के साधन के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे।

लिआ वर्गीस, दक्ष

संध्या आर, दक्ष

स्मिता मठ, दक्ष;

डॉ. रेहाना मंज़ूर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;

लखविंदर कौर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;

अपूर्वा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी;

दीपिका किन्हल, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी

66 भारतीय विधि आयोग, एक सौ चौदहवीं रिपोर्ट, 1986। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080883.pdf>

67 न्याय विभाग, डैशबोर्ड। यहां उपलब्ध है: [https://dashboard.doj.gov.in/gn/operational\\_gram\\_nyayalaya](https://dashboard.doj.gov.in/gn/operational_gram_nyayalaya)

68 कानून और न्याय मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 123वीं रिपोर्ट, 2022। यहां उपलब्ध है: [https://raiyasabha.nic.in/rsnew/समिति\\_साइट/कमेटी\\_फाइल/रिपोर्टफाइल/18/171/123\\_2022\\_12\\_14.pdf](https://raiyasabha.nic.in/rsnew/समिति_साइट/कमेटी_फाइल/रिपोर्टफाइल/18/171/123_2022_12_14.pdf)

69 रु. 18 लाख (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये + वाहन के लिए 5 लाख रुपये + कार्यालय की साज-सज्जा के लिए 3 लाख रुपये)।



## तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

थीम	विविधता			बुनियादी ढांचा	काम का बोझ
	नया	नया	नया	नया	नया
● क्लस्टर में सबसे अच्छा	अनुसूचित जाति के न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप-न्यायालय) (%), जुलाई 2022	अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप-न्यायालय) (%), जुलाई 2022	ओ. बी. सी. न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप-न्यायालय) (%), जुलाई 2022	कोर्ट हॉल की कमी (%), अगस्त 2022	लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%), जनवरी 2023
● क्लस्टर में सबसे खराब	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर
संकेतक	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत
स्कोरिंग गाइड	NA	NA	NA	14.7	24.18
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>					
आंध्र प्रदेश	91	69	119	-4.0	28.40
बिहार	68	77	51	20.2	25.04
छत्तीसगढ़	128 ●	79	123	2.7	26.79
गुजरात	108	2	55	1.1	25.09
हरियाणा	56	NA <sup>8</sup>	33	27.7 ●	26.48
झारखंड	39	35	36	4.6	21.90
कर्नाटक	85	66	75	14.3	21.81
केरल	79	9	106	5.8	36.90 ●
मध्य प्रदेश	73	56	90	24.0	28.87
महाराष्ट्र	80	5	120	-7.3 ●	23.14
ओडिशा	11	0 ●	48	16.9	25.25
पंजाब	83	0 ●	99.95	14.9	26.48
राजस्थान	63	58	94	15.9	19.97
तमिलनाडु	93	68	122	9.3	18.62 ●
तेलंगाना	82	117	125 ●	-3.1	32.28
उत्तर प्रदेश	64	45	83	25.4	23.20
उत्तराखंड	83	125 ●	96	21.1	24.18
पश्चिम बंगाल	0 ●	0 ●	0 ●	17.6	23.59
<b>छोटे राज्य</b>					
अरुणाचल प्रदेश	NA <sup>5</sup>	104 ●	NA <sup>12</sup>	36.6	23.55 ●
गोवा	0 ●	33 ●	15 ●	-6.0 ●	23.14
हिमाचल प्रदेश	57	91	38	13.7	16.60
मेघालय	NA <sup>6</sup>	57	NA <sup>13</sup>	46.5 ●	9.23
मिजोरम	NA <sup>5</sup>	NA <sup>9</sup>	NA <sup>14</sup>	35.4	23.55 ●
सिक्किम	0 ●	66	116 ●	28.6	7.36
त्रिपुरा	63 ●	61	NA <sup>14</sup>	32.8	0.56 ●
<b>रैंक रहित राज्य</b>					
असम	65	52	0	13.4	23.55
मणिपुर	254	71	70	33.9	11.59
नागालैंड	NA <sup>5</sup>	76 <sup>10</sup>	0	11.8	23.55
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	NA <sup>7</sup>	NA <sup>11</sup>	NA <sup>15</sup>	NA <sup>3</sup>	23.59
चंडीगढ़	74	NA <sup>8</sup>	25	-3.3	26.48
दमन और दीव	0	0	244	-14.3	23.14
दिल्ली	54	12	0	32.5	21.66
जम्मू और कश्मीर	67	60	NA <sup>16</sup>	38.2	28.34
लद्दाख	588	78	NA <sup>14</sup>	47.1	28.34
लक्षद्वीप	NA <sup>5</sup>	74	NA <sup>14</sup>	0.0	36.90
पुडुचेरी	0	0	93	-38.5	18.62

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत, न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। v. पीपी प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए उपलब्ध नहीं है। vii. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

3. संसद के प्रश्न में 0 स्वीकृत और 13 वास्तविक अर्धनस्थ अदालत के न्यायाधीशों को दिखाया गया है। 5. कोई एससी आरक्षण नहीं और कोई एससी न्यायाधीश नहीं। 6. अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 7. एससी आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 8. कोई एसटी आरक्षण नहीं और कोई एसटी न्यायाधीश नहीं। 9. कोई एसटी आरक्षण नहीं है। 10. एसटी न्यायाधीशों का डेटा न्याय विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। 11. कोई एसटी न्यायाधीश नहीं। 12. ओ. बी. सी. आरक्षण नहीं। 13. ओ. बी. सी. के लिए कोई विशेष आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 14. कोई ओ. बी. सी. आरक्षण नहीं और कोई ओ. बी. सी. न्यायाधीश नहीं। 15. कोई ओ. बी. सी. न्यायाधीश नहीं। 16. कोई ओ. बी. सी. श्रेणी नहीं दी गई।

## तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

थीम	काम का बोझ				
	नया	लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%), जनवरी 2023)	लंबित मामले (10+ वर्ष) (उप-न्यायालय) (%), जनवरी 2023)	उच्च न्यायालय की औसत विचाराधीनता (वर्ष, फरवरी 2022)	केस क्लियरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (%), 2022)
● क्लस्टर में सबसे अच्छा	लंबित मामले (10+ वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%), जनवरी 2023)	लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%), जनवरी 2023)	लंबित मामले (10+ वर्ष) (उप-न्यायालय) (%), जनवरी 2023)	उच्च न्यायालय की औसत विचाराधीनता (वर्ष, फरवरी 2022)	केस क्लियरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (%), 2022)
● क्लस्टर में सबसे खराब	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
संकेतक	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत	राष्ट्रीय औसत
स्कोरिंग गाइड	24.07	19.09	9.73	NA	95
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>					
आंध्र प्रदेश	20.47	11.65	1.33	7.48	73
बिहार	15.77	28.45	19.29	4.96	113
छत्तीसगढ़	6.46 ●	10.12	0.36	4.08	77
गुजरात	13.60	13.43	7.54	4.90	92
हरियाणा	24.80	6.84	0.24 ●	6.75	103
झारखंड	20.00	23.66	6.02	6.60	101
कर्नाटक	18.95	16.51	3.09	5.23	82
केरल	15.21	18.47	1.03	6.50	156 ●
मध्य प्रदेश	27.08	16.84	1.01	NA <sup>18</sup>	84
महाराष्ट्र	25.76	20.64	8.41	NA <sup>18</sup>	72
ओडिशा	21.75	25.83	16.51	6.05	131
पंजाब	24.80	5.78 ●	0.31	6.75	103
राजस्थान	17.22	22.10	4.87	5.46	65 ●
तमिलनाडु	21.95	16.80	4.32	6.38	107
तेलंगाना	18.01	13.72	1.48	6.85	103
उत्तर प्रदेश	40.07 ●	19.16	16.35	11.34 ●	96
उत्तराखंड	6.72	11.07	1.97	3.58 ●	81
पश्चिम बंगाल	39.46	28.64 ●	19.73 ●	9.89	121
<b>छोटे राज्य</b>					
अरुणाचल प्रदेश	4.27	NA <sup>17</sup>	NA <sup>17</sup>	3.61 ●	90
गोवा	25.76 ●	18.54	5.38	NA <sup>18</sup>	72 ●
हिमाचल प्रदेश	4.37	12.44	1.16	3.10	80
मेघालय	0.09	26.85 ●	10.49 ●	2.09	128 ●
मिजोरम	4.27	9.94	2.24	3.61 ●	90
सिक्किम	0.61	0.65 ●	0.16 ●	1.85	111
त्रिपुरा	0.00 ●	7.52	3.73	0.99 ●	107
<b>रैंक रहित राज्य</b>					
असम	4.27	12.69	1.61	3.61	90
मणिपुर	10.40	16.90	2.75	3.38	99
नागालैंड	4.27	20.97	5.70	3.61	90
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39.46	39.69	13.23	9.89	121
चंडीगढ़	24.80	5.72	0.26	6.75	103
दमन और दीव	25.76	18.03	3.91	NA <sup>18</sup>	72
दिल्ली	13.83	14.17	1.35	NA <sup>18</sup>	88
जम्मू और कश्मीर	15.52	18.14	4.31	5.71	127
लद्दाख	15.52	6.76	0.35	5.71	127
लक्षद्वीप	15.21	NA <sup>17</sup>	NA <sup>17</sup>	6.50	156
पुडुचेरी	21.95	20.54	6.34	6.38	107

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत, न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। v. पीपी प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए उपलब्ध नहीं है। vii. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 18. आंकड़ों की गणना नहीं की जा सकी।

### तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

संकेतक	काम का बोझ		रुझान		
	केस क्लियरेंस रेट (उप-अदालत) (%), 2022	लंबित मामले (प्रति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) (%), सीवाई '18-' 22)	लंबित मामले (प्रति उप-न्यायालय न्यायाधीश) (%), सीवाई '18-' 22) <sup>20</sup>	कुल लंबित मामले (उच्च न्यायालय) (%), सीवाई '18-' 22)	कुल लंबित मामले (उप-न्यायालय) (%), सीवाई '18-' 22) <sup>20</sup>
	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	89	1.7	5.8	3.6	8.4
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>					
आंध्र प्रदेश	90	-14.0	17.5	7.2	14.0
बिहार	93	12.2	1.6	8.4	7.7
छत्तीसगढ़	89	6.6	2.9	8.9	8.1
गुजरात	117 ●	8.6	0.4	7.6	0.9 ●
हरियाणा	82	3.6	19.4 ●	4.4	18.3 ●
झारखंड	96	-7.3	-0.01 ●	-0.6	6.5
कर्नाटक	95	-5.4	3.6	3.3	5.2
केरल	113	1.4	4.3	2.3	5.6
मध्य प्रदेश	91	9.4	5.5	6.9	8.8
महाराष्ट्र	92	12.6	11.2	9.4	8.2
ओडिशा	90	-1.1	3.8	0.2	7.2
पंजाब	100	3.6	8.2	4.4	10.6
राजस्थान	96	31.3 ●	4.6	20.8 ●	7.1
तमिलनाडु	98	-1.5	2.4	-0.7	5.5
तेलंगाना	95	-15.5 ●	9.0	5.0	16.1
उत्तर प्रदेश	72 ●	2.5	5.7	3.2	11.5
उत्तराखंड	86	14.4	5.8	7.8	9.7
पश्चिम बंगाल	80	-4.7	7.4	-1.0 ●	3.3
<b>छोटे राज्य</b>					
अरुणाचल प्रदेश	NA <sup>17</sup>	4.8	NA <sup>17</sup>	10.0	NA <sup>17</sup>
गोवा	113 ●	12.6	11.5	9.4	7.5
हिमाचल प्रदेश	95 ●	21.3 ●	13.5 ●	24.7 ●	15.8 ●
मेघालय	103	7.5	-2.4	6.7	2.7
मिजोरम	111	4.8	12.8	10.0	10.3
सिक्किम	97	-7.2	3.4	-4.2	6.4
त्रिपुरा	104	-21.4 ●	-10.5 ●	-10.2 ●	-4.6 ●
<b>रैंक रहित राज्य</b>					
असम	72	4.8	8.5	10.0	12.4
मणिपुर	103	-3.0	5.6	-0.1	6.7
नागालैंड	63	4.8	4.2	10.0	5.8
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	76	-4.7	-1.3	-1.0	2.4
चंडीगढ़	76	3.6	17.7	4.4	17.4
दमन और दीव	97	12.6	7.7	9.4	4.3
दिल्ली	71	8.3	6.2	8.6	13.4
जम्मू और कश्मीर	74	-13.2	NA <sup>21</sup>	-8.8	NA <sup>21</sup>
लद्दाख	81	-13.2	NA <sup>21</sup>	-8.8	NA <sup>21</sup>
लक्षद्वीप	NA <sup>17</sup>	1.4	NA <sup>17</sup>	2.3	NA <sup>17</sup>
पुडुचेरी	114	-1.5	3.8	-0.7	1.8

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज़, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। v. उप-न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। vi. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vii. सीवाई-केलेडर वर्ष; वित्त वर्ष; वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 19. रुझान संकेतकों के लिए विचार किए गए सभी 5 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, उनके लिए 3 साल की प्रवृत्ति की गणना की गई है। 20. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के लिए सभी 5 वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग डेटा पर विचार किया गया। इसलिए, 3 साल की प्रवृत्ति की गणना की गई है। 21. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इस संकेतक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका 5 साल का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था।

### तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

संकेतक	रुझान				
	न्यायाधीश रिकॉर्ड (उच्च न्यायालय) (पीपी, सीवाई '18-' 22)	न्यायाधीश रिकॉर्ड (उप-न्यायालय) (पीपी, सीवाई '18-' 22) <sup>20</sup>	केस क्लियरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (पीपी, सीवाई '18-' 22)	केस क्लियरेंस रेट (उप-अदालत) (पीपी, सीवाई '18-' 22)	खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (पीपी, वित्त वर्ष '17-' 21)
	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	-0.99	-0.66	1.03	-1.65	0.94
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>					
आंध्र प्रदेश	-12.01 ●	3.01	6.23	-0.23	-0.97
बिहार	0.35	-2.99	4.48	2.98	1.83
छत्तीसगढ़	-1.44	-1.38	-2.53	-3.46	0.30
गुजरात	0.51	-0.40	1.08	-1.43	0.16
हरियाणा	-0.75	3.18 ●	4.93	-0.68	1.40
झारखंड	-5.47	-4.80 ●	3.02	-1.12	-0.55
कर्नाटक	-5.65	-0.64	2.72	0.18	8.24 ●
केरल	-0.71	0.10	13.56 ●	5.12 ●	-3.59
मध्य प्रदेश	1.19	-2.43	-0.52	-0.61	1.25
महाराष्ट्र	1.83	1.72	-3.20	-0.85	-0.57
ओडिशा	-0.22	-0.60	6.34	2.35	0.65
पंजाब	-0.75	-1.38	4.93	1.79	-3.32
राजस्थान	3.37 ●	2.33	-5.78 ●	-0.07	4.19
तमिलनाडु	-0.82	0.23	1.67	-0.62	-1.08
तेलंगाना	-4.53	0.20	13.03	4.85	-5.20 ●
उत्तर प्रदेश	-0.53	-2.22	-1.38	-3.30	4.96
उत्तराखंड	3.33	-2.32	-5.69	-1.39	1.20
पश्चिम बंगाल	-2.92	0.00	5.20	-13.67 ●	1.40
<b>छोटे राज्य</b>					
अरुणाचल प्रदेश	-4.24	-4.93 ●	-1.37	NA <sup>17</sup>	10.57 ●
गोवा	1.83 ●	0.49	-3.20 ●	0.76	1.97
हिमाचल प्रदेश	-0.15	0.10	-2.71	-1.06	-0.79
मेघालय	-0.42	-2.26	5.53	-0.26	5.30
मिजोरम	-4.24	1.99 ●	-1.37	2.87 ●	-0.36
सिक्किम	-2.78	0.65	5.73 ●	-0.77	-2.83 ●
त्रिपुरा	-6.42 ●	-3.66	0.25	-5.53 ●	8.81
<b>रैंक रहित राज्य</b>					
असम	-4.24	-1.32	-1.37	-4.41	-1.69
मणिपुर	-4.00	2.09	4.32	-0.17	0.13
नागालैंड	-4.24	-1.18	-1.37	-5.39	2.01
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-2.92	NA <sup>22</sup>	5.20	-3.61	8.17
चंडीगढ़	-0.75	0.00	4.93	-4.32	-1.15
दमन और दीव	1.83	6.67	-3.20	-1.89	12.62
दिल्ली	-1.06	-3.39	-1.34	-3.11	6.32
जम्मू और कश्मीर	-5.20	NA <sup>21</sup>	8.11	NA <sup>21</sup>	NA <sup>21</sup>
लद्दाख	-5.20	NA <sup>21</sup>	8.11	NA <sup>21</sup>	NA <sup>21</sup>
लक्षद्वीप	-0.71	NA <sup>17</sup>	13.56	NA <sup>17</sup>	0.91
पुडुचेरी	-0.82	0.77	1.67	1.15	3.58

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज़, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। v. उप-न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। vi. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vii. सीवाई-केलेडर वर्ष; वित्त वर्ष; वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 20. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के लिए सभी 5 वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग डेटा पर विचार किया गया। इसलिए, 3 साल की प्रवृत्ति की गणना की गई है। 21. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इस संकेतक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका 5 साल का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था। 22. डेटा पिछले 4 वर्षों के लिए 0 स्वीकृत अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों को दर्शाता है।



**कानूनी सहायता**

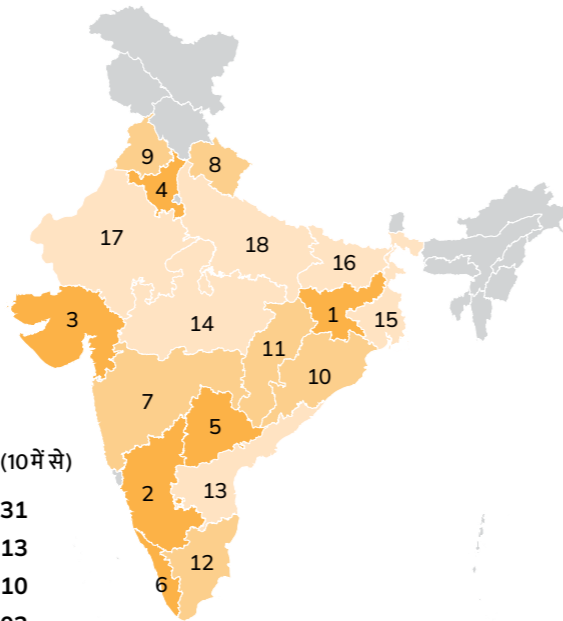
# कानूनी सहायता रैंकिंग

रंग गाइड  
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक (IJR 3) **15**

समूह (क्लस्टर)

- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ तक)



## मानचित्र 15: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
14	4	1
7	16	2
6	9	3
2	5	4
4	6	5
1	7	6
5	1	7
17	10	8
3	3	9
15	8	10
8	15	11
12	11	12
10	14	13
9	12	14
13	17	15
16	2	16
11	13	17
18	18	18

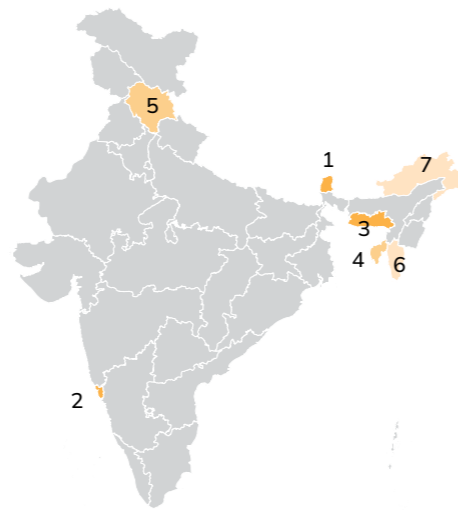
राज्य	स्कोर (10 में से)
झारखंड	6.31
कर्नाटक	6.13
गुजरात	6.10
हरियाणा	6.02
तेलंगाना	5.92
केरल	5.85
महाराष्ट्र	5.73
उत्तराखंड	5.63
पंजाब	5.59
ओडिशा	5.44
छत्तीसगढ़	5.33
तमिलनाडु	5.32
आंध्र प्रदेश	5.27
मध्य प्रदेश	5.01
पश्चिम बंगाल	4.88
बिहार	4.41
राजस्थान	4.36
उत्तर प्रदेश	3.24

## मानचित्र 16: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
6	6	2
5	3	3
7	5	4
4	7	5
3	2	6
2	4	7

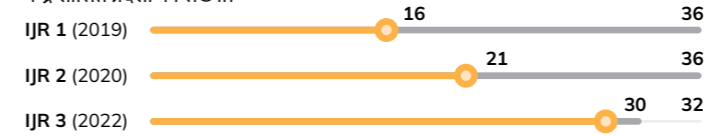
राज्य	स्कोर (10 में से)
सिक्किम	4.96
गोवा	4.41
मेघालय	4.15
त्रिपुरा	3.70
हिमाचल प्रदेश	3.62
मिजोरम	3.33
अरुणाचल प्रदेश	3.10



# उम्मीदें बढ़ाना

### राज्य बजट

अपने कानूनी सहायता बजट में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या।



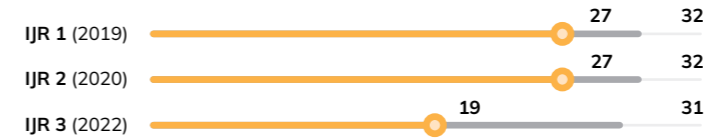
### महिलाएँ

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक है।



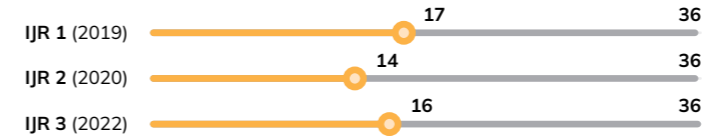
### ग्रामीण कवरेज

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा कवर किए गए गाँवों की औसत संख्या 150 से कम है।



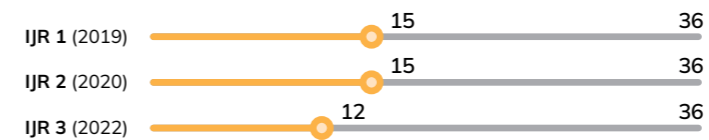
### बुनियादी ढांचा

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ कम से कम एक कानूनी सेवा क्लिनिक एक जेल में कार्य करता है।



### विवाद का समाधान

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ लोक अदालतों ने मुकदमेबाजी से पहले के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा किया।



\*राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या (36 में से) जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे।

### बजट

किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने कानूनी सहायता के लिए अपने पूरे राज्य बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया।



### कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च

**₹0.73**  
एनएएलएसए

**₹3.84**  
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

**₹4.57**  
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश+ एनएएलएसए

2020-21 के लिए बजट डेटा, मार्च 2021 के लिए जनसंख्या डेटा

### ग्रामीण कवरेज

विधिक या कानूनी सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले गाँवों की औसत संख्या 42 से बढ़कर 127 हो गई।



### विचाराधीन समीक्षा समिति

2021 में यू. टी. आर. सी. द्वारा जमानत के लिए अनुशासित 42,486 कैदियों में से केवल **39%** को रिहा किया गया था।



## अध्याय 4

# निःशुल्क कानूनी सहायता: सभी के लिए न्याय एक दूर के सपने समान

दुनिया भर में लगभग 5.1 बिलियन लोगों के पास न्याय तक सार्थक पहुंच नहीं है।

## परिचय

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि निःशुल्क कानूनी सहायता एक कार्यशील आपराधिक न्याय प्रणाली का आवश्यक तत्व है।<sup>2</sup> मुफ्त या आसान से मिलने वाली कानूनी सहायता चाहे प्रतिनिधि के द्वारा हो, परामर्श हो, मध्यस्थता हो, जागरूकता या रेफरल बढ़ाती हो- सभी के लिए न्याय तक पहुंचना सरल बनाती है।

तीसरा आईजेआर बजट पर दो नए पहलू जोड़ता है जिसमें बजट में सुधार और जिला कानूनी सेवाओं (डीएलएसए) में फ्रंट कार्यालयों की उपस्थिति शामिल है। इन पहलुओं में

२०२० के बाद सभी बड़े और छोटे दोनों राज्यों में, प्रमुख बदलाव देखे गए हैं जिसका मुख्य कारण बजट उपयोग में सुधार, मामलों का निपटान लोक अदालतों के द्वारा, और लैंगिक विविधता के सुधार की वजह से है।

झारखंड राज्य ने लगातार इस तालिका में सुधार किया है। वह 2019 में चौदहवें पायदान और 2020 में चौथे पायदान से, इस वर्ष पहले पायदान पर आ गया है। वहीं कर्नाटक, राज्य द्वारा बजट आवंटन में सुधार और पैनल वकीलों के बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व और पैरालीगल वॉलंटियर्स की सहायता से 14 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे पायदान पर आ गया है जो सभी बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे ज्यादा उछाल है। गुजरात 2019 में छठे और 2020 में नौवें स्थान से इस वर्ष तीसरे पद पर आ गया है। दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र इस वर्ष छह स्थान गिर कर, २०२० में पहले स्थान से अब सातवें स्थान पर आ गया है, जिसका मुख्य कारण कानूनी सहायता क्लीनिकों और निधि का ख़राब उपयोग है। दूसरे स्थान पर रहा बिहार पिछड़ कर अब सोलहवें स्थान पर आ गए हैं और उत्तर प्रदेश 2019 और 2022 में अठारहवां स्थान पर ही है।

## सहायता की किरण

कठिन संकट के समय पर( मार्च से जून के बीच मई ), कानूनी सहायता हेतु संस्थानों ने अपने परंपरागत काम के परे जा कर, दोनों निःशुल्क सहायता एवं मानवीय सहायता दी, जिसका प्रभाव इस चार महीने की अवधि में सीधे 71 लाख से अधिक लाभार्थियों पर हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने जेलों और न्यायपालिका के सहायता से 42, 772 विचाराधीन कैदी और 16,391 दोषियों को अंतरिम जमानत और पैरोल दी। इन संस्थानों द्वारा प्रवासी घर की ओर यात्रा कर रहे हैं लोगो को भोजन और दवा की भी सुविधा दी गयी थी।<sup>4</sup>

## कोविड-19 और विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियाँ (UTRCs)

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा, अप्रैल से जून 2020 के बीच में 18 राज्यों के डीएलएसए के कामकाज पर अध्ययन से ये बात सामने आई है कि 284 जिलों में से सिर्फ 231 जिलों में ही UTRC बने है। इन् में से सिर्फ 78 %यूटीआरसी हर हफ्ते मीटिंग के लिए मिलते है। चार राज्य-मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड- में आधे से भी कम अनिवार्य बैठकें हुए।<sup>5</sup>

छोटे राज्यों में, सिक्किम 2020 में तीसरे स्थान से बढ़कर 2022 में पहले स्थान पर आ गया, जबकि गोवा 2019 में शीर्ष स्थान पर रहने के बाद 2022 में दूसरे स्थान पर आ गया। लगातार सुधार होने के

कारण मेघालय 2019 में छठे से, 2020 में पांचवें स्थान पर से इस वर्ष तीसरे स्थान पर आ गया है, जबकि मिजोरम 2019 में दूसरे स्थान से खिसक कर 2020 में 6 चौथा और इस साल छठे स्थान पर आया है। अरुणाचल प्रदेश सातवें स्थान पर ही रहा।

## मानव संसाधन

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव रिक्ति (% , 31 मार्च, 2022)

प्रति लाख आबादी पर पैरा कानूनी वॉलंटियर्स (संख्या, 30 जून, 2022)

सचिवों को डीएलएसए के % के रूप में मंजूरी (% , 31 मार्च, 2022)

'कानूनी सहायता प्रदाताओं' में वकील (पैनल, रिटर्न,रिमांड), जेल जाने वाले वकील और, हाल ही में, कानूनी सहायता के लिए डिफेंस काउंसिल के पूर्णकालिक कार्यालय आते है। पैरालेगल वॉलंटियर्स जो पूरे देश में नियुक्त किए गए हैं उनका कार्य समुदाय और कानूनी सेवा संस्थानों के बीच की कड़ी को जोड़ना है। इनके कार्यों में कानूनी साक्षरता फैलाना, कानूनी सलाह देना और जैसे ही कोई भी विवाद होता है, उसका वहीं समाधान की सुविधा प्रदान करना है।<sup>6</sup>

**पूर्णकालिक सचिवों के बीच रिक्तियाँ:** कर्मचारियों की उपलब्धता में कमी निःशुल्क कानूनी संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रत्येक डीएलएसए की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास होना होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक न्यायिक अधिकारी को सचिव के रूप में और सहायक कर्मचारियों का एक समूह भी नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, प्रत्येक डीएलएसए में वकील और पैरालीगल वॉलंटियर्स होने चाहिए।

विधिक सहायता के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 2012<sup>7</sup> से सचिव को पूर्णकालिक बनाने पर जोर दिया गया है। कानूनी सहायता प्राधिकरणों में पद स्वीकृत करना और कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। मार्च 2022 तक डीएलएसए की संख्या 2020 में 669 से बढ़कर 2022 में 676 हो गई है।<sup>8</sup> मगर पूर्णकालिक सचिवों के लिए सिर्फ 603 स्वीकृत पद

थे जिसका मतलब है कि देश में सचिव के 73 पदों में कमी है। इस स्वीकृत पदों में भी केवल 533 पूर्णकालिक सचिवों की नियुक्ति की गई जो 143 पदों की रिक्ति मौजूदा डीएलएसए की संख्या के मुकाबले दर्शाती है।

छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रिक्तियों में वृद्धि देखी गई।<sup>9</sup> अठारह राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र और ओडिसा के सारे जिलों में पूर्णकालिक सचिव हैं।<sup>10</sup> मगर दूसरे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कमी देखी गयी है। मेघालय (73 प्रतिशत), त्रिपुरा (60 प्रतिशत),जम्मू एवं कश्मीर (41 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (31प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (28 प्रतिशत) और तेलंगाना (18 प्रतिशत) में सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की गई। नौ राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों ने एक भी पूर्णकालिक सचिव को मंजूरी या नियुक्ति नहीं दी।<sup>11</sup> उत्तर प्रदेश (71/74) में न्यायिक जिलों (Judicial Districts) की तुलना में कम डीएलएसए है, जबकि तेलंगाना (11/10),अरुणाचल प्रदेश (25/7) और मिजोरम (8/2) में न्यायिक जिलों की तुलना में अधिक डीएलएसए हैं।<sup>12</sup>

**वकील और पैरालीगल वॉलंटियर्स:** कानूनी सहायता मुख्यतः पैनलबद्ध वकील करते हैं जिन्हें नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए, जेलों का दौरा, या लोक अदालतों में सहायता करने के लिए कहा जा सकता है। जून 2022 तक पूरे 36 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में 50,316 वकील हैं जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। यह 2020 के आंकड़े 59,591 से कुल 16 % कम है।<sup>13</sup>

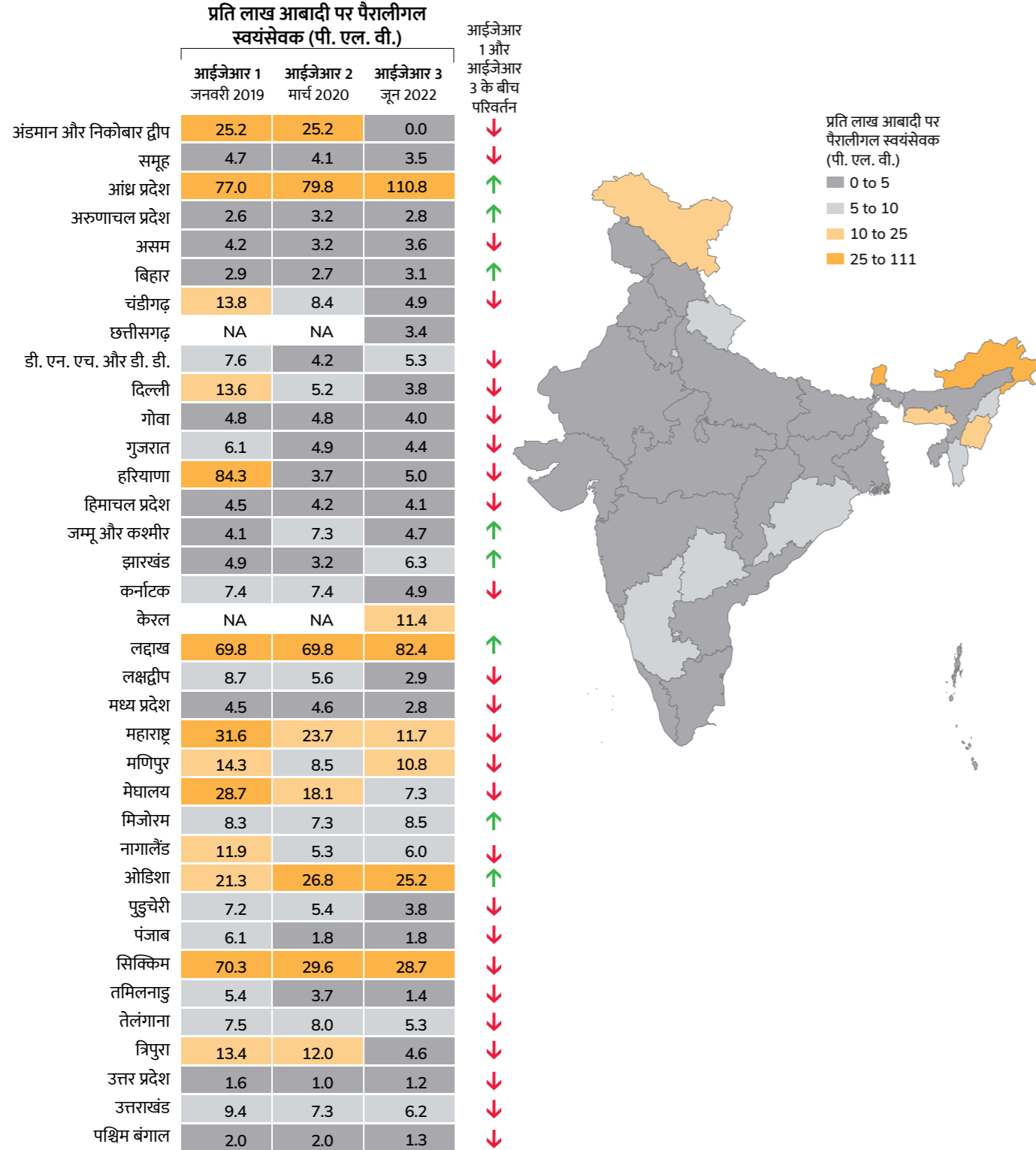
हालाँकि नालसा विनियम<sup>14</sup> इस प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है मगर पैनल में वकीलों की संख्या स्थापित करने के लिए कोई एक समान नीति मौजूद नहीं है। हालाँकि कुछ राज्यों में वकीलों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर तमिल नाडु के 32 जिलों में सारे विधिक सेवा संस्थानों का मिला कर 4438 वकील सूचीबद्ध थे, जबकि बिहार जिसकी जनसंख्या तमिल नाडु से ज्यादा है उसमें 37 जिले में सिर्फ 2129 वकील ही सूचीबद्ध थे।महाराष्ट्र में 5461 सूचीबद्ध वकील हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार है, में केवल 2,405 सूचीबद्ध वकील हैं। चौदह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>15</sup> में वकीलों का संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

1 शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए पथप्रदर्शक, सभी के लिए न्याय - न्याय पर कार्य बल की रिपोर्ट, अप्रैल 2019। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2019/06/Justice-for-All-report-1.pdf>  
2 सिद्धांत 1, आपराधिक न्याय प्रणालियों में कानूनी सहायता तक पहुंच के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और दिशानिर्देश, 2012।  
3 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, महामारी का जवाब : कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा सेवाओं का दस्तावेजीकरण, 2021। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI%20Reponding%20to%20th%20Pandemic%20Vol%201.pdf>  
4 NALSA का सांख्यिकीय स्नेपशॉट, 2020। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/statistical-snapshot/statistical-snapshot-2020>  
5 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, विचाराधीन समीक्षा समितियों के कार्यक्रम पर अध्ययन (अप्रैल से जून 2020 तक)। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.humanrightsinitiative.org/publication/study-vicharadhin-samiksah-samitiyon-ke-karyakram-par>

6 NALSA (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम 2010, हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर NALSA. एस. ओ. पी. 2011 और पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए NALSA की योजना, 2009 जो इन कानूनी सहायता प्रदाताओं की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।  
7 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, तालुक कानूनी सेवा समितियों और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियों के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश। (दिसंबर 2011 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में आयोजित कार्य समूहों की चर्चाओं के आलोक में)।  
8 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की संख्या पर डेटा NALSA के राज्य प्रोफाइल से है: डेटा का विस्तृत प्रतिनिधित्व (31 मार्च 2022 तक)। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/state-profil-2021-22>  
9 मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।  
10 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।  
11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डी. एन. एच. और डी. डी., लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम।  
12 प्रत्येक राज्य में न्यायिक जिलों की संख्या पर डेटा NALSA की राज्य प्रोफाइल डेटा का विस्तृत प्रतिनिधित्व (31 मार्च 2022 तक) से है। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/state-profil-2021-22>  
13 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आंकड़े जनवरी 2019 तक के हैं।  
14 NALSA (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम, 2010।  
15 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।

### चित्र 31: पैरालीगल वॉलंटियर्स : संख्याओं का मानचित्रण

(पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) लोगों और कानूनी सहायता प्रणाली के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रति डीएलएसए 50 सक्रिय पीएलवी के नालसा द्वारा बनाए गये नियम के बावजूद, यह संख्या सभी जिलों में एक समान नहीं है। 36 में से 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2020 और 2022 के बीच पीएलवी की संख्या कम कर दी।)



स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

पैरालीगल वॉलंटियर्स योजना में भी उपयुक्त संख्याओं का मुद्दा झलक कर आता है। नालसा प्रत्येक डीएलएसए<sup>16</sup> में 50 पैरालीगल वॉलंटियर्स का सुझाव देता है। परन्तु, 2022 में कई राज्य जैसे बिहार (4,446/1,850), दिल्ली (1,104/550), गुजरात (2,812/1,600) ने आवश्यकता से अधिक पीएलवी नियुक्त किये हैं, वहीं अन्य राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश (368/550), राजस्थान (1,449/1,800) और उत्तर प्रदेश (2,863/3,550) ने अपेक्षित संख्या से कम नियुक्तियाँ करी हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स कानूनी संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर तैयार करे थे जो जागरूकता फैलाने, परामर्श देने और समुदाय और कानून के बीच में दूरियाँ मिटाने का काम करते हैं। पीएलवी योजना के तेरह वर्ष के बाद भी कानूनी सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में उनकी क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। बीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी संख्या में कटौती की है।<sup>17</sup> पूरे देश में पीएलवी की संख्या में 15 प्रतिशत<sup>18</sup> गिरावट आई है, जब उनकी संख्या 2020 में 53,679 से 2022 में 45,636 हो गई।

### विविधता

पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , 30 जून 2022)

महिला पैरालीगल वॉलंटियर (% , 30 जून 2022)

एनएलएसए निधि का उपयोग (% , 2021-22) कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (% , 2021-22) राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (% , 2020-21)

**महिला पैनल वकील:** कानूनी सेवाओं का हर स्तर पर आम जनता का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। हालाँकि कानूनी सहायता समझने में जाति संरचना के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी है, लेकिन लिंग विविधता का डेटा का अनुमान सबको है। 2020 और 2022 के बीच, अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने महिला पैनल वकीलों की हिस्सेदारी बढ़ाई। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी हिस्सेदारी में 7 प्रतिशत, 18<sup>19</sup> से 25 फीसदी की वृद्धि देखी गयी है। मेघालय में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 60.4 प्रतिशत है, जिसके बाद नागालैंड (51.4 प्रतिशत), गोवा (45.3 प्रतिशत), सिक्किम (44.7 प्रतिशत) और केरल (42.4 प्रतिशत) थे। राजस्थान (8.6 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (10.5 प्रतिशत) के पैनल वकीलों में महिलाओं की

हिस्सेदारी सबसे कम पायी गई।

**महिला पैरालीगल वॉलंटियर्स:** राष्ट्रीय स्तर पर महिला पैरालीगल वॉलंटियर्स का सभी वॉलंटियर्स में हिस्सा मार्च 2020 में 35 प्रतिशत<sup>20</sup> से बढ़कर जून 2022 तक 40 प्रतिशत हो गया। सभी राज्यों में से कर्नाटक, गोवा, केरल और दिल्ली जैसे चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला पैरालीगल स्वयंसेविकाएँ थीं। लद्दाख में यह संख्या सबसे ज़्यादा 82 प्रतिशत और दूसरे नंबर पर सिक्किम में 76 प्रतिशत थी। नागालैंड (23 प्रतिशत), त्रिपुरा (25 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (25 प्रतिशत) और बिहार (27 प्रतिशत) ने महिलाओं का सबसे कम हिस्सा दर्ज किया।

### ट्रांसजेंडर्स: एक लंबा रास्ता

2014 में, उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को कानूनी की पहचान प्रदान करी।<sup>21</sup> 2022 तक, केवल 587 पैरालीगल ट्रांसजेंडर्स हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 183 हैं, जिसके बाद कर्नाटक (137) आता है जबकि सत्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>22</sup> में कोई भी ट्रांसजेंडर्स पैरालीगल नहीं काम करता है। ट्रांसजेंडर्स का न्याय सहायता के लिए चुने हुए वकीलों और सचिवों के बीच का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं है।

### बजट

एनएलएसए निधि का उपयोग (% , 2021-22)

कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (% , 2021-22)

राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (% , 2020-21) **नया**

नालसा (एक केंद्रीय निकाय) और राज्य दोनों मिलकर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वित्त प्रदान करते हैं। नालसा के अनुदान आमतौर पर ऐसे कार्यों के लिए होते हैं जिनमें लोक अदालतों का आयोजन, समझौता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वकीलों, पैरालीगल्स, मीडिएटर्स और लोक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों को भुगतान किया जाता है, जबकि राज्यों के योगदान का मुख्यतः योजना तंत्र, कर्मचारी और प्रशासनिक गतिविधियों में खर्च में होता है। राज्य अनिवार्यतः धारा 357-A के तहत पीड़ित मुआवजा कोष में भी योगदान देते हैं।

16 NALSA की पैरालीगल वॉलंटियर्स योजना। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/preventive-strategic-legal-services-schemes/scheme-for-para-legal-volunteers>  
 17 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।  
 18 जनवरी 2019 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और लक्षद्वीप के आंकड़े।  
 19 यह आंकड़ा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020 से है और इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (रैंक नहीं), लक्षद्वीप (रैंक नहीं) का डेटा शामिल नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट में दोहराया गया है कि इन राज्यों से मार्च 2017 के डेटा की अनुपलब्धता है।  
 20 Ibid  
 21 राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 2012 की 400]।  
 22 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।



पिछले दो वर्षों में, कानूनी सेवाओं के लिए कुल आवंटन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। नालसा द्वारा राज्यों को किया जाने वाला वित्तपोषण 2021-22<sup>23</sup> में 46 प्रतिशत बढ़कर 144.3 करोड़ रुपये हो गया (2020-21 में 99 करोड़ रुपये के मुकाबले)<sup>24</sup>। कानूनी सहायता बजट में राज्यों के योगदान में भी वृद्धि देखी गयी। उदाहरण स्वरूप, 2019-20 में, हरियाणा सरकार ने कुल कानूनी सहायता बजट का 68 प्रतिशत योगदान किया और शेष 32 प्रतिशत नालसा के माध्यम से आया। 2021-22 में, हरियाणा का राज्य योगदान 83 प्रतिशत बढ़ गया और केवल 6.5 करोड़ रुपये नालसा द्वारा पूरे कानूनी सहायता बजट के 38.6 करोड़ रुपये में दिया गया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, राज्यों की कानूनी सहायता पर खर्च असमान और कम रहा है। 2017-18 में, 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>25</sup> ने किसी भी प्रकार से कानूनी सेवाओं में वित्त योगदान नहीं किया था।<sup>26</sup> 2021-22<sup>27</sup> तक सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कानूनी सहायता बजट के लिए योगदान दिया है। योगदान करने की वृद्धि विभिन्न मामलों को सुझाती है: कानूनी सहायता की बढ़ती जागरूकता और बेहतर और अधिक व्यापक रूप से कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के महत्व की एक बढ़ती हुई मान्यता जो पूरी की जानी चाहिए,। नागालैंड और चंडीगढ़ को छोड़कर, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कानूनी सहायता बजट के 60 प्रतिशत से अधिक योगदान किया। चार राज्य—गोवा, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश—ने 90 प्रतिशत से अधिक योगदान किया। असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के योगदान में थोड़ी कमी देखी गई।

रोचक तौर पर, 2021-22 में नालसा के अनुदान के कुल उपयोग में कमी आई। राज्यों को आवंटित किए गए 183 करोड़ रुपये (1.83 अरब) में से 138 करोड़ रुपये (1.38 अरब) का इस्तेमाल ही नहीं किया गया।<sup>28</sup> केवल झारखंड और मणिपुर ने 100 प्रतिशत का उपयोग किया, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम (प्रत्येक 97 प्रतिशत), जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने केवल 50 प्रतिशत अनुदान का इस्तेमाल किया किया। गोवा ने सबसे कम (49) प्रतिशत का ही उपयोग किया।<sup>29</sup>

राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (2020-21): राज्यों ने अपने आवंटित बजटों का अधिकांश, 50 प्रतिशत<sup>30</sup> से अधिक का उपयोग किया, हालांकि चंडीगढ़ (38.5 प्रतिशत), मेघालय (49 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (35 प्रतिशत) जैसे अन्य राज्यों में इस उपयोग की कमी आई। उत्तर प्रदेश ने 133 करोड़ रुपये (1.33 अरब) के आवंटन में से 87 करोड़ रुपये (0.87 अरब) का उपयोग ही नहीं किया। कर्नाटक और

### चित्र 32: बजट का उपयोग

किसी राज्य के कानूनी सहायता खर्च में राज्यों को खुद का पैसा और केंद्र से नालसा द्वारा प्राप्त पैसा इस्तेमाल करना होता है। निम्नलिखित आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य दोनों निधियों का कितनी अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं।

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	उपयोग (%)	
	नालसा निधि का उपयोग किया गया (%), 2021-22	राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग किया गया (%), 2020-21
आंध्र प्रदेश	50	100
बिहार	61	70
छत्तीसगढ़	75	54
गुजरात	77	93
हरियाणा	82	78
झारखंड	100	51
कर्नाटक	69	100
केरल	70	69
मध्य प्रदेश	65	94
महाराष्ट्र	87	83
पंजाब	50	81
राजस्थान	74	96
तमिलनाडु	76	99
तेलंगाना	81	57
उत्तर प्रदेश	68	86
उत्तराखंड	57	35
उत्तराखंड	73	72
पश्चिम बंगाल	73	72
उत्तराखंड	67	89
छोटे राज्य		
अरुणाचल प्रदेश	97	NA
गोवा	49	81
हिमाचल प्रदेश	77	99
मेघालय	63	49
मिजोरम	97	92
सिक्किम	125	75
त्रिपुरा	59	96

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए), राज्यों के बजट दस्तावेज

आंध्र प्रदेश ने अपनी पूरी राशियों का उपयोग किया जबकि केवल बारह राज्यों ने 80 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया।<sup>31</sup>

### आधारभूत संरचना

राज्य न्यायिक जिलों के % के रूप में डी. एल. एस. ए. (%), 31 मार्च 2022)  
गाँव प्रति कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या, 2021-22)  
प्रति जेल कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या, 2021-22)  
डी. एल. एस. ए. में सामने के कार्यालयों की उपस्थिति (%), 30 जून 2022) नया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत हुआ जो कानूनी सेवा संस्थानों के एक नेटवर्क का नेतृत्व करता है। इस नेटवर्क में राज्य के (37), जिला (676) और उप-विभागीय या तालुक स्तर (2,361), साथ ही अपीलीय अदालतों यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल है।

मार्च 2020 से 2022 तक, जब कोरोना महामारी पूरे विश्व पर छाई हुए थी, कानूनी सेवा संस्थानों (LSIs) के नेटवर्क में काफी बढ़ोति हुई; 7 नए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSAs) और 82 और तालुका कानूनी सेवा समितियों (TSCs) को जोड़कर, जिनकी कुल संख्या क्रमशः 676 और 2,361 हो गई।

**मुख्य कार्यालय:** सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक कानूनी सेवा संस्थान, सहित को "मुख्य कार्यालय"<sup>32</sup> होने की आवश्यकता होती है। मुख्य कार्यालय रिटेनर वकील और/या पैरालीगल वॉलंटियर्स<sup>33</sup> द्वारा संचालित सेवा प्रदान हेतु कार्यालय हैं, जिनमें केवल कानूनी सहायता और सलाह ही नहीं, बल्कि वकीलों और ग्राहकों के बीच मामले की स्थिति के बारे में संवाद भी होता है।<sup>34</sup>

इस रिपोर्ट की तीसरी संस्करण के लिए, लेखकों ने नालसा से राज्यों में कानूनी सेवा संस्थानों और मुख्य कार्यालयों की संख्या के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध किया। नालसा केवल DLSAs पर मुख्य कार्यालयों की जानकारी प्रदान कर सका और इस प्रकार रिपोर्ट में केवल जिले के स्तर पर मुख्य कार्यालयों को शामिल किया गया है। अधिकांश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सभी DLSAs में मुख्य कार्यालय स्थापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में 23 DLSAs के 25 मुख्य कार्यालय थे जिसमें दिल्ली में 11 DLSAs के 12 मुख्य कार्यालय, सिक्किम में 4 DLSAs के 8 मुख्य कार्यालय और पुडुचेरी में 1 DLSA

के 2 मुख्य कार्यालय थे। मेघालय के अलावा सभी राज्यों में सभी DLSAs में मुख्य कार्यालयों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिसमें 11 DLSAs में 9 कार्यालय थे, और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 25 DLSAs के 15 मुख्य कार्यालय थे।

**कानूनी सहायता क्लिनिक:** सभी के लिए न्याय की पहुंच के लिए कानूनी सेवाएँ उन समुदायों के लिए मौजूद होनी चाहिए जिनको इन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। कानूनी सहायता क्लिनिकों का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कानूनी परामर्श, रेफरल और प्रतिनिधित्व सेवाएँ प्रदान करना है जहाँ लोग "भौगोलिक, सामाजिक और अन्य बाधाएँ"<sup>35</sup> से जूझ रहे हैं। नालसा का नियम क्लिनिकों की संख्या और स्थान का निर्धारण किए बिना कहता है की हर "एक गांव या गांवों के एक समूह" में एक क्लिनिक होना चाहिए।<sup>36</sup>

मार्च 2020 से मार्च 2022 तक, भारत के करीब 6 लाख गांवों में कानूनी सहायता क्लिनिकों की संख्या 66.6 प्रतिशत कम हो गई जब इसमें 14,159 से 4723 की गिरावट दर्ज की गयी। इसका मतलब है कि प्रति कानूनी सहायता क्लिनिक के गांवों का राष्ट्रीय औसत 42 से 127 बढ़ गया। अधिकांश राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के गांवों में कानूनी सेवा क्लिनिकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। कानूनी सहायता के कार्यकर्ताओं के अनुसार, कानूनी सहायता क्लिनिकों की संख्या में आकस्मिक गिरावट अनुकूलन प्रयासों (Optimisation Efforts) का हिस्सा है।

पूर्ण प्रदर्शन के मूल्यांकन की बिना कानूनी सहायता क्लिनिकों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना कठिन है। नालसा के अनुसार, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच, ऐसे क्लिनिक जिनमें लोग गए थे, उनकी संख्या 11.9 लाख थी, जिनमें से 7.3 लाख को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी। यह 2017-18 से अब तक इन क्लिनिकों में लोगों की सबसे अधिक संख्या रही है, जब 6.9 लाख लोग आए थे और 5.6 लाख को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी।<sup>37</sup>

केवल केरल और त्रिपुरा के पास 1 क्लिनिक है जो कम से कम 10 गांवों को कवर करता है और केंद्रशासित प्रदेशों में—चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी के पास 1 क्लिनिक है, जो औसतन कम से कम 10 गांवों को सहायता पहुँचाता है। शेष बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में यह आउटरीच बहुत खराब है। झारखंड में 2,107 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,019 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था; बिहार में 814 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था और राजस्थान में 475 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही कानूनी सेवा क्लिनिक था जिसने राज्य में सभी गांवों (19,567) को कवर किया है।

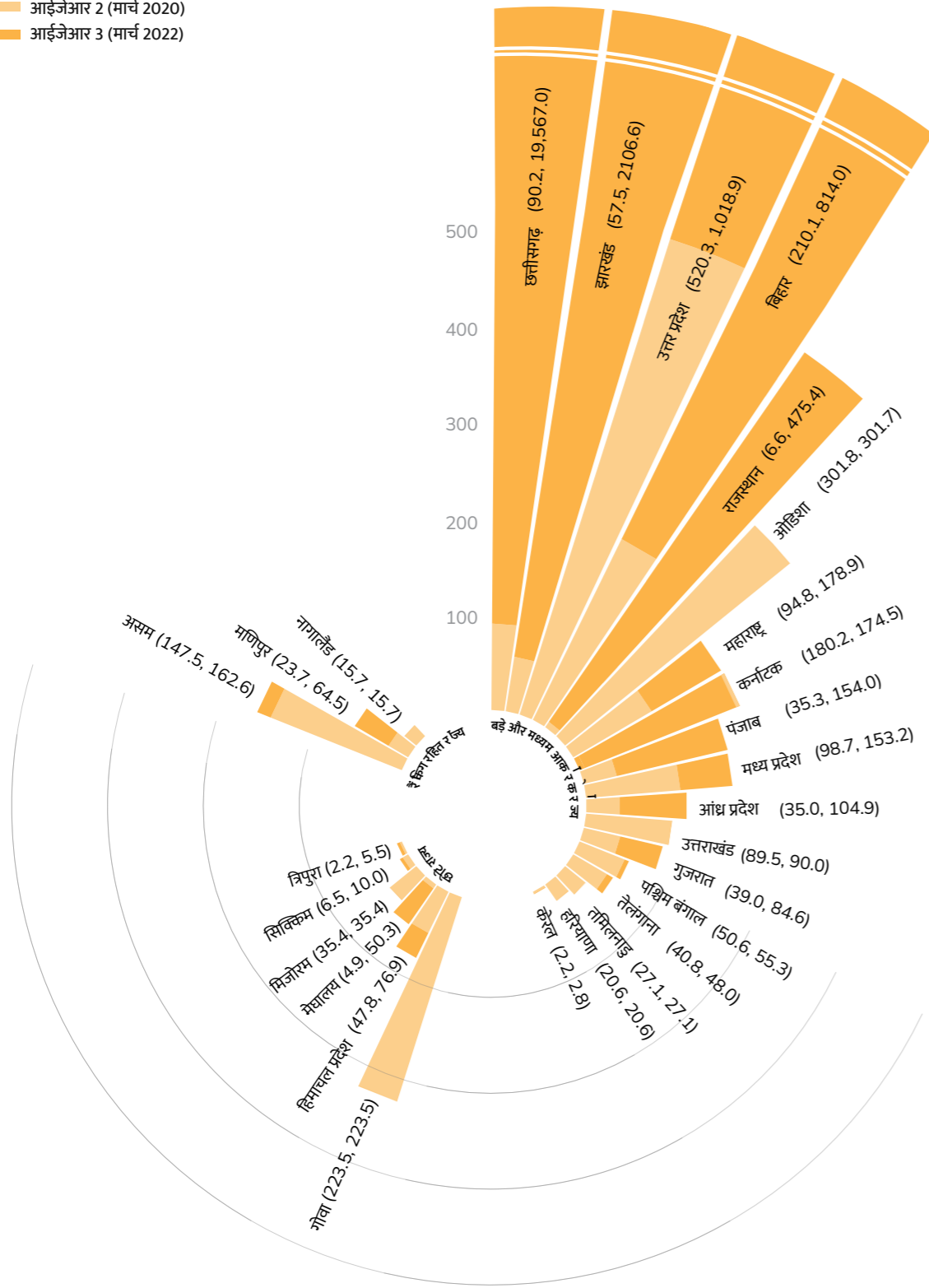
23 2021-22 में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अनुदान। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/grants-and-accounts/grands/grants-2021-2022>  
24 2020-21 में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अनुदान। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/grants-and-accounts/grands/grants-2020-2021>  
25 झारखंड, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डीएनएच और डीडी और लक्षद्वीप।  
26 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019, पृ. 85. यहां उपलब्ध है: <https://www.tatatrusts.org/upload/pdf/overall-report-single.pdf>  
27 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, लक्षद्वीप के लिए डेटा अनुपलब्ध था।  
28 इस रिपोर्ट में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को NALSA निधि के कुल आवंटन में पिछले वर्ष की लंबित शेष राशि शामिल है। NALSA द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटन का डेटा NALSA की राज्य प्रोफाइल से है दस्तावेज। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/state-profiles-2021-22>  
29 यह संकेतक सिक्किम को रैंकिंग से बाहर करता है क्योंकि इसने 2021-22 में राज्य को आवंटित की तुलना में अधिक उपयोग दर्ज किया है। गैर-रैंकिंग वाले राज्यों में, दिल्ली और नागालैंड में आवंटित से अधिक उपयोग दर्ज किया गया।  
30 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात।

31 गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।  
32 NALSA (मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं) विनियम, 2010  
33 NALSA सक्षम कानूनी सेवा विनियम, 2010  
34 फ्रंट ऑफिसों पर NALSA के दिशानिर्देश।  
35 NALSA (कानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011।  
36 Ibid  
37 अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के बीच कानूनी सेवा क्लिनिकों के संबंध में NALSA की सांख्यिकीय जानकारी। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics/legal-service-clinics-april-2017-to-march-2018>

### चित्र 33: एक कानूनी सहायता क्लिनिक पर कितने प्रति गाँव

NALSA नियमों के अनुसार "एक गाँव या गाँवों के समूह की सेवा" के लिए एक क्लिनिक की आवश्यकता होती है। हालाँकि, देश भर में कानूनी सेवा क्लिनिकों की संख्या में भारी गिरावट के कारण प्रति कानूनी सेवा क्लिनिक गाँवों का राष्ट्रीय औसत 2020 में 42 से बढ़कर 2022 में 127 हो गया है।

आईजेआर 2 (मार्च 2020)  
आईजेआर 3 (मार्च 2022)



नोट 1. आई. जे. आर. 3 में गाँवों की संख्या के अवरोही क्रम में राज्यों को समूह के भीतर व्यवस्थित किया गया है। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) में गाँव हैं लेकिन गाँवों में कोई कानूनी सेवा क्लिनिक नहीं है।  
स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

**जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक:** NALSA (कानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 में कहा गया है जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिकों का होना अनिवार्य है।<sup>38</sup> कैदियों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए मार्गदर्शिकाएँ<sup>39</sup> के माध्यम से यह दिशा-निर्देशित किया गया है कि कुछ चयनित वकीलों को 'जेल दौर करे वाले वकील' नामित किया जाना चाहिए और उन्हें सप्ताह में कम से कम दो बार जेल में जाना चाहिए।<sup>39</sup> आदर्श रूप से, प्रत्येक जेल के पास अपनी कानूनी सहायता क्लिनिक होनी चाहिए। हालाँकि, 20 राज्यों/केंद्र<sup>40</sup> शासित प्रदेशों में अब भी इस मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता है।<sup>41</sup> गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्लिनिकों की संख्या जेलों की संख्या से अधिक है।<sup>43</sup> गुजरात के 32 जेलों में 58 क्लिनिक, पश्चिम बंगाल के 60 जेलों में 72 क्लिनिक, पंजाब के 26 जेलों में 27 क्लिनिक, और छत्तीसगढ़ के 33 जेलों में 34 क्लिनिक हैं। छोटे राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में जेलों से अधिक क्लिनिकें हैं—2 जेलों के लिए 5 क्लिनिकें हैं जबकि मेघालय, गोवा और सिक्किम में प्रत्येक जेल में क्लिनिकें हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में अब तक सभी जेलों में क्लिनिकें नहीं हैं।

### कार्यभार

पी. एल. ए. मामले: प्राप्त मामलों के % के रूप में निपटाए गए (%), 2021-22)

एस. एल. एस. ए. एल. ए.: मुकदमे से पहले के मामले कुल मामलों के % के रूप में निपटाए गए (%), 2021-22)

कुल एल. ए. एन. एल. ए. + एस. एल. एस. ए. एल. ए.: निपटाए गए मामलों में मुकदमे से पहले के मामलों का हिस्सा (%), 2021-22)

लोक अदालत: वैकल्पिक विवाद समाधान(Alternate Dispute Resolution) तंत्रों के लिए विरोध होने के बावजूद उनके अदालतों में लंबित मामलों में हस्तक्षेप कर न्यायिक प्रणाली को सुधारने की क्षमता है। एडीआर विवादों को समझौते के माध्यम से समाधान करने का एक सस्ता और समय-कुशल तरीका प्रदान करने की क्षमता है। लोक अदालतें, जिन्हें 'लोगों की अदालतें' भी कहा जाता है, वैकल्पिक विवाद समाधान का एक प्रमुख माध्यम है। उन्हें राज्य की कानूनी सेवा संस्थानों

और नालसा की संरक्षण में दोनों तरीकों से आयोजित किया जाता है और वे दो प्रकार के मामलों को संलग्न करते हैं:

- किसी भी न्यायालय के सामने कोई भी लंबित मामले।
- कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और किसी अदालत के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है, या एक मामला मुकदमे होने के पहले के चरण में हो।<sup>44</sup>

इसी संदर्भ में सरकार द्वारा स्थायी लोक अदालतें<sup>45</sup> भी स्थापित की गई हैं ताकि आवश्यक प्री लिटिगेशन समझौता और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे कि परिवहन सेवाएँ, डाक सेवाएँ, टेलीफोन सेवाएँ आदि के विवादों का समझौता प्रदान किया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार प्रत्येक राज्य प्राधिकरण को स्थायी लोक अदालत स्थापित करने का अधिकार है जो वो आवश्यकता के अनुसार काम कर सकते हैं।<sup>46</sup> 2022 मार्च तक, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी स्थायी लोक अदालत सक्रिय नहीं थी।<sup>47</sup> 2021-22 में, उन्होंने 29,153 बैठकों के बीच 118,136 मामलों को निपटाया, जिनकी कुल समझौते की कीमत लगभग 466 करोड़ (4.66 अरब) थी।<sup>48</sup> यह 2018-19 से वृद्धि है, जब लोक अदालतों ने 26,615 बैठकों के बीच 102,625 मामलों को निपटाया किया।<sup>49</sup> केवल 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 50 प्रतिशत से अधिक मामले को निबटारा(Disposal) जिसमें गुजरात ने प्राप्त सभी मामलों में निबटारा किया।<sup>50</sup> महाराष्ट्र द्वारा मुकदमे सुलझाने की दर 2019-20 में 83 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 36 प्रतिशत हो गई। केरल ने केवल 4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 8 प्रतिशत और बिहार ने मात्र 11 प्रतिशत मुकदमों का निबटारा किया।

### प्री लिटिगेशन मामले

**राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निबटारे प्री लिटिगेशन मामले:** जिस प्रकार लोक अदालतें प्री लिटिगेशन मामलों को निबटारती हैं, वह न्यायिक कार्य प्रणाली के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालाँकि यह प्रक्रिया आलोचना से मुक्त नहीं है, लेकिन यह लंबित मामलों में एक बड़े बोझ तले न्यायिक प्रणाली और मुकदमा करने वालों को कुछ राहत प्रदान करता है। प्री लिटिगेशन मामलों का निबटारा किए जाने वाले प्रतिशत और कुल मामलों का निबटारा और संज्ञान में लिए गए कुल मामलों की संख्या महत्वपूर्ण माप है।<sup>51</sup>

38 हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2016। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-for-hirasat-men-rekhe-gaye-vyaktiyon-ka-pratinidhitva>। NALSA ने 2022 में इस योजना को संशोधित किया है और प्रत्येक जिले में डीएलएसए को प्रत्येक परिसर के भीतर एक जेल कानूनी सहायता क्लिनिक (पीएलएसी) स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। NALSA (कानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 और हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए एसओपी, 2016।

39 हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2016।

40 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

41 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

42 अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

43 कुछ मामलों में, जेलों से अधिक न्यायिक जिलों में सेवा प्रदान करती हैं। ऐसे मामलों में, प्रत्येक डीएलएसए उसी जेल में एक क्लिनिक स्थापित करता है।

44 धारा 10, NALSA लोक अदालत विनियम, 2009। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-loc-adalat-regulations-2009>

45 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी-22ई: 'राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए हैं और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

46 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987>

47 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

48 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक स्थायी लोक अदालतों पर NALSA सांख्यिकी, यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics/permanent-loc-adalat-april-2021-to-march-2022>

49 अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक स्थायी लोक अदालतों पर NALSA सांख्यिकी। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics/permanent-loc-adalat-april-2018-to-march-2019>

50 छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब।

51 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019, op. cit., p. 86.

## चित्र 34: लोक अदालतों का प्रदर्शन

निम्नलिखित तालिका राष्ट्रीय लोक अदालतों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्री लिटिगेशन मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाती है।

	राष्ट्रीय लोक अदालतें (2021-22)		एसएलएसए लोक अदालतें (2021-22)			कुल एल. ए. मुकदमों से पहले के मामलों का निपटारा (%) <sup>1</sup>	एस. एल. एस. ए. एल. ए.: उठाए गए मामलों में पूर्व-मुकदमा (%) <sup>2</sup>
	मुकदमों से पहले के मामलों का उठाए गए	मुकदमों से पहले के मामलों का निपटारा	मुकदमों से पहले के मामलों का उठाए गए	मुकदमों से पहले के मामलों का निपटारा	कुल मामलों का निपटारा किया गया बड़े और मध्यम आकार के राज्य		
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>							
आंध्र प्रदेश	100,828	63,271	7,395	1,657	19,558	25.1	8.5
बिहार	1,619,511	173,734	1,241	6	1,260	74.0	0.5
छत्तीसगढ़	481,462	256,225	10	10	1,511	70.7	0.7
गुजरात	684,495	92,563	19,456	255	50,840	9.1	0.5
हरियाणा	115,349	45,945	0	0	183,542	13.1	0.0
झारखंड	540,222	366,866	20,741	19,289	25,336	78.9	76.1
कर्नाटक	286,268	108,199	175	23	5,221	6.6	0.4
केरल	120,363	25,422	27,738	4,858	184,575	16.8	2.6
मध्य प्रदेश	1,970,848	343,195	3,925	47	17,282	71.7	0.3
महाराष्ट्र	18,072,798	3,908,090	15	1	45	93.2	2.2
ओडिशा	257,100	10,733	0	0	1,770	22.0	0.0
पंजाब	219,112	25,264	374	18	6,294	11.4	0.3
राजस्थान	654,802	146,809	985	84	17,182	29.7	0.5
तमिलनाडु	127,932	31,159	57,398	7,517	76,747	11.9	9.8
तेलंगाना	102,418	95,270	2,803	1,605	9,043	14.0	17.7
उत्तर प्रदेश	11,842,568	6,571,895	46,978	24,010	65,708	74.6	36.5
उत्तराखंड	27,511	5,927	12	12	19,190	15.8	0.1
पश्चिम बंगाल	164,907	33,245	58,340	42,179	93,743	20.6	45.0
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचल प्रदेश	6,775	531	211	91	211	44.8	43.1
गोवा	4,506	264	312	47	1,857	5.4	2.5
हिमाचल प्रदेश	63,405	22,047	0	0	73,822	29.3	0.0
मेघालय	3,445	628	316	34	619	57.0	5.5
मिजोरम	6,976	1,589	464	169	551	88.4	30.7
सिक्किम	172	109	1,157	492	1,590	75.4	30.9
त्रिपुरा	11,367	1,690	7,908	1,280	29,317	21.7	4.4
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,490	404	0	0	35,117	8.8	0.0
चंडीगढ़	25,846	145	681	37	0	1.0	4.5
डी. एन. एच. और डी. डी.	1,784	82	0	0	0	20.4	0.0
दिल्ली	104,453	87,776	9,127	8,769	0	22.8	5.9
जम्मू और कश्मीर	147,288	109,019	999	547	822	45.2	10.5
लद्दाख	674	478	1	0	0	25.8	0.0
लक्षद्वीप	106	59	0	0	149,500	92.2	0.0
पुडुचेरी	4,200	184	4,512	190	5,191	5.6	4.0
<b>कमहान राज्य</b>							
असम	391,148	34,920	2,033	1,051	43	47.9	3.0
मणिपुर	1,280	940	0	0	0	88.3	0.0
नागालैंड	3,144	1,098	0	0	4,728	92.3	0.0
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>38,166,553</b>	<b>12,565,775</b>	<b>275,307</b>	<b>114,278</b>	<b>1,082,215</b>	<b>60.0</b>	<b>10.6</b>

टिप्पणी: 1. एन. एल. ए. + एस. एल. एस. ए. एल. ए.: निपटारे गए मामलों में मुकदमों से पहले के मामलों का हिस्सा। 2. एस. एल. एस. ए. एल. ए.: मुकदमों से पहले के मामलों का निपटारा कुल मामलों के % के रूप में किया गया स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एन. ए. एल. एस. ए.)

अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक आयोजित पांच राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 2.06 करोड़ (20,583,396) मामलों का निबटारा किया, जिनमें 1.26 करोड़ (12,565,775) प्री लिटिगेशन मामले थे, जिनकी कुल कीमत 7,322 करोड़ थी। यह 2018-19 से वृद्धि है, जब इतने ही राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हुआ था और कुल 0.59 करोड़ (5,908,612) की कीमत के मामलों का निबटारा हुआ था, जिनमें 0.33 करोड़ (3,294,463) प्री लिटिगेशन मामले थे। उत्तर प्रदेश (65.7 लाख मामलों) ने सबसे अधिक प्री लिटिगेशन मामलों का निबटारा किया जिसके बाद महाराष्ट्र (39.1 लाख) और झारखंड (3.7 लाख) आते हैं। प्री लिटिगेशन मामलों की संख्या के साथ तुलना करने पर, 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल मामलों में से 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का निबटारा किया।<sup>52</sup> तेलंगाना (93 प्रतिशत) ने सारे राज्यों में सर्वाधिक मामलों का निबटारा किया, जबकि उड़ीसा (4 प्रतिशत) और गोवा (6 प्रतिशत) ने सबसे कम मामलों में निबटारा किया। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्री लिटिगेशन मामलों के स्तर पर प्राप्त किए गए मामलों में 10 प्रतिशत से कम मामलों का निबटारा किया।<sup>53</sup>

**राज्यों द्वारा आयोजित लोक अदालतों द्वारा उठाए गए प्री लिटिगेशन मामले:** 2021-22 के दौरान एसएलएसए (SLSAs) के द्वारा आयोजित 74,480 लोक अदालतों में, हरियाणा (54,762) ने सबसे अधिक आयोजित किया, और उसके बाद गुजरात (5,157) तालिका में दूसरे पायदान पर आया। राष्ट्रीय रूप में, इन लोक अदालतों ने कुल 10 लाख मामलों का संज्ञान लिया, जिनमें वे केवल 11 प्रतिशत का प्री लिटिगेशन स्तर पर निबटारा किया गया। झारखंड उल्लेखनीय अपवाद है क्योंकि यह एकमात्र राज्य है जिसने प्राप्त हुए मामलों में से 50 प्रतिशत प्री लिटिगेशन मामलों को निपटारा किया। अधिकांश राज्यों ने प्री लिटिगेशन स्तर पर प्राप्त किए गए मामलों के साथ 10 प्रतिशत से कम मामलों को निपटारा और 4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश—हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख और उड़ीसा—ने कोई मामला नहीं निपटारा।

**राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतों द्वारा उठाए गए प्री लिटिगेशन मामले:** सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों और एसएलएसए द्वारा आयोजित लोक अदालतों को मिलाकर प्री लिटिगेशन स्तर पर 1.27 करोड़ मामलों का निबटारा किया। राष्ट्रीय स्तर पर 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों<sup>54</sup> ने 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का प्री लिटिगेशन स्तर पर निबटारा किया जबकि 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 प्रतिशत से कम मामलों को निपटारा।<sup>55</sup> महाराष्ट्र (93 प्रतिशत) में प्री लिटिगेशन स्तर पर सबसे अधिक मामलों का निबटारा हुआ था, जिसके बाद झारखंड में 79 प्रतिशत था। सबसे कम स्तर पर कर्नाटक है जिसमें निबटारे की दर मात्र 6.6 प्रतिशत था और उसके बाद गुजरात (9.1 प्रतिशत) की दर आती है। छोटे राज्यों में, मिजोरम (88 प्रतिशत) ने सबसे अधिक प्री लिटिगेशन मामलों को निबटारा किया जबकि गोवा (5 प्रतिशत) सबसे पीछे रहा।

52 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

53 असम, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी और ओडिशा।

54 बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश।

55 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और पुडुचेरी।

56 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड।

57 निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 565/2012) में अदालत दिनांक 11 मई 2018। यहां उपलब्ध है: <https://indiankanoon.org/doc/134824430/>

पीड़ित प्रतिकार योजना (विक्टिम कंपनसेशन स्कीम) - कानूनी सहायता प्रणाली की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक पीड़ित प्रतिकार योजना है, जो उन पीड़ितों या निर्भरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने किसी अपराध के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान या चोट से कष्ट उठाया है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। हालांकि व्यापक दिशा-निर्देश होते हुए भी, विभिन्न पीड़ित प्रतिकार योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया गया। 2016-17 से 2021-22 तक, राज्यीय कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरणों ने कुल मिलाकर 97,037 आवेदन प्राप्त किए जिनमें कंपेंसेशन की मांग की गई थी। इनमें से, सभी राज्यों को मिला कर, केवल 64,333 (66 प्रतिशत) आवेदनों का निबटारा किया गया।

2021-22 में, दिल्ली (2,421), छत्तीसगढ़ (2,195), ओडिशा (1,898), राजस्थान (1,517) और गुजरात (1,188) को सबसे अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। कुल 8,363 आवेदनों का निर्णय लिया गया था, जिनमें 123 करोड़ रुपये (1.23 अरब) की राशि का वितरण किया गया। इन राज्यों ने सभी प्राप्त किए गए कंपेंसेशन का 55 प्रतिशत का योगदान दिया। राष्ट्रीय रूप से, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 15,173 आवेदनों पर लगभग 222 करोड़ रुपये (2.22 अरब) का कंपनसेशन प्रदान किया। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड ने सबसे कम कंपेंसेशन प्रदान किया। आंध्र प्रदेश ने 62 मामलों पर 86.4 लाख रुपये प्रदान किए, जबकि तेलंगाना ने 69 मामलों पर 87.7 लाख रुपये और उत्तराखंड ने 46 आवेदनों पर 1.05 करोड़ रुपये प्रदान किए। कंपेंसेशन राशि को अदालत द्वारा तय किया जाता है जिसमें अपराध की गंभीरता और पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

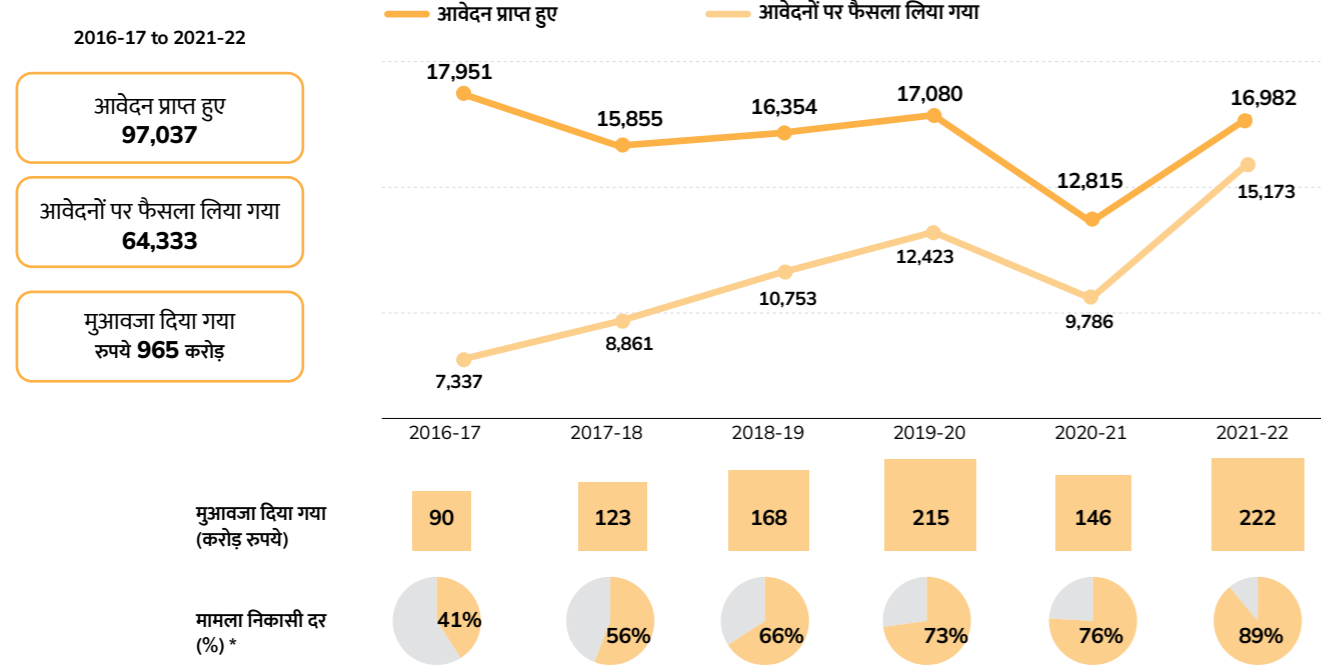
राष्ट्रीय रूप से, गोवा ने सबसे कम मात्रा में कंपेंसेशन प्रदान किया जहां केवल 2,50,000 रुपये 34 आवेदनों के तहत प्रदान किए गये।

पूरे देश में, कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा 89 प्रतिशत मामले निर्णीत किए गए थे। बारह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों<sup>56</sup> ने प्राप्त मामलों के केवल 60 प्रतिशत से कम मामलों का निबटारा किया। अरुणाचल प्रदेश ने केवल 10 प्रतिशत और केरल ने 25 प्रतिशत मामलों का निबटारा किया। छोटे राज्यों में, मिजोरम ने सबसे कम केसों (5 प्रतिशत) का निबटारा किया और सिक्किम ने उन सभी मामलों का समाधान किया जो उन्हें मिले।

इसके अलावा, डेटा से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मुआवजा<sup>57</sup> को पुनर्प्राप्ति का एक तरीका के रूप में जानने में आम जानता की जागरूकता की कमी है। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को नालसा के मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया था

### चित्र 35: पीड़ित मुआवजा

व्यापक दिशानिर्देशों के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न पीड़ित मुआवजा योजनाओं का कार्यान्वयन घटिया बना हुआ है।



\* प्राप्त होने वाले प्रत्येक 100 आवेदनों पर निर्णय लिया जाता है। स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

जिसमें विशेष रूप से यौन शोषण के पीड़ितों को हक देने की बात की गई थी। हालांकि, 2021 में पूरे देश में दर्ज 121,161 यौन शोषण के मामलों की तुलना में 2020-21 में मुआवजा के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों (12,815) की संख्या कुल मामलों का केवल 10.5 प्रतिशत थी।

पांच वर्षों के अवलोकन में (2016-17 से 2021-22 तक), अदालतों

द्वारा प्राप्त मामलों की संख्या और कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त संख्या को अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 तक पहुँचने की आवश्यकता थी। 2016 से, राष्ट्रीयस्तर पर कुल 97,037 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल 66 प्रतिशत (64,333) का निर्णय लिया गया था। सभी आवेदन जिनका 'निर्णय' लिया गया है, उनमें आवश्यक रूप से मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है।

### कानूनी सहायता रक्षा प्राधिकरण प्रणाली

80 प्रतिशत आबादी, जो इसके हकदार हैं, के लिए स्वतंत्र और गुणवत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व की पहुंच में सुधार और विस्तार करने की आवश्यकता ने आपराधिक मामलों में नए और अधिक जवाबदेह कुशल कानूनी प्रतिनिधित्व खोजने के लिए प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

2019 में, नालसा ने 13 जिलों में कानूनी सहायता रक्षा प्राधिकरण योजना ( Legal Aid Defence Counsel Scheme) का प्रारंभ किया। इसमें क्रिमिनल मामलों में पूर्व-गिरफ्तारी से लेकर अपील के स्तर तक सत्र, विशेष और मैजिस्ट्रेट कोर्टों में कानूनी

प्रतिनिधित्व, सलाह और संदर्भ प्रदान करने के लिए पूर्णकालिक वकीलों की भर्ती की गई है। नालसा का सुझाव है कि प्रत्येक ऐसी इकाई में अधिकतम 14 वकील और 5 सहायक कर्मचारी होने चाहिए। यह इकाई डीएलएसए के परिसर से काम करेगी और इसे प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक समिति द्वारा चयनित किया जाएगा, जिसमें जुर्म के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा।

2022 के जुलाई में, यह परियोजना 350 जिलों तक विस्तारित की गई। वर्तमान में अविकसित होने के बावजूद, इसका मूल्य तभी पता चलेगा जब इसको नागरिकों द्वारा इस्तेमाल करे जाने का विस्तार होगा और सलाहकार और नागरिक दोनों की संतुष्टि का मूल्यांकन किया जाएगा।

58 यौन उत्पीड़न के मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376-ए-ई (बलात्कार) और धारा 354-ए-डी (शौल भंग करने के इरादे से हमला) के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। डेटा यहां से लिया गया है भारत में अपराध, 2021। यहां उपलब्ध है: <https://ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2021>  
 59 एल. ए. डी. सी. को 17 वीं अखिल भारतीय बैठक, 2019 में अपनाया गया। एनएलएसए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना, 2021। यहां उपलब्ध है <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/legal-aid-defense-counsel-system-2>

### अनावश्यक पूर्व-न्यायिक निर्वासन

नितदिन बढ़ते हुए जेल में कैदियों की जनसंख्या के संबंध में चिंतित होकर, 2013 में उच्चतम न्यायालय 'In Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisons'<sup>60</sup> के तहत, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा), गृह मंत्रालय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एएसएलएसए) को अंडरट्रायल समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना करने के लिए निर्देश दिए थे। जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार सभी कैदियों के मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने का कार्य भी सौंपा था। इसके अलावा उन्हें यह ताकत भी दी गई थी कि वह पात्र कैदियों को रिहा करने की सिफारिश भी कर सकती थी।

जिला और सत्र न्यायाधीश यूटीआरसी का प्रमुख होते हैं और उसका सम्मेलन करते हैं। इस यूटीआरसी में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जेलों के अधिकारी-इन-चार्ज और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा योग्य कैदियों की सूची तैयार की जाती है, जो कारागार प्राधिकरण द्वारा साझा की गई होती है।<sup>61</sup>

पहले, यूटीआरसी को हर चौथाई साल<sup>62</sup> में मिलने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसका क्षेत्राधिकार धारा 436-ए सीआरपीसी<sup>63</sup> के तहत आने वाले मामलों और जमानत देने में असमर्थ कैदियों के मामलों की समीक्षा करने के तहत सीमित था। बाद में, इसमें कैदियों की 14 श्रेणियों को शामिल किया गया।<sup>64</sup> मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत में, भरे हुए जेलों को खाली करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिए कि यूटीआरसी हर हफ्ते एक बार मिलें।<sup>65</sup>

नालसा के डेटा से पता चलता है कि जनवरी से दिसंबर 2021 तक, पूरे देश में 665 डीएलसीए के द्वारा कुल 10,028 यूटीआरसी की बैठकें बुलाई गईं। 26 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश<sup>66</sup> में वे कम से कम एक चौथाई में एक बार मिले। केवल सिक्किम ने एक चौथाई में 13 बैठकें बुलाई, जो हर हफ्ते बैठक करते थे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश (12 बैठकें) की बैठकें की संख्या थी। हालांकि दादरा और

नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और मिजोरम ने पूरे वर्ष भर में एक भी बैठक नहीं बुलाई।

सिक्किम, जिसमें 452 कैदी<sup>67</sup> थे, सबसे अधिक बैठकें आयोजित की जिसमें केवल 2 कैदियों के लिए रिहाई की सिफारिश की, जिसमें से केवल एक को रिहा किया गया था। राष्ट्रीय रूप में, 42,486 कैदियों की रिहाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन केवल 16,743 यानी 39% वास्तविक रूप में रिहा किए गए थे। गोवा और जम्मू और कश्मीर ने उन सभी को रिहा किया जिनकी रिहाई की सिफारिश की गई थी। तेरह राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश<sup>68</sup> ने 50% से अधिक को रिहा किया जबकि पांच<sup>69</sup> ने 20% से कम को रिहा किया।

नालसा के राष्ट्रव्यापी अभियान में यूटीआरसी के तहत रिहाई के पात्र कैदियों की पहचान जुलाई और अगस्त 2022 के बीच हुई। इस अभियान में नामित हुए 47,618 कैदियों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 24,789 कैदियों को रिहा किया गया था। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में विचाराधीन कैदियों के कुल 5.8% को रिहा किया गया जिससे देश की जेलों में कुल अधिभोग दर (Occupancy Rate) 5.7 प्रतिशत बिंदु की कमी हुई (130% से 124.3% तक)। उत्तर प्रदेश (8,409) ने सबसे अधिक और उसके बाद पश्चिम बंगाल (2,107), महाराष्ट्र (1,717) और पंजाब (1,531) ने सबसे अधिक कैदियों को रिहा किया।

यदि देखा जाए तो कुल भारतीय जेलों में कैदियों की जनसंख्या का 77% विचाराधीन कैदियों की होती है, यूटीआरसी एक मूल्यवान तंत्र है जिसका उद्देश्य जेलों में कैदियों की जनसंख्या को कम करने की दिशा में होता है। इसके अलावा, 2016 के उच्चतम न्यायालय के आदेश ने उन्हें "2016 मॉडल प्रिजन मैनुअल में उठाई गई मुद्दों को सम्बोधित करने के साथ-साथ नियमित जेल दौरों" के साथ निर्देशित किया है। इससे यह एक प्रभावशाली जिला स्तर का संस्थान बन गया है जिसके द्वारा जेल प्रबंधन, स्थितियाँ और कैदियों की न्याय तक पहुंच को सुधारा जा सकता है।

**प्रो. विजय राघवन**, टीआईएसएस-प्रयास; **नूपुर**, सामाजिक न्याय केंद्र; **मधुरिमा धानुका**, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल; **नयनिका सिंघल**, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; **लखविंदर कौर**, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

60 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियाँ (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 406/2013)  
 61 विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समितियों के लिए NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrcs>  
 62 उच्चतम न्यायालय ने 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 406/2013) में 5 फरवरी 2016 के आदेश के तहत यूटीआरसी को हर तिमाही में कम से कम एक बार मिलने का निर्देश दिया।  
 63 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436-ए अधिकतम अवधि प्रदान करती है जिसके लिए एक विचाराधीन व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे हिस्से तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, तो उसे अदालत द्वारा प्रतिभू के साथ या उसके बिना उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाएगा।  
 64 उच्चतम न्यायालय ने 1382 जेलों में अमानवीय परिस्थितियों में 6 मई 2016 के आदेश के तहत (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 406/2013) कैदियों की 14 श्रेणियों को शामिल करने के लिए यूटीआरसी के दायरे को बढ़ाया, ताकि शीघ्र रिहाई पर विचार किया जाए।  
 65 23 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय ने पुनः कहा जेलों में कोविड-19 वायरस का संक्रमण (सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 1/2020) सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़भाड़ कम करने के लिए नई स्थापित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों और स्थानीय कानूनी सेवा संस्थानों के साथ मिलकर साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया था।  
 66 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।  
 67 भारतीय जेल सांख्यिकी, 2020. पी. 45. यहां उपलब्ध है: [https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI\\_2020\\_as\\_on\\_27-12-2021\\_0.pdf](https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI_2020_as_on_27-12-2021_0.pdf)  
 68 असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।  
 69 छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।  
 70 NALSA's release UTRC@75, भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में UTRCs द्वारा कैदियों की रिहाई के लिए एक अभियान। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/report-2/a-bharat-ke-75-ve-svatantrata-divas-ko-manane-ke-liye-vicharaadhin-sameeksha-samitiyon-dwara-kaidiyon-ke-liye-abhiyan-rihaai-yutiarsai-75>  
 71 NALSA की रिपोर्ट रिकॉर्ड करती है कि अभियान की अवधि (16 जुलाई-13 अगस्त 2022) के दौरान 14,162 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था और सितंबर 2022 में रिपोर्ट जारी होने तक 16 जुलाई के बीच 24,789 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।  
 72 इस आंकड़े की गणना 31 दिसंबर 2021 तक जेल सांख्यिकी भारत द्वारा दर्ज की गई जेल अधिभोग दरों के आधार पर की गई है।

### चित्र 36: विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों का प्रदर्शन

यूटीआरसी जिला-स्तरीय समितियां हैं जो समय-समय पर सभी कैदियों के मामलों की समीक्षा करती हैं और रिहाई के लिए पात्र कैदियों की सिफारिश करती हैं। निम्नलिखित आंकड़ा जनवरी और दिसंबर 2021 के बीच यूटीआरसी के प्रदर्शन को दर्शाता है।

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	विचाराधीन कैदियों की संख्या (दिसंबर 2020)	जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक यू. टी. आर. सी. द्वारा रिहा करने के लिए अनुशंसित विचाराधीन कैदियों की संख्या	यू. टी. आर. सी. की सिफारिश पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या	जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक यू. टी. आर. सी. द्वारा अनुशंसित विचाराधीन कैदियों का हिस्सा	यू. टी. आर. सी. की सिफारिश पर विचाराधीन कैदियों का हिस्सा जारी किया गया	
आंध्र प्रदेश	5,001	1,323	428	26.5	8.6	
बिहार	44,187	865	480	2.0	1.1	
छत्तीसगढ़	11,963	501	68	4.2	0.6	
गुजरात	10,195	602	177	5.9	1.7	
हरियाणा	14,951	334	83	2.2	0.6	
झारखंड	17,103	481	283	2.8	1.7	
कर्नाटक	10,577	719	562	6.8	5.3	
केरल	3,569	207	6	5.8	0.2	
मध्य प्रदेश	31,712	2,606	449	8.2	1.4	
महाराष्ट्र	26,171	9,958	1,466	38.0	5.6	
ओडिशा	15,619	3,865	1,936	24.7	12.4	
पंजाब	15,643	1,206	658	7.7	4.2	
राजस्थान	16,930	4,517	1,276	26.7	7.5	
तमिलनाडु	8,709	2,012	1,566	23.1	18.0	
तेलंगाना	3,946	125	56	3.2	1.4	
उत्तर प्रदेश	80,557	2,411	1,354	3.0	1.7	
उत्तराखंड	3,906	2,458	1,541	62.9	39.5	
पश्चिम बंगाल	20,144	1,985	933	9.9	4.6	
<b>छोटे राज्य</b>						
अरुणाचल प्रदेश	127	214	90	168.5	70.9	
गोवा	419	47	47	11.2	11.2	
हिमाचल प्रदेश	1,574	40	2	2.5	0.1	
मेघालय	821	306	143	37.3	17.4	
मिजोरम	609	0	0	0.0	0.0	
सिक्किम	328	2	1	0.6	0.3	
त्रिपुरा	472	242	160	51.3	33.9	
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	194	0	0	0.0	0.0	
चंडीगढ़	619	0	0	0.0	0.0	
डी. एन. एच. और डी. डी.	138	0	0	0.0	0.0	
दिल्ली	14,506	1,964	906	13.5	6.2	
जम्मू और कश्मीर	3,717	15	15	0.4	0.4	
लद्दाख	21	0	0	0.0	0.0	
लक्षद्वीप	2	0	0	0.0	0.0	
पुडुचेरी	156	0	0	0.0	0.0	
<b>क्रमहीन राज्य</b>						
असम	6,495	3,314	1,970	51.0	30.3	
मणिपुर	506	79	18	15.6	3.6	
नागालैंड	261	88	69	33.7	26.4	

विचाराधीन समीक्षा समितियों पर एन. ए. एल. एस. ए. की ओ. पी. में विचाराधीन और दोषी दोनों को रिहाई की सिफारिश के लिए अपनी पात्रता और मानदंडों में शामिल किया गया है। कुछ राज्यों में रिहाई के लिए अनुशंसित और रिहा किए गए दोषियों की संख्या शामिल हो सकती है। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrscs>  
 स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)

### तालिका 6: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	समूह में श्रेणी			आईजेआर 3 अंक (10 में से)	संकेतकों में सुधार (12 में से)¹	बजट	
	आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022			कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (% 2021-22)	राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग किया गया (% 2020-21)
	सबसे अच्छा	मध्य	सबसे खराब			जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
<b>राष्ट्रीय औसत</b>							
<b>बड़े और मध्यम आकार के राज्य</b>							
आंध्र प्रदेश	10	14	13	5.27	5	83.6	99.93
बिहार	16	2	16	4.41	6	80.6	70
छत्तीसगढ़	8	15	11	5.33	10	85.0	54
गुजरात	6	9	3	6.10	8	88.5	93
हरियाणा	2	5	4	6.02	6	83.1	78
झारखंड	14	4	1	6.31	9	63.8	51
कर्नाटक	7	16	2	6.13	10	76.7	99.97
केरल	1	7	6	5.85	6	78.3	69
मध्य प्रदेश	9	12	14	5.01	7	91.9	94
महाराष्ट्र	5	1	7	5.73	7	77.6	83
ओडिशा	15	8	10	5.44	9	87.8	81
पंजाब	3	3	9	5.59	7	76.5	96
राजस्थान	11	13	17	4.36	7	85.0	99
तमिलनाडु	12	11	12	5.32	9	84.0	57
तेलंगाना	4	6	5	5.92	4	84.3	86
उत्तर प्रदेश	18	18	18	3.24	9	96.1	35
उत्तराखंड	17	10	8	5.63	8	77.9	72
पश्चिम बंगाल	13	17	15	4.88	7	62.6	89
<b>छोटे राज्य</b>							
अरुणाचल प्रदेश	7	7	7	3.10	6	NA²	NA²
गोवा	1	1	2	4.41	5	95.7	81
हिमाचल प्रदेश	3	6	5	3.62	9	71.8	99
मेघालय	6	5	3	4.15	8	78.7	49
मिजोरम	2	4	6	3.33	3	69.7	92
सिक्किम	4	3	1	4.96	7	92.3	75
त्रिपुरा	5	2	4	3.70	3	69.9	96
<b>रैंक रहित राज्य</b>							
असम	Not ranked				7	73.8	65
मणिपुर	Not ranked				3	80.2	57
नागालैंड	Not ranked				6	35.6	76
<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Not ranked				2	NA²	NA²
चंडीगढ़	Not ranked				6	49.5	38
दमन और दीव	Not ranked				NA	NA²	NA²
दिल्ली	Not ranked				9	77.0	80
जम्मू और कश्मीर	Not ranked				NA	77.0	71
लद्दाख	Not ranked				NA	69.8	0
लक्षद्वीप	Not ranked				4	100.0	0
पुडुचेरी	Not ranked				4	89.5	93

आंकड़ों के स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एन. ए. एल. एस. ए.); प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; जेल सांख्यिकी भारत (पी. एस. आई.), राष्ट्रीय अपराध आयोग ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। संक्षेप डी. एल. एस. ए.: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण; एल. ए.: लोक अदालत; पी. एल. ए.: स्थायी लोक अदालत; पी. एल. वी.: अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक; एस. एल. एस. ए.: राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में एन. ई. डब्ल्यू. संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए-उपलब्ध नहीं है। vii. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष।

1. संकेतकों की गिनती जिन पर आई. जे. आर. 2 की तुलना में एस. टी. ई. में सुधार हुआ है। आई. जे. आर. 2 और आई. जे. आर. 3 दोनों में मौजूद केवल गैर-टी. आर. अंत संकेतकों पर विचार किया गया है। बेंचमार्क वाले संकेतकों के लिए, यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा करता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही बेंचमार्क के भीतर इसके मूल्य में गिरावट आई हो। यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है, लेकिन इसके मूल्य में सुधार होता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है। डी एंड एन एच/डी एंड डी, जे एंड के और लद्दाख मूल्य आईजेआर 2 के साथ तुलनीय नहीं हैं, और इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया है। 2. राज्य कानूनी सहायता बजट के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।





**राज्य मानव  
अधिकार आयोग  
(एस एच आर सी)**

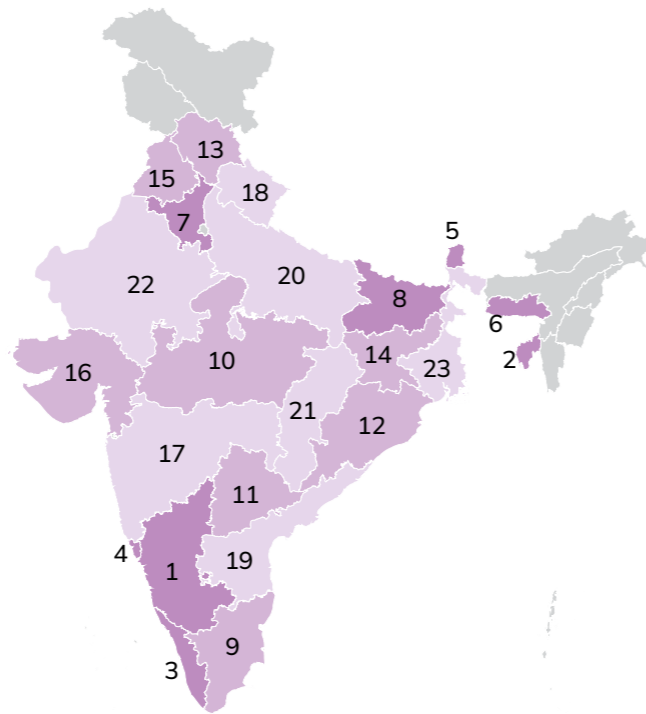
# मानचित्र 17: एसएचआरसी रैंकिंग

संकेतक 7

रंग गाइड

- श्रेष्ठ (रैंक 1 से 8)
- मध्य (रैंक 9 से 16)
- खराब (रैंक 17 से 23)

रैंक	राज्य	स्कोर (10 में से)
1	कर्नाटक	5.99
2	त्रिपुरा	5.83
3	केरल	5.75
4	गोवा	5.70
5	सिक्किम	5.52
6	मेघालय	5.51
7	हरयाणा	5.35
8	बिहार	5.33
9	तमिलनाडु	5.31
10	मध्यप्रदेश	5.23
11	तेलंगाना	4.89
12	ओडिशा	4.44
13	हिमाचल प्रदेश	4.40
14	झारखंड	3.79
15	पंजाब	3.64
16	गुजरात	3.43
17	महाराष्ट्र	3.39
18	उत्तराखंड	3.28
19	आंध्रप्रदेश	3.16
20	उत्तरप्रदेश	2.94
21	छत्तीसगढ़	2.46
22	राजस्थान	2.45
23	पश्चिमबंगाल	2.10



- 9 राज्य के मानवाधिकार आयोग 50% और अधिक सदस्यों की रिक्तियों के साथ कार्य कर रहे हैं।
- केवल 6 राज्यों के कार्यकारी कर्मचारियों में महिलाएं हैं।
- 2020-21 में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 105 करोड़ रुपये का बजट था।
- 50% एस.एच.आर.सी. के पास अधिकतम 1-5 जांच कर्मचारी हैं।

## तालिका 7: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

थीम >	मानव संसाधन		विविधता		कार्यभार	बजट			
	एस. एच. आर. सी. कुल कर्मचारी रिक्ति (%), 2020-21	एस. एच. आर. सी. कार्यकारी कर्मचारी रिक्ति (%), मार्च 2022	एस. एच. आर. सी. महिला कर्मचारी (%), 2020-21	कार्यकारी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), मार्च 2022	औसत सी. सी. आर. दर (%), 2018-19, 2019-20, 2020-21	उपयोग किया गया बजट (%), 2020-21	उपयोग किया गया बजट (पीपी, वित्त वर्ष 16-20)		
स्कोरिंग गाइड >	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर		
रैंक	स्कोर	मानव संसाधन	विविधता	कार्यभार	बजट	उपयोग किया गया बजट	उपयोग किया गया बजट		
आंध्र प्रदेश <sup>1</sup>	19	3.16	NA	0	NA	NA	NA		
बिहार	8	5.33	29.0	0.0	8.5	0.0	100	119	3.84
छत्तीसगढ़	21	2.46	NA <sup>2</sup>	50.0	NA <sup>3</sup>	0.0	98	106	2.21
गोवा	4	5.70	23.5	0.0	3.8	25.0	73	85	2.69
गुजरात	16	3.43	71.3	0.0	13.0	0.0	NA <sup>3</sup>	95	0.97
हरियाणा	7	5.35	33.0	0.0	18.5	0.0	99	94	-1.28
हिमाचल प्रदेश	13	4.40	66.7	0.0	8.3	0.0	NA <sup>5</sup>	81	14.42
झारखंड	14	3.79	36.4	50.0	14.3	0.0	89	88	4.37
कर्नाटक	1	5.99	21.6	0.0	43.7	0.0	118	86	-1.33
केरल	3	5.75	4.8	0.0	NA <sup>4</sup>	25.0	80	109	3.06
मध्य प्रदेश	10	5.23	12.4	0.0	7.6	0.0	105	100	0.00
महाराष्ट्र	17	3.39	40.0	25.0	16.7	0.0	61	50	-5.70
मेघालय	6	5.51	6.5	0.0	34.5	25.0	61	65	-7.79
ओडिशा	12	4.44	31.9	25.0	14.9	0.0	86	76	-1.44
पंजाब	15	3.64	94.0	50.0	9.1	50.0	79	99	-0.29
राजस्थान	22	2.45	59.4	25.0	10.7	0.0	52	48	-10.21
सिक्किम	5	5.52	-61.5	25.0	33.3	0.0	90	75	4.73
तमिलनाडु	9	5.31	13.6	0.0	21.4	0.0	71	100	-0.01
तेलंगाना	11	4.89	15.3	25.0	24.1	0.0	NA <sup>6</sup>	101	NA <sup>6</sup>
त्रिपुरा	2	5.83	31.3	0.0	18.2	0.0	86	95	13.41
उत्तर प्रदेश	20	2.94	62.4	50.0	NA <sup>3</sup>	50.0	45	100	0.00
उत्तराखंड	18	3.28	91.5	0.0	0.0	0.0	82	100	0.00
पश्चिम बंगाल	23	2.10	17.0	50.0	12.8	0.0	74	32	-10.20

टिप्पणी: 1. एपी एस. एच. आर. सी., कुरनूल का गठन डब्ल्यू. ई. एफ. 21.03.2021। 2. डेटा प्रदान नहीं किया गया है (आर. टी. आई. + वेबसाइट)। 3. राज्य से कोई जवाब नहीं आया। 4. एस. एच. आर. सी. महिला कर्मचारियों पर अलग समेकित डेटा नहीं रखता है। 5. काम करना शुरू किया डब्ल्यू. ई. एफ. जुलाई 2020। 6. टी. एस. आर. सी. ने काम करना शुरू कर दिया। 19.12.2019।  
 स्रोत: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन



## अध्याय 5

## नया

# एस.एच.आर.सी.: क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं

देश भर की सरकारें, चाहे केंद्र में हों या राज्यों में, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। इसकी बाध्यता हमारे संविधान की आधारीक संरचना(Basic Structure) में लिखी हुई है। यह बाध्यता संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता को साकार करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों में दायित्वों के अनुरूप भी है जो देश ने राष्ट्रों के समुदाय के सदस्य के रूप में किए हैं। धरेलू स्तर पर, राज्य की सभी एजेंसियों को इन सीमाओं के भीतर काम करना आवश्यक है।

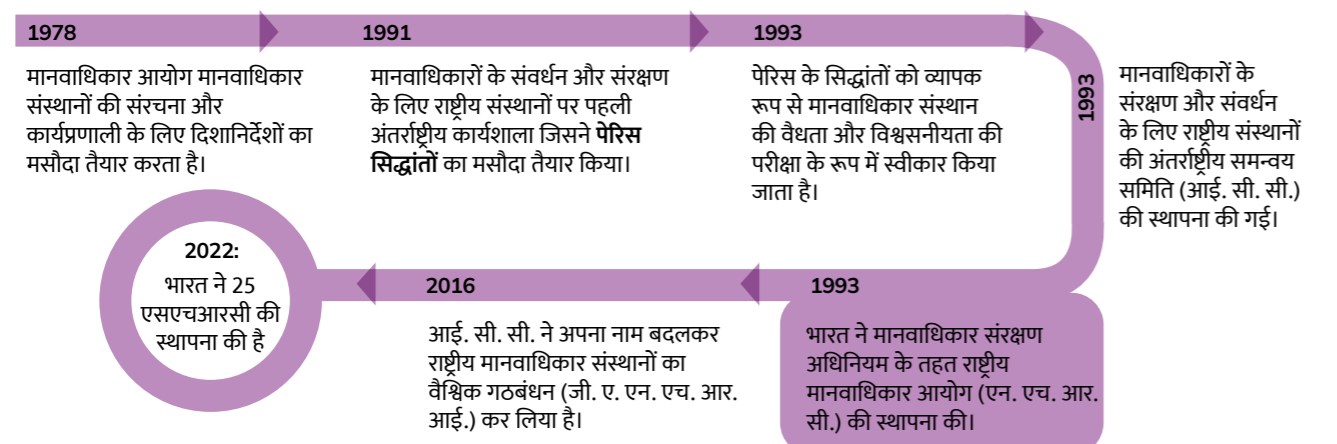
मानवाधिकारों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, 1993 में भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पी.एच.आर.ए. या PHRA), 1993 के तहत अपने पहले समर्पित मानवाधिकार संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना की। तब से, एनएचआरसी की तर्ज पर 25 राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) की स्थापना और की गई है।

अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में, मानवाधिकार आयोगों को व्यक्ति, उनके प्रतिनिधि, तीसरे पक्ष, गैर-सरकारी संगठन या कोई अन्य प्रतिनिधि निकाय द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

उनके पास अपनी इच्छा से संदिग्ध मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच शुरू करने की शक्ति भी है। उन्हें सरकार द्वारा संचालित किसी भी जेल, अस्पताल, किशोर या कल्याण गृह का दौरा करने और वहां रहने की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करना अनिवार्य है। आयोगों द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश भी की जाती है। मानव अधिकारों की संस्कृति और समझ को बढ़ावा देना इनके कार्य का हिस्सा है जिसके लिए आयोगों द्वारा अनुसंधान और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। चूँकि उन्हें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, वे शपथ के तहत गवाहों को बुला और जांच कर सकते हैं, हलफनामों (affidavit) पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन का आदेश दे सकते हैं और किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं।

शिकायत प्राप्त होने पर, एस.एच.आर.सी. को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह मामला उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और अधिकारों के उल्लंघन का उचित मामला बनाता है। ऐसे मुद्दों में विचार करने के बाद, या तो शिकायत को खारिज कर देना चाहिए या पी.एच.आर.ए. की धारा 18 के तहत की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए। हालाँकि, एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित होने के बावजूद, आयोग द्वारा दिए गए सुझाव मुख्य रूप से पक्षकारों के

## अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास की समयरेखा



## जी.ए.एन.एच.आर.आई और पेरिस सिद्धांत

सभी क्षेत्रों में 110 से अधिक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एन.एच.आर.आई.), उनके सदस्यों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (जीएएनएचआरआई)<sup>2</sup> दुनिया भर में सबसे बड़े मानवाधिकार नेटवर्क में से एक है - जिसमें से भारत भी एक सदस्य है।<sup>3</sup> 1991 में राष्ट्रीय संस्थाओं पर पहली अंतरराष्ट्रीय

कार्यशाला में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पेरिस सिद्धांतों का मसौदा तैयार किया गया और अपनाया गया, जो एनएचआरआई के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।<sup>4</sup> 1993 में मानवाधिकारों पर वियना विश्व सम्मेलन द्वारा स्थापित और स्वीकृत, इन सिद्धांतों को एक संस्थान की वैधता और विश्वसनीयता की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है।<sup>5</sup> भारत पेरिस सिद्धांतों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।<sup>6</sup>

लिए बाध्यकारी नहीं हैं और यह, यकीनन, इन निकायों के डिजाइन में प्राथमिक खामियों में से एक है।

हाल ही में 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय<sup>7</sup> ने पाया कि यह धारणा कि "आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों में कानूनी मान्यता का अभाव है, और इसलिए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, उस देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को संबोधित करने की दिशा में अच्छा संकेत नहीं है जहां लिखित संविधान सर्वोच्च शासन करता है" और निर्णय दिया कि पी.एच.आर.ए. की धारा 18 के तहत एस.एच.आर.सी. के सुझाव सरकारी अधिकारियों पर बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।

## SHRC की संरचना

राज्य आयोगों की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। दो सदस्य - एक पूर्व उच्च न्यायालय या जिला अदालत के न्यायाधीश और दूसरा विशेषज्ञ "मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के साथ" - एक सचिव के साथ कार्यकारी कर्मचारी का समूह बनाते हैं।<sup>7</sup> अध्यक्ष और सदस्य निर्णय लेने वाली संस्था बनाते हैं जो कि अनुपालन के लिए निर्देश/सिफारिशें जारी करने योग्य होती है। सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी होता है, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे नहीं होता, सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करता है।

2020-21,<sup>8</sup> 13 राज्यों ने अपने कुल कर्मचारियों में 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों के साथ काम किया।<sup>9</sup> केवल असम और सिक्किम एस.एच.आर.सी. में स्वीकृत से अधिक कर्मचारी थे।<sup>10</sup> राष्ट्रीय स्तर पर, 25 आयोगों में 43.5 प्रतिशत रिक्तियां थीं।

## मानव संसाधन

SHRC, कुल स्टाफ रिक्ति (% , 2020-21)

SHRC कार्यकारी स्टाफ रिक्ति (% , 2022)

एस.एच.आर.सी. में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्यों - न्यायिक और गैर-न्यायिक - का होना आवश्यक है। 2022 तक, पंजाब को छोड़कर सभी एसएचआरसी में अध्यक्ष मौजूद थे; छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर में कार्यवाहक अध्यक्षों के अधीन काम चल रहा था और 6 राज्यों में दो में से एक सदस्य गायब था।<sup>11</sup> उत्तर प्रदेश, मणिपुर और झारखंड में बिना किसी सदस्य के काम चल रहा था। 2010 में स्थापित झारखंड आयोग, 2018 से केवल एक कार्यवाहक अध्यक्ष(Acting Chairperson) और सचिव के साथ काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ आयोग जो 2001 में स्थापित किया गया है, 2020 से एक कार्यवाहक अध्यक्ष और एक सदस्य के साथ काम कर रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल आयोग सचिवों/सीईओ के बिना काम करते हैं।

1 अब्दुल साथर बनाम सरकार के प्रधान सचिव और 5 अन्य के मामले में 5 फरवरी 2021 का आदेश, W.P.1 नहीं 2006 का 41791. यहाँ उपलब्ध है: <https://www.mhc.tn.gov.in/judis/index.php/casestatus/viewpdf/590370>

2 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जी. ए. एन. एच. आर. आई.) सदस्य-आधारित वैश्विक गठबंधन है जो दुनिया भर में सबसे बड़े मानवाधिकार नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह एन.एच.आर.आई. का समर्थन करने के लिए पेरिस सिद्धांतों के अनुसार काम करता है और पेरिस सिद्धांतों के साथ एन. एच. आर. आई. का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सहकर्मी-समीक्षा आधारित मान्यता प्रक्रिया आयोजित करता है। देखिए: <https://ganhri.org/>

3 जी. ए. एन. एच. आर. आई. मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को एक साथ लाता है और उनका समर्थन करता है। देखिए <https://ganhri.org/>

4 पेरिस सिद्धांत, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जी. ए. एन. एच. आर. आई.) यहाँ उपलब्ध है: <https://ganhri.org/paris-principles/>

5 मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान-इतिहास, सिद्धांत, भूमिका और जिम्मेदारियाँ, 2010। यहाँ उपलब्ध है: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf)

6 जी. ए. एन. एच. आर. आई. की मान्यता प्रक्रिया एन. एच. आर. आई. को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के संबंध में मान्यता देने के लिए एक सहकर्मी समीक्षा है। पेरिस सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करने के लिए भारत को 'ए' का दर्जा दिया गया है। देखिए <https://ganhri.org/membership/>

7 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21। यहाँ उपलब्ध है: [https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct\\_2021\\_0.pdf](https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf)

8 आंकड़ा राज्य आयोगों से प्राप्त आर. टी. आई. प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।

9 बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

10 बिहार, हरियाणा, केरल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के आंकड़े 2022 तक के हैं। छत्तीसगढ़ और गुजरात एसएचआरसी ने कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आंशिक जानकारी प्रदान की। नतीजतन, उन्हें 0 अंक दिए गए हैं।

11 छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

अधिकार के उल्लंघन की स्वतंत्र जांच किसी भी आयोग की प्रभावशीलता का केंद्र है। इसकी क्षमता कर्मचारियों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। कानून में "कम से कम पुलिस महानिरीक्षक रैंक समान अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे पुलिस और जांच कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों" का प्रावधान है।<sup>12</sup>

अपने स्वयं के कैडर की अनुपस्थिति में, आयोगों को सरकार के भीतर से और प्रशासन या अदालतों के अनुभव वाले लोगों के बीच से लिए गए कर्मचारियों पर भरोसा करना चाहिए।<sup>13</sup> व्यावहारिक संचालन में महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ, पुलिस अधीक्षक (एसपी), अतिरिक्त अधीक्षक (एएसपी) या उपाधीक्षक ( डीपी एसपी) और आयोग में प्रतिनियुक्ति(Deputation) पर एक निरीक्षक मिलकर राज्य आयोगों की जांच शाखा बनाते हैं।

### चित्र 37: आयोगों में रिक्तियाँ

भारत के 25 एसएचआरसी में रिक्ति एक गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर पर औसतन, लगभग 2 में से 1 पद रिक्त है, 94% के साथ पंजाब में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं।

	कार्यकारी कर्मचारी (मार्च 2022)		कुल कर्मचारी (2020-21)		
	स्वीकृत	नियुक्त	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति (%)
आंध्र प्रदेश	4	4	NA	NA	NA
असम	4	4	32	38	Extra staff
बिहार	4	4	100	71	29
छत्तीसगढ़	4	2	98	NP <sup>2</sup>	NA
गोवा	4	4	34	26	24
गुजरात	4	4	80	23	71
हरियाणा	4	4	97	65	33
हिमाचल प्रदेश	4	4	36	12	67
झारखंड	4	2	22	14	36
कर्नाटक	4	4	111	87	22
केरल	4	4	42	40	5
मध्य प्रदेश	4	4	105	92	12
महाराष्ट्र	4	3	30	18	40
मणिपुर	4	2	41	10	76
मेघालय	4	4	31	29	6
ओडिशा	4	3	69	47	32
पंजाब	4	2	182	11	94
राजस्थान	4	3	69	28	59
सिक्किम	4	3	13	21	Extra staff
तमिलनाडु	4	4	81	70	14
तेलंगाना	4	3	98	83	15
त्रिपुरा	4	4	32	22	31
उत्तर प्रदेश	4	2	85	32	62
उत्तराखंड	4	4	47	4	91
पश्चिम बंगाल	4	2	94	78	17
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>1,629</b>	<b>921</b>	<b>43.5</b>

स्वीकृत जांच कर्मचारी की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग थी। कुछ ने अपनी प्रतिक्रिया में कांस्टेबलों की संख्या को शामिल किया,<sup>14</sup> जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों ने उन्हें शामिल नहीं किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड को छोड़कर सभी ने सदस्यों की कमी की सूचना दी। 2022<sup>15</sup> में ग्यारह आयोगों ने एक से पांच तक की संख्या में जांच स्टाफ के साथ काम किया। असम, झारखंड, मणिपुर और सिक्किम आयोगों ने कोई जांच कर्मचारी न होने की सूचना दी।

एक पूर्ण समूह के अभाव में जांच करने और यह तय करने के लिए कि क्या मानवाधिकारों के उल्लंघन में देरी हुई है हर साल लंबित मामलों की संख्या साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। हर साल हजारों पीड़ित मानवाधिकार आयोगों से संपर्क करते हैं। सिर्फ 2020-21 में ही सभी

एसएचआरसी में 1,02,608 शिकायतें थीं। आठ एसएचआरसी ने प्राप्त शिकायतों में से 60 प्रतिशत से कम का निपटारा किया,<sup>16</sup> मेघालय (28 प्रतिशत) ने सबसे कम निवारण किया, इसके बाद महाराष्ट्र (29 प्रतिशत), राजस्थान (30 प्रतिशत) और ओडिशा (48 प्रतिशत) का स्थान रहा। बिहार (99 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (94 प्रतिशत) ने प्राप्त मामलों में लगभग सभी को निपटा दिया। 2020-21 के अंत में अनसुलझे मुद्दों की संख्या 33,312 था।

### कार्यभार

औसत मामला निपटान दर  
(%, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

2018-19 और 2020-21 के बीच, 3 आयोगों- मणिपुर (28 प्रतिशत), राजस्थान (52 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (45 प्रतिशत) ने औसत केस क्लीयरेंस दर 60 प्रतिशत से कम दर्ज की। इस अवधि के दौरान असम (122 प्रतिशत), कर्नाटक (118 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (105 प्रतिशत) ने प्राप्त संख्या से अधिक मामलों को निपटारा किया, जबकि बिहार में 100 प्रतिशत मामले के निपटारे की दर दर्ज की गई।

यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी शिकायतों को पूरी तरह से इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं थीं या अंततः उनकी जांच, निर्णय और सुधारात्मक उपायों के लिए सुझाव दिए गए थे।

पेरिस सिद्धांत एनएचआरआई की संरचना और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के अनुसार प्रावधान करते हैं "जो नागरिक समाज के बहुलवादी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है।" नतीजतन, सिद्धांतों के साथ तालमेल रखने के लिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को 2019 में संशोधित किया गया ताकि वैधानिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पांच सदस्यों में से एक महिला को शामिल किया जा सके। हालाँकि, अपने अस्तित्व के ढाई दशकों में, एन.एच.आर.सी. में कभी भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही। इतने समय में केवल तीन महिला सदस्य रहीं, और कभी भी दो महिला सदस्यों ने एक ही समय में सेवा नहीं की।

### विविधता

कुल स्टाफ में महिलाओं की हिस्सेदारी  
(%, 2020-21)  
कार्यकारी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%, 2022)

बहुलवाद पर जोर देने के बावजूद, पीएचआरए संशोधन, हालांकि, राज्य आयोगों तक विस्तारित नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2020-21 तक आयोगों के समग्र कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.1 प्रतिशत थी। न तो उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट और न ही एसएचआरसी की वेबसाइटें किसी विविधता का दस्तावेजीकरण करती हैं और न ही अपने सदस्यों की जाति, धर्म या लिंग संरचना का उल्लेख करती हैं। 2022 तक, केवल 6 आयोगों में सदस्य या सचिव के रूप में महिलाएँ थीं। वहाँ कोई महिला अध्यक्ष नहीं थीं और केवल केरल, मेघालय और पंजाब में एक-एक महिला सदस्य थीं। केवल असम, गोवा और उत्तर प्रदेश में सचिव स्तर पर महिलाएँ थीं।

### 2016-17 और 2020-21 के बीच उपयोग किया गया बजट:

मानवाधिकार आयोग राज्य सरकारों से मिलने वाले वित्त पोषण पर निर्भर करते हैं, जो खुद अपनी प्राथमिकताओं और उन प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं। कुल स्वीकृत और उपयोग किए गए धन का पांच साल (2016-2020) का आकलन इन संस्थानों को दी जाने वाली कम प्राथमिकता का संकेत देता है। 2016 और 2020 के बीच, नौ आयोगों ने धन के उपयोग में वृद्धि दर्ज की, जिसमें हिमाचल प्रदेश (14.42 प्रतिशत अंक) ने उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद सिक्किम (4.73 प्रतिशत अंक) और झारखंड (4.37 प्रतिशत अंक) का स्थान रहा। लेकिन नौ राज्यों<sup>20</sup> में इस कोष की उपयोग कमी दर्ज की गई जिसमें राजस्थान (-10.21 प्रतिशत अंक) में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल (-10.20 प्रतिशत अंक) और महाराष्ट्र (-5.70 प्रतिशत अंक) का स्थान रहा। चार राज्य-असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 2016-17 और 2020-21 के बीच अपने पूरे स्वीकृत बजट का उपयोग किया।

### बजट और व्यय

उपयोग किया गया बजट (%, 2020-21)  
बजट का उपयोग किया गया  
(पीपी, वित्तीय वर्ष 2016-17 - 2020-21)

**2020-21 में उपयोग किया गया बजट:** 2020-21 में, स्वीकृत बजट राज्यों में रु. 64 लाख से लेकर 8 करोड़ तक था। हरियाणा का आयोग, जिसे 2020 में 2,500 शिकायतें मिलीं को सबसे अधिक (8 करोड़ रुपये) स्वीकृत किये गये। इसके बाद तेलंगाना का स्थान रहा, जहां 4,319 शिकायतें प्राप्त हुईं और 7.6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। 1,381 शिकायतों के साथ हिमाचल प्रदेश को सबसे कम 64 लाख रु. स्वीकृत किये गये।

2020-21 में 25 एसएचआरसी में कुल रु. 105 करोड़ के बजट का

नोट: 1. राज्यों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। 2. वास्तविक कर्मचारियों का डेटा न तो आर. टी. आई. के माध्यम से या इसकी वेबसाइट पर प्रदान किया गया है। एनए उपलब्ध नहीं है। स्रोत: आई. जे. आर. दल द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन

12 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 27 (1) (बी)। यहाँ उपलब्ध है: [https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAAct\\_2021\\_0.pdf](https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAAct_2021_0.pdf)  
13 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, मानवाधिकार आयोग एक नागरिक पुस्तिका, 2004।  
14 बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल।  
15 जांच कर्मचारियों की स्वीकृत और काम करने की क्षमता पर डेटा राज्य आयोगों से प्राप्त आर. टी. आई. जवाबों पर आधारित है। इसे इस रिपोर्ट के लिए एक संकेतक के रूप में स्थान नहीं दिया गया है।

16 गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।  
17 पेरिस सिद्धांत, 'स्वतंत्रता और बहुलवाद की संरचना और गारंटी'। यहाँ उपलब्ध है: <https://ganhri.org/paris-principles/>  
18 असम, गोवा, केरल, मेघालय, पंजाब और उत्तर प्रदेश।  
19 बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, सिक्किम और त्रिपुरा।  
20 हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

आवंटन हुआ। ग्यारह आयोग,<sup>21</sup> ने 2019-20 और 2020-21 के बीच बजट आवंटन में वृद्धि दर्ज की जबकि 10 राज्यों में यह बजट कम कर दिया गया।<sup>22</sup> मणिपुर के बजट में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जहां यह

आँकड़ा 2019-20 में 83 लाख से 2020-21 में 1.3 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। जबकि उत्तराखंड का बजट 67 प्रतिशत नीचे गिरकर रुपये 3 करोड़ से 1 करोड़ रह गया।

### चित्र 38: तीन वर्षों में एसएचआरसी द्वारा प्राप्त और निपटाए गए मामले

राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी टेढ़ी-मेढ़ी थी। तीन वर्षों (2018-2021) में औसत राष्ट्रीय केस क्लीयरेंस दर 75% है जबकि 2020-21 में यह 68% है।

	मामले प्राप्त हुए			मामले निपटाए गए			मामले की मंजूरी दर <sup>4</sup>		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
आंध्र प्रदेश <sup>1</sup>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
असम	302	310	304	476	370	270	158	119	89
बिहार	8,062	6,105	6,828	7,676	6,475	6,777	95	106	99
छत्तीसगढ़	1,326	1,120	1,294	1,425	1,046	1,219	107	93	94
गोवा	289	159	279	286	97	163	99	61	58
गुजरात	3,210	3,087	NR	3,201	3,031	NR	100	98	NA
हरियाणा	2,405	2,823	2,501	1,939	3,707	2,109	81	131	84
हिमाचल प्रदेश <sup>2</sup>	NA	NA	1,381	NA	NA	1,300	NA	NA	94
झारखंड	944	639	719	838	608	594	89	95	83
कर्नाटक	5,570	4,545	4,704	6,527	6,547	4,429	117	144	94
केरल	10,847	9,689	8,803	10,379	7,536	5,868	96	78	67
मध्य प्रदेश	9,422	9,651	8,677	10,291	9,842	9,014	109	102	104
महाराष्ट्र	6,770	4,659	3,763	5,368	3,559	1,083	79	76	29
मणिपुर	89	126	216	31	21	67	35	17	31
मेघालय	21	23	32	16	18	9	76	78	28
ओडिशा	4,246	3,540	4,442	2,633	5,191	2,137	62	147	48
पंजाब	12,046	11,100	11,121	10,987	10,193	5,884	91	92	53
राजस्थान	5,647	5,544	2,154	3,846	3,199	652	68	58	30
सिक्किम	11	7	6	11	6	5	100	86	83
तमिलनाडु	13,701	13,408	11,999	10,429	10,311	7,253	76	77	60
तेलंगाना <sup>3</sup>	NA	NA	4,319	NA	NA	2,873	NA	NA	67
त्रिपुरा	65	66	55	64	53	43	98	80	78
उत्तर प्रदेश	29,375	22,635	22,989	13,995	7,672	12,023	48	34	52
उत्तराखंड	2,201	1,921	1,893	2,068	1,594	1,290	94	83	68
पश्चिम बंगाल	4,013	3,896	4,129	1,877	2,858	4,234	47	73	103
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>120,562</b>	<b>105,053</b>	<b>102,608</b>	<b>94,363</b>	<b>83,934</b>	<b>69,296</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>68</b>

टिप्पणी: 1. एपी एस. एच. आर. सी., कुरुनूल का गठन डब्ल्यू. ई. एफ. 21.03.2021। 2. एस. एच. आर. सी. का गठन किया गया। 01.07.2020। 3. टी 3. एस. एच. आर. सी. का गठन किया गया और इसने काम करना शुरू कर दिया। 19.12.2019। 4. प्राप्त प्रत्येक 100 मामलों के लिए मामलों का निपटारा किया जाता है। एनए: उपलब्ध नहीं है। एनआर: कोई जवाब नहीं।

स्रोत: आई. जे. आर. दल द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन

21 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु।  
22 असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

2020-21 में अधिकांश एसएचआरसी ने अपने 60 प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया।<sup>23</sup> हालाँकि पश्चिम बंगाल (32.2 प्रतिशत), मणिपुर (45.1 प्रतिशत) और राजस्थान (48.3 प्रतिशत) ने राज्यों में सबसे कम बजट का उपयोग दर्ज किया। केवल 5 आयोगों-असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड- ने अपने पूरे बजट का उपयोग किया। बिहार (119 प्रतिशत), केरल (109 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (106 प्रतिशत) और तेलंगाना (101 प्रतिशत) के आयोगों ने अपने आवंटित बजट से अधिक का उपयोग करने का रिकॉर्ड बनाया।

2019-20 और 2020-21 के बीच, 10 आयोगों ने बजट उपयोग में वृद्धि दिखाई।<sup>24</sup> राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों ने औसतन 86 प्रतिशत का उपयोग किया - 2019-20 में 80 प्रतिशत से वृद्धि हुई।

### राज्य मानवाधिकार आयोगों की वेबसाइटों की स्थिति

एन. एच. आर. सी. की वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हुए और इन सेवाओं को कितना सुलभ होना चाहिए, इस पर विचार करते हुए, आईजेआर ने शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देशों की उपलब्धता, शिकायतों और निर्णयों की स्थिति के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं में जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आयोगों की वेबसाइटों की उपयोगकर्ता-मित्रता (user-friendliness) का मूल्यांकन किया (लेकिन रैंक नहीं किया)। इन वेबसाइटों को अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच तीन बार चेक किया गया था।

वर्तमान में कार्यरत 25 आयोगों में से केवल 4 राज्यों में - अर्थात् आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और तेलंगाना - के पास कोई कार्यशील वेबसाइट नहीं है। उत्तराखंड को छोड़कर, किसी भी राज्य ने अपने नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं का पूरा विवरण नहीं दिया। केवल 11 आयोगों ने नागरिकों को शिकायतें दर्ज करने के बारे में दिशानिर्देश प्रदान किए, जबकि केवल 6 आयोगों ने अपनी वेबसाइटों पर नियमित रूप से शिकायतों के निर्णय अपलोड किए।

अधिकांश वेबसाइटें केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थीं और उन्हें राज्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं कराया गया। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी पर वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र,

2021 में 23.48 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले थे - 2020-21 में 22,989 - और उसी वर्ष के दौरान ₹5.7 करोड़ प्राप्त हुए।

23 बजट के उपयोग के आँकड़ों में आंध्र प्रदेश द्वारा उपयोग शामिल नहीं है क्योंकि आयोग का गठन 2021 में किया गया था।  
24 बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब और त्रिपुरा।

बिहार और उत्तर प्रदेश में जानकारी क्रमशः कन्नड़, मराठी और हिंदी में उपलब्ध थी। केरल के लिए मलयालम में वेबसाइट देखने का विकल्प दिया गया था, हालाँकि, यह सुविधा सक्रिय नहीं थी।

2021 में 23.48 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले थे - 2020-21 में 22,989 - और उसी वर्ष के दौरान ₹5.7 करोड़ प्राप्त हुए।

### क्रियाविधि

यह अध्ययन चार विषयों- मानव संसाधन, विविधता, कार्यभार और बजट में सात संकेतकों पर 25 मानवाधिकार आयोगों की क्षमता को दर्शाता है। प्रत्येक विषय आयोगों के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निर्धारित पूर्व शर्तों का प्रतिनिधित्व करता है और यह सात संकेतक सभी राज्यों में समान रूप से उपलब्ध जानकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे राज्यों द्वारा अपने लिए निर्धारित मानकों के मुकाबले निष्पक्ष तुलना संभव हो पाती है। प्रत्येक संकेतक पर एस.एच.आर.सी. के प्रदर्शन को कुल स्कोर प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है जो तुलनात्मक रैंकिंग की अनुमति देता है।

**राज्य जहां तुलना संभव नहीं थी** : आईजेआर असम और मणिपुर को बाकी राज्यों से तुलना के लिए छोड़ देता है। इसका कारण है कि वहां सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) की दीर्घकालिक उपस्थिति ने न्याय प्रशासन को बेहद प्रभावित किया है और इसलिए उन राज्यों के साथ तुलना की अनुमति नहीं देता है जिनके पास ये कानून नहीं हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद राज्य में एस. एच. आर. सी. को बंद कर दिया गया था।

**निर्धारित मानक**: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना, शक्तियों और कार्यों की रूपरेखा देता है, और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया गया है। ग्लोबल अलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स (GANHRI) और पेरिस सिद्धांतों के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी उल्लेख किया गया है।

**स्कोरिंग और रैंकिंग**: जिन राज्यों में कुछ संकेतक नहीं मिल रहे थे, वहाँ हमने निम्नलिखित कार्य किया। यदि आँकड़ा इसलिए गायब था क्योंकि डेटा के गायब होने के लिए एक विशेष वस्तुनिष्ठ परिस्थिति (Objective Circumstance) थी, जैसे कि आयोग की स्थापना हुए पांच साल से भी कम समय हुआ हो, तो हमने इसके अंक निर्धारण पर काम करते समय मापदंडों की संख्या को कम कर दिया। हालाँकि, यदि मूल्य इसलिए गायब था क्योंकि राज्य ने डेटा प्रदान नहीं किया था या आंशिक डेटा प्रदान किया था, तो स्कोरिंग सभी राज्यों के लिए सामान्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जारी रही।

### चित्र 39: एसएचआरसी तक पहुंचाए मामले

एन. एच. आर. सी. वेबसाइट को एक मॉडल के रूप में उपयोग करते हुए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने उपयोगकर्ता-मित्रता एस. एच. आर. सी. की वेबसाइटों का मूल्यांकन किया (लेकिन रैंक नहीं किया)। वेबसाइटों को अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच तीन बार चेक किया गया था। उत्तराखंड को छोड़कर किसी भी राज्य ने अपने नागरिकों को सेवाओं का पूरा गुलदस्ता नहीं दिया।

■ हां/उपलब्ध ■ आंशिक रूप से उपलब्ध ■ उपलब्ध नहीं

राज्य	एस. एच. आर. सी. स्थापित	वेबसाइटों पर स्थानीय भाषाएं	शिकायत सुविधाएं				आदेशों और निर्णयों की उपलब्धता	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण
			एच. आर. सी. नेट का लिंक	वेबसाइटों पर स्थानीय भाषाएं	ऑफलाइन मामले दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	मामलों की स्थिति (ऑनलाइन और ऑफलाइन)		
आंध्र प्रदेश	2021		कोई वेबसाइट नहीं					
असम	1996	NA	NA	NA	Yes	NA	NA	NA
बिहार	2008	Hindi	Yes	Available <sup>2</sup>	Yes	NA	Yes <sup>3</sup>	NA
छत्तीसगढ़	2001	NA	Yes	NA	Yes	Yes	NA	NA
गोवा	2011	NA	NA	NA	NA	NA	Yes <sup>4</sup>	Yes
गुजरात	2006	NA	NA	NA	Yes	Yes	NA	Yes
हरियाणा	2012	NA	Yes	NA	NA	NA	Available	NA
हिमाचल प्रदेश	2020	NA	Yes	Available	NA	Available	NA	NA
झारखंड	2010	NA	NA	NA	NA	NA	Available	NA
कर्नाटक	2007	Kannada	Yes	Available	NA	Available	Available	NA
केरल	1998	NA	Yes	NA	FAQs	NA	Available	NA
मध्य प्रदेश	1995	NA	Yes	NA	Guidelines	NA	NA	NA
महाराष्ट्र	2001	Marathi	Yes	NA	Available <sup>5</sup>	Yes	NA	NA
मणिपुर	2018		कोई वेबसाइट नहीं					
मेघालय	2016		कोई वेबसाइट नहीं					
ओडिशा	2000	NA	Yes	Available	Available	Yes	NA	NA
पंजाब	1997	Yes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
राजस्थान	1999	Hindi	NA	Available	Available	Yes	Yes <sup>6</sup>	NA
सिक्किम	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
तमिलनाडु	1997	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
तेलंगाना	2019		कोई वेबसाइट नहीं					
त्रिपुरा	2016	NA	Available	NA	Available	Available	NA	NA
उत्तर प्रदेश	1996	Yes	Available	NA	NA	Available	Yes <sup>6</sup>	NA
उत्तराखंड	2013	Yes	Available	Available	Available	Available	Available	NA
पश्चिम बंगाल	1995	No	NA	NA	NA	NA	Available	NA

**आंकड़ों के स्रोत:** आंकड़ों तक पहुंचने के लिए विभागीय वेबसाइटों और वार्षिक रिपोर्टों पहली पसंद थीं। हालाँकि, चूंकि वेबसाइटें अक्सर पुरानी, अपूर्ण थीं और धारा 4, आरटीआई अधिनियम के तहत सक्रिय रूप से जानकारी का खुलासा नहीं करती थीं; मानव संसाधन के बारे में विस्तृत जानकारी, 2016 से 2022 के बीच की अवधि से संबंधित लैंगिक विविधता, कार्यभार और बजट की मांग 145 आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से की गई थी। हमने अपनी रिपोर्ट में ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का भी उपयोग किया।<sup>25</sup>

मांगा गया सभी डेटा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत जनता के किसी भी अनुरोध के बिना सक्रिय रूप से खुलासा किए जाने की वैधानिक परिभाषा के भीतर था। बजट से संबंधित आंकड़ों के लिए राज्य के बजट दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था।

**माया दारूवाला**, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;  
**नयनिका सिंघल**, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

1. विभाजन के बाद पुनर्गठित किया गया। 2. आसानी से उपलब्ध नहीं है, पृष्ठ के नीचे एसएचआरसी द्वारा प्रकाशित सभी सूचनाओं को देखने के बाद पाया जा सकता है। 3. वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण निर्णय; वर्षवार व्यवस्थित; आदेश और निर्णय हिंदी में उपलब्ध हैं। 4. 39 महत्वपूर्ण निर्णय उपलब्ध हैं। 5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सूचीबद्ध हैं लेकिन सुलभ नहीं हैं; दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। 6. केवल महत्वपूर्ण निर्णय। स्रोत: एसएचआरसी की वेबसाइटें

25 ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया, 2019, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया: वर्किंग ऑफ एनएचआरसी/एसएचआरसी (1993-2018)। यहाँ उपलब्ध है: <https://transparencyindia.org/wp-content/uploads/2019/12/Protection-of-Human-Rights-in-India-as-on-9th-Dec-2019.pdf>

# अन्य भाग

आर टी आई

आंकड़ों से जुड़ी समस्याएं

कार्यप्रणाली

निष्कर्ष

अध्याय 4

# आईजेआर 2022 के लिए आंकड़ों का संग्रह के लिए आर.टी.आई. का उपयोग करने का अनुभव: एक टिप्पणी<sup>1</sup>

इस अध्याय में तीसरे आई. जे. आर. द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू. टी.) से जानकारी और आंकड़े एकत्र करने के लिए भारत के प्राथमिक पारदर्शिता कानून, अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) का उपयोग करने के अनुभव को दर्ज किया गया है।

हमने केवल सांख्यिकीय जानकारी मांगी-जिनमें से कोई भी, हमारे विचार में, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8,9,11 और 24 के तहत प्रकटीकरण या खुलासे (Disclosure) से मुक्त नहीं है। यह धाराएं उन आधारों को उल्लिखित करती हैं, जहाँ जानकारी तक पहुंच को वैध रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। जहाँ कई सार्वजनिक प्राधिकरण जानकारी देने में आगे थे, वहीं अन्य ने या तो हमारी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया या फिर हमें हस्तांतरण खंड का प्रयोग कर दूसरे कार्यालयों में हमें जाने कहा, जिससे पारदर्शिता के वैधानिक दायित्व (Statutory Obligation) से बचा जा सके। कुछ ने हमारे बार बार याद दिलाने और अपील लगाने के बावजूद हमारे आर. टी. आई. आवेदनों का जवाब नहीं दिया। हमारे आर. टी. आई. हस्तक्षेपों का एक संख्यात्मक अवलोकन नीचे दिया गया है। इस विवरण में सूचना अनुरोधों का जवाब देते समय सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अपनाई गई अच्छी और बुरी प्रथाओं के कई उदाहरण दिए गए हैं।

## संख्यात्मक अवलोकन (Numerical Overview)

मार्च और दिसंबर 2022 के बीच, आई. जे. आर. दल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 313 आर. टी. आई. आवेदन प्रस्तुत किए।

- 1) पुलिस विभाग (72 बार अनुरोध)<sup>2</sup>
- 2) मुख्य सचिव का कार्यालय (36 बार अनुरोध)<sup>3</sup>
- 3) फॉरेंसिक विभाग (32 बार अनुरोध)<sup>4</sup>
- 4) राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (37 बार अनुरोध)<sup>5</sup> और

- 5) राज्य मानवाधिकार आयोग (136 बार अनुरोध, जहाँ भी संभव हुआ )

हमें कुल 839 जवाब मिले जिसमें कुछ पूरी तरह से या आंशिक रूप से जानकारी प्रदान करते थे, कुछ अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे थे और कुछ विभिन्न आधारों पर जानकारी से इनकार करते हैं, जैसे कि जानकारी पुलिस मुख्यालय (उत्तराखंड) में नहीं है या आर. टी. आई. अधिनियम 2005 (त्रिपुरा) की धारा 24 (4) के तहत आंतरिक सुरक्षा और जांच के आधार पर जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालाँकि सीसीटीवी लगाने की जानकारी राज्य की आंतरिक सुरक्षा या जांच को प्रभावित नहीं करती है।

## स्थानांतरण

तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के पुलिस विभागों से 100 से अधिक जवाबों से संकेत मिलता है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और कामकाज से सम्बंधित जानकारी को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। लगभग सभी राज्यों में, आर. टी. आई. को अन्य सरकारी प्राधिकरणों जैसे जिला स्तर के पुलिस प्रशासन, उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था जिससे वह हमें सीधा जानकारी भेज सकें। कई राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने हमारे आर. टी. आई. आवेदनों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को स्थानांतरित कर दिया। कुछ मामलों में, जिन लोगों ने स्थानांतरित आवेदन प्राप्त किए, उन्होंने इन जानकारीयों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया।

उदाहरण के लिए, सी. सी. टी. वी. पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत आर. टी. आई. आवेदन (उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये निर्देश जारी किए

थे) को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उनके अंतर्गत गृह और न्याय विभाग आते हैं।

## किसी भी प्रतिक्रिया का अभाव

सामान्य मामलों में आर. टी. आई. आवेदनों का जवाब देने के लिए वैधानिक समय सीमा 30 कैलेंडर दिन होती है। हालांकि, कुछ सार्वजनिक अधिकारियों ने मांगी हुई जानकारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (एस. एच. आर. सी.) ने बार-बार फोन पर पूछताछ करने और अध्यक्ष को संबोधित एक विशेष पत्र लिखने के बावजूद जवाब नहीं दिया, जिसमें प्रतिक्रिया की कमी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था। मणिपुर और लक्षद्वीप के पुलिस विभागों ने भी सीसीटीवी कैमरा स्थापना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के फॉरेंसिक विभागों ने अपनी संरचना, संगठन, वित्त, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों पर प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया।

## शुल्क पर व्यय

हमने शुल्क भुगतान पर कुल मिलाकर रु 17,202 खर्च किए। इसमें आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क दोनों शामिल हैं जिन्हें प्रतिलिपि या पुनरुत्पादन शुल्क (Copying या reproduction charges) के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officials या पी. आई. ओ.) ने हमें डाक शुल्क का भी भुगतान करने के लिए कहा।

यदि आवेदक वैध रूप से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है, ऐसी स्थिति में आवेदक को मुफ्त में जानकारी प्राप्त करने का हकदार है। इस श्रेणी के अलावा आवेदन शुल्क का भुगतान सभी नागरिकों के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है। हालाँकि, आईजेआर. द्वारा

## भुगतान किए गए शुल्क का श्रेणी-वार विभाजन नीचे दिया गया है:

सार्वजनिक प्राधिकरण	भुगतान किए गए शुल्क
पुलिस विभाग (डी. जी. पी. और मुख्य सचिव)	₹ 8,260
फॉरेंसिक विभाग	₹ 1,517
कानूनी सेवा प्राधिकरण	₹ 380
राज्य मानवाधिकार आयोग	₹ 7,045

सार्वजनिक प्राधिकरणों (public authorities) की सभी श्रेणियों से मांगी गई जानकारी को आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत वैधानिक दायित्व के रूप में स्वेच्छा से प्रकट किया जाना चाहिए था (कृपया विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को सौंपे गए आर. टी. आई. आवेदनों के पाठ के लिए <https://indiajusticereport.org/> देखें)। मांगी गई जानकारी का अधिकतम हिस्सा इतना मौलिक और नागरिकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जान पड़ती है कि इसे बिना किसी आरटीआई अधिनियम के "वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों" के अनुसार संबंधित एजेंसियों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए था।<sup>7</sup> आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत स्वेच्छिक प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) का उद्देश्य लोगों द्वारा औपचारिक आर. टी. आई. आवेदनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता को कम करना है।

अत्यधिक शुल्क की मांग और अनुचित अपेक्षाएँ

मांगी गई जानकारी की सामान्य प्रकृति के बावजूद, कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों ने ऐसी जानकारी की आपूर्ति के लिए भी अत्यधिक शुल्क लिया जो उन्हें अपनी वेबसाइटों पर स्वेच्छा से प्रकाशित करनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए, केरल एस.एच.आर.सी. ने वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए 3,000 रुपये का बिल भेजा। आई. जे. आर. टीम ने इस शुल्क का भुगतान न करने का फैसला किया। इसी तरह, मध्य प्रदेश एस.एच.आर.सी. ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट की आपूर्ति करने के लिए 1,010 रुपये के अतिरिक्त शुल्क की मांग की।

## अत्यधिक शुल्क की मांग और अनुचित अपेक्षाएँ

शुल्क से संबंधित सबसे अनूठी प्रतिक्रियाएं गोवा और तमिलनाडु से आईं। गोवा के पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) के कार्यालय द्वारा, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, 2 रुपये की शाही राशि का भुगतान करने की मांग की गई। पेरनेम, गोवा में उप-मंडल (Sub Divisional) पुलिस अधिकारी के कार्यालय के पी. आई. ओ. ने 4 रुपये के भुगतान करने की मांग की, जबकि मापुसा कार्यालय ने 6 रुपये मांगे। मापुसा पी. आई. ओ. ने भारतीय नागरिक होने का पहचान प्रमाण (Identity proof) भी मांगा। तीनों पी. आई. ओ. ने गोवा के आर. टी. आई. नियमों के तहत अनुमत (Permissible), शुल्क भुगतान के वैकल्पिक तरीकों के बारे में हमें सलाह देने के बजाय वहाँ आकर व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने पर जोर दिया। जवाब तैयार करने और डाक द्वारा हमें भेजने पर किए गए सार्वजनिक धन के व्यय की राशि पी. आई. ओ. द्वारा की जा रही मांगों से कहीं अधिक होगी। इसके बजाय, सार्वजनिक संसाधनों और समय के व्यर्थ खर्च से बचने के लिए जानकारी तुरंत प्रदान की जा सकती थी।

10 रुपये आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न (attach) करने के बावजूद, तमिलनाडु के फॉरेंसिक विज्ञान विभाग के पी. आई. ओ. ने यह कहते हुए हमारा आवेदन वापस कर दिया कि उन्हें लिफाफे में ड्राफ्ट नहीं मिला। ये अनुभव सार्वजनिक अधिकारियों के एक स्पष्ट इरादे का संकेत देते हैं कि वह अनुरोधित जानकारी को

1 वेकटेश नायक, निदेशक, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, मार्च 2023 द्वारा आईजेआर के लिए तैयार किया गया नोट।  
 2 सभी पुलिस थानों में सी. सी. टी. वी. लगाने पर, सभी पुलिस थानों में सी. सी. टी. वी. की संख्या, उनकी स्थिति और कार्यप्रणाली और परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह के फैसले के अनुसार बजटीय आवंटन।  
 3 अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करना और राज्य और जिला स्तर की निरीक्षण समितियों की स्थापना, एस. एल. ओ. सी. और डी. एल. ओ. सी. की संरचना और आयोजित बैठकों की संख्या।  
 4 राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं पर; वार्षिक रिपोर्ट, उपलब्ध मानव संसाधन (वैज्ञानिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की रक्तियां), बजट (स्वीकृत और उपयोग), कार्यभार (प्राप्त मामले, निपटान और लंबित), प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रभागों की संख्या और उनके बुनियादी ढांचे और उपकरण।  
 5 मानव संसाधन (कर्मचारी, सचिव, अध्यक्ष, पैनेल वकील), बजट और व्यय, पैरालिगल वॉलंटियर्स (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग), कानूनी सहायता लाभार्थियों, पीड़ित मुआवजे और विचाराधीन समीक्षा समितियों के संदर्भ में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की क्षमता।

7 भारत सरकार की समर्पित वेबसाइट पर सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश 3.0 यहां देखें-अत्यधिक शुल्क की मांग <https://guidelines.india.gov.in/introduction/03/03/2023> पर एक्सेस किया गया।

साझा नहीं करना चाहते हैं और जब आर. टी. आई. आवेदन को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए छूट को लागू नहीं किया जा सका तो पारदर्शिता के कर्तव्य से बचने के उनके प्रयास को भी दर्शाते हैं।

## गेटवे की समस्याएं

कुछ राज्य सरकारों ने देश में कहीं से भी आर. टी. आई. आवेदन जमा करने के लिए सुविधाजनक ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। देश के किसी भी कोने में बैठे नागरिक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से तुरंत भुगतान किया जा सकता है। डाक परिवहन प्रारंभिक वर्षों में आर. टी. आई. आवेदन जमा करने का पसंदीदा तरीका था लेकिन उसके कारण होने वाली देरी से बचने के लिए इस नई सुविधा के अंतर्गत आर. टी. आई. आवेदन तुरंत पी. आई. ओ. तक पहुंचाया जाता है।

हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने इस सुविधा को अपनाया है। हालाँकि, हरियाणा एस. एच. आर. सी. की तरफ से हमारे ऑनलाइन आर. टी. आई. आवेदन का कभी कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक कि पी. आई. ओ. की प्रतिक्रियाओं की कमी के खिलाफ, इस सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत की गई पहली अपील भी 45 दिनों की वैधानिक समय सीमा तक लंबित रही। वेबसाइट के इस दावे के बावजूद कि एसएचआरसी उन 12 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से एक है, जिसके पोर्टल के माध्यम से ही आर. टी. आई. आवेदन जमा किए जा सकते हैं हमें इसके अध्यक्ष द्वारा कॉल और पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद हमारी टीम ने शुल्क के लिए एक आई. पी. ओ. (भारतीय डाक आदेश) संलग्न करते हुए डाक द्वारा नए सिरे से वही प्रश्न प्रस्तुत किए। पी. आई. ओ. ने यह कहते हुए आवेदन वापस कर दिया कि आई. पी. ओ. संलग्न नहीं किया गया था। तीसरा आर. टी. आई. आवेदन दिसंबर 2022 में दायर किया गया था और इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय भी जवाब का इंतजार था।

## लापता पी. आई. ओ.

पुडुचेरी की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने हमारे आर. टी. आई. आवेदन को यह बताते हुए वापस कर दिया कि पी. आई. ओ. की नियुक्ति नहीं की गई है। आर. टी. आई. अधिनियम लागू होने के 17 साल बाद भी पी. आई. ओ. की नियुक्ति नहीं करना इन निकायों (bodies) के प्रमुखों को सौंपे गए वैधानिक दायित्व का स्पष्ट उल्लंघन है। आर. टी. आई. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना अनुरोध प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व है। पी. आई. ओ. सार्वजनिक प्राधिकरण का मुख्य व्यक्ति है जो इन कर्तव्यों का पालन करता है। हालाँकि पी. आई. ओ. की नियुक्ति न होने से सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं – जो कि 100 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित (funded) हैं – अपने रिकॉर्ड से

संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के उनके कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते हैं।

## आर. टी. आई जांच नियम के अनुसार एक प्रश्न

हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एस.एच.आर.सी. ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए शुरूआती आर.टी.आई. आवेदन लौटा दिए। एस.पी. एस.एच.आर.सी. ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 2006 आरटीआई नियमों का हवाला दिया, जो प्रत्येक आरटीआई आवेदन के दायरे को केवल एक विषय और एक वर्ष तक सीमित करता है। इसके बाद आईजेआर टीम ने इनकी रिक्तियों, स्टाफिंग, बजट, वार्षिक रिपोर्ट और केसलॉड आदि के बारे में जानकारी मांगने के लिए 37 और आर.टी. आई. आवेदन दायर किए। हालाँकि यह सारी जानकारी आर.टी.आई अधिनियम की धारा 4(1) के विभिन्न खंडों के तहत उनकी वेबसाइट पर स्वेच्छा से प्रकट की जानी चाहिए थी। इस तरह के प्रकटीकरण की अनुपस्थिति ने हमें औपचारिक रूप से जानकारी मांगने के लिए मजबूर किया है। एक आरटीआई आवेदन को खारिज करके और आरटीआई आवेदनों को विषय और वर्ष-वार विभाजित करने पर जोर देकर, एस.एच.आर.सी. ने न केवल अपने कार्यभार को 37 गुना बढ़ाया, बल्कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 7 (1) में निहित स्पष्ट प्रावधान का भी उल्लंघन किया जिसके अनुसार सभी सूचना अनुरोधों का यथासंभव शीघ्रता से निबटारा (disposed) किया जाना चाहिए।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ और बिहार एस.एच.आर.सी. ने भी उनके संगठन के बारे में बुनियादी जानकारी के लिए दिए गए प्रारंभिक आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए अपने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित आर.टी.आई. नियमों में लगाई गई 'एक विषय वस्तु और 150 शब्दों की सीमा' का हवाला दिया। फिर हमने उनमें से प्रत्येक को 9 अलग-अलग आर.टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें मांगी गई जानकारी का पहली बार में ही आसानी से खुलासा किया जा सकता था। शब्द सीमा और विषय वस्तु प्रतिबंध पर उनके आग्रह का पालन करने के बावजूद, बिहार एस.एच.आर.सी. ने अभी तक अपने कर्मचारियों की संरचना, स्टाफिंग में लिंग विविधता, आवंटित बजट, साथ ही प्रत्येक वर्षों में किए गए व्यय के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया है। महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 150 शब्दों की सीमा से अधिक होने के कारण आर.टी.आई. आवेदन को खारिज कर दिया। हालाँकि, पी.आई.ओ. पहले 150 शब्दों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता था।

एक आर.टी.आई. आवेदन केवल धारा 8 या 9 में उल्लिखित कारणों से खारिज कर दिया गया, जिसमें छूट खंड शामिल हैं, अन्य कुछ नहीं। हालाँकि कुछ राज्य शब्द सीमाएँ और विषय वस्तु जैसे प्रतिबंध

लगाते हैं, लेकिन इन्हें किसी आर.टी.आई. आवेदन को अस्वीकार करने या इसे अनदेखा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

यह बताया जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकरण को सौंपा गया एक आर.टी.आई. आवेदन भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का एक प्रयोग है जिसमें लिखित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति शामिल है। इस अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं – जो कि इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों को सूचीबद्ध करता है और जो यह कहता हो कि नागरिकों को खुद को व्यक्त करते समय शब्द सीमा और विषय वस्तु सीमाओं के दायरे में वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि यह सिद्धांत इन राज्यों के आर.टी.आई. नियमों पर लागू किया जाता है, तो वे न्यायिक जांच में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे।

## अनुरोधों और संबंधित उपाख्यानो (anecdotes) की संदिग्ध अस्वीकृति

प्रकटीकरण के कर्तव्य से बचने के लिए, कुछ अन्य पी.आई.ओ. ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध छूटों या उनकी संबंधित सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत पूरे संगठनों को आर.टी.आई. अधिनियम के दायरे से छूट दी। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के पी.आई.ओ. ने राज्य सरकार की 2005 की एक अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें इसे सुरक्षा और खुफिया संगठनों की सूची में रखा गया था, जिन्हें आर.टी. आई. अधिनियम के तहत पारदर्शिता के सामान्य दायित्वों से बाहर रखा गया है। ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और गुजरात की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा भी इसी तरह के छूट प्रावधानों का दावा किया गया था। त्रिपुरा के पुलिस विभाग के पी.आई.ओ. और असम के धुबरी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पी.आई.ओ. ने भी अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट का हवाला देते हुए सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। हालाँकि ऐसी अधिसूचनाओं में दी गई छूट के कारण उनके उत्तरों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उन्हें आर.टी.आई. अधिनियम के दायरे से बाहर रखने से संबंधित राज्य सरकारों की कार्रवाई चिंतनीय है।

आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 24 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आर.टी.आई. अधिनियम में उल्लिखित पारदर्शिता के सामान्य दायित्वों से उनके “सुरक्षा और खुफिया” संगठनों को बाहर करने की अनुमति देती है। वे केवल ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं जो भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित होती है जिसे वे अपनी फाइलों में रखते हैं।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की जानकारी की मांग

कुछ पी.आई.ओ. ने सीसीटीवी कैमरा लगवाने और/या पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी देने से इनकार करने के लिए आर.टी. आई. अधिनियम की धारा 8(1) के तहत सूचीबद्ध वैधानिक छूट का इस्तेमाल किया। गुजरात में, राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए सीसीटीवी कैमरों के उपयोग और फोरेंसिक जांच उद्देश्यों के लिए वीडियो फुटेज निकालने के लिए पुलिस कर्मियों को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी शामिल थी। जहां अरुणाचल प्रदेश की एफ.एस.एल. ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट देने वाली सरकारी अधिसूचना की एक प्रति प्रस्तुत की, वहीं गुजरात पी.आई.ओ. ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया।

हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त के पी. आई. ओ. ने भी आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) का हवाला देते हुए सी. सी. टी. वी. कैमरा लगाने के संबंध में सौंपे गए आर. टी. आई. आवेदन को खारिज कर दिया। यह धारा ऐसी जानकारी को गोपनीय माने जाने की अनुमति देती है जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गुप्त रूप से प्रदान की गई जानकारी के स्रोत का प्रकटीकरण होता हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसरण में सीसीटीवी कैमरा लगाने के संबंध में आर.टी.आई. आवेदन के नमूने के एक अध्ययन के बाद यह पता चल सकता है कि यह विषय धारा 8(1)(जी) के तहत उल्लिखित छूट के किसी भी आधार के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि ऊपर प्राधिकरणों द्वारा कहा गया है।

फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि पी. आई. ओ. ने इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से अपना दिमाग लगाए बिना छूट का हवाला देकर आर. टी. आई. आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि यह जानकारी केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए मांगी गई थी। भले ही कोई क्षणिक रूप से पी. आई. ओ. से सहमत हो जाए, लेकिन आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत ऐसी कथित 'छूट' वाली जानकारी का खुलासा करने में भी अपार सार्वजनिक हित है, क्योंकि व्यापक सार्वजनिक हित धारा 8 (1) (जी) के तहत संरक्षित हितों के किसी भी नुकसान से अधिक है क्योंकि अंत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानूनी हिरासत में हिंसा से, जीवन और अंगों की रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को लगाने का निर्देश जो दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि बिहार के मुख्य सचिव कार्यालय के पी.आई.ओ. ने जवाब दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में जानकारी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है - इस तथ्य के बावजूद कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन पर आती है। पश्चिम बंगाल के पुलिस निदेशालय (Directorate) से यह उत्तर मिला कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में बजटीय आवंटन और धन का उपयोग राज्य सरकार से संबंधित मामले हैं। उत्तराखंड पुलिस के पी.आई.ओ. ने हमें सलाह दी कि हम प्रत्येक जिले

8 छूट खंड उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां (i) मांगी गई जानकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है (ii) यदि प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से कानून की अदालत द्वारा निषिद्ध है, (iii) संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन का कारण बनता है (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य, या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी (v) किसी व्यक्ति को उपलब्ध जानकारी उसका प्रत्येकी संबंध है (vi) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी (vii) प्रकटीकरण से किसी भी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरों में पड़ सकती है, (viii) जांच की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है (ix) कैबिनेट के कागजात जिसमें परिषद के मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं (x) व्यक्तिगत जानकारी जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

के पी.आई.ओ. से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उन पुलिस स्टेशनों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनके उपयोग में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की संख्या, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित जिला निरीक्षण समितियों की संख्या और उनके कामकाज के बारे में विवरण लें।

## निष्कर्ष

यहां तक कि जिन सार्वजनिक प्राधिकरणों ने या तो निःशुल्क या अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान की, उनमें से किसी ने भी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में पूरी जानकारी प्रदान नहीं की। कुछ मामलों में, उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का अधिक अर्थ निकालना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस ने वर्षवार विवरण प्रदान करने के बजाय, समग्र रूप से पाँच वर्ष की अवधि में लगे सीसीटीवी कैमरों की बजटीय जानकारी प्रदान की।

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दिए गए बजटीय आंकड़ों से यह पता नहीं

चला कि ये आंकड़े हजारों में, लाखों में या करोड़ों में थे। बिहार पुलिस विभाग ने केवल दो वर्षों के लिए बजटीय आंकड़े उपलब्ध कराए - उस अवधि की शुरुआत से लेकर अंत तक, जिसके लिए हमने जानकारी मांगी थी। जबकि मेघालय पुलिस ने हमारे अनुरोध से अधिक जानकारी प्रदान की। हालाँकि, उसने वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जो माँगी गई थी। इस पी. आई. ओ. ने हमें पुलिस विभाग और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चुने गए विक्रेता के बीच पूरा पत्राचार भेजा। पुलिस को सौंपे गए आइटम के साथ खरीद आदेश भी हमारे साथ साझा किए गए थे। इसके अलावा, मेघालय की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि सभी जानकारी अधिकारियों के पास उपलब्ध थी और उनमें से कुछ भी सार्वजनिक डोमेन से अलग या दूर रखने की आवश्यकता नहीं थी।

**वेंकटेश नायक,**  
राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, भारत

## अध्याय 7

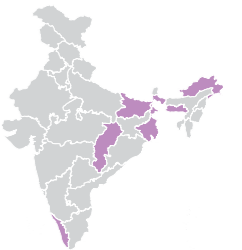
# आंकड़ों में चुनौतियाँ

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की रैंकिंग - चाहे स्तंभवार हो या पूर्णतः - पूरी तरह से राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मात्रात्मक (quantitative) आंकड़ों पर निर्भर करती है जिसमें संख्याएं और आंकड़े शामिल हैं। आंकड़ा जितना सटीक होगा, उसके निष्कर्ष उतने ही निष्पक्ष होंगे। गलत और पुराना आंकड़ा न केवल एक झूठी और अक्सर अनुचित तस्वीर पेश करता है, बल्कि इसमें सुधार के रास्ते भी बाधित करता है। इसे संबोधित करने के लिए, आंकड़ों को एक महत्वपूर्ण लेंस के साथ देखना और नुकसान को कम करने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य रूप से, आई. जे. आर. ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), पुलिस संगठन पर आंकड़े (डी. ओ. पी. ओ.), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.), भारतीय जेल सांख्यिकी भारत (पी. एस. आई.) रिपोर्ट, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन. जे. डी. जी.) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट और डैशबोर्ड का उपयोग किया है। ये राज्य द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के राष्ट्रीय एकत्रीकरण हैं। इसके अलावा, आईजेआर ने संसदीय प्रश्नों, राज्य के बजट दस्तावेजों और अंत में, आर. टी. आई. प्रश्नों के उत्तरों पर भरोसा किया है। डेटा सेट विभिन्न एजेंसियों और प्रकाशनों के रिकॉर्ड में एक ही विषय से संबंधित कई कठिन विसंगतियों को दिखाते हैं। कुछ चुनौतियाँ नीचे चित्रित हैं।

### जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

राज्य	2020-21 के अंत में लंबित आवेदन	2021-22 में प्राप्त आवेदन	कुल अनुप्रयोग (बी + सी)	आवेदनों का निपटान 2021-22 में किया जाता है	2021-22 के अंत में लंबित आवेदन	2021-22 [(B + C)-E] के अंत में वास्तविक विचाराधीनता
A	B	C	D	E	F	G
अरुणाचल प्रदेश	0	42	42	4	7	38
बिहार	654	1,002	1,656	785	348	871
छत्तीसगढ़	617	2,195	2,812	1,253	1,267	1,559
केरल	81	560	641	139	123	502
मेघालय	79	158	237	75	23	162
पश्चिम बंगाल	33	356	389	246	38	143



9 लोकसभा अतारंजित प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022। यहां उपलब्ध है: <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf>

10 न्यायाधीशों की संख्या पर न्याय विभाग का पोर्टल। यहां उपलब्ध है: <https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/index.php>

11 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ई-जेल पोर्टल। यहां उपलब्ध है: <https://eprisons.nic.in/public/DashBoard>

12 NALSA की वेबसाइट कानूनी सेवा क्लीनिक, मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामलों, स्थायी लोक अदालतों, राष्ट्रीय लोक अदालतों और पीड़ित मुआवजा योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित आंकड़े दर्ज करती है। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics>



## डैशबोर्ड

पारदर्शी सरकारी आंकड़े न केवल नागरिकों को सरकारी आंकड़ों की दक्षता को ट्रैक करने की सहूलियत देते हैं, बल्कि सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के बीच आंकड़ों को साझा करने की सुविधा भी देते हैं। तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में आंकड़ों के एक प्रमुख संसाधन के रूप में उभरने के कारण, नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड बनाने वाली सरकारी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रसार हुआ है।

न्याय वितरण में सुधार के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा प्राथमिक ई-गवर्नेंस पहलों में से एक 'ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट' है। वर्तमान में अपने तीसरे चरण में, इस पहल ने 3,256 अदालत परिसरों का आंकड़ा उपलब्ध कराया है, 688 जिला अदालतों की व्यक्तिगत वेबसाइटें स्थापित की हैं, और ई-फाइलिंग और ई-भुगतान के बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक मजबूत अदालत प्रबंधन प्रणाली बनाई है।<sup>13</sup> इस परियोजना ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) भी लागू किया है, जो कि सभी अदालतों में लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों का राष्ट्रीय भंडार है।<sup>14</sup>

एन.जे.डी.जी. के अलावा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय विभाग द्वारा शुरू किए गए अन्य पोर्टलों का उपयोग भी किया गया है,<sup>15</sup> जिसमें जिला न्यायपालिका स्तर पर मानव संसाधनों और विविधता के आंकड़ों को एकत्रित करने वाले पोर्टल, साथ ही ग्राम न्यायालयों का वितरण भी शामिल है।<sup>16</sup> इसके अलावा, रिपोर्ट में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ-साथ नालसा डैशबोर्ड द्वारा विकसित ई-जेल पोर्टल से भी आंकड़े एकत्र किये गए हैं।

हालांकि डिजिटलीकरण पर जोर देना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार अभी भी एकत्र किए गए आंकड़ों की क्षमता को अधिकतम नहीं कर पाई है। गुम आंकड़ों के बिंदु, विभिन्न डेटासेट में विसंगतियों के साथ-साथ अभिलेखीय आंकड़े (Archival Data) तक सीमित पहुंच जैसी समस्याएं ऐसे पोर्टलों के पूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। इन पोर्टलों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

- ई-जेल पोर्टल जेलों और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, यह अभी वर्तमान समय के आंकड़े प्रदान

करता है और अभिलेखीय आंकड़े अभी तक पहुंच योग्य नहीं है। इसके अलावा इसमें विस्तृत और अलग-थलग विषय के अनुसार वर्गीकृत जानकारी का भी भारी अभाव है। उदाहरण के लिए, यह विचाराधीन कैदियों और दोषियों के रूप में जेल की आबादी का कोई वर्गीकरण प्रदान नहीं करता है और न ही यह अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण प्रदान करता है।

- ग्राम न्यायालयों पर डीओजे पोर्टल, देश भर में इन निकायों के वितरण के साथ-साथ मामले के निपटान पर आंकड़े एकत्रित करता है, हालांकि वह एक महीने से अधिक समय तक आंकड़ों को संग्रहीत नहीं करता है।<sup>17</sup>
- इसी तरह, डीओजे पोर्टल अपने आंकड़ों की संख्याओं में विसंगतियां दिखाता है जो जिला न्यायपालिका स्तर पर मानव संसाधनों और विविधता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, डैशबोर्ड न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत संख्या को एक स्थान पर 482 लेकिन दूसरे स्थान पर 526 दिखाया गया है।

## मानकीकरण का अभाव

आंकड़े एकत्रित करने और प्रकाशित करने के लिए एक विशिष्ट समय अवधि की अनुपस्थिति किसी भी मुद्दे में पूरी तस्वीर पेश करने की क्षमता को कम कर देती है। उदाहरण के लिए, बीपीआर एंड डी हर साल जनवरी तक के आंकड़ों के साथ 'पुलिस संगठन पर आंकड़े' प्रकाशित करता है। उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट 1 जनवरी 2022 तक उपलब्ध होती है। इसी तरह, एनसीआरबी की 'प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' देश भर की जेलों पर हर साल दिसंबर तक का डेटा लाती है, और नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2021 तक उपलब्ध होती है। ये दोनों संगठन गृह मंत्रालय के अधीन हैं।

न्यायपालिका के आंकड़ों को विभिन्न स्तरों पर बनाए रखा जाता है, जिसकी शुरुआत जिला अदालतों से होती है, जिसके लिए आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और कई प्लेटफॉर्म पर यह रिपोर्ट्स जैसे कि ई-कोर्ट, एनजेडीजी के साथ-साथ प्रत्येक उच्च न्यायालयों की वार्षिक रिपोर्ट जैसी रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है। हालांकि, आंकड़ों को अलग-अलग समय पर एकत्र किया जाता है और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट 2019 की है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 2006 की वार्षिक रिपोर्ट है।

कुछ एजेंसियां वित्तीय वर्ष के आंकड़े एकत्र करती हैं जबकि अन्य कैलेंडर वर्ष का उपयोग करती हैं। उच्चतम न्यायालय की 2020-21

की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष प्रारूप का उपयोग करती है कुछ उच्च न्यायालय मासिक, अन्य त्रैमासिक और अन्य वार्षिक रूप से आंकड़े प्रदान करते हैं। कुछ उच्च न्यायालय वित्तीय वर्ष प्रारूप का उपयोग करते हैं जबकि अन्य कैलेंडर वर्ष का उपयोग करते हैं।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट कैलेंडर और वित्तीय वर्ष दोनों प्रारूपों में आती है। मार्च 2019 के बाद नालसा के डैशबोर्ड को अपडेट किया जाना बाकी है। राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट- 25 में से 17 राज्यों ने वार्षिक रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। अन्य आयोग अनियमित रूप से प्रकाशित करते हैं या कभी भी प्रकाशित नहीं करते हैं।

## श्रेणी और संग्रह में परिवर्तन

अधिक विवरण जोड़ने हेतु अपने प्रारूपों में सुधार करते हुए, 2018 में, बी.पी.आर.एंड डी. के डी.ओ.पी.ओ. ने कुल पुलिस थानों की संख्या के साथ यातायात/विशेष पुलिस थानों को एकत्रित किया। अगले वर्ष उन्होंने पुलिस थानों को रेलवे पुलिस थानों के साथ जोड़ा गया और 2020 में वर्गीकरण को पूरी तरह से ग्रामीण, शहरी और विशेष उद्देश्य वाले पुलिस थानों में बदल दिया गया और यातायात पुलिस थानों को उनका अपना अध्याय दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2016 तक, बी. पी. आर. एंड डी. ने 12 पैमानों में से 6 रैंक के लिए जाति सम्बन्धित आंकड़ा प्रदान किया। 2017 और 2018 के लिए, इसे घटाकर 4 रैंक कर दिया गया और 2019 और 2020 में फिर से 6 रैंक पर वापस ला दिया। जबकि महिलाओं पर आंकड़े प्रत्येक रैंक के लिए वर्गीकृत है, एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के लिए समान विभाजन उपलब्ध नहीं है।

पुलिस संगठन (डी. ओ. पी. ओ.) के आंकड़ों ने 2017 में पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए सेवा प्रशिक्षण की सूचना दी। 2017 के बाद से यह जारी नहीं रखा गया। इसी तरह एक ओर जिला अदालत के न्यायाधीशों और राज्य पुलिस के लिए जाति और लिंग पर आंकड़ा प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या आई. पी. एस. अधिकारी पदों के लिए ऐसा कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। 2013 तक पुलिस के लिए उपलब्ध धर्म के आधार पर आंकड़े अब उपलब्ध नहीं हैं।

## 'अन्य' आंकड़े

अक्सर अन्य विस्तृत आंकड़ों के निहितार्थों (implications) को एक

अनिश्चित श्रेणी "अन्य या अन्य यदि कोई हो" की उपस्थिति से अनदेखा कर दिया जाता है। ये कॉलम जो अक्सर अवशिष्ट और अनिर्धारित जानकारी रखते हैं, वे एन. सी. आर. बी. और बी. पी. आर. डी. के राष्ट्रीय डेटा सेट में मौजूद होते हैं। अक्सर उनमें व्याख्यात्मक टिप्पणियों नहीं होती हैं जिससे यह बताया जा सके कि वे क्या तात्पर्य रखते हैं या एक विस्तृत और स्पष्ट तस्वीर को अस्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वीकृत, वास्तविक और खाली पुलिस पदों को सूचीबद्ध करने के बाद बी. पी. आर. डी. 'अन्य यदि कोई' पुलिस कर्मियों को सूचीबद्ध करता है। अक्सर ये एक बड़ी संख्या होती हैं।

पी. एस. आई. भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और 'अन्य' के तहत कैदियों पर होने वाले खर्च का विवरण देता है। 'अन्य' श्रेणी अक्सर उच्च व्यय दिखाती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा की 'अन्य' श्रेणी 306.5 करोड़ रुपये का व्यय दर्शाती है जो उनके कुल व्यय का 87.5 प्रतिशत है। व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि इस श्रेणी के खर्च में 'स्वच्छता, रिमांड के दौरान कैदियों की आवाजाही के लिए परिवहन सुविधाओं, परीक्षण, स्थानांतरण, अस्पतालों आदि पर किया गया खर्च शामिल हो सकता है।'<sup>18</sup>

पी. एस. आई. कैदियों के प्रकारों को भी दोषी, विचाराधीन, बंदी और 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत करता है। देश भर में 'अन्य' कैदियों की संख्या 547 है। एक अन्य अस्पष्ट श्रेणी जेल में मौतों से संबंधित है। पी. एस. आई. कैदियों की मौत को 'प्राकृतिक' और 'अप्राकृतिक' कारणों और 'अन्य' के कारण होने के रूप में दर्ज करता है। प्राकृतिक कारणों में उम्र बढ़ने और बीमारी के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। जबकि प्राकृतिक कारणों को अंग विफलता के प्रकार या एच. आई. वी. या कैंसर जैसी बीमारियों में काफी विस्तार के साथ वर्गीकृत किया जाता है और अप्राकृतिक मौतों में आत्महत्या, लापरवाही के कारण होने वाली मौतें, दुर्घटनाएं और 'अन्य' शामिल हैं। मौतों की यह श्रेणी अस्पष्ट बनी हुई है, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो।

निस्संदेह आपराधिक न्याय प्रणाली की एक अधिक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए अधिक से अधिक आंकड़ों को सामने रखा जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है और एकीकृत किया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्य है जो प्रगति पर है जो मानक संचालन प्रोटोकॉल, निरंतरता और लगातार बढ़ती बारीकियों से लाभान्वित होगा।

13 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति न्यायिक प्रणाली द्वारा अपनाई गई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) पहलों को प्रदर्शित करती है। यहाँ उपलब्ध है: <https://ecommitteesci.gov.in/significant-achievements/>

14 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, यहाँ उपलब्ध है: <https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/index.php>

15 न्यायाधीशों के बल पर न्याय विभाग पोर्टल। यहाँ उपलब्ध है <https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/index.php>

16 न्याय विभाग का ग्राम न्यायालय पोर्टल। यहाँ उपलब्ध है: [https://dashboard.doj.gov.in/gn/notified\\_gram\\_nyayalaya](https://dashboard.doj.gov.in/gn/notified_gram_nyayalaya)

17 रैकिंग के लिए, आई. जे. आर. लोकसभा के अंतरांकित प्रश्न संख्या में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करता है। 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022। यहाँ उपलब्ध है <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf>

18 भारतीय जेल सांख्यिकी, 2021, तालिका 12.4, पृ. 276. यहाँ उपलब्ध है: <https://ncrb.gov.in/en/prison-statistics-india-2021>

## अध्याय 8

# कार्यप्रणाली

मापन प्रक्रिया-हमें विकास के बारे में अध्ययन, तुलना, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालने में और-नीतिगत निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है।

संख्याओं के निर्धारण के माध्यम से विभिन्न गुणों का मूल्यांकन सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों का मूल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 2022 संस्करण (edition) के जरिए, हम न्याय प्रणाली के चार प्रमुख स्तंभों, अर्थात् पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता और चौथे ताकतवर स्तंभ राज्य मानव अधिकार आयोग के माध्यम से राज्यों में न्याय क्षमता में सुधार के दायरे के साथ-साथ स्थिरता का मानचित्रण करते हैं। पिछले दो संस्करणों की तरह, हमारे आकलन को गहरा और व्यापक बनाने के उद्देश्य से नए संकेतक जोड़े गए हैं। चार मुख्य स्तंभों में सत्रह नए संकेतक जोड़े गए हैं, जिससे संकेतकों की कुल संख्या 102 हो गई है।

यह आई.जे.आर. राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस.एच.आर.सी.) की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन अलग से करता है, न कि किसी राज्य की समग्र रैंकिंग के हिस्से के रूप में।

सभी स्तंभों को छह विषयों के आधार पर मापा जाता है: बजट, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता और रुझान (या सुधार का इरादा)।

### चरण 1: रूपरेखा

चारों स्तंभों के आंकड़ों के संकेतक :

	स्तंभ	कुल संकेतक	नए संकेतक
1.	पुलिस	30	4
2.	जेल	29	6
3.	न्यायपालिका	28	5
4.	कानूनी सहायता	15	2
	कुल	102	17

स्तंभों पर संकेतक निम्नलिखित विषयों को कवर करते हैं:

1. आधारभूत संरचना
2. मानव संसाधन
3. विविधता (लिंग, एससी/एसटी/ओबीसी)
4. बजट
5. कार्यभार
6. रुझान (पिछले पांच वर्षों में बदलाव)

प्रत्येक विषय एक स्तंभ के कामकाज के लिए आवश्यक पूर्व शर्त (precondition) का प्रतिनिधित्व करता है। बजट प्रति कार्यकर्ता या प्रति व्यक्ति प्राप्त, उपयोग और खर्च किए गए धन को मापता है; बुनियादी ढांचा, अर्थात् उपलब्ध बुनियादी भौतिक संसाधन; मानव संसाधन स्वीकृत और कार्यस्थल पर उपलब्ध कर्मियों पर ध्यान देता है; कार्यभार एक विशेष उपप्रणाली के भीतर एक पदाधिकारी पर सेवा वितरण का भार दर्शाता है; और विविधता यह आकलन करती है कि ये प्रणालियाँ उन आबादी का कितना प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी सेवा के लिए उन्हें स्थापित किया गया है। छठे विषय, 'रुझान' का उपयोग, जहां संभव हो, यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि किसी विशेष विषय में पांच वर्षों में सुधार हुआ है या गिरावट देखी गई। अंत में कुल रैंकिंग पर पहुंचने पर इस विषय को भी ध्यान में रखा जाता है।

### चरण 2: समूहीकरण (clustering)

भारत भर में जनसांख्यिकी (Demography) और भूगोल दोनों के संदर्भ में व्यापक विविधताएं, तुलना करना कठिन बना देती हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस क्षमता गोवा या सिक्किम की तुलना में अतुलनीय है। राज्यों के बीच निष्पक्ष तुलना करने के लिए, रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार समूहों में विभाजित करती है:

#### समूह 1 (रैंकिंग)

अठारह बड़े और मध्यम आकार के राज्य या 100 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले राज्य।

#### समूह 2 (रैंकिंग)

100 लाख तक की आबादी वाले सात छोटे आकार के राज्य, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा।

#### समूह 3 (रैंक नहीं किए गए)

8 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आंकड़ा प्रदान किया गया है लेकिन उन्हें रैंक नहीं किया गया है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।

#### समूह 4 (रैंक नहीं किए गए)

तीन राज्य ऐसे हैं जहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) लागू है, अर्थात् मणिपुर, असम और नागालैंड। रिपोर्ट इन पर आंकड़े प्रदान करती है लेकिन उन्हें रैंक नहीं करती है।

#### चरण 3: फिल्टर करना

सभी संकेतक सरकारी आंकड़ों की उपलब्धता और राज्यों में तुलनीयता के आधार पर चुने जाते हैं। बेंचमार्क यानी विभिन्न मानक जहां भी उपलब्ध हो जैसे कि कानूनों में, नीतिगत घोषणाओं में और उच्चतम न्यायालय के फैसलों में से लिए जाते हैं। सरकारी सुझावों का भी उपयोग किया जाता है। स्तंभों में सत्रह नए संकेतक हैं, जिनमें से कुछ न्यायपालिका के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों में विविधता, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क और राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों की हिस्सेदारी को मापने वाले संकेतक हैं।

#### आधारभूत

आई.जे.आर. 2022 प्रेस में जाने के समय उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करता है। ये हैं:

बजट दस्तावेजों की असमान उपलब्धता और प्रत्येक बजट प्रमुखों को रिकॉर्ड करने के तरीके में भिन्नता के कारण राज्य के बजट दस्तावेजों

के बजाय लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दस्तावेजों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, कानूनी सहायता के लिए, राज्य के बजट दस्तावेजों का उपयोग किया गया क्योंकि बजटीय आंकड़े सीएजी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे।

#### ई-जेल पोर्टल

भीड़भाड़ वाली जेलों पर दो संकेतकों के लिए - एक राज्य में क्षमता से ज़्यादा भारी हुई जेलों की हिस्सेदारी और 150 प्रतिशत तक भारी हुई जेलों की हिस्सेदारी - रिपोर्ट में ई-जेल पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पोर्टल में 1,367 जेलों की सूची है, जिनमें से 53 जेलों को कुल संख्या में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि वे कार्यात्मक नहीं हैं या संबंधित जेल विभागों के पास जेलों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, या उनमें से कुछ राजस्व विभाग के अंतर्गत आती हैं। इस रिपोर्ट में, जुलाई से अक्टूबर 2022 तक, तीन महीने की अवधि में ई-जेलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

#### वर्ष के अंत में लंबित मामले

न्यायपालिका स्तंभ के तहत 'वर्ष के अंत में लंबित मामलों' संकेतक के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वर्ष की शुरुआत/अंत में लंबित मामलों का डेटा एनजेडीजी के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए, अदालत द्वारा चर्चा में इस्तेमाल पुराने आंकड़ों को कुछ गणनाओं के लिए उपयोग किया गया है। विभिन्न उच्च न्यायालय वेबसाइटों के आंकड़ों से तुलना करने पर इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है।

स्तंभ/विषय	तिथि/अवधि	स्रोत	स्तंभ/विषय	तिथि/अवधि	स्रोत
पुलिस	1 जनवरी 2022	पुलिस संगठनों 2022 पर आंकड़े	कानूनी सहायता	2020-21, 2021-22, मार्च 2022, जून 2022	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण
जेल	31 दिसंबर 2021	जेल सांख्यिकी भारत 2021	जनसंख्या के आंकड़े	मार्च 2020, मार्च 2021	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2019
न्यायपालिका	2022, दिसंबर 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022, जनवरी 2023	राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय समाचार, न्याय विभाग, संसदीय प्रश्न	बजट के आंकड़े	2020-21	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों के बजट दस्तावेज

1 पहले की रिपोर्ट में, जम्मू और कश्मीर को क्लस्टर IV में शामिल किया गया था। अगस्त 2019 से यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए इसे क्लस्टर III में स्थानांतरित कर दिया गया है। किसी भी तरह से, एक केंद्र शासित प्रदेश या ए. एफ. एस. पी. ए. राज्य के रूप में इसे स्थान नहीं दिया गया है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय 2020 में हुआ था। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डेटा को जहां भी उपयोग किया जाता है, वहां मिला दिया जाता है।

स्रोत	कैलेंडर वर्ष	वर्ष (क) की शुरुआत में लंबित मामले	वर्ष (बी) के दौरान स्थापित मामले	वर्ष (सी) के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले (डी = ए + बी-सी)
अदालती समाचार	2017	2,89,445	1,38,285	1,20,310	3,07,420
अदालती समाचार	2018	3,07,420	1,33,734	1,09,766	3,31,388
एनजेडीजी	2019	3,31,388	1,33,704	1,07,918	3,57,174
एनजेडीजी	2020	3,57,174	98,566	74,206	3,81,534
एनजेडीजी	2021	3,81,534	1,23,289	98,161	4,06,662
एनजेडीजी	2022	4,06,662	1,37,741	1,16,249	4,28,154

### राज्य नागरिक पोर्टल

इन राज्य-वार पोर्टलों द्वारा नौ बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनका मूल्यांकन सेवाओं की पहुंच, भाषा और पूर्णता के आधार पर किया गया। पोर्टल के कामकाज में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक दो बार इन नौ सेवाओं की जांच करके राज्य नागरिक पोर्टल के अनुपालन का आकलन किया गया था। पोर्टल के एक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होने पर एक अंक दिया गया; और सामग्री की पूर्णता के लिए प्रति सेवा एक अंक दिया गया था। जहां एक सेवा को विभिन्न उप-भागों में विभाजित किया गया था, उस चिह्न को भी उप-विभाजित किया गया था। उदाहरण के तौर पर, यदि सेवा चोरी/बरात/वाहन, हथियारों और अन्य संपत्तियों पर विवरण प्रदान करने की मांग करती है, तो तीन उप-श्रेणियों में से प्रत्येक को 0.3 का अधिकतम स्कोर आवंटित किया गया था। इसलिए 'अपूर्ण' सेवाओं को भी आंशिक अंक दिए गए थे।

### राज्य मानवाधिकार आयोग

मौजूदा 25 एस.एच.आर.सी. से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए, 136 आर.टी.आई. आवेदन दायर किए गए थे, क्योंकि एस.एच.आर.सी. के लिए पूरा आंकड़ा न तो एकत्र किया गया था, न ही प्रकाशित किया गया था, या सक्रिय रूप से जनता के सामने प्रकट नहीं किया गया था। सात संकेतकों में से प्रत्येक पर प्रदर्शन की गणना चरण 4 और 5 के समान तरीकों का उपयोग करके की गई थी। असम और मणिपुर को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) की उपस्थिति के कारण रैंकिंग से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद एस.एच.आर.सी. को भंग कर दिया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एस.एच.आर.सी. की स्थापना, शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है, और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क (मानक) के रूप में उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जी.ए.एन.एच.आर.आई.)

और पेरिस सिद्धांतों के तहत स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी उल्लेख किया गया है।

### चरण 4: स्कोरिंग की विधि

आई.जे.आर. 2019 और 2020 की तरह, आंकड़ों को एक सामान्य पैमाने पर फिर से आधारित किया गया था ताकि प्रत्येक संकेतक को 1 से 10 के पैमाने पर स्कोर दिया जा सके, जिसमें 1 सबसे कम या कम से कम वांछनीय (desirable) स्थिति है, और 10 उच्चतम या सर्वोत्तम स्कोर का संकेत देता है। बीच के अंकों को यह दिखाने के लिए अंशांकित किया गया कि कोई राज्य सर्वोत्तम और न्यूनतम के संबंध में कहां खड़ा है। जहां कोई राज्य अपने लिए निर्धारित बेंचमार्क को पूरा करता है या उससे आगे निकल जाता है, तो उसे 10 का स्कोर प्राप्त होता है। ऐसे मामलों में जहां कोई बेंचमार्क उपलब्ध नहीं था, राज्य को 10 का 'शीर्ष' स्कोर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य एक आदर्श क्षमता तक पहुंच गया है, इसका अर्थ केवल यह है कि वह अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम है। प्रत्येक सूचक के अंकों को एकत्र किया गया और एक स्तंभ स्कोर पर पहुंचने के लिए औसत किया गया, 1 से 10 के पैमाने पर भी स्कोर किया गया। रेखा गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean) का उपयोग करके औसत निकाला गया क्योंकि इस विधि में अत्यधिक बाहरी आंकड़ों द्वारा विरूपण (Distortion) की संभावना कम होती है। इस प्रकार, प्रत्येक स्तंभ के लिए प्रत्येक राज्य को 10 में से एक अंक और उसके समूह में एक रैंक मिली। फिर समग्र स्कोर तक पहुंचने के लिए स्तंभ स्कोर का औसत भी 10 में से निकाला गया।

### चरण 5: स्कोरिंग और रैंकिंग

प्रत्येक समूह के लिए, रिपोर्ट ने चरण 4 में उल्लिखित पद्धति को स्तंभ के प्रत्येक संकेतक पर लागू किया। उन राज्यों के लिए जिनके आंकड़े कुछ संकेतकों के लिए अपरिहार्य कारण (Unavoidable Reasons) के कारण गायब थे - वहाँ संकेतकों की संख्या कम कर दी गई थी।

इसका एक उदाहरण हरियाणा का है जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, वहाँ भी संकेतकों की संख्या कम कर दी थी।

कुछ राज्यों को आधुनिकीकरण निधि के लिए अनुदान (grant) नहीं मिला था, ऐसे राज्यों में उनके स्कोर निकालते समय संकेतकों की संख्या भी तदनुसार कम कर दी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए न्यायपालिका का आकलन करने में उनके विभाजन से पहले अलग-अलग आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण केवल तीन-वर्षीय रुझानों का उपयोग किया गया है।

### चरण 6: विषयों और भारों में संकेतक की एकरूपता

प्रत्येक संकेतक, थीम और स्तंभ को समान महत्व दिया गया है ताकि किसी एक पहलू को दूसरे पर अधिक महत्व न दिया जाए। अध्ययन किसी एक तत्व को अधिक या कम महत्व देकर व्यक्तिपरकता (subjectivity) नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक आंकड़े का विवरण पूरे परिणाम को प्रभावित करता है।

### चरण 7: आंकड़ों की जाँच

स्रोत के आंकड़ों की जांच दो समय पर की गई: रैंकिंग का प्रारंभिक सेट तैयार होने के बाद, और रैंकिंग का अंतिम सेट तैयार होने के बाद (दूसरे शब्दों में, वेब और प्रिंट आउटपुट से पहले)। अंतिम आउटपुट पर तीसरे दौर की जाँच की गई।

### अन्य बिंदु

#### दशमलव को पूर्णांकित करना

रिपोर्ट में दशमलव को, आंकड़ों को पढ़ने में आसानी के माध्यम से रखा गया। जहां संख्याएं बड़ी थीं, वहाँ दशमलव को शामिल नहीं किया गया और जहां वे छोटी थीं और भिन्नता में थी, वहाँ दशमलव को शामिल किया गया था - आवश्यकतानुसार एक या दो स्थानों पर।

#### प्रतिशत अंक का उपयोग

रिपोर्ट प्रवृत्ति या परिवर्तन संकेतकों के लिए माप की एक इकाई के रूप में प्रतिशत अंक का उपयोग करती है। इसकी गणना वृद्धि या कमी को उजागर करने के लिए दो प्रतिशत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

#### केंद्र शासित प्रदेश और राज्य

केंद्र शासित प्रदेशों और आफ्रसा राज्यों को क्रमबद्ध नहीं किया गया है जैसा कि पहले ही चरण 2 में उल्लेख किया गया है। अगस्त 2019 तक, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रवृत्ति संकेतकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए ये दोनों प्रवृत्ति संकेतकों में शामिल नहीं हैं। इसी तरह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों का विलय (merged) 26 जनवरी 2020 को किया गया था। इन दोनों के लिए अलग-अलग आंकड़ों को जोड़ा जाता है।

#### अंकगणितीय माध्य की तुलना में रेखा गुणोत्तर माध्य

एक ऐसे परिदृश्य में जहां एक राज्य कुछ चरण में बहुत अच्छा या बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं, और परिणामस्वरूप एक स्तंभ में उच्च या निम्न स्कोर करते हैं, रेखा गुणोत्तर माध्य जो आउटलायर i.e औसत से अत्यधिक संख्या या न्यूनतम चरम चर को सामान्य करता है।

#### साझा न्यायालय क्षेत्राधिकार

उन राज्यों के लिए जो न्यायालय क्षेत्राधिकार साझा करते हैं, रिपोर्ट में उन्हीं आंकड़ों का उपयोग किया गया जहां उचित हो। उदाहरण के लिए, प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश की जनसंख्या की गणना पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जनसंख्या को मिलाकर की गई क्योंकि दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक ही उच्च न्यायालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

#### ताकत और सीमाएं

न्याय क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग हमारे देश के संदर्भ में एक अभूतपूर्व अभ्यास है जिसका उद्देश्य असमान और अब तक छुपी हुई जानकारी को एक साथ लाना है। इस साल की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 7 छोटे राज्यों और 18 बड़े राज्यों की न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर से स्थान दिया गया है। हम प्रत्येक रिपोर्ट के साथ सिस्टम की अधिक गहनता से जांच करते हैं और, हमेशा की तरह, केवल सबसे सटीक आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हैं। इतने अधिक आंकड़ों का प्रसारण संभावित हस्तक्षेप और इन संस्थानों के सुधार हेतु सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, बल्कि असमान आंकड़ों की उपलब्धता के कारण होने वाले आंतरिक अंतराल से भी संकेत मिलता है कि देश भर में विश्वसनीय, सुसंगत, समय पर और सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा सिस्टम स्थापित करना कितना जरूरी है जो कि भविष्य में सफलता के लिए सहयोगात्मक आंतरिक योजना (Collaborative Internal Planning) की सुविधा प्रदान करता है।

रिपोर्ट को सरकारी संगठनों, न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त डीजीपी, पुलिस और विभिन्न उप-प्रणालियों के अन्य विशेषज्ञों द्वारा चल रहे आकलन और सिफारिशों से लाभ मिलता है क्योंकि यह रिपोर्ट कई विशिष्ट नागरिक समाज समूहों के बीच एक साझेदारी है। इस प्रकार कई अलग-अलग दृष्टिकोणों का समावेश संकेतकों और रेटिंग के चयन की पुष्टि करता है।

2 गृह मंत्रालय की स्मार्ट पुलिसिंग पहल राज्यों को राज्य नागरिक पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की सलाह देती है। <https://digitalpolice.gov.in/>

यह रिपोर्ट न्याय प्रणाली के चयनित पहलुओं पर एक विशुद्ध मात्रात्मक अभ्यास (Quantitative Exercise) है। इसका मूल्यांकन अक्सर आंकड़ों की अनुपलब्धता और कमी तथा इसकी विसंगतियों के कारण सीमित होता है। यह रिपोर्ट कर्तव्य धारक, पदाधिकारी और हितधारक (Stakeholder) के खुद के विचार को रिपोर्ट में साझा करने की आकांक्षा नहीं रखता है जैसा कि कई अध्ययन और सर्वेक्षण में किया जाता है। फिर भी यह रिपोर्ट न्याय प्रशासन में शामिल संरचनाओं का

मूल्यांकन, सेवा और प्रतिक्रिया के स्तर की ओर इशारा करता है।

यहां आंकड़ों का चित्रण अन्य गुणात्मक अध्ययनों के लिए भी एक आवश्यक पूरक है और कई समस्याओं के संभावित समाधानों की ओर नज़र ले जाने में मदद करता है। हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट दूसरों को न्याय वितरण प्रणाली की संरचना का समग्र और अधिक विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

## सुझाव

**1** पुलिस स्टेशनों और मुकदमे के पहले न्यायालय में **24\*7 कानूनी मार्गदर्शन एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।**

उच्चतम न्यायालय के परमवीर सिंह सैनी के फैसले को पूरी तरह से लागू करें, जिसमें पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग की जांच के लिए हर पुलिस स्टेशन को **सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का आदेश** दिया गया है।

**3** रिक्तियों को तत्काल भरें।

हमें पहले उत्तरदाताओं के लिए प्राथमिकता के **आधार पर संसाधनों में वृद्धि** शुरू करने की आवश्यकता है।

**5** कानून से जुड़ी **हर प्रणालियों में जाति, लिंग और विशेष रूप से सक्षम लोगों की विविधता बढ़ाना।**

**6** प्रशिक्षण को एक सम्मानजनक भाग मानें और **सभी प्रशिक्षण सुविधाओं में मानव और वित्तीय संसाधनों को प्राथमिकता दें।**

**7** कैदियों की **14 श्रेणियों की रिहाई के लिए यूटीआरसी दिशानिर्देश सुनिश्चित करें**

यूटीआरसी और न्यायाधीशों सहित जेलों का दौरा करने के लिए आधिकारिक रूप से अनिवार्य किए गए सभी लोगों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इनके इन दौरों को इनके **प्रशासनिक प्रदर्शन की समीक्षा से जोड़ा जाना चाहिए।**

**8** एसएचआरसी को **पूर्ण संसाधनयुक्त होना चाहिए** और सक्रिय रूप से समुदाय तक पहुंचना चाहिए।

**9** न्याय वितरण प्रणाली को एक आवश्यक सेवा के रूप में नामित करें और इसे **हर समय प्रभावी न्याय वितरण प्रदान करने के लिए हर पहले उत्तरदाता के लिए बढ़ाएं, विस्तारित करें और सुसज्जित करें।**













**26. केस क्लीयरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{केस क्लीयरेंस रेट (एक्स)} = \text{उच्च न्यायालय के मामलों का निपटारा (सिविल + आपराधिक)}}{\text{उच्च न्यायालय में दायर मामले (दीवानी + आपराधिक)}} \times 100$$

2017	X1
2018	X2 ((X2/X1)-1)*100 = a
2019	X3 ((X3/X2)-1)*100 = b
2020	X4 ((X4/X3)-1)*100 = c
2021	X5 ((X5/X4)-1)*100 = d
2022	X6 ((X6/X5)-1)*100 = e

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2018 से 2022 तक।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट

**27. केस क्लीयरेंस रेट (अधीनस्थ अदालत) (प्रतिशत अंक)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{केस क्लीयरेंस रेट (एक्स)} = \text{अधीनस्थ अदालती मामलों का निपटारा (सिविल + आपराधिक)}}{\text{दाखिल किए गए अधीनस्थ अदालती मामले (दीवानी + आपराधिक)}} \times 100$$

2017	X1
2018	X2 ((X2/X1)-1)*100 = a
2019	X3 ((X3/X2)-1)*100 = b
2020	X4 ((X4/X3)-1)*100 = c
2021	X5 ((X5/X4)-1)*100 = d
2022	X6 ((X6/X5)-1)*100 = e

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2018 से 2022 तक।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट

**28. खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)।**

**सूत्र:**

[न्यायपालिका व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (जे. ई.)]- [राज्य व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (एस. ई.)]

2015-16	JE = X1
2016-17	X2 ((X2/X1)-1)*100 = a
2017-18	X3 ((X3/X2)-1)*100 = b
2018-19	X4 ((X4/X3)-1)*100 = c
2019-20	X5 ((X5/X4)-1)*100 = d
2020-21	X6 ((X6/X5)-1)*100 = e

PE = औसत (a,b,c,d,e)

2015-16	JE = X1
2016-17	X2 ((X2/X1)-1)*100 = a
2017-18	X3 ((X3/X2)-1)*100 = b
2018-19	X4 ((X4/X3)-1)*100 = c
2019-20	X5 ((X5/X4)-1)*100 = d
2020-21	X6 ((X6/X5)-1)*100 = e

SE = औसत (a,b,c,d,e)

**बेंचमार्क:** शून्य से बड़ा।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21।  
**डेटा स्रोत:** भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; खुला बजट भारत; गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग

# कानूनी सहायता

## बजट

**1. कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (%)**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन}}{\text{कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन + एनएएलएसए द्वारा आवंटन}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** उच्चतर, बेहतर  
**अवधि/तिथि:** 2021-22।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए); राज्य बजट दस्तावेज

**2. राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन}}{\text{कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन + एनएएलएसए द्वारा आवंटन}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 100%।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2020-21।  
**आँकड़ा स्रोत:** राज्य बजट दस्तावेज

**3. एनएएलएसए निधि का उपयोग (%) किया गया।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{एनएएलएसए निधियों का उपयोग किया गया}}{\text{एनएएलएसए निधियों को पिछले वर्ष से आगे बढ़ाया गया और इस वर्ष प्राप्त किया गया}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 100%।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2021-22।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

## मानव संसाधन

**4. डी. एल. एस. ए. सचिव रिक्ति (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{वास्तविक डी. एल. एस. ए. सचिव}}{100 - \text{स्वीकृत डी. एल. एस. ए. सचिव}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 0 प्रतिशत।  
**स्कोरिंग गाइड:** कम, बेहतर  
**अवधि/तिथि:** मार्च 2022।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।  
**नोट:** डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

**5. पी. एल. वी. प्रति लाख जनसंख्या (व्यक्ति)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पी. एल. वी.)}}{\text{राज्य की जनसंख्या}}$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** मार्च 2022 (जनसंख्या); जून 2022 (पी. एल. वी.)।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

**6. सचिवों को डी. एल. एस. ए. (%) के रूप में स्वीकृत किया गया।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{स्वीकृत डी. एल. एस. ए. सचिव}}{\text{कुल स्वीकृत डीएलएसए}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 100%।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** मार्च 2022।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।  
**नोट:** डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

## विविधता

**7. महिला पैनल वकील (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{महिला पैनल वकील}}{\text{कुल पैनल वकील}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** जून 2022।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

**8. महिला पीएलवी (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{महिला पैरा कानूनी स्वयंसेवक (पी. एल. वी.)}}{\text{कुल पैरा कानूनी स्वयंसेवक}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** जून 2022।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।

## इन्फ्रास्ट्रक्चर

**9. डी. एल. एस. ए. राज्य न्यायिक जिलों के रूप में (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{कुल डीएलएसए}}{\text{न्यायिक जिले}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 100%।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** मार्च 2022।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।  
**नोट:** डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

**10. डी. एल. एस. ए. में अग्रणी कार्यालयों की उपस्थिति (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{डी. एल. एस. ए. में कुल फ्रंट ऑफिस}}{\text{कुल डीएलएसए}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 100%।  
**स्कोरिंग गाइड:** उच्चतर, बेहतर

**अवधि/तिथि:** जून 2022।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।  
**नोट:** डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

**11. प्रति जेल कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{जेलों में कानूनी सेवा क्लीनिक}}{\text{कुल जेल}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** 1 प्रति जेल।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** दिसंबर 2021 (कुल जेल), 2021-22 (कानूनी सेवा क्लीनिक)।  
**डेटा स्रोत:** जेल सांख्यिकी भारत, 2021; राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

**12. गाँव प्रति कानूनी सेवा चिकित्सालय (संख्या)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{बसे हुए गाँव}}{\text{गाँवों में कानूनी सेवा चिकित्सालय}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना कम, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2011 (गाँव), 2021-22 (कानूनी सेवा क्लीनिक)।  
**डेटा स्रोत:** प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।

## वर्कलोड

**13. पी. एल. ए. मामले प्राप्त (%) के रूप में निपटारा गया।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{स्थायी लोक अदालतों (पी. एल. ए.) द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता है}}{\text{स्थायी लोक अदालतों द्वारा प्राप्त मामले}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2021-22।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

**14. कुल लोक अदालतें: निपटारा गए मामलों में मुकदमेबाजी से पहले के मामलों का हिस्सा (%)।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{लोक अदालतों द्वारा मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा किया जाता है}}{\text{लोक अदालतों द्वारा निपटारा गए कुल मामले}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2021-22। डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)।  
**नोट:** लोक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतें और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एस. एल. एस. ए.) द्वारा संचालित अदालतें शामिल हैं।

**15. एस. एल. एस. ए. लोक अदालतें: मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा कुल मामलों के रूप में किया जाता है।**

**सूत्र:**

$$\frac{\text{राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एस. एल. एस. ए.) द्वारा निपटारा गए मुकदमेबाजी से पहले के मामले}}{\text{राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एस. एल. एस. ए.) द्वारा उठाए गए कुल मामले}} \times 100$$

**बेंचमार्क:** उपलब्ध नहीं है।  
**स्कोरिंग गाइड:** जितना अधिक, उतना बेहतर।  
**अवधि/तिथि:** 2021-22।  
**डेटा स्रोत:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

# संदर्भ

## लेख-लेखक, शीर्षक, "समाचार पत्र, तिथि अध्ययन।

1. महामारी का जवाब देना: जेल और भीड़भाड़, (राज्यों के भीड़भाड़ कम करने के प्रयास), राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, 2020।
2. कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट।
3. रेणुका साने, नेहा साने, 'पुलिस के लिए बजट', लाइव मिंट, 11 अप्रैल 2017।

## पुलिस

1. पुलिस सुधार के लिए पद्मनाभैया समिति, 2000।
2. पुलिस संगठन, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पर डेटा।
3. 'सरकार एपी महिला पुलिस शाखा के लिए नियमों को अधिसूचित करती है', द हिंदू, 13 जनवरी 2022।
4. मानव शक्ति आवश्यकता अध्ययन, बैंगलोर सिटी पुलिस, जनग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी, 2014।
5. पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस स्टेशनों में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए मानव शक्ति की राष्ट्रीय आवश्यकता; पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, अगस्त 2014
6. भारत की जनगणना, 2011
7. एन. ए. एल. एस. ए. बनाम भारत संघ, [2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 400]
8. राज्यसभा, अतारांकित प्रश्न सं। 701, 8 फरवरी 2023
9. राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
10. प्रशिक्षण मास्टर प्लान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, 2009
11. परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह [2020 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3543]।
12. भारत में अपराध, 2021, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो
13. ऑर्डर जी. ओ. (सुश्री) नं. 167/2014 गृह, 2014, गृह विभाग, केरल सरकार,
14. 'केरल पुलिस साइबरडोम वार्नाक्राई रैनसमवेयर हमले के खिलाफ चेतावनी देता है', इंडियन एक्सप्रेस, 15 मई 2017

15. शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल1) 2017 की संख्या 2302]

## जेल

1. ग्लोबल प्रिजन ट्रेड्स, 2022, पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल
2. री: जेलों में कोविड-19 वायरस का संक्रमण [सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) सं. 1/2020]
3. ई/सी. एन. 15/2016/10, मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग का पच्चीसवां सत्र, 2016
4. जेल सांख्यिकी भारत, 2021, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो
5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सलाहकार सं। वी-17013/01/2011-पीआर
6. मॉडल जेल नियमावली, 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
7. 'सेंटर टू लॉन मॉडल प्रिजन्स एक्ट: अमित शाह', हिंदुस्तान टाइम्स, 5 सितंबर 2022 में 'जेल में बंद सभी दोषी प्रकृति से अपराधी नहीं हैं, और उन्हें समाज में वापस लाने का एक तरीका होना चाहिए'।
8. कर्नाटक की जेलों के अंदर, 2019, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल,

## न्यायपालिका

1. न्याय विकास पोर्टल, 31.08.2022 पर कोर्ट हॉल की राज्यवार उपलब्धता का विवरण।
2. बजट और शासन जवाबदेही केंद्र और दक्ष, भारत में न्यायपालिका के लिए बजट पर पंद्रहवें वित्त आयोग को ज्ञापन, 2019
3. भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 2020-21
4. डेटा बोलो: महामारी, 2022 के दौरान जिला न्यायालयों के प्रदर्शन पर एक नज़र; विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
5. ई-समिति समाचार पत्र, जून 2020; भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
6. वार्षिक रिपोर्ट 2020-21; भारत का सर्वोच्च न्यायालय
7. न्यायपालिका में मानव शक्ति योजना पर एक सौ बीसवीं रिपोर्ट: एक खाका, 1987; भारत का विधि आयोग

8. कानून की देरी पर 85 वीं रिपोर्ट: अदालतों में बकाया, 2002; गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति
9. इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [आपराधिक अपील सं। 2012 का 254-262]
10. बकाया और बैकलॉग: अतिरिक्त न्यायिक (डब्ल्यूओ) श्रमशक्ति का निर्माण, 2014; भारत का विधि आयोग,
11. अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक न्यायाधीश शक्ति की गणना के लिए टिप्पणी, 2016; राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति, 12. लोकसभा के उत्तर, बजट सत्र-17 वीं लोकसभा, 2020 का तीसरा सत्र।
13. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 'पिछले 5 वर्षों में पिछड़े समुदायों से उच्च न्यायालयों में केवल 15 प्रतिशत न्यायाधीशों की नियुक्ति: न्याय विभाग से लेकर पार पैनल तक', इकोनॉमिक टाइम्स, 2023।
14. भारतीय विधि आयोग, 245 वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2014
15. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रणाली में विचाराधीनता और विलंब को कम करने के लिए राष्ट्रीय पहल की सम्मेलन कार्यवाही, 2018
16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016
17. विघटनकारी विलम्ब: उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में विलम्ब का विश्लेषण; दक्ष,
18. विधि और न्याय मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 123 वीं रिपोर्ट, 2022।

## कानूनी सहायता

1. सभी के लिए न्याय-न्याय पर कार्य बल की रिपोर्ट; शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए पथप्रदर्शक, अप्रैल 2019
2. एन. ए. एल. एस. ए. का सांख्यिकीय चित्र, 2020
3. विचाराधीन समीक्षा समितियों के कार्यकरण पर अध्ययन (अप्रैल से जून 2020 तक)।
4. राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल,

5. एन. ए. एल. एस. ए. (निशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम 2010
6. एनएएलएसए (कानूनी सेवा चिकित्सालय) विनियम, 2011
7. हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर एनएएलएसए एस. ओ. पी. 2011
8. पैरालिगल स्वयंसेवकों के लिए एनएएलएसए की योजना, 2009
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ [2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 400]।
10. अग्रिम कार्यालयों पर एनएएलएसए दिशानिर्देश
11. धारा 10, नालसा लोक अदालत विनियम, 2009
12. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी-22ई
13. निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ [डब्ल्यू. पी. (C) नहीं। 565/2012]
14. भारत में अपराध, 2021।
15. एन. ए. एल. एस. ए. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना, 2022
16. विचाराधीन समीक्षा समितियों के लिए एनएएलएसए की मानक संचालन प्रक्रिया
17. 1382 जेलों में पुनः अमानवीय स्थितियाँ [डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 406/2013]
18. एन. ए. एल. एस. ए. का रिलीज़ \_ UTRC@75 अभियान।

## राज्य मानवाधिकार आयोग।

1. अब्दुल साथर बनाम सरकार के प्रधान सचिव और 5 अन्य [2006 का डब्ल्यू. पी. सं. 41791]
2. धारा 21, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
3. मानवाधिकार आयोग: एक नागरिक पुस्तिका, 2004; राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल,
4. पेरिस सिद्धांत, 'स्वतंत्रता और बहुलवाद की संरचना और गारंटी
5. भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण: एन. एच. आर. सी./एस. एच. आर. सी. का कार्यकरण (1993-2018); ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, 2019.

# तालिकाओं, आंकड़ों, मानचित्रों की सूची

तालिकाओं की सूची	Pg. No
<b>राष्ट्रीय निष्कर्ष</b>	
तालिका 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए श्रेणी और अंक	11
तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए श्रेणी और अंक तालिका	11
<b>पुलिस</b>	
3: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	48
<b>जेलों</b>	
4: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	78
<b>न्यायपालिका</b>	
5: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	102
<b>कानूनी सहायता</b>	
6: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	125
<b>एसएचआरसी</b>	
7: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	131

## आंकड़ों की सूची

<b>राष्ट्रीय निष्कर्ष</b>	चित्र 1: आई. जे. आर. 2020 और आई. जे. आर. 2022 के बीच सुधार स्कोरकार्ड	12
	चित्र 2: आई. जे. आर. 2019, आई. जे. आर. 2020 और आई. जे. आर. 2022 पर प्रदर्शन	13
	चित्र 3: स्तंभों में महिलाओं की हिस्सेदारी	15
	चित्र 4: पुलिस कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को 33 प्रतिशत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?	16
	चित्र 5: पुलिस में 'अन्य' का जिज्ञासु मामला	17
	चित्र 6: जनसंख्या अनुपात के अनुसार निर्णय	19
	चित्र 7: स्तंभों में रिक्तियां	20
	चित्र 8: न्याय प्रणाली के लिए बजट	23
	चित्र 9: कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा	24
	चित्र 10: राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों का हिस्सा	25
	चित्र 11: अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले	26
	चित्र 12: उच्च न्यायालयों में लंबित मामले	27
<b>पुलिस</b>	चित्र 13: पुलिस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां	38
	चित्र 14: महिला पुलिसकर्मी: संख्या बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत कम है	40
	चित्र 15: भारत: पुलिस प्रशिक्षण बजट (2020-21)	43
	चित्र 16: पुलिस की उपस्थिति: ग्रामीण-शहरी विभाजन	44
	चित्र 17: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति	54
	चित्र 18: पुलिस थानों में सीसीटीवी: एक अनुपालन रिपोर्ट	58
<b>जेलों</b>	चित्र 19: भारतीय जेलों में रहने की दर	66
	चित्र 20: जेलों में भीड़भाड़	67
	चित्र 21: निरोध अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदी	68
	चित्र 22: प्रदान की गई कैदियों और सुविधाओं का शैक्षिक विवरण	70
	चित्र 23: मानदंडों को पूरा करना	71
	चित्र 24: पिछले दशक में जेल के बजट के उपयोग की राष्ट्रीय प्रवृत्ति	74
	चित्र 25: प्रति कैदी दैनिक खर्च	76

## न्यायपालिका

चित्र 26: न्यायाधीशों की रिक्तियां और मामले की मंजूरी दर	90
चित्र 27: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीश बनाम अधीनस्थ न्यायालयों में योग्यता	93
चित्र 28: महिला न्यायाधीश	94
चित्र 29: प्रति न्यायाधीश लंबित मामले	97
चित्र 30: मामले की मंजूरी दर	99

## कानूनी सहायता

चित्र 31: पैरालिगल स्वयंसेवक: संख्या का मानचित्रण	114
चित्र 32: बजट उपयोग	116
चित्र 33: प्रति कानूनी सहायता क्लिनिक गाँव	118
चित्र 34: संख्या के आधार पर लोक अदालतों का प्रदर्शन	120
चित्र 35: पीड़ित मुआवजा	122
चित्र 36: विचाराधीन समीक्षा समितियों का प्रदर्शन	124

## एसएचआरसी

चित्र 37: आयोगों में रिक्तियां	134
चित्र 38: तीन वर्षों में एसएचआरसी द्वारा प्राप्त और निपटाए गए मामले	136
चित्र 39: एसएचआरसी तक पहुँच	138

## मानचित्रों की सूची

### राष्ट्रीय निष्कर्ष

मानचित्र 1: समग्र रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	10
मानचित्र 2: समग्र रैंकिंग; छोटे राज्य	10
मानचित्र 3: रैंकिंग विविधता; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	14
मानचित्र 4: रैंकिंग विविधता; छोटे राज्य	14
मानचित्र 5: मानव संसाधन की रैंकिंग: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	18
मानचित्र 6: मानव संसाधन की रैंकिंग: छोटे राज्य	18
मानचित्र 7: रैंकिंग का इरादा: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	22
मानचित्र 8: रैंकिंग का इरादा: छोटे राज्य	22

### पुलिस

मानचित्र 9: पुलिस रैंकिंग: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	32
मानचित्र 10: पुलिस रैंकिंग: छोटे राज्य	32

### जेलों

मानचित्र 11: कारागार श्रेणीकरण: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	62
मानचित्र 12: जेलों की श्रेणीकरण; छोटे राज्य	62

### न्यायपालिका

मानचित्र 13: न्यायपालिका रैंकिंग: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	86
मानचित्र 14: न्यायपालिका श्रेणीकरण: छोटे राज्य	86

### कानूनी सहायता

मानचित्र 15: कानूनी सहायता श्रेणीकरण: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	110
मानचित्र 16: कानूनी सहायता श्रेणीकरण: छोटे राज्य	110

### एसएचआरसी

मानचित्र 17: एसएचआरसी रैंकिंग	130
-------------------------------	-----



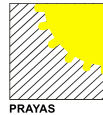
## इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के विषय में

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2022 अलग-अलग राज्यों में काम कर रही औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक करने के लिए सरकार के अपने आंकड़ों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र व्यापक मात्रात्मक सूचकांक है। यह IJR दक्ष, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, सामान्य कारण, सामाजिक न्याय केंद्र, कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र और टीआईएसएस-प्रयास के साथ साझेदारी में की गयी एक सहयोगी कोशिश है। पहली बार 2019 में प्रकाशित, IJR के तीसरे संस्करण में राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का आकलन शामिल है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पुलिस, न्यायपालिका, कारागारो और कानूनी सहायता में बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता के मात्रात्मक माप के आधार पर न्याय देने के लिए हर एक राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और लगातार कमियों को ट्रैक करना जारी रखता है।

मुख्य रिपोर्ट, डेटा का अन्वेषण करने और अन्य के लिए <https://indiajusticereport.org> पर जाएं।

हमसे संपर्क करें:- ईमेल आईडी: [indiajusticereport@gmail.com](mailto:indiajusticereport@gmail.com)

फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403



Data/design partner



Supported by:



TATA TRUSTS



Cyrus Guzder

Fiona & Louis Miranda